

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



मार्च 2021

खंड 75 अंक 3

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
देबा प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
एस. गंगाधरन

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2021

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<https://bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

वृद्धि के लिए नए अवसरों का सृजन शक्तिकान्त दास	1
---	---

लेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति	7
कोविड -19 के समय में अपरंपरागत मौद्रिक नीति	41
केंद्रीय बजट 2021-22: एक आकलन	57
गृहस्थ (हाउसहोल्ड) वित्तीय बचत और गृहस्थ ऋण- जीडीपी अनुपात के आकलन - 2020-21 की दूसरी तिमाही	81

वर्तमान सांख्यिकी	95
--------------------------	-----------

हाल के प्रकाशन	141
-----------------------	------------

भाषण

वृद्धि के लिए नए अवसरों का सृजन
शक्तिकान्त दास

वृद्धि के लिए नए अवसरों का सृजन* शक्तिकान्त दास

मैं सबसे पहले बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। बेशक यह संबोधन आभासी माध्यम पर होगा क्योंकि यही मौजूदा समय की बाध्यकारी वास्तविकता है। मैं बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को 184 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ देश के सबसे पुराने सेवारत चैंबर होने के साथ-साथ, आपने इस शहर ही नहीं बल्कि राष्ट्र की नियति पर भी अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 'कॉर्पोरेट ऐज़ ए सिटीजन' के तत्वावधान में, कारोबार में नैतिक व्यवहार, कौशल प्रशिक्षण एवं संतुलित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए, यह चैंबर वृहत्तर और अधिक न्यायसंगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आप अपने प्रयासों में पूर्णतः सफल हों, इसके लिए मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस महामारी से उत्पन्न नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए चैंबर हर संभव कोशिश कर रहा है। वस्तुतः, आज के अपने संबोधन को मैं 'वृद्धि के लिए नए अवसरों का सृजन' विषय पर केंद्रित करना चाहूँगा।

यद्यपि महामारियाँ विरल घटनाएँ होती हैं और वे शायद ही अपने पिछले अध्यायों को दुहराती हों, फिर भी उनके प्रभावों और नीतिगत उपायों का अध्ययन से हमें बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। भारत में ऐसी चार भयंकर महामारियों, यथा 1896 के प्लेग, 1918 के स्पैनिश फ्लू, 1958 के एशियन फ्लू और 1974 के चेचक ने दर्शाया है कि इन सभी महामारियों के दौरान जीडीपी में संकुचन/मंदी आई है। और, जान-माल की क्षति के हिसाब से, 1918 का स्पैनिश फ्लू 'मदर ऑफ ऑल पैनडेमिक्स' यानी महामारियों की जननी रहा। हालांकि यह देखा गया है कि हालात में बहुत तेज़ी से सुधार आया और महामारी के दो वर्षों के अंदर ही हालात सुधर गए। केवल स्पैनिश फ्लू की महामारी इसका अपवाद रही जिसमें चार वर्ष बाद 1922 में जीडीपी प्रति व्यक्ति, महामारी-

पूर्व स्तर पर दुबारा पहुँच पाई। इन महामारियों के बाद नीतिगत उपायों में चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए प्रावधान करने और इसके साथ ही, अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभावों को कम करने पर अनिवार्य रूप से ध्यानकेंद्रित किया गया। यह देखा गया कि वृद्धि, सरकारी व्यय पर अत्यधिक निर्भर हो गई, जबकि अपवादस्वरूप किए गए राजकोषीय उपायों से समय पर और सुचिन्तित तरीके से बाहर निकलना निकट भविष्य में समष्टि-आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अर्थव्यवस्था को स्थायी आधार पर पुनर्जीवित करने के लिए, निजी उपभोग पर व्यय एवं निवेश को तेज करने पर नीतिगत ध्यान देना ही सबसे जरूरी था।

कोविड-19 महामारी के दौरान राजकोषीय और मौद्रिक नीतिगत उपाय

पिछला वर्ष पूरे विश्व में अकल्पनीय कष्टों और दुखों का साक्षी रहा है और इसमें जान-माल की बहुत ही भयंकर क्षति हुई है। पूरे विश्व की सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने इसके विनाशकारी प्रभावों से लड़ने के लिए सभी परंपरागत और अपरंपरागत नीतिगत उपाय किए। वैश्विक स्तर पर, सरकारों ने महामारी की रोकथाम के लिए 2020 में बड़े-बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज दिये, जो करीब 14 ट्रिलियन डॉलर (वैश्विक जीडीपी का 13.5 प्रतिशत) था (आईएमएफ, 2021)। इसके परिणामस्वरूप, घाटा और कर्ज के स्तरों में उछाल आ गया। भारत में भी, केंद्रीय सरकार ने आर्थिक पैकेजों की एक श्रृंखला घोषित की, जिसमें सबसे पहले समाज के कमजोर तबकों को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके बाद, वृद्धि को पुनर्जीवित करने के लिए उपभोग और निवेश को गति प्रदान करने के लिए प्रति-चक्रिय उपाय किए गए।

दूसरी तरफ, केंद्रीय बैंकों ने, अग्रसक्रिय होकर कई परंपरागत और अपरंपरागत मौद्रिक नीति संबंधी उपायों की रूपरेखा बनायी और उन्हें कार्यान्वित किया, जो उनके अनुभवों और पिछले संकटों, और खासकर 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) पर आधारित थे। अधिकतर केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरें घटा दी हैं, पात्र प्रतिपक्षकारों के दायरे को बढ़ा दिया है और संपार्श्विक नियमों को आसान बना दिया है, वहीं रेपो परिचालनों की मात्रा और अवधि को भी बढ़ा दिया है। उन्होंने, महामारी-जनित उच्च अनिश्चितता को कम करने और निम्नतर दीर्घावधि ब्याज दरों की

* श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में गुरुवार, 25 फरवरी 2021 को दिया गया संबोधन।

सुविधा देने के लिए, अपने आस्ति खरीद कार्यक्रम (एपीपी) भी विस्तारित कर दिये हैं। इन उपायों को, भविष्य की मौद्रिक नीति के 'रुख' को संप्रेषित करते हुए, अंतर्निहित और सुस्पष्ट भावी मार्गदर्शन (फॉरवर्ड गाइडेंस) से और अधिक सशक्त बनाया गया।

भारत में, रिज़र्व बैंक ने कोविड-19 के मद्देनजर कई परंपरागत और अपरंपरागत उपाय किए। अपरंपरागत उपायों के अलावा, आरबीआई ने दीर्घावधि रेपो परिचालन (एलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) की शुरुआत की ताकि सिस्टम और क्षेत्र-विशेष चलनिधि को बेहतर बनाया जा सके और क्षेत्रवार ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा दबाव को दूर किया जा सके। कतिपय अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं, वहीं मोचन दबावों को कम करने के लिए म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) की भी शुरुआत की गयी। कई केंद्रीय बैंकों के विपरीत, आरबीआई की आस्ति खरीद से इसके तुलन पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा और इसलिए, इसने केंद्रीय बैंकिंग के मूल सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। ये खरीद जोखिम-मुक्त सरकारी (सॉवरिन) बॉन्डों (राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों सहित) तक सीमित थीं। वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाले बिना, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों को प्रोत्साहित करने पर ही हमारा ध्यान केंद्रित था। साथ ही, सहकारी परिणाम हासिल करने के लिए, भावी मार्गदर्शन (फॉरवर्ड गाइडेंस) को रिज़र्व बैंक की संचार रणनीति में प्रमुखता दी गई। हालत में सुधार को बल देने के लिए प्रचुर चलनिधि सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता ने चलनिधि संबंधी भय को दूर कर दिया और बाजार के मनोभावों को बल प्रदान किया। हम वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए, प्रचुर चलनिधि के प्रावधान के जरिये हालात में सुधार की प्रक्रिया को समर्थन देना जारी रखेंगे।

व्यापार और भुगतान संतुलन पर प्रभाव

जीडीपी और व्यापार में कोविड-19 जनित गिरावट के प्रभाव की तुलना यदि 2008 के जीएफसी से की जाए तो विपरीत प्रवृत्तियों का पता चलता है। 2020 के दौरान वैश्विक जीडीपी में अनुमानतः 3.5 प्रतिशत का संकुचन हुआ है, जो जीएफसी के दौरान हुए 0.1 प्रतिशत की तुलना में बहुत ज्यादा है। वहीं 2020 के दौरान वाणिज्यिक व्यापार में 9.2 प्रतिशत संकुचन हुआ है जबकि 2009 में यह 22.3 प्रतिशत था। इस भिन्नतायुक्त पैटर्न के

पीछे, हाल के घटनाक्रम के दौरान विभिन्न देशों में लॉकडाउन से प्रेरित विभिन्न घरेलू कारकों की ही प्रमुख भूमिका रही होगी।

यद्यपि वाणिज्यिक व्यापार में 2020 के अंत से पुनरुद्धार के प्रारम्भिक संकेत मिलने लगे हैं, सेवा क्षेत्र में हालात में सुधार अभी भी गति नहीं पकड़ पाया है क्योंकि सुस्त सीमापार पर्यटन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण इस क्षेत्र के समग्र प्रदर्शन पर अब भी असर पड़ रहा है। कुछेक एशियाई देशों और चिकित्सा उपकरणों एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे कतिपय क्षेत्रों द्वारा असमान वैश्विक व्यापार के हालात में सुधार हुआ लेकिन यह कब तक बरकरार रहेगा यह एक चिंता का विषय है। वैश्विक व्यापार गतिविधियों के पुनरुद्धार में एक महत्वपूर्ण बाधा है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अब भी जारी व्यवधान। नवंबर 2020 से लदान लागतों में बहुत तेज वृद्धि हुई है और माल सुपुर्दगी समय भी खिंच गया है, जिससे समान की कीमतों में तेजी आई है। इन मुद्दों पर समूचे विश्व के नीति निर्माताओं द्वारा तत्काल ध्यान दिया जाना अपरिहार्य है।

मांग और आपूर्ति आघातों का प्रभाव भुगतान संतुलन पर भी परिलक्षित होता है। एक ओर, पण्य-निर्यातक देशों ने, अपने व्यापार के निवल मान पर ऋणात्मक आघातों के कारण, चालू खाते में निम्नतर अधिशेषों का सामना किया, वहीं दूसरी ओर, भारत जैसे निवल पण्य-आयातक देश इससे लाभान्वित हुए और कम घाटा दर्ज किया। यहाँ तक कि अधिशेष भी दर्ज किया। कच्चे तेल की कीमतें कम होने और महामारी के आरंभिक दिनों में कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन के कारण कमजोर मांग होने की वजह से अप्रैल-जनवरी 2020-21 के दौरान भारत के तेल आयात बिल में 42.5 प्रतिशत की कमी आयी। वस्तुओं के व्यापार के विपरीत, यात्रा प्रतिबंधों के कारण यात्रा से होने वाली आय में तेजी से हुई गिरावट के बावजूद भारत के सेवाक्षेत्र का निवल निर्यात अपेक्षाकृत सुदृढ़ रहा। अधिकांश अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारत के सेवाक्षेत्र के निर्यात को सॉफ्टवेयर निर्यात से बल मिला। घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों को कोर ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं के लिए वैश्विक मांग बढ़ने से लाभ मिला क्योंकि महामारी के दौरान उनके ग्राहकों का फोकस आईटी संचालन के लिए नए मॉडल पर केंद्रित रहा। मेजबान देशों में बड़े पैमाने पर नौकरियां समाप्त होने के कारण विप्रेषण के अंतर्वाहों में कमी आई। इसके बावजूद व्यापार घाटा कम होने और सेवाओं का निवल निर्यात मजबूत होने की बदौलत विप्रेषण में आयी गिरावट की अच्छी खासी भरपाई हुई।

जैसा कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने उल्लेख किया है, भारत के आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का रुख वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत रहा और डिजिटल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलने के कारण इसमें वर्ष 2020 में सकारात्मक रूप से वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 (अप्रैल-दिसंबर) में, भारत में 40.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ जो एक साल पहले के 31.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। भारत के आशावादी विकास दृष्टिकोण और पर्याप्त वैश्विक चलनिधि की स्थिति ने भी वर्ष 2020-21 (19 फरवरी तक) में घरेलू इक्विटी बाजार में 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रेरित किया। अनिवासी भारतीयों ने भी भारत में बैंकों में राशि जमा करने में बहुत बढ़ोतरी की। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान चालू और पूंजी खाता दोनों में अधिशेष की स्थिति रही जो विदेशी मुद्रा भंडार में हुई वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। 19 फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 583.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें मार्च 2020 समाप्त होने के बाद से 106.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। घरेलू और वैश्विक सुधार दोनों से जुड़ी प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों द्वारा बाह्य क्षेत्र के परिदृश्य में बदलाव जारी रहेगा।

कोविड के बाद भारत में उभरते अवसर

अब मैं भारत में कोविड के बाद कुछ उभरते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने विशेष रूप से उल्लेखनीय सात प्रमुख क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है।

(i) विनिर्माण और आधार-संरचना

विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि में सुधार हेतु अग्रणी भूमिका निभा रहा है जबकि सघन रूप से एक-दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क पर आधारित कई सेवाओं के उप-क्षेत्रों को इस संकट ने बुरी तरह प्रभावित किया है। एक सशक्त विनिर्माण क्षेत्र और आधार-संरचना को विकसित करने की दिशा में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान और केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत की गई पहल से बाकी क्षेत्रों के साथ इसके मजबूत जुड़ाव को स्वीकार किया गया है। प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का अभिन्न अंग बनाना है। यह श्रम बाजार में सुधारों के साथ-साथ, विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक उन्नत वक्र रेखा में विकास को आगे बढ़ाने के लिए सहायक हो सकता है और इसकी रोजगार क्षमता का लाभ उठा सकता है।

(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मौजूदा सदस्यता का लगभग दो-तिहाई हिस्सा छोटे और मझोले उद्यमों का है। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र लगभग 6.33 करोड़ उद्यमों के विशाल नेटवर्क के साथ अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन के रूप में उभरा है, जिसका योगदान हमारे सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 30 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 48 प्रतिशत¹ का है। यह क्षेत्र लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और इस मामले में केवल कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। यह क्षेत्र महामारी के दौरान विशेष रूप से कमजोर हुआ है, जिसके कारण दबाव से निपटने और इस क्षेत्र के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। इस संबंध में, सरकार द्वारा दो प्रमुख योजनाएं, अर्थात्, आपातकालीन ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) और गौण ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) की शुरुआत की गई। रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती, उच्च संरचनात्मक और टिकाऊ चलनिधि, ऋण चुकौती पर स्थगन, परिसंपत्ति वर्गीकरण पर रोक, ऋण पुनर्गठन पैकेज और नए एमएसएमई उधारकर्ताओं को संवितरित ऋण पर सीआरआर छूट के रूप में विभिन्न प्रकार के मौद्रिक और विनियामक उपायों द्वारा इनको विधिवत सहयोग प्रदान किया गया है। इन उपायों से न केवल एमएसएमई क्षेत्र में तनाव को कम करने में सहायता मिलेगी बल्कि नए अवसर भी खुलेंगे। आगे चलकर, रिजर्व बैंक एमएसएमई क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को सहयोग देने के लिए तैयार है।

(iii) प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष

भारत में डिजिटल विस्तार ने एक नई ऊँचाई हासिल कर ली है। अब समय आ गया है कि इसके अनुप्रयोगों का लाभ उठाया जाए और साथ ही साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। लगभग 1.2 बिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर और 750 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर के साथ, भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार और सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है²।

¹ एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

² 31 मार्च, 2020 के अनुसार। स्रोत: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)।

डिजिटल क्षमताओं में सुधार और संयोजकता के सर्वव्यापी होने के साथ ही तकनीकी नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी संचालित क्रांति भारत की अर्थव्यवस्था को जल्दी ही और मौलिक रूप से बदलने के लिए तैयार है। उनके पास कृषि, विनिर्माण और व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच में सुधार करने की क्षमता है। इसके कारण वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय समावेशन बेहतर होने की संभावना है और सूचना की असमानता और ऋण जोखिम कम हो सकता है। इसी तरह, खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ऑडियो-विज़ुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम और दूरस्थ शिक्षा द्वारा आवश्यक कौशल और स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले कौशल के बीच तालमेल को सुदृढ़ किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार मेडिकल रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन, स्मार्टफोन और मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से निदान और डॉक्टर के दूरस्थ प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। कृषि उत्पादों की बिक्री का मार्गदर्शन करने के लिए वास्तविक समय बाजार की जानकारी का उपयोग करके और कृषि निर्गमों के मार्गदर्शन के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मृदा, जल और जलवायु आंकड़ों का उपयोग करके 'सटीक खेती' हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का अंगीकरण कृषि क्षेत्र में उच्च मूल्य वर्धन कर सकता है। लेन-देन की अपनी कम लागत के साथ ई-कॉमर्स क्षेत्र पहले से ही बाजार संरचना में क्रांति ला रहा है जिसकी पराकाष्ठा गहन बाजार एकीकरण में हुई है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत में अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय (जीईआरडी) मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रेरित है जिसमें कुल अनुसंधान एवं विकास में 56 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एक वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार अधिनायक बनने के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र आगे आए जैसा कि कई उभरते बाजारों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हुआ है।

(iv) स्वास्थ्य

कोविड-19 के पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्र निस्संदेह एक प्रमुख कमजोरी (फॉल्ट लाइन) के रूप में और साथ ही जबरदस्त विकास अवसरों के क्षेत्र के रूप में उभरा है। 3000 से अधिक कंपनियों के नेटवर्क के साथ, भारत अब संख्या के अनुसार फार्मास्यूटिकल उत्पादन में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, इस क्षेत्र में सालाना 12

बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार अधिशेष पैदा हो रहा है। भारत अब टीकों की वैश्विक मांग के आधे से अधिक की आपूर्ति करता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और कम उत्पादन लागत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि दिखाई पड़ने की उम्मीद है। कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में यह आशा की जाती है कि टीकों और दवाओं के लिए बढ़ी हुई वैश्विक मांग की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी होगी। भविष्य में इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए किफायती रूप से मूल्य श्रृंखला के हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र आपूर्ति बढ़ाई जाए। कॉर्पोरेट सेक्टर को इस क्षेत्र में स्तर और कौशल सृजन के लिए ज्यादा निवेश करने की जरूरत है।

(v) निर्यात को प्रोत्साहन

वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे अपनी गहरी मंदी से उबर रही है, वैश्विक व्यापार गतिविधि के आगे चक्रीय उत्थान की स्थिति में होने की संभावना है। भारत के मामले में, ऐसे संरचनात्मक सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है जो मजबूत विकास और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में घरेलू उद्योग की व्यापक भूमिका की नींव रख सकते हैं। क्षेत्रीय शक्तियों और संभावित अवसरों पर आधारित पीएलआई योजना कुछ ऐसे विजेता क्षेत्रों की पहचान करती है जो घरेलू निर्माताओं को किफायत प्राप्त करने में और वैश्विक बाजार में उनके पदचिह्नों का विस्तार करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस योजना के बारे में कंपनियों से प्राप्त प्रतिक्रिया- विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण उद्योग में बहुत उत्साहजनक बतायी गयी है। यह निर्यात प्रोत्साहन खाद्य उत्पादों अन्य क्षेत्रों जैसे परिधान और वस्त्र; पूंजीगत वस्तुएं; ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक; और इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी-कंडक्टर से भी आने की संभावना है; चूंकि पीएलआई योजना के तहत प्रोत्साहन संरचना की परिकल्पना अगले पांच वर्षों के लिए की गई है, इसलिए घरेलू उद्योग को दीर्घावधि में व्यवहार्य बने रहने के लिए गुणवत्ता और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके अपनी ताकत विकसित करने की जरूरत है।

(vi) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

एक अन्य नीतिगत क्षेत्र, जिसकी भारत के निर्यात और विकास को टिकाऊ प्रोत्साहन देने के लिए ध्यान देने की जरूरत है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है। संभावित एफटीए को न केवल

घरेलू ताकत और वैश्विक अवसर बल्कि महामारी के बाद की अवधि में उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य को भी संज्ञान में लेने की जरूरत है। भावी एफटीए को तैयार करते समय, एफटीए के साथ भारत का अनुभव एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देशक हो सकता है। प्रमुख विचार उन देशों और क्षेत्रों की पहचान करने में होना चाहिए जिनमें न केवल घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक बाजार के रूप में संभावना है बल्कि उनमें घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाने की गुंजाइश है, विशेष रूप से पीएलआई योजना के तहत कवर किए गए क्षेत्रों में। ब्रेक्सिट के बाद का परिदृश्य ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ अलग व्यापार समझौतों के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करता है। एफटीए इन अर्थव्यवस्थाओं के साथ न केवल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा दे सकता है बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में भी अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण, अफ्रीका में भारतीय फर्मों से निर्यात और निवेश की अपार संभावनाएं भी पैदा हो गई हैं। भारतवशियों की बड़ी उपस्थिति इस क्षमता का दोहन करने में मदद कर सकती है।

(vii) सेवा निर्यात

विश्व सेवा व्यापार में सुधार, जो महामारी के पूर्व की अवधि में माल व्यापार की तुलना में तेजी से हुआ के वर्तमान सीमा पार यात्रा प्रतिबंधों के कारण धीमी रहने की उम्मीद है। तथापि दक्षता के साथ व्यापार किए जाने पर अधिक जोर दिया रहा है। इसमें अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर सेवाओं की मांग बढ़ी है और लाए गए

निरंतर वैश्विक मूल्य शृंखला पुनर्संरचना (ग्लोबल वैल्यू चेन रीकॉन्फिगरेशन) द्वारा नए व्यवसाय के अवसर बढ़े हैं। इससे आईटी कंपनियों के सॉफ्टवेयर निर्यात में सृष्टिता भी आई है। डब्ल्यूटीओ (फरवरी 2021) के एक हालिया अध्ययन में आकलन है कि 2030 तक डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण वैश्विक व्यापार में वृद्धि औसतन 2 प्रतिशत सालाना अधिक होगी। इससे व्यापार लागत को कम करने और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने से व्यापार के लिए नए अवसर खुलेंगे। डिजिटलीकरण पर हमारे द्वारा अधिक ध्यान दिए जाने को देखते हुए, भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक देश होने के नाते, बढ़ी हुई सेवाओं का हमें लाभ मिलने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, हम एक निर्णायक परिवर्तन की संक्रांति पर हैं। सारी दुनिया के विपरीत, भारत में कोविड-19 के मामलों में गिरावट आई है और हमारे लिए इस गिरावट का लाभ उठाना और कड़ी मेहनत से अर्जित सफलता को आधार बनाकर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। हालांकि, देश के कुछ हिस्सों में संक्रमण के मामले फिर से शुरू हो गए हैं। हमें सतर्क, दृढ़ और तैयार रहने की जरूरत है। कोविड युद्ध जारी है। 2020 की लड़ाई जीती गई है लेकिन इसके लिए जीवन, आजीविका और आर्थिक गतिविधियों के मामले में काफी अधिक कीमत चुकानी पड़ी है। हमें 2021 की लड़ाई भी जीतने की जरूरत है। आइए, इस युद्ध को भी अंततः जीत लेने का संकल्प लें।

धन्यवाद, सुरक्षित रहें, नमस्कार।

लेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

कोविड -19 के समय में अपरंपरागत मौद्रिक नीति

केंद्रीय बजट 2021-22: एक आकलन

गृहस्थ (हाउसहोल्ड) वित्तीय बचत और गृहस्थ ऋण-
जीडीपी अनुपात के आकलन - 2020-21 की दूसरी तिमाही

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

अपने-अपने आवाम को टीका लगाने की जिस तरह से देशों के बीच होड़ मची है, उससे लगता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में पटरी पर लौट आएगी। हालांकि, बॉन्ड विजलैन्टी इस सुधार में रोड़ा अटका सकते हैं, वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर सकते हैं और उभरते बाजारों से पूंजी बहिर्गमन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक प्रतिफल वक्र के व्यवस्थित क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन इसके लिए दोनों को साथ आना होगा और तभी तबाही को पहले ही रोका जा सकता है। भारत में उच्च वृद्धि को फिर से हासिल करने के लिए फिजाँ में बेचैनी है जिसके संकेत इस बात से मिलते हैं कि पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है और इसमें बदलाव आ रहा है तथा कॉर्पोरेट्स के कमाई संबंधी परिणामों ने बाजार की प्रत्याशाओं को भी मात दे दी है। मुद्रास्फीति में वृद्धि होने का दबाव देखने को मिला है।

भूमिका

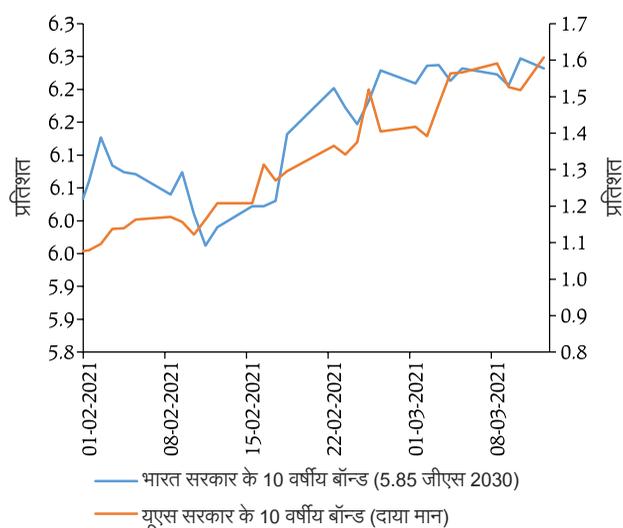
चार्ल्स डिकेंस ने अपनी पुस्तक ग्रेट एक्सपेक्टेडेंस में लिखा है, मार्च में सूरज गर्म चमकता है और हवा शीतल बहती है। दिन में गर्मी, और रात में ठंड रहती है। सर्दी जा रही होती है और वसंत का आगमन हो रहा होता है जिसमें कुछ ही पल में हवाएं चलने लगती है, बादल छा जाते हैं, एवं आसमान का रंग बादल जाता है और फिर मौसम मनोरम हो जाता है।

मार्च की शुरुआत में पांच घटनाएँ घटित हुईं। पहला, विश्व स्तर पर और भारत में कम दाम पर बॉन्ड की फ्लैश बिक्री के बाद स्थिरता लौटी जो मार्च के आगमन की शुरुआत हो गई, जिसने बॉन्ड पहरुओं को पुकारने के लिए उकसा दिया जो बाजार को कब्जे में लेने के लिए पूरी तैयारी के साथ वापस आ गए हैं¹ (चार्ट 1)। भारत में, 10 वर्षीय प्रतिफल बेंचमार्क अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के दौरान औसत 5.93 प्रतिशत था जो 2 फरवरी को केंद्र सरकार के बाजार उधारी कार्यक्रम की घोषणा से बढ़कर 6.13 प्रतिशत हो गया, जो कि अपेक्षा से कहीं ज्यादा था²। हालांकि, 5

* यह लेख माइकल देब्रत पात्र, कुणाल प्रियदर्शी, शशिधर एम लोकरे, अभिलाषा, कृष्ण मोहन कुशवाहा, अभिनंदन बोराड, जॉन विजय गुरिया, मनु शर्मा, शोभित गोयल, इप्सिता पाद्री, रचित सोलंकी, अवनीश कुमार, ऋषभ कुमार, रिगजेन यंगडोल, साक्षी अवस्थी, शशि कांत, अशीष थॉमस जॉर्ज, अवधेश कुमार शुक्ला, देबा प्रसाद रथ, प्रजा दास और समीर रंजन बेहरा ने तैयार किया है। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और यह भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

¹ फाइनेंशियल टाइम्स, 27 फरवरी 2021

चार्ट 1: भारत तथा यूएस में सरकारी बॉन्ड प्रतिफल



स्रोत: ब्लूमबर्ग

फरवरी को रिजर्व बैंक द्वारा उपायों की घोषणा किए जाने के बाद, बेंचमार्क 11 फरवरी तक 5.96 प्रतिशत तक कम हो गया। इसके बाद, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के रूप में वैश्विक प्रभाव-विस्तार, राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणाओं, केंद्रीय बैंक के रुख के उलटफेर और आशंकाओं के बीच मुद्रास्फीति भय ने और अमेरिकी ट्रेजरी की प्राथमिक नीलामी में उदासीन प्रतिक्रिया ने बॉन्ड बाजारों में दुनिया भर में खलबली मचा दी। 10 वर्षीय अमेरिकी बेंचमार्क के लगभग 1 प्रतिशत से बढ़कर 1.6 प्रतिशत हो जाने से भारत में निरंतर बिक्री और मंदड़िया बीकावली से बॉन्ड बाजार गर्त में चला गया था; 5 मार्च तक, भारत में बेंचमार्क 6.23 प्रतिशत तक पहुंच गया था, लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा भारी ऑपरेशन ट्विस्ट की घोषणाओं से राहत मिली और 9 मार्च को बेंचमार्क लगभग 6.21 प्रतिशत पर रहा। यद्यपि, यूएस प्रतिफल में बढ़ोतरी से हुए प्रभाव-विस्तार के बाद प्रतिफल सुदृढ़ हो गया।

यद्यपि उथल-पुथल थोड़े समय के लिए था, तथापि इसने परिणामों से पहले बहुत दूर तक चलने वाली प्रत्याशाओं के अस्थिर प्रभाव की झलक दे दी, मानो वसंत के आगमन के साथ ही ग्रीष्म ऋतु बहुत पीछे नहीं रह सकता – मानो जितना सुधार होना था हो गया है और मुद्रास्फीति आसपास ही है। यह एक चीर-परिचित कथानक है। महामारी में मिश्रित उपायों की जरूरत

² ब्लूमबर्ग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, बाजार सहभागियों को 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट में घोषित ₹12 लाख करोड़ रुपये सकल उधारी के स्थान पर ₹10.6 लाख करोड़ रुपये की अपेक्षा थी।

पड़ती है मसलन राजकोषीय प्रोत्साहन; मौद्रिक निभाव; रोक कर रखी गयी मांग को रिलीज करना; टीकाकरण शुरू करना, जिनके बूते बॉन्ड विजलैन्टी फलते-फूलते हैं। चूंकि वर्ष 2021 के लिए संवृद्धि का पूर्वानुमान लगाया गया है, इसलिए उन्हें उनमें लंबे निष्क्रिय मुद्रास्फीति की काली छाया दिखती है, जो बॉन्ड का कट्टर दुश्मन है क्योंकि यह उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली नियत आय के वास्तविक मूल्य को कम कर देता है। इन अव्यक्त चिंताओं के साथ, बॉन्ड विजलैन्टी केंद्रीय बैंक के उदार रहने के वादे के बारे में संशयपूर्ण हो जाते हैं और कोलाहल शुरू कर देते हैं। इसका बहाना देश-विशिष्ट विशेष प्रकृति के कारक हो सकते हैं जैसे कि भारत में प्रत्याशा से अधिक सरकारी उधारी यद्यपि यह दोनों सकल और निवल मामले पिछले वर्ष से कम हैं; संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में निकट भविष्य में संतुलित-मुद्रास्फीति की वापसी, लेकिन जैसा कि फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष ने बताया था, मुद्रास्फीति की गति समय के साथ बदल सकती है, लेकिन पैसे के साथ नहीं। इसके अलावा, फेड ने कहा है कि यह आगे जाने वाले 2 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति को लक्षित करेगा, जिससे कुछ समय के लिए मुद्रास्फीति को 2 प्रतिशत से अधिक सहन किया जा सकता है। लगभग अचानक से, मुद्रास्फीति के बारे में सबसे बुरी आशंका फिर से बढ़ गई है। संभवतः इस बात कि सीमा है कि आर्थिक सुधार में महंगाई का डर कितना दूर तक जा सकता है!

फिर भी, संभावित खतरों या समस्याओं का पूर्व ज्ञान एक सुनियोजित लाभ देता है: बॉन्ड विजलैन्टी फिर से निकल पड़े है, प्रकट रूप में वे स्वेच्छाचारी सरकारों और केंद्रीय बैंकों को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार, वे आर्थिक सुधार को कमजोर और तेज वित्तीय बाजारों अस्थिर कर सकते हैं। अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर आशंकाएं पहले ही उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) पर मंडराने लगी हैं। निवेशकों ने ईएमई स्टॉक और बॉन्ड से पैसा निकालना शुरू कर दिया है, जिससे लगातार आ रहे अंतर्वाह अचानक समाप्त हो, जो कि अक्टूबर 2020 से निर्बाध रहा था। अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ) का कहना है कि उभरती इक्विटी और कर्ज बाजार में विदेशी निवेश फरवरी के उत्तरार्द्ध में ऋणात्मक हो गया, जिससे वर्ष 2013 के टेपर टैंट्रम की आशंका फिर से प्रबल होने लगी है। यद्यपि, कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बाह्य शेष और कर्ज प्रोफाइल वर्ष 2013 की तुलना में आज बेहतर आकार में हैं, फिर भी वे इससे बचे नहीं हैं। हालांकि, निवेशक अधिक समझदार हो

गए हैं जिसमें अप्रभावी रूप से व्यापक कर्ज-बिक्री के कारण कॉर्पोरेट बॉन्ड के साथ विशेष रूप से आस्तियों को लक्षित करना पड़ता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में कम प्रतिफल का "पुश" कारक और उभरते बाजारों में संभावित मुद्रा अधिमूल्यन का "पुल" कारक उल्टा हो सकता है। उप-शून्य वास्तविक प्रतिफल ने भी निवेशकों को वित्तीय बाजारों के अन्य क्षेत्रों में प्रशंसक बनाने के लिए प्रेरित किया है; प्रतिफल में हाल ही में वृद्धि ने स्वाभाविक रूप से इक्विटी और विदेशी मुद्रा बाजारों में उतार-चढ़ाव को घबराए हुए देखा है। बॉन्ड की कीमतें ज्यादातर समय के लिए प्रतिचक्रीय होती हैं। यह सुविधा उन्हें इक्विटी के लिए बहुत आकर्षक विविधता लाने वाली बनाती है, जिनमें से कीमतें आर्थिक चक्र के साथ मिलकर अधिक प्रचक्रीय होती है, जिससे यह ऊपर और नीचे होती रहती है।

दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने इस बात पर जोर दिया कि वे निभाव की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति सच्चे रहें। इस संदर्भ में, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में एक प्रेस साक्षात्कार में की गई टिप्पणी पर विचार करना सार्थक है, जिसे व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था:

“प्रतिफल वक्र का एक क्रमिक विकास क्रमबद्ध होना चाहिए, यह अन्यथा नहीं हो सकता है... .. पिछले साल की आरबीआई की कार्रवाइयों को देखें... अप्रैल से अब तक, हमने ₹3 लाख करोड़ से अधिक का कुल खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) किया है। अगले वर्ष की उधार आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस बात का कोई कारण नहीं है कि वर्तमान वर्ष में हमने जितना किया है उससे आरबीआई को अगले वर्ष यानी 2021-2022 में कम ओएमओ करना चाहिए ...। हमने परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के लिए इस छूट को बढ़ाया है। इससे एक और ₹4 लाख करोड़ के लिए गुंजाइश हो जाएगा। अब हम इसका गणन करते हैं। पिछले वर्ष के ओएमओ का ₹3 लाख करोड़, यह और भी अधिक हो सकता है, ₹4 लाख करोड़ का गुंजाइश एचटीएम छूट की वजह से बना, जो कि ₹7 लाख करोड़ है। निवल उधारी ₹9 लाख करोड़ है, इसलिए, भारत सरकार की उधार आवश्यकता को ठीक से प्रबंध किया जा सकता है ... चलनिधि पर्याप्त बनी रहेगी, हम उचित समय पर चलनिधि उपलब्ध कराएंगे और हम देखेंगे कि उधार कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है।”

केंद्रीय बैंकों के इस प्रकार के अग्रगामी मार्गदर्शन से तनाव भी कम हो जाता है - अगर वे मुश्किल से हुए आर्थिक पुनरुत्थान को देखते हैं, और विनियामकीय सहनशीलता से निर्मित वित्तीय स्थिरता, जिसे साहसिकता से खतरा है, तो उन्हें चिंता हो सकती है। क्या वे अधिक आक्रामक कार्रवाइयों में संलिप्त होंगे? आखिरकार, उनके पास आस्ट्रेलिया खरीददारी का ब्रह्मास्त्र। यदि बॉन्ड का प्रतिफल बहुत अधिक हो जाता है, तो केंद्रीय बैंकों द्वारा बॉन्ड खरीद का अथक भार बाजारों को स्थिर करेगा, लेकिन ऐसा बाजार गतिविधि की कीमत पर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के संकल्प का हालिया पुनर्विचार एक अनुस्मारक है कि यदि वे ऐसा करने के लिए दृढ़ हैं तो केंद्रीय बैंकों के पास बॉन्ड के प्रतिफल की उच्चतम सीमा निश्चित करने की मारक क्षमता है। बाजार में शिथिलता के संकेतों का लाभ उठाने हेतु परिदृश्य को परिमार्जित करने के लिए निवेशकों को अपने जोखिम को समझना चाहिए। लाभ-अलाभ, टीआईपीएस और पॉलिसी स्टिमुलस से परे बाजार जो महसूस नहीं करता है, वह यह है कि अर्थव्यवस्था अपने मौजूदा स्थिति में उच्च ब्याज दरों का सामना किसी भी तरीके से नहीं कर सकती है। इसमें सुधार हो रहा है लेकिन निश्चित रूप से अभी तक खतरे से बाहर नहीं है। प्रतिफल वक्र के एक क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जो प्रयास कर रहा है उसमें बहुत समझदारी है। लेकिन इस तांडव को रोकने के लिए दोनों को साथ आना होगा।

बाकी सब चीज कि तरह ही समष्टि-आर्थिक नीति बनाना भी प्रदर्शन प्रभाव पर निर्भर करता है। ऐसे देशों में भी, जो नवाचार सफल होते हैं, वे अलग-अलग स्तर के साथ सफलता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, एई के लिए काम करने वाले दो प्रयोगों ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी अच्छा काम किया - व्यापार उदारीकरण; और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। दोनों जिन्होंने बाद के कई लोगों को उत्साहित नहीं किया वे पूंजी खाता उदारीकरण और स्वतंत्र रूप से अस्थायी विनिमय दर हैं। अब, एई में, राजकोषीय नीति सक्रिय प्रतिभागी मोड पर है और मौद्रिक नीति निभाव है। इसी तरह की नीतिगत रुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता है। यह एक आवश्यक विन्यास है, लेकिन क्या यह विफल होना चाहिए, क्योंकि इससे पूंजी बहिर्वाह और मुद्रा मूल्यहास हो जाएगा। दोनों कारकों से पता चलता है कि भारत

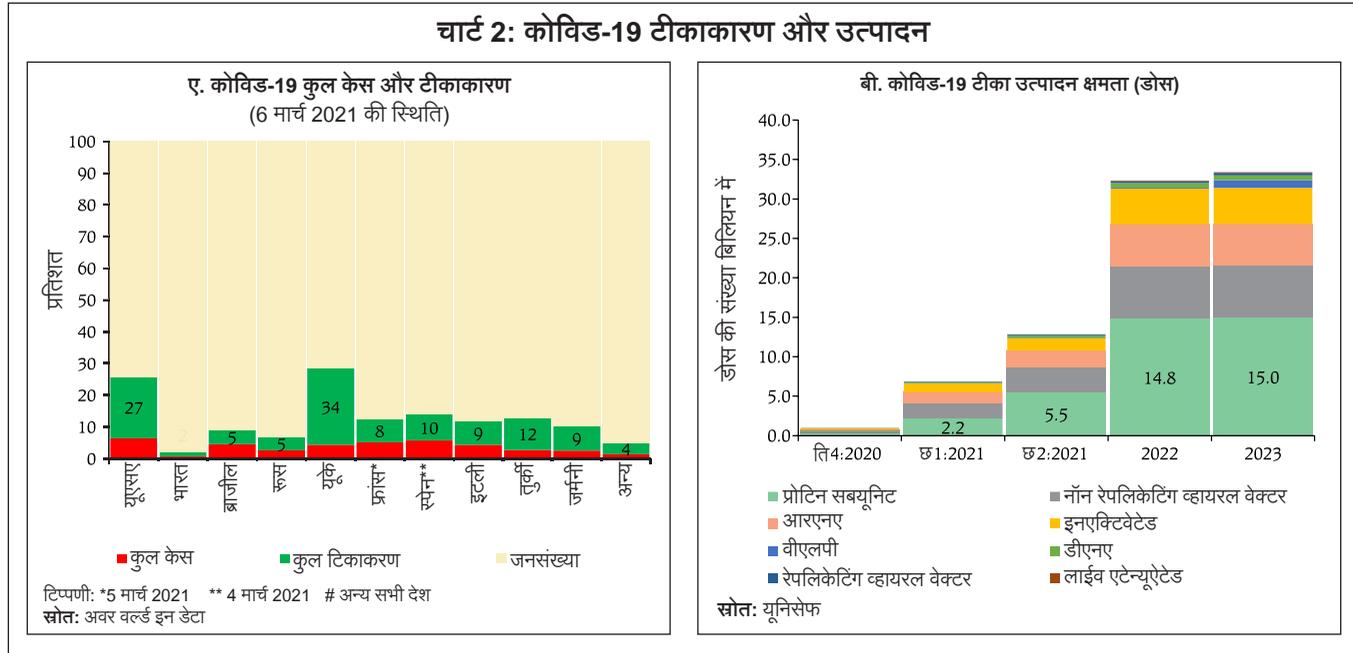
अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से अलग हो जाएगा और तूफान से बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर - अर्थव्यवस्था पर प्रतिलाभ की दर - सार्वजनिक कर्ज के स्टॉक पर ब्याज की दर से अधिक है, जो कर्ज धारणीयता की आवश्यक स्थिति है। आज सार्वजनिक कर्ज की मात्रा जीडीपी का लगभग 90 प्रतिशत है जो मार्च 2026 के अंत में घटकर जीडीपी का लगभग 85 प्रतिशत हो जाएगा। भारत को यह करना है कि वह पर्याप्त शर्त को पूरा करे - कर्ज का भुगतान करने के लिए ब्याज भुगतान के बराबर का राजस्व अधिशेष उत्पन्न करें। दूसरा, भारत को मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता हासिल है³।

दूसरी तरफ, दिसंबर से लेकर अब तक कोविड-19 टीकों की 363 मिलियन से अधिक खुराक दुनिया भर में दी गई है। अमीर देशों ने जरूरत से ज्यादा 1 बिलियन से अधिक खुराक का स्टॉक कर लिया है। पृथ्वी पर 18 प्रतिशत वयस्कों की संख्या 54 सबसे अमीर देशों में है, लेकिन टीके के 40 प्रतिशत ऑर्डर - उनके प्रत्येक वयस्क को 2.5 दो-खुराक देने के लिए पर्याप्त हैं। चूंकि अमीर देशों ने अपनी आबादी का टिकाकरण करने की होड़ मचा रखी है, इसलिए गरीब देश हाशिये पर खड़े होकर टकटकी लगाए हुए हैं। कोवैक्स कार्यक्रम, एक वैश्विक गठबंधन जो गरीब देशों को मुफ्त खुराक वितरित करता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित है, के माध्यम से कोई वैक्सीन प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बन गया। घाना को टीके भारत द्वारा प्रदान किए गए थे (चार्ट 2)।

भारत ने दिलों-जान को जीत लिया है - ठीक उसी तरह जैसे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय क्रिकेट दल को सलाह दिया था - दिल जीतिए। 16 मार्च तक, 70 देशों में कुल 5.9 करोड़ टीके निर्यात किए गए हैं। इनमें से, 81 लाख निःशुल्क खुराक हैं 20 देशों में भेजी गयीं हैं, कोवैक्स के अंतर्गत 1.65 करोड़ और वाणिज्यिक शर्तों पर 3.4 करोड़ निर्यात की गयीं हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए 2 लाख खुराक देने की भी घोषणा की है। अमेरिका के एक शीर्ष वैज्ञानिक डॉ. पीटर होटेज के अनुसार, भारत ने "दुनिया को बचाया" है। जहां कोविड-19 टीकाकरण अभियान को यूरोप में उत्पादन खामियों

³ भारत की मौद्रिक विश्वसनीयता बरकरार है, बाजार के इस विश्वास के लिए धन्यवाद कि देश भविष्य में तेजी से बढ़ सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स 4 मार्च 2021.

चार्ट 2: कोविड-19 टीकाकरण और उत्पादन



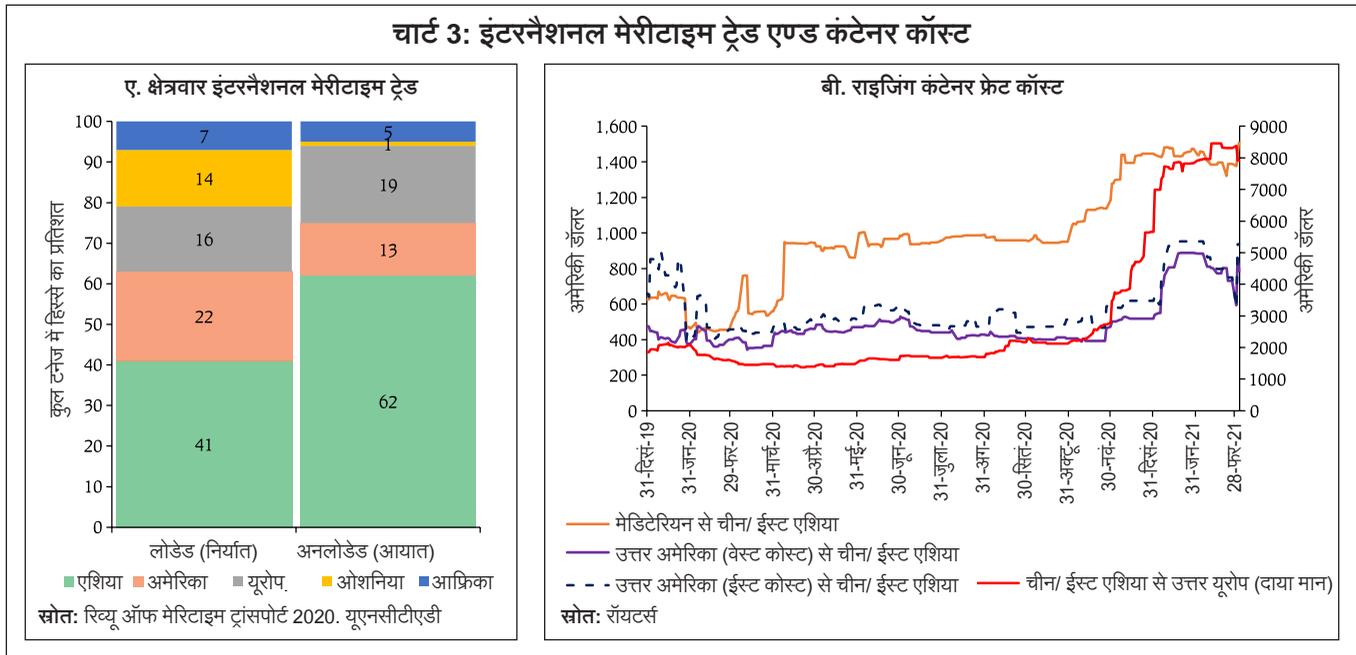
का सामना करना पड़ा है, अमेरिका में वितरण को झटके लगे हैं, और हर जगह आपूर्ति के लिए एक भू-राजनैतिक संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, वहीं एक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्युटिकल कंपनी⁴ कैसाबियांका नाम के लड़के की तरह खड़ा है, जो जलते हुए डेक पर खड़ा था, जब उसके सिवाय सारे लोग भाग गए थे⁵। साल के अंत तक, यह 1.5 बिलियन कोविड-19 शॉट्स को 1.3 बिलियन में जोड़ देगा - खसरे से लेकर तपेदिक तक से होने वाली बीमारियों के 1.5 बिलियन खुराक के मुकाबले है जो पहले से ही सालाना उत्पादन करता है। ये शॉट सस्ते हैं और इन्हें बेहद-कम तापमान पर स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। वे दुनिया के गरीबों का टीकाकरण करेंगे।

तीसरा, 15 मार्च को, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत के विदेशी व्यापार पर अनंतिम डेटा जारी किया जिसमें दिखाया गया था कि दिसंबर 2020 के बाद से लगातार दो महीनों तक चलने वाले व्यापारिक निर्यात में गिरावट आई और काफी कम हो गई। सांख्यिकीय आधार प्रभावों से सार निकालने पर पता चलता है कि यह एक अधिक घोर संकट को कम करता है। वैश्विक व्यापार संचालन व्यवधानों से बहाली के लिए एक नई चुनौती उभरी है। दुनिया के चारों ओर, महामारी ने एक असाधारण स्तर तक व्यापार को बाधित कर दिया है, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप

में मालवाहकों की चाल को अव्यवस्थित कर दिया है। इस झंझावात में शिपिंग कंटेनर है, जो वैश्वीकरण का कर्ता-धर्ता है। चूंकि वे पहली बार 1956 में तैनात किए गए थे, इसलिए कंटेनरों ने सामानों को मानक आकार के रिसेप्टेकल्स में पैक करने और, क्रेन द्वारा रेल कारों और ट्रकों पर चढ़ाने की सुविधा प्रदान कर व्यापार में क्रांति ला दी, जिसने सही मायने में दुनिया को सिकोड़ दिया है। महामारी की शुरुआत में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में लाखों मास्क ले जाने वाले कंटेनर वहीं खाली और तितर-बितर पड़े हुए हैं, और अक्सर समुद्री यातायात जाम में कई दिनों तक फंस जाते हैं क्योंकि जहाजरानी कंपनियों ने अपने जहाजों को अपने सबसे लोकप्रिय मार्गों पर केंद्रित कर दिया है जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप को एशिया से जोड़ता है। इसके अलावा, महामारी और इसके प्रतिबंधों ने बंदरगाह श्रमिकों और ट्रक चालकों की उपलब्धता को सीमित कर दिया है, जिससे दक्षिणी कैलिफोर्निया से सिंगापुर तक कार्गो को संभालने में देरी हुई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बंदरगाहों पर खाली कंटेनरों के ढेर लगे हुए हैं; भारत के कोलकाता बंदरगाह पर कंटेनर कम पड़ गए हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों के निर्माता अपने माल को 1,000 मील पश्चिम में मुंबई के बंदरगाह पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, जहां आपूर्ति बेहतर है। थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया के चावल निर्यातक कंटेनर हासिल करने की असंभवता के कारण उत्तरी अमेरिका के लिए पोतलदान नहीं कर रहे हैं (चार्ट 3)।

⁴ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे

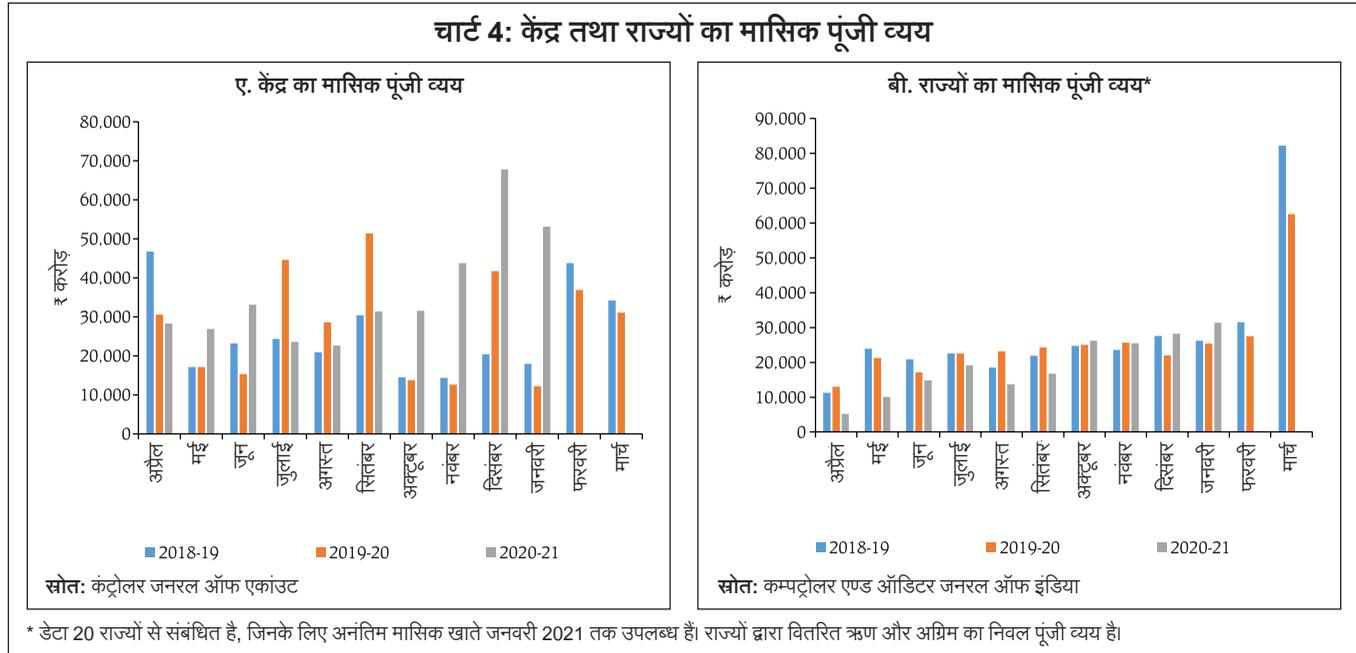
⁵ फेलिसिया हेमैस, 1826 की कविता कैसाबियांका की शुरुआती पंक्तियां।



चौथा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने 9 मार्च को अपनी अंतरिम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अनुमान लगाया गया कि भारत वर्ष 2021 और 2022 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। उनकी राय में, नए म्यूटेशन के फैलने से जोखिम के बावजूद, भारत में आर्थिक गतिविधि महामारी-पुर के स्तर से कहीं ज्यादा हो गई है। आईएमएफ के आर्थिक सलाहकार ने 8 मार्च को बताया था कि क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व जीडीपी के 7 प्रतिशत के साथ, भारत में जो होता है उसका दुनिया के कई अन्य देशों के लिए निहितार्थ है। वर्ष 2021-22 में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ती मांग के साथ भारत दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए सकारात्मक सुनिश्चित करता है। हालांकि अभी भी हिचकिचाहट है, ऐसे संकेत हैं कि पूंजीगत व्यय चक्र बढ़ रहा है और इसमें परिवर्तन हो रहा है। पहला, केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय में वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान 11.6 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष गिरावट से सुधार हुआ और अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान 144.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इसमें एक तीव्र बदलाव आया (चार्ट 4ए)। दूसरा, 20 राज्यों के लिए अनंतिम मासिक लेखा से पता चलता है कि पूंजीगत व्यय (संवितरित ऋण और अग्रिमों का निवल) वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के दौरान धीरे-धीरे

सुधर कर महामारी-पूर्व के स्तर तक आ गया है, जिसमें दिसंबर और जनवरी में क्रमशः 28.4 और 23.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। (चार्ट 4 बी)। अब तक 9 राज्यों ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने बजट पेश किए हैं, जिसमें 2021-22 के लिए उनका संयुक्त पूंजीगत व्यय 2020-21 के संशोधित अनुमान से 35.7 प्रतिशत अधिक है। तीसरा, वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए त्रैमासिक परिणाम प्रमुख राजस्व वृद्धि में लगातार सुधार के साथ पूंजीगत सामान उत्पादक फर्मों के पुनरुद्धार के संकेत दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्मों ने ऑर्डर बुक में स्वस्थ विस्तार भी दर्ज किया है, जिसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रीन एनर्जी बिजनेस, सड़क और हाईवे, रेलवे और मेट्रो सेवाओं की मांग शामिल है। चौथा, रियल एस्टेट क्षेत्र में पुनरुद्धार हुआ है। फंसे स्टॉक में कमी होने के साथ, निर्माण गतिविधि ने वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। यह स्टील की खपत में प्रतिबिंबित होता है, जो निर्माण गतिविधि के लिए निकटस्थ संकेतक है। पांचवां, मशीनरी और उपकरण में निवेश में स्पष्ट रूप से सुधार हो रहा है जो कि संकुचन के लंबे समय के बाद पूंजीगत वस्तुओं के आयात और उत्पादन में ऊपर की ओर सह-संचलन से स्पष्ट है। छठा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में आबंटन को तीन साल के उच्च स्तर तक बढ़ा दिया है, जो

चार्ट 4: केंद्र तथा राज्यों का मासिक पूंजी व्यय



आकर्षक मूल्यांकन, राजस्व प्राप्ति की उज्ज्वल संभावनाओं और ऑर्डर बुक की वृद्धि से प्रेरित है।

26 फरवरी को, रिज़र्व बैंक ने भारत की मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क की समीक्षा करते हुए, मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट का प्रकाशन फिर से शुरू कर उसे जारी किया। मुद्रास्फीति के लक्ष्य की 31 मार्च, 2021 तक समीक्षा की जानी है - विषय की सामयिक प्रासंगिकता के मद्देनजर, लोक हित का ध्यान मुख्य रूप से लक्ष्य और उसके चारों ओर सहनशीलता बैंड पर होगा। लेकिन यह रिपोर्ट संभवतः जीवन काल में एक बार भेंट करने जैसा है जिसके समृद्ध गुलदस्ते में कई फूल हैं जो झेंप कर अनदेखा रह जाते हैं। उन्हें मुरझाने नहीं देना चाहिए; उन्हें धूप में रखने की जरूरत है:

- ईएमई मुद्रास्फीति को लक्षित कर रहे हैं (आईटी) और नवाचार लागू कर रहे हैं, जिसमें आईटी फ्रेमवर्क के साथ विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप का मिलाप भी शामिल है; वे लक्ष्य कम कर रहे हैं और बैंड को संकुचित कर रहे हैं।
- लचीली आईटी (एफआईटी) का समय भारत के उस दौर में नहीं आया जब इसे वर्ष 2016 में विधायी अधिदेश प्राप्त हुआ बल्कि उसके पहले वर्ष 2013 की प्रचंड गर्मी में टेपर टैंट्रम के साथ आ गया था।

- मौद्रिक नीति जनता और सरकार के बीच एक संविदा है। मुद्रास्फीति वह मीट्रिक है जिसके द्वारा इस संविदा का मूल्यांकन किया जा सकता है। भारत में, दोहरे अंकों की सीमा पर मुद्रास्फीति के लिए एक सामाजिक असहिष्णुता समय-समय पर प्रकट हुई है।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुशासन को कम किए बिना, लचीलेपन को फ्रेमवर्क में शामिल किया जाना चाहिए।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का दृष्टिकोण क्रमिकतावादी और प्रगामी रहा है, जो नीतिगत दर निर्धारित करते समय पिछली मुद्रास्फीति रीडिंग द्वारा संचालित किए बिना आउटपुट प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।
- एफआईटी से पहले भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन चल रहे थे, जिससे वृद्धि धीमी हो गयी - भारत की प्रवृत्ति वृद्धि में मंदी; बचत और निवेश दरों में कमी; पूंजी स्टॉक और रोजगार की वृद्धि में गिरावट; जनसांख्यिकीय लाभांश में विपर्यय के संकेत; बढ़ती व्यापार संरक्षणवाद और जलवायु परिवर्तन की मजबूरियों के संबंध में न्यून अनुकूल बाहरी वातावरण।

- एमपीसी ने यह सब देखा है - सर्वसम्मत फैसले से लेकर विभाजित विचार तक; बाहरी और आंतरिक दोनों सदस्यों के असहमत से लेकर सहमत विचार तक; एफआईटी व्यवस्था में मौद्रिक नीति बनाने में सामूहिक सोच और निःशुल्क लाभभागी का अभाव।
- मुद्रा बाजार में मौद्रिक संचरण पूर्ण और यथोचित तेजी से हुआ है लेकिन बॉन्ड बाजारों में पूर्ण से कम है; जबकि ऋण देने और बैंकों की जमा दरों के प्रसारण में सुधार हुआ है, सभी श्रेणियों के ऋण और जमा बाह्य बेंचमार्क आगे और संचरण में सुधार कर सकते हैं।
- 'अस्थायी का भय' और 'मूल्यवृद्धि का भय' के मद्देनजर ईएमई एफआईटी को अपनाने में देरी कदम उठाने वाले रहे हैं। व्यवहार में, अधिकांश ईएमई ने ... अत्यधिक पूंजी प्रवाह और ... विनिमय दर की अस्थिरता से निपटने के लिए अक्सर और बड़े हस्तक्षेपों का सहारा लिया है।

लेख का शेष भाग पांच खंडों में व्यवस्थित है। खंड II में वैश्विक स्थितियों का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। खंड III में, हमने घरेलू अर्थव्यवस्था में हाल के घटनाक्रम पर चर्चा की है। खंड IV में देश में व्याप्त वित्तीय बाजार की स्थितियों का सारांश दिया गया है जबकि खंड V में समापन टिप्पणी दी गई है।

II. वैश्विक हालात

जहां देशों ने अपनी आबादी और अन्य लोगों को भी टीका लगाने में तेजी लायी है, बावजूद इसके कि वे वायरस के फिर से बढ़ाने और म्यूटेंट स्ट्रेन्स की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं वर्ष 2020 कि चौथी तिमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधि में मंदी के प्रभाव के कारण वर्ष 2021 का पहली तिमाही फीका पड़ने लगा है। पहले की तुलना में अब यह अधिक संभावना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में खोई हुई गति को फिर से हासिल करेगी।

यह ओईसीडी के नवीनतम अंतरिम दृष्टिकोण द्वारा प्रमाणित होता है। वर्ष 2021 के वैश्विक वृद्धि के पूर्वानुमान को तीन महीने की अवधि में 1.4 प्रतिशत अंक से संशोधित किया

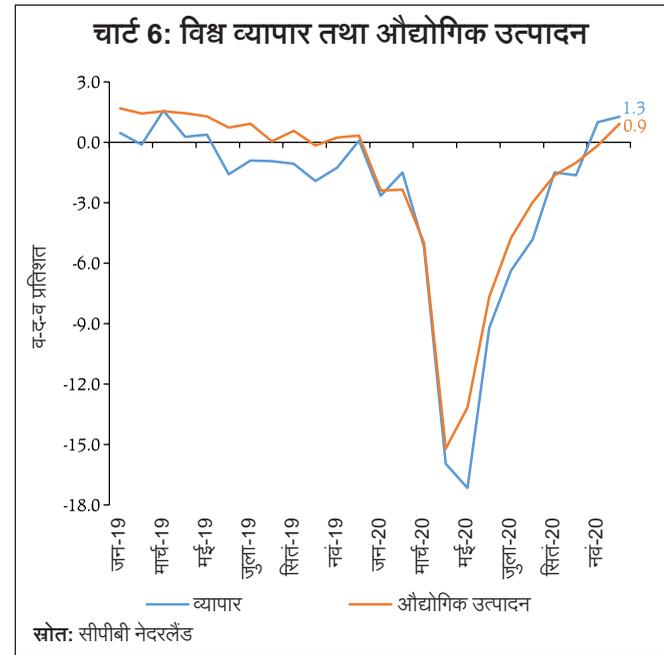
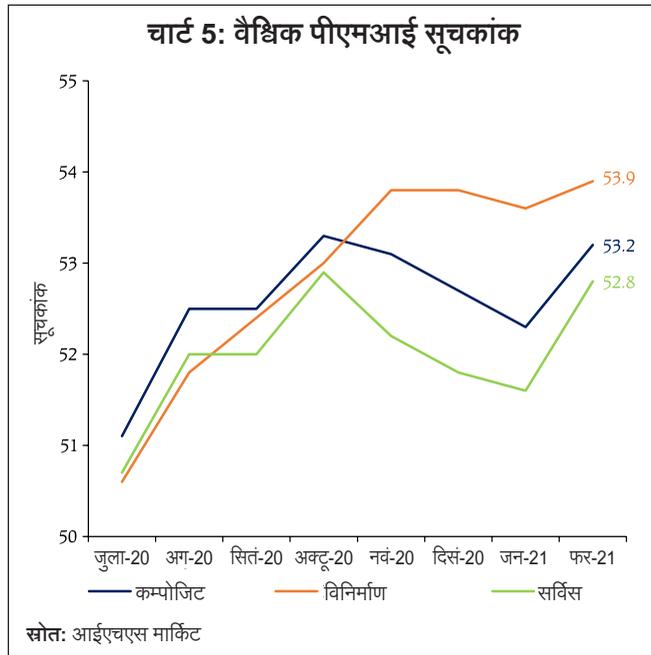
सारणी 1: जीडीपी वृद्धि अनुमान- चयनित ई और ईएमई

प्रतिशत

देश	2021		2022	
	दिसं 2020	मार्च 2021	दिसं 2020	मार्च 2021
 विश्व	4.2	5.6	3.7	4.0
उन्नत अर्थव्यवस्था				
 यूएस	3.2	6.5	3.5	4.0
 यूके	4.2	5.1	4.1	4.7
 यूरो क्षेत्र	3.6	3.9	3.3	3.8
 जापान	2.3	2.7	1.5	1.8
उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं				
 ब्राजील	2.6	3.7	2.2	2.7
 रूस	2.8	2.7	2.2	2.6
 भारत	7.9	12.6	4.8	5.4
 चीन	8.0	7.8	4.9	4.9
 दक्षिण आफ्रिका	3.1	3.0	2.5	2.0

स्रोत: ओईसीडी

गया है (सारणी 1)। संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के लिए वृद्धि का पूर्वानुमान दोगुना से अधिक हो गया है, जिसका कारण यूएस \$1.9 ट्रिलियन का राजकोषीय प्रोत्साहन और तेजी से टीकाकरण रहा है। ओईसीडी ने वैश्विक उत्पादन को इस वर्ष के मध्य तक महामारी से पहले के स्तर को पार करने का अनुमान लगाया है, हालांकि कई देश उस स्तर से पिछड़ जाएंगे, जो कोविड-19 से पूर्व विश्व में वर्ष 2022 के अंत तक अपेक्षित था (ओईसीडी, 2021)।



मार्च 2021 के आरंभिक आंकड़ों के बीच, फरवरी 2021 के लिए वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जिसमें यूएस अग्रणी रहा और इसके बाद भारत का स्थान रहा है (चार्ट 5)। इस संकेतक के भीतर, वैश्विक विनिर्माण ने तीन साल के शिखर को छू लिया, लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनपुट और आउटपुट कीमतों में लागत दबाव घटकर उच्च स्तर पर पहुंच गया।

अमेरिका में, श्रम बाजार महामारी से प्रेरित शीतकालीन मंदी से उबर गया, जिसने 3,06,000 नौकरियां छीन ली थी। फरवरी में, 3,79,000 पद सृजित किए गए, जो जनवरी की तुलना में लगभग 2.3 गुना अधिक है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में बेरोजगारी लाभ के नए दावों की संख्या बढ़कर 745,000 हो गई, जो दिसंबर की शुरुआत के बाद से 4 सप्ताह की चल औसत सबसे कम थी। यूरो क्षेत्र में, स्पेन में बेरोजगारी फरवरी में पांच साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई, जबकि जर्मनी में खुदरा बिक्री में गिरावट और बिक्री कर के पुनः अंशांकन के कारण गिरावट जारी रही⁶।

एक साल पहले के मुकाबले दिसंबर 2020 में विश्व व्यापार में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 6)। वर्ष 2020 के अंत तक, वैश्विक व्यापार ने वर्ष की शुरुआत में अपने स्तर को प्राप्त कर लिया था और कोविड-19 से हुए नुकसान की भरपाई कर ली थी।

वर्ष 2020 की शुरुआत में औद्योगिक उत्पादन भी अपने स्तर पर वापस आ गया है।

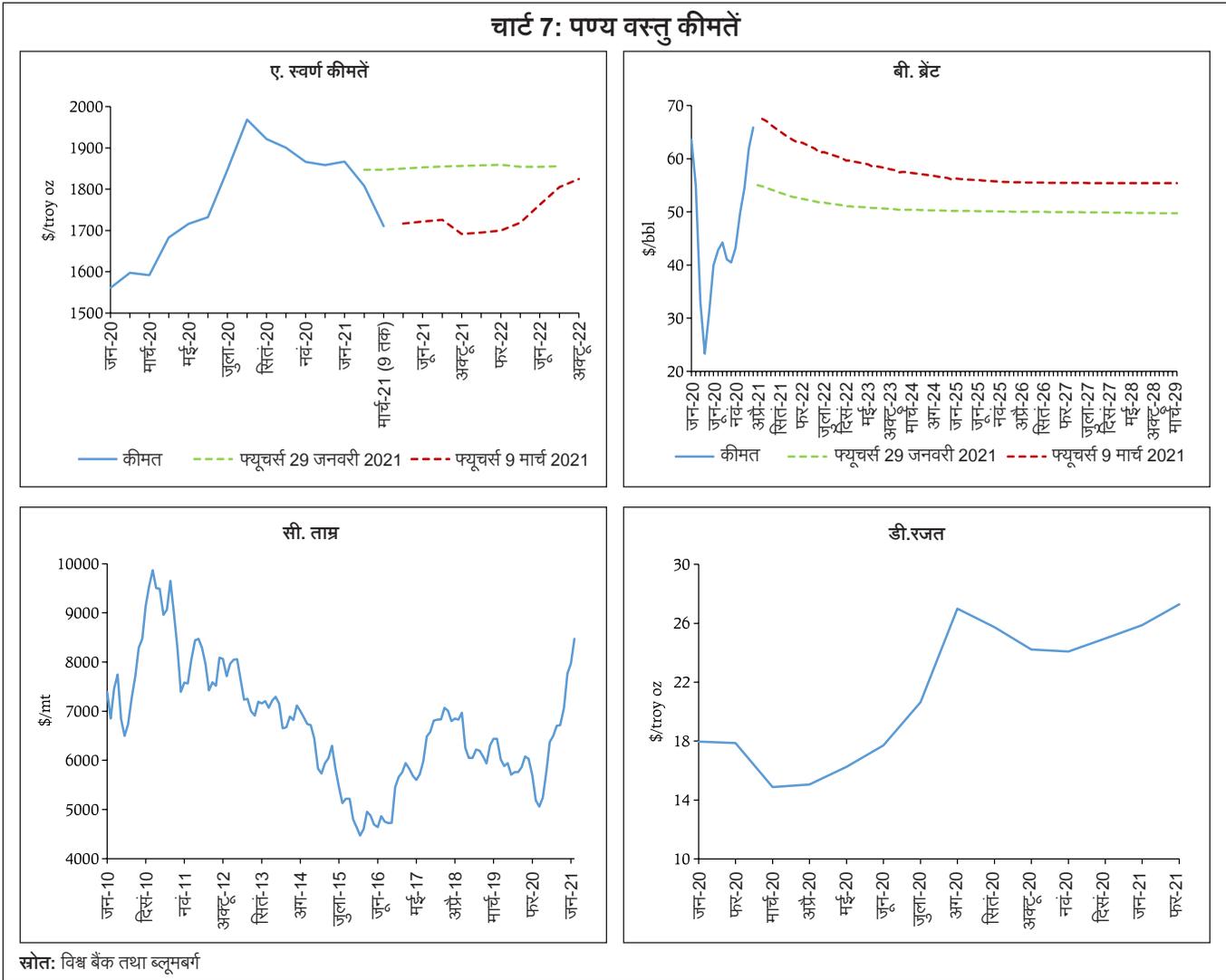
आर्थिक अनिश्चितता घटने के साथ, सोने में सुरक्षित निवेश की मांग में कमी के चलते गिरावट जारी रही। मार्च 2020 की पहली छमाही में सोने की कीमतें मई 2020 के बाद सबसे कम थीं। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी है क्योंकि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) ने अपनी नवीनतम बैठक में अप्रैल 2021 तक उत्पादन पर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया। ब्रेंट की कीमतें मार्च के दूसरे सप्ताह में दुनिया के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता - सऊदी अरब के बाद पहली बार मार्च के दूसरे सप्ताह में 70 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गईं, जिसमें कहा गया था कि इसकी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया गया था, जिसने वैश्विक आपूर्ति की सुरक्षा और स्थिरता को निशाना बनाया था। एक आम सहमति बन रही है कि एक कमोडिटी सुपर-साइकल निर्मित हो रहा है (गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चैस एंड कंपनी आदि) [चार्ट 7]।

वैश्विक वित्तीय बाजार की स्थिति गोल्डिलॉक्स अवस्था⁷ में है। जनवरी के अंत में गिरावट के बाद, दुनिया भर के शेयर बाजार फिर से फरवरी के मध्य में यूएस एस एंड पी और भारतीय

⁶ फाइनेंशियल टाइम्स, 2 मार्च 2021.

⁷ गोल्डिलॉक्स अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें वृद्धि और मुद्रास्फीति न तो बहुत अधिक होती है न ही बहुत कम बल्कि वृद्धि और मुद्रास्फीति एकदम संतुलित होती है। यह नाम बच्चों की कहानी 'तीन भालू' से आया है।

चार्ट 7: पण्य वस्तु कीमतें

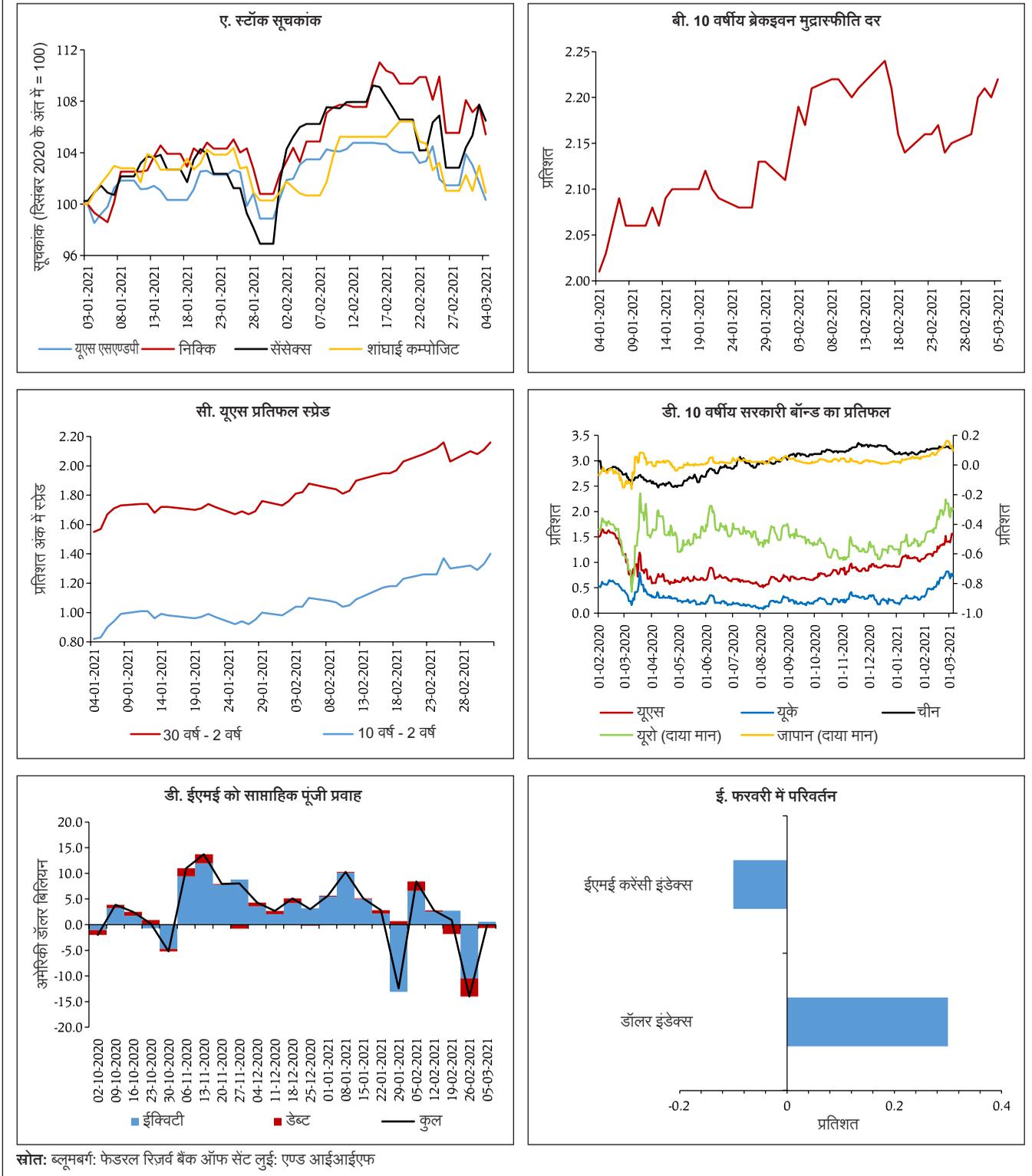


संसेक्स के साथ नए शिखर पर पहुँच गया (चार्ट 8 ए)। मजबूत वृद्धि और कारोबारी आय की प्रत्याशाओं के कारण 1990 के बाद जापान का निक्केई पहली बार 30,000 से आगे निकल गया।

उसी समय, संस्फीति व्यापार में मजबूती आ रही है और 10-वर्षीय लाभ-अलाभ दर, जो बाजार की मुद्रास्फीति प्रत्याशा का एक प्रमुख पैमाना है, तेजी से बढ़ी (चार्ट 8 बी)। मजबूत रिकवरी की उम्मीद से प्रेरित और इसलिए मुद्रास्फीति में मजबूती के कारण अमेरिकी बॉन्ड में बिकवाली रही। लंबी अवधि के बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई है – 10-वर्षीय प्रतिफल 1.6 प्रतिशत के करीब है, जबकि 30-वर्षीय प्रतिफल 2.25 प्रतिशत के करीब है। निकट भविष्य में और राजकोषीय प्रोत्साहन के होने और

टीकाकरण की गति में तेजी आने से दीर्घावधि दरें बढ़ गईं, जबकि सन्निकट दरें स्थिर रहीं, जिससे प्रतिफल वक्र की ढलान में वृद्धि हुई (चार्ट 8सी)। बॉन्ड्स में बिकवाली और प्रतिफल कर्व का ढालवाँ होना यूएस के अलावा अन्य क्षेत्रों में तेजी से फैला। 10-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिफल ने अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम (यूके), यूरो क्षेत्र, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अन्य में एक वर्ष में अपने उच्चतम स्तरों पर रहा। अक्टूबर 2020 के बाद पहली बार ईएमई से दुनिया भर के पूंजी बाजारों और पूंजीगत बहिर्वाह में सुधार की वजह से प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई, जिससे ईएमई मुद्रा सूचकांक कमजोर हो गया (चार्ट 8ई और 8एफ)। 30 ईएमई के लिए डेटा को कवर करने वाले आईआईएफ के क्रॉस-बॉर्डर प्रवाह के दैनिक ट्रैकर से पता चलता है कि मार्च के पहले सप्ताह के दौरान विदेशी

चार्ट 8: वित्तीय बाजार



निवेश लगभग यूएस \$290 मिलियन के दैनिक बहिर्वाह में बदल गया, जबकि फरवरी में दैनिक अंतर्वाह लगभग यूएस \$325 मिलियन था।

उभरते बाजार आस्तियों के लिए कीमतों के दबाव में आने से, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) ने उभरते बाजार इक्विटीज के व्यापक गेज को एक महीने से भी कम समय से डॉलर के संदर्भ में 7 प्रतिशत तक डुबो दिया है। जेपी मॉर्गन के वैश्विक ईएमबीआई सूचकांक द्वारा ट्रैक किए गए कर्ज में वर्ष 2020 के अंत तक लगभग 4 प्रतिशत का नुकसान दर्ज किया गया है⁸।

दो महीने के अंतराल के बाद, प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने फरवरी में बैंक इंडोनेशिया और बैंको डी मेक्सिको दोनों के साथ दरों में कटौती को फिर से शुरू किया और अपनी नीतिगत दरों को क्रमशः 25 आधार अंकों को घटाकर 3.5 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत कर दिया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने घोषणा की है कि महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम के तहत आस्ति खरीद वर्ष के पहले महीनों की तुलना में अगली तिमाही में काफी अधिक गति से होगी। दूसरी ओर, फेडरल रिज़र्व और रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड) ने न्यूनतम उपयोग के साथ कुछ अस्थायी महामारी-सहायता सुविधाओं को समाप्त करने की घोषणा की है।

यह एमपीसी के विप्रेषण के संशोधन का भी समय रहा है। जहां मौद्रिक नीति के मूल उद्देश्य और सांकेतिक अवलंब यूके और न्यूजीलैंड दोनों के लिए समान हैं, वहीं कुछ तत्वों को निर्णय लेने और नीति-कार्यान्वयन प्रक्रिया में जोड़ा गया है। आरबीएनजेड की एमपीसी को, अन्य बातों के अलावा, धारणीय घर की कीमतों की सरकार की नीति पर उसके निर्णयों के प्रभाव की रूपरेखा तैयार करना अपेक्षित है। बैंक ऑफ इंग्लैंड एमपीसी के विप्रेषण को अद्यतन किया गया है, जो सरकार की आर्थिक रणनीति को दर्शाता है, जो कि वृद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करता है जो

पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ है और शुद्ध शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था के संक्रमण के अनुरूप है।

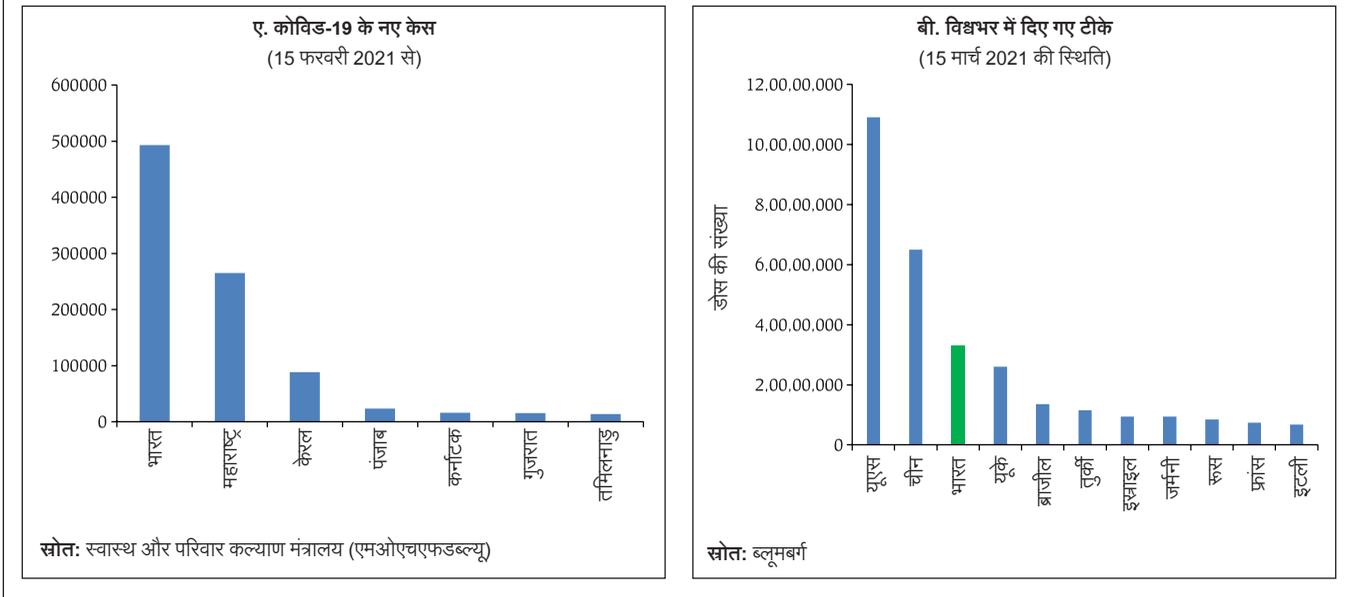
राजकोषीय मोर्चे पर प्रमुख घटना यूएस \$1.9 ट्रिलियन की नयी प्रोत्साहन वाली अमेरिकी बचाव योजना थी, जो अमेरिका में दूसरा सबसे बड़ा राजकोषीय प्रोत्साहन था जिसके लिए कानून बनाया गया और यह एक वर्ष के भीतर सर्वाधिक प्रोत्साहन था। ओईसीडी का अनुमान है कि वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही से लेकर वर्ष 2022 की पहली तिमाही तक कार्यान्वयन के अपने पहले पूरे वर्ष में, प्रोत्साहन योजना लगभग 3-4 प्रतिशत उत्पादन का विस्तार करेगी, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वर्तमान अतिरिक्त क्षमता के बराबर है। घरेलू अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति की संभावनाओं में सुधार करते हुए यह अन्य अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से कनाडा और मैक्सिको में भी मांग बढ़ाएगा।

III. घरेलू घटनाक्रम

फरवरी के मध्य से ही स्थानीय स्तर पर कोविड-19 मामलों के बढ़ने से भारत के टीकाकरण अभियान को झटका लगा। 16 मार्च तक, भारत में सक्रिय मामले 2,23,432 थे जिसमें मार्च के पहले पखवाड़े के दौरान दैनिक मामले औसतन लगभग 20,000 थे; कुल मामलों का 85 प्रतिशत 6 राज्यों में था (चार्ट 9ए)। टीकाकरण की गति बढ़ रही है, इसी अवधि में 2.5 करोड़ खुराक दी गयी है। कुल मिलाकर, भारत ने अब तक (16 मार्च, 2021) लगभग 3.3 करोड़ खुराकें दी हैं, जो कि विश्व स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रमों में तीसरा सबसे अधिक है (चार्ट 9 बी)। इस बीच, कोवाक्सिन - भारत बायोटेक द्वारा विकसित ड्रग - ने तेजी से उभरते हुए वेरिएंट के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रतिरक्षाजनकता के साथ 81 प्रतिशत की अंतरिम वैक्सीन प्रभावकारिता दिखाई है। टीकाकरण की तेज गति तेज बहाली की आश जगाती है, यह देखते हुए कि कोविड-19 संक्रमण में हाल ही में बढ़ोतरी काफी हद तक कुछ राज्यों तक सीमित है, और आंशिक रूप से लॉकडाउन/मार्केट बाजार अवधि/रात में कर्फ्यू के संदर्भ में प्रतिबंध मुख्य रूप से स्थानीय तौर पर हैं।

⁸ फाइनेंशियल टाइम्स 6 मार्च 2021.

चार्ट 9: कोविड-19 केस और दिए गए टीके

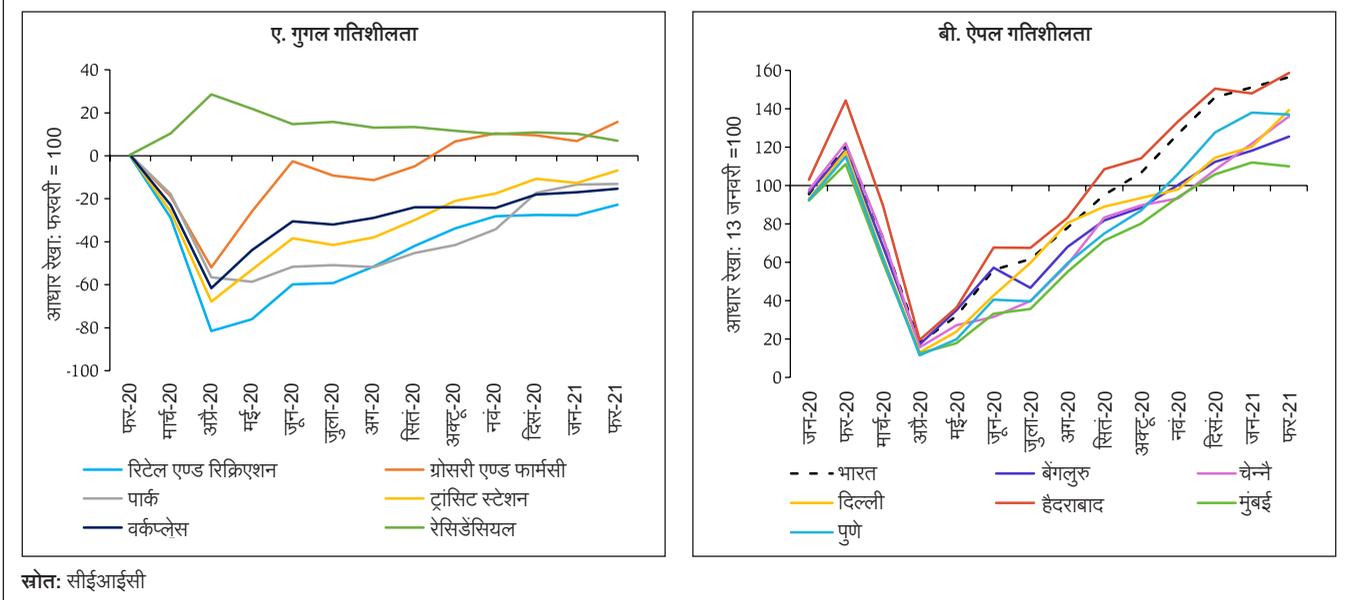


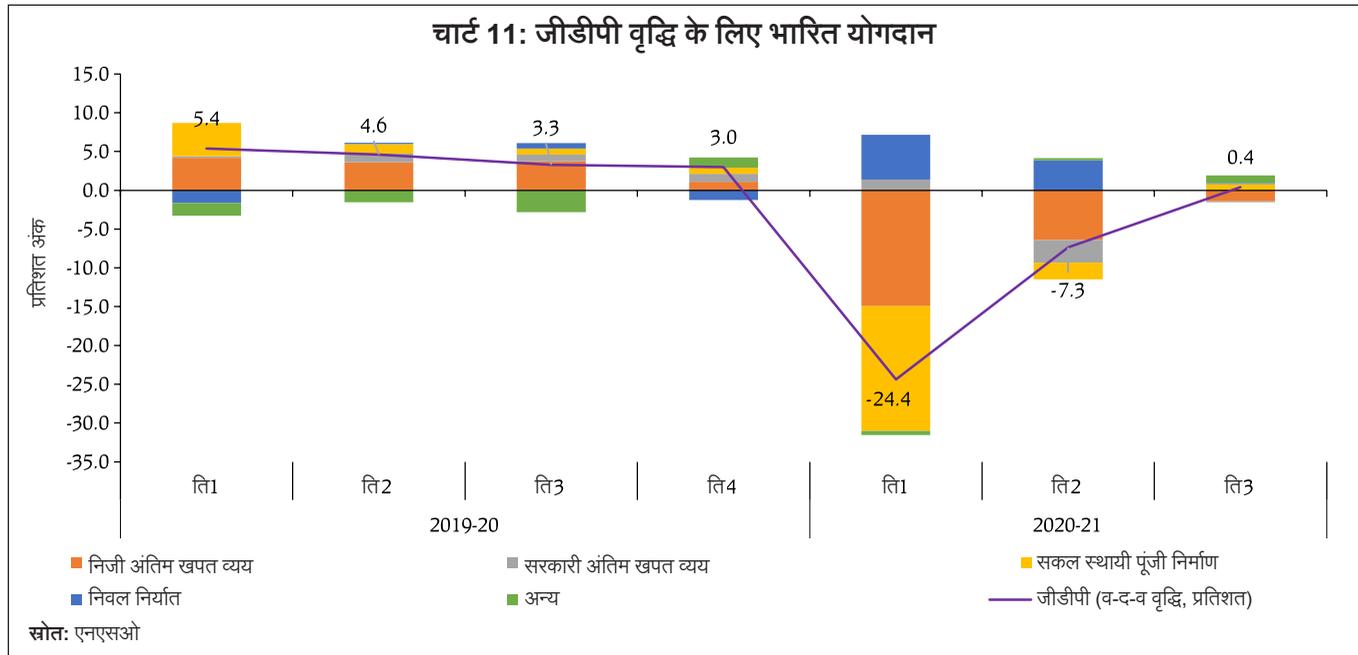
मोबिलिटी संकेतक, जैसे कि ऐप्पल मोबिलिटी इंडेक्स, दर्शाता है कि फरवरी और मार्च 2021 के दौरान सभी प्रमुख शहरों में आवागमन सामान्य हो गया है, जबकि कोविड-19 मामलों में हालिया बढ़ोतरी के कारण मुंबई और पुणे में थोड़ा कम था (चार्ट 10)। मार्च में लगभग कुछ हद तक खुदरा और मनोरंजन को छोड़कर, गूगल मोबिलिटी सूचकांक सतत सुधार को भी दर्शाता है।

समग्र मांग

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की राष्ट्रीय आय का दूसरा अग्रिम अनुमान (एसएई) दर्शाता है कि सभी घटकों के बीच संकुचन की गति सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) के साथ ऋणात्मक क्षेत्र से बाहर निकल रही है (चार्ट 11)। निजी खपत में सुधार, रुकी हुई मांग का मजबूत प्रदर्शन, सरकार द्वारा खर्च, मजबूत कृषि प्रदर्शन, और विनिर्माण, निर्माण, बैंकिंग और

चार्ट 10: गतिशीलता संकेतक

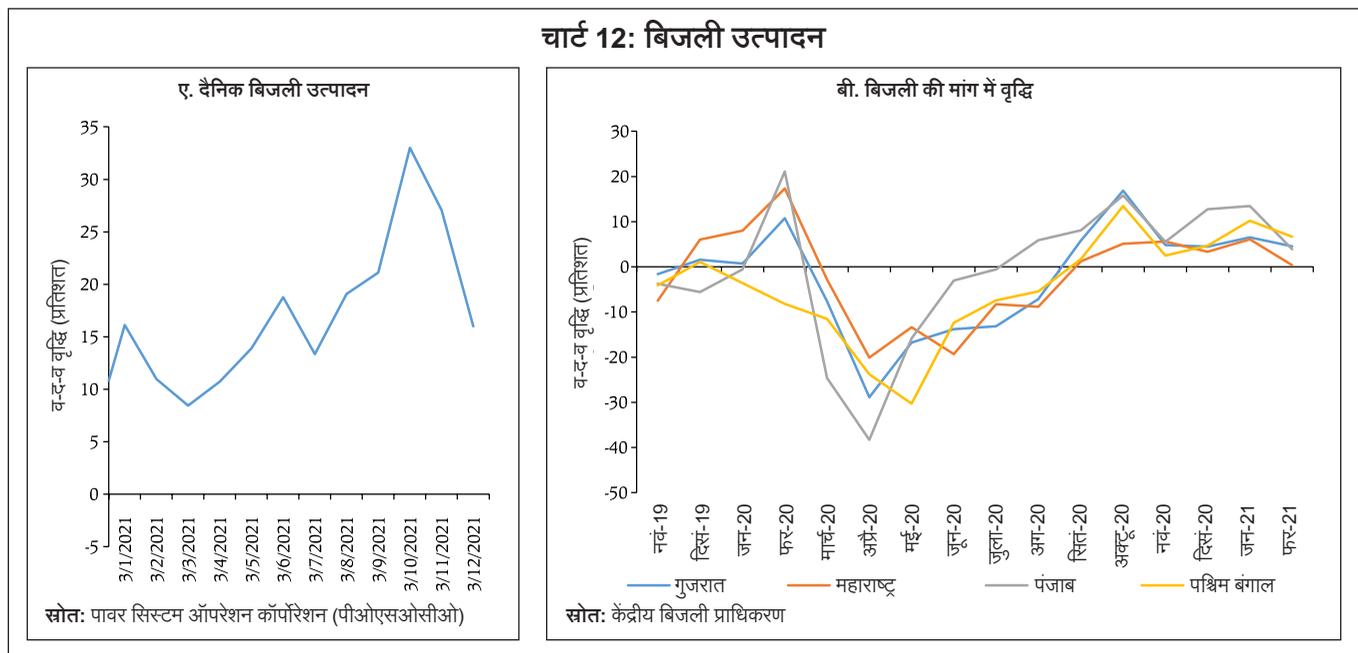


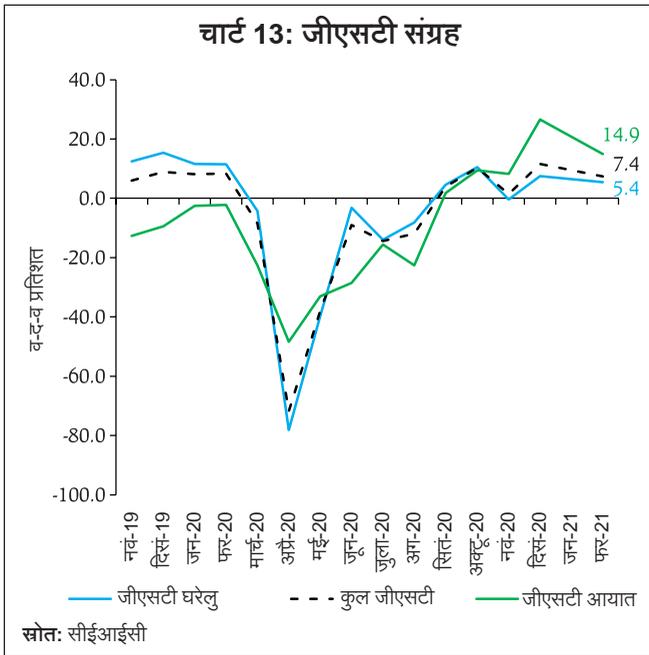


रियल एस्टेट गतिविधि मुनासिब तरीके से फिर से चालू हो जाने से बहाली का आधार मिला।

समग्र मांग का व्यापक आधार पर विस्तार हो रहा है, और सतत सुधार दर्ज करने के लिए स्थितियाँ जारी हैं। एक साल पहले की तुलना में मार्च के दौरान बिजली उत्पादन 16.5 प्रतिशत अधिक था (चार्ट 12ए)। देश में बिजली की औसत मांग फरवरी में 3.5 प्रतिशत बढ़ी, जो लगातार छठे महीने बिजली की

मांग में वृद्धि दर्ज की गयी है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बिजली की खपत जहां औद्योगिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं का कुल मांग का 40 प्रतिशत हिस्सा है, वहीं यह 0.4 से बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 12बी)। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारतीय बिजली क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण को 'ऋणात्मक' से 'स्थिर' में अपग्रेड किया है। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा खुदरा व्यापार सर्वेक्षण

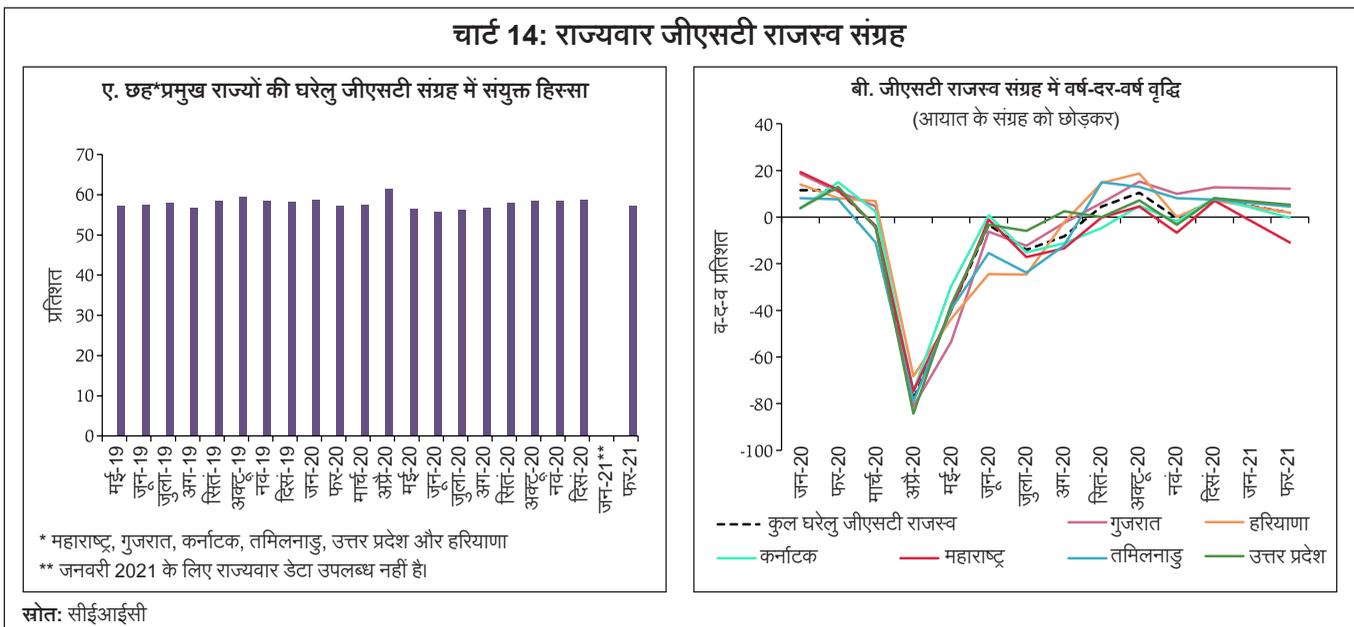




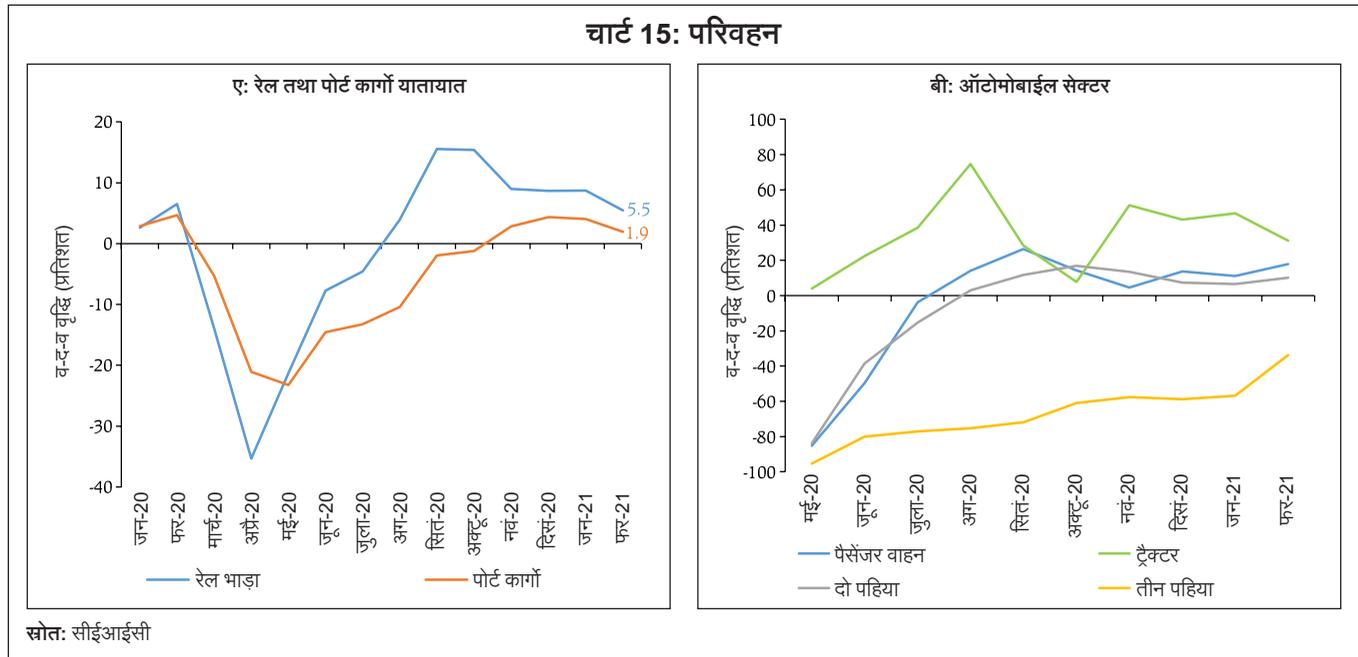
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत संग्रह फरवरी 2021 में सीधे पांचवें महीने के लिए ₹1 लाख करोड़ से ऊपर बने रहे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि और निरंतर कारोबारी गतिविधि को दर्शाता है। घरेलू लेनदेन से संग्रह 5.4 प्रतिशत और आयात से 14.9 प्रतिशत बढ़ा (चार्ट 13)। घरेलू जीएसटी राजस्व संग्रह के अंतर-राज्य विश्लेषण से संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने कुल का 57 प्रतिशत योगदान दिया (चार्ट 14)।

महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में नए कोविड-19 मामलों में उछाल से परिवहन के उच्च आवृत्ति संकेतक फरवरी 2021 में वृद्धि के कुछ गिरावट को दर्शाते हैं। पोर्ट कार्गो की वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत और घरेलू एयर कार्गो उप-सामान्यीकृत दुलाई मात्रा में वापस आ गई। दूसरी ओर, रेलवे माल दुलाई यातायात फरवरी 2021 में 5.5 प्रतिशत की दर से बढ़ता रहा (चार्ट 15 ए)। ट्रैक्टर की बिक्री फरवरी में तेजी से जारी रही, जिसने सुदृढ़ कृषि/ग्रामीण क्षेत्र की बदौलत 31.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है (चार्ट 15 बी)। यात्री वाहनों और थोक खंड में दो पहिया संचालित वृद्धि

के 13वें संस्करण ने संकेत दिया कि फरवरी 2021 में खुदरा बिक्री कोविड-19 के पहले के स्तर का 93 प्रतिशत थी, जो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं और त्वरित सेवा रेस्तरां द्वारा संचालित थी। उद्योग आशावादी है कि कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि विकसोन्मुख पुनरुत्थान को प्रभावित नहीं करेगा।



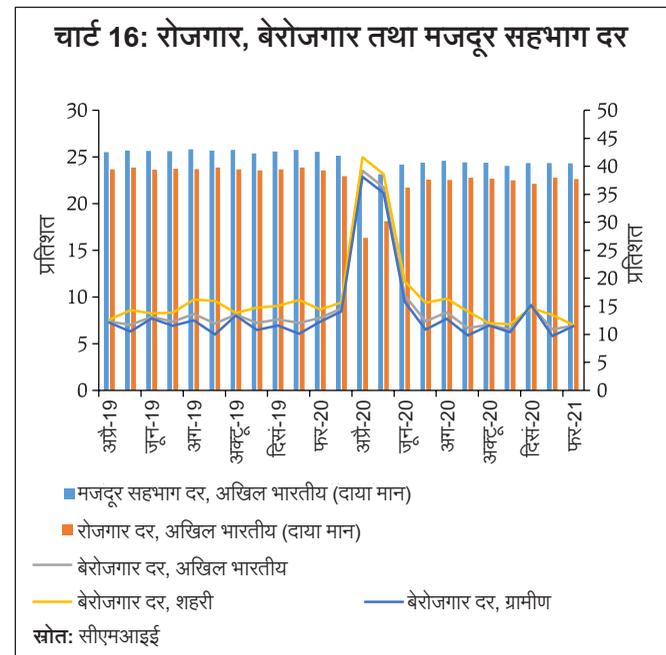
9 बीएस-VI मानदंडों के कार्यान्वयन के कारण ऑटोमोबाइल थोक और खुदरा बिक्री दोनों के डेटा पिछले वर्ष के डेटा से तुलना योग्य नहीं हैं।



के साथ कम आधार प्रभाव के बूते ऑटोमोबाइल सेक्टर⁹ ने फरवरी में वृद्धि का प्रदर्शन किया। वैश्विक अर्धचालक आउटलेज के बावजूद यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में वृद्धि हुई। हालांकि, दो पहिया वाहनों के निबंधन में संकुचन आया।

रोजगार संबंधी भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) के हाउसहोल्ड सर्वेक्षण से पता चलता है कि फरवरी 2021 में एक औसत रोजगार दर एक महीने पहले के 37.9 प्रतिशत से मामूली रूप से कम होकर 37.7 प्रतिशत पर आ गई थी। नतीजतन, जनवरी 2021 में औसत बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशत हो गई, लेकिन महामारी से पहले के 7.8 प्रतिशत (फरवरी 2020) के स्तर से कम थी [चार्ट 16]। फरवरी में श्रम बल की भागीदारी 40.5 प्रतिशत थी, जो एक महीने पहले 40.6 प्रतिशत थी। शहरी क्षेत्रों में उनके ग्रामीण समकक्षों की संख्या में वृद्धि हुई है, शहरी बेरोजगारी में 7.0 प्रतिशत की कमी आई है, जो पिछले तीस महीनों में सबसे कम है। दूसरी ओर, ग्रामीण रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसमें बेरोजगारी बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई जो एक महीने पहले 5.8 प्रतिशत थी। शहरी भारत में श्रम के पुनः समावेश का त्वरित कदम आर्थिक गतिविधि को सामान्य करने के लिए प्रतिबिंबित हो सकता है।

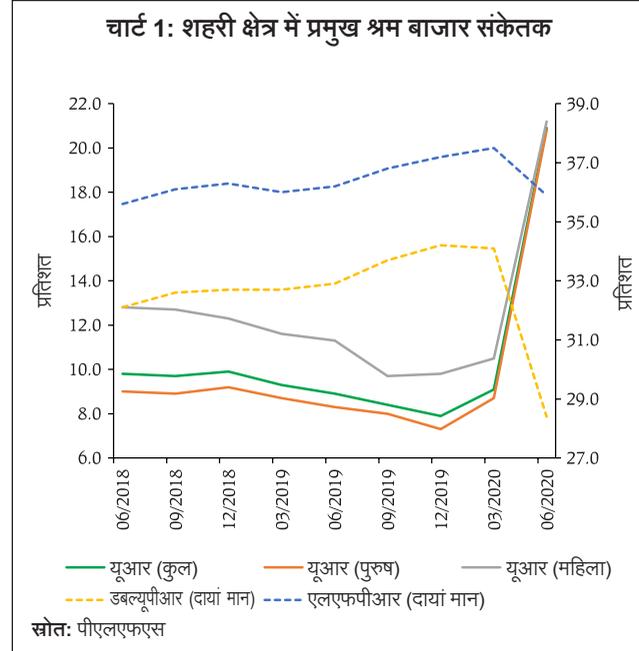
शहरी क्षेत्रों के लिए समय-समय पर श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) जारी करने के माध्यम से, पहली बार अप्रैल-जून 2020 के दौरान श्रमिकों के सामने आने वाले व्यवधान की सीमा पर एक आधिकारिक अनुमान लगाया गया है जब आर्थिक गतिविधि अपने अधोगति पर थी (बॉक्स 1)।



बॉक्स I: अप्रैल-जून 2020 में शहरी श्रम बाजार में उतार-चढ़ाव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने अब शहरी क्षेत्रों के लिए अप्रैल-जून 2020 के लिए अपने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से डेटा जारी किया है। श्रम बाजार ने कोविड-19 के अत्यधिक प्रकोप और लॉकडाउन के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों को झेला। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन¹ के अनुसार, भारत ने 2020 में काम के घंटे में 13.7 प्रतिशत की वार्षिक औसत हानि दर्ज की। आधिकारिक संख्या, काफी हद तक, प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी के संदर्भ में वैकल्पिक डेटा स्रोतों के अनुरूप हैं, जो बेरोजगारी दर (यूआर) में तेज वृद्धि दिखा रहे हैं (चार्ट 1)। भारत में बेरोजगारी में यह तेज वृद्धि अमेरिका की घटना के समान है, जहां श्रमिकों को अस्थायी तौर पर हटाकर समायोजन हुआ, और यूरो क्षेत्र की घटना के विपरीत है, जहां कामगार या तो नौकरी प्रतिधारण योजना के कारण पेरल पर रहे या जॉब मार्केट को पूरी तरह से छोड़ दिए (ईसीबी 2020)।

अप्रैल-जून 2020 के दौरान, बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2020 में 9.1 प्रतिशत से बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो गई और अक्टूबर-दिसंबर 2019 में 7.9 प्रतिशत। इसी अवधि के दौरान, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) घटकर 35.9 प्रतिशत हो गई जो जनवरी-मार्च 2020 में 37.5 प्रतिशत थी। हालांकि, जनवरी-जून 2020 में श्रमिक आबादी अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में भारी गिरावट आई है, जो जनवरी-मार्च 2020 में 34.1 प्रतिशत और अक्टूबर-दिसंबर 2019



में 34.2 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-जून 2020 में नौकरी के ज्यादा नुकसान को दर्शाता है।

एक रोजगार श्रेणी से दूसरे में संक्रमण के मामले का विश्लेषण करने पर कोविड-19 का प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है (सारणी 1)। इसके लिए, एक ही व्यक्ति की गतिविधि को दो निकटवर्ती

सारणी 1: निकटवर्ती तिमाहियों में गतिविधि वार व्यक्तियों (>15 वर्ष) का संवितरण

जनवरी-मार्च 2020 के दौरान गतिविधि	अप्रैल-जून 2020 के दौरान गतिविधि							सभी ((3+4+5+6+7))
	अपना खाता कामगार, मालिक	गृह उद्योग में सहायक	स्वरोजगार (1+2) #	नियमित मजदूरी/ वेतन	अनियत मजदूर	बेरोजगार	श्रम बल में शामिल नहीं	
	1	2	3	4	5	6	7	
1. अपना खाता कामगार, मालिक	6.6	0.0	11.4	0.2	0.0	1.0	0.9	13.5
2. गृह उद्योग में सहायक	0.0	1.1	1.7	0.0	0.0	0.1	0.4	2.2
3. स्वरोजगार (1+2) #	7.1	1.2	14.1	0.2	0.0	1.2	1.4	16.9
4. नियमित मजदूरी/ वेतन	0.1	0.0	0.3	18.7	0.0	2.1	1.1	22.2
5. अनियत मजदूर	0.0	0.0	0.2	0.1	1.8	2.5	0.5	5.1
6. बेरोजगार	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	3.7	0.3	4.3
7. श्रम बल में शामिल नहीं	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	50.8	51.6
8. सभी	7.3	1.3	14.8	19.2	2.1	9.9	54.1	100.0

टिप्पणी: # : स्तंभ और पंक्ति 3 में, स्वरोजगार कामगार जो गृह उद्योग में काम करते थे, लेकिन बीमारी या अन्य कारणों से काम नहीं कर रहे थे, को भी शामिल किया गया है।

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई।

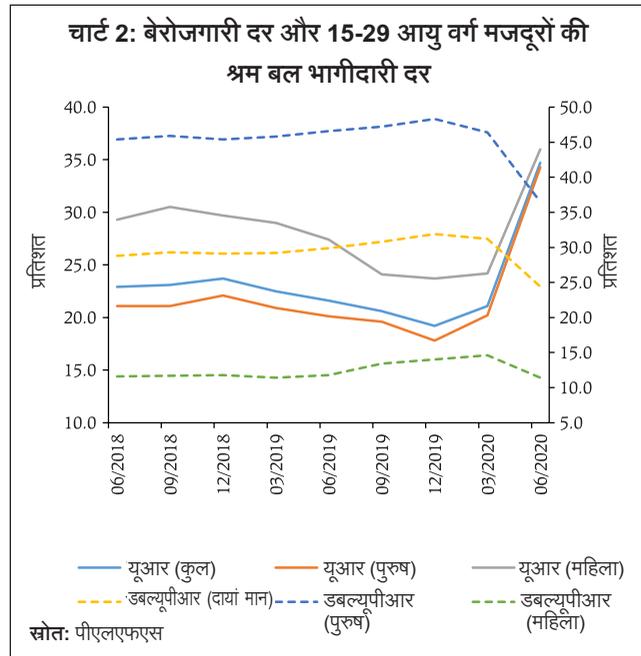
(जारी ...)

¹ अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (2021), आईएलओ मॉनिटर: कोविड 19 और वर्ल्ड ऑफ वर्क. सातवाँ संस्करण

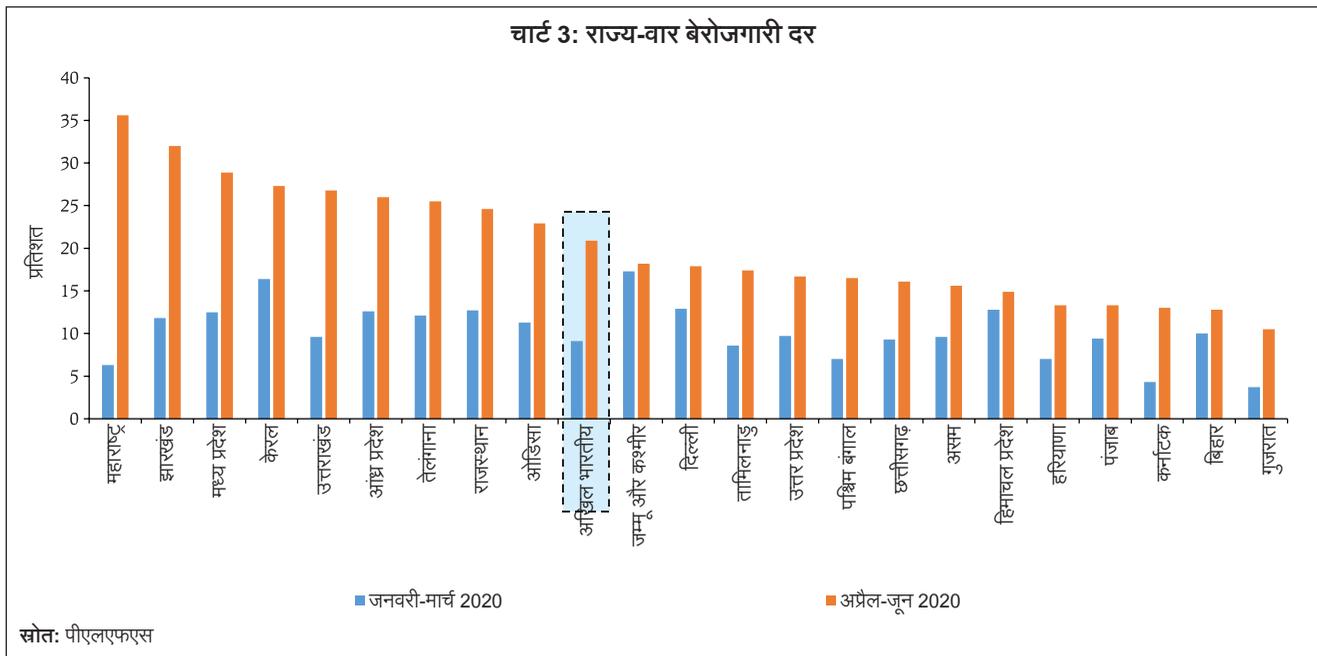
तिमाहियों के लिए ट्रैक किया गया है। यह देखा जा सकता है कि सभी श्रेणी के कामगार बुरी तरह प्रभावित हुए थे, जिसमें कुल कामकाजी उम्र की आबादी (> 15 वर्ष) में बेरोजगारों की हिस्सेदारी जनवरी-मार्च 2020 में 3.7 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-जून 2020 में 9.9 प्रतिशत हो गयी और इसी अवधि में श्रम बल सहभागिता 48.4 प्रतिशत से घटकर 45.9 प्रतिशत हो गयी। जहां ज्यादातर अनियत मजदूर बेरोजगारी में धकेल दिए गए थे, वहीं नियमित मजदूरी पाने वाले और स्वरोजगार करने वाले बेरोजगार हो गए और कुछ पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों से बाहर हो गए।

इसके अलावा, कम आयु वर्ग के श्रमिकों को असमानता का सामना करना पड़ा क्योंकि बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2020 में 21.1 प्रतिशत से असामान्य रूप से उच्च स्तर तक बढ़ कर 34.7 प्रतिशत हो गई और यह समग्र बेरोजगारी में वृद्धि से बहुत अधिक है। इसका बोझ मुख्य रूप से युवा पुरुष श्रमिकों द्वारा वहाँ किया गया था (चार्ट 2)।

श्रम डेटा के राज्य-स्तरीय विश्लेषण से पता चलता है कि शहरी बेरोजगारी महाराष्ट्र में सबसे अधिक थी, जो भारत का सबसे



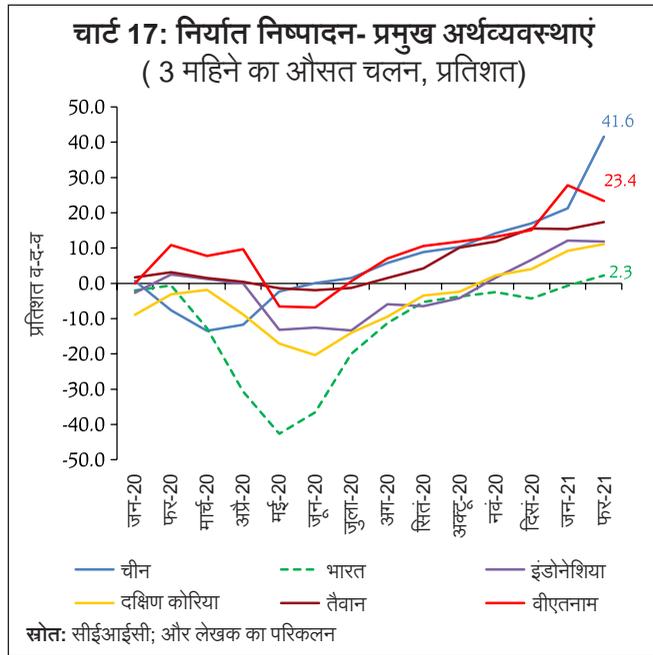
शहरीकृत और औद्योगिक राज्य है (चार्ट 3)। संयोग से, कोविड-19 संक्रमण की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र में दर्ज की गई है।



संदर्भ

ईसीबी (2020), द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैनेडेमिक ऑन द यूरो एरिया लेबर मार्केट, ईसीबी इकोनोमिक बुलेटिन(8)। https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202008_02~bc749d90e7.en.html से लिया गया है।

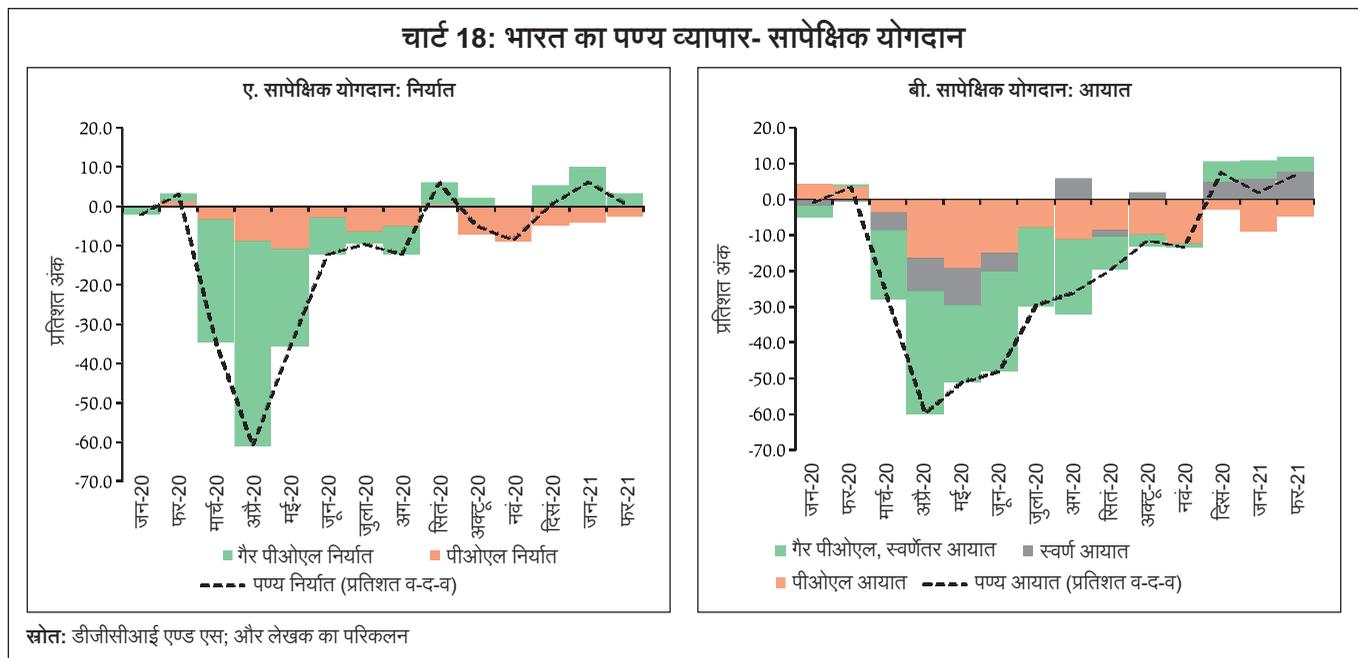
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, (2021), कोविड-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क, आईएलओ मॉनिटर।

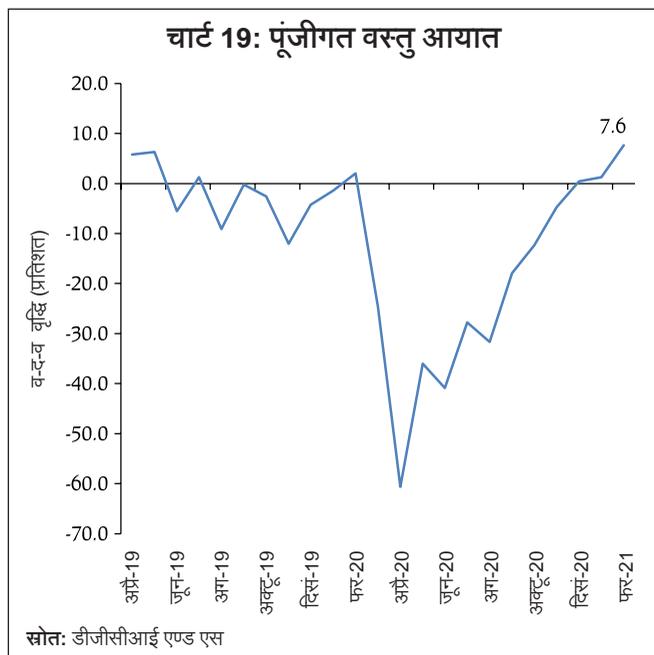


वैश्विक कारोबारी माहौल में सुधार के साथ ही हाल के महीनों में भारत के वाणिज्यिक वस्तुओं का व्यापार पुनः पटरी पर लौट आया, क्योंकि वैक्सीन रोलआउट उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से होने की वजह से अर्थव्यवस्थाएं लॉकडाउन से बाहर आ रही हैं। हालांकि, व्यापारिक निर्यात में सुधार प्रमुख एशियाई समकक्षों से कम है (चार्ट 17)।

फरवरी 2021 के लिए पण्य निर्यात और आयात सामान्य होकर महामारी से पहले के स्तर पर आ गए हैं। गैर-तेल निर्यात लगातार छठे महीने वृद्धि क्षेत्र में रहा। फरवरी 2021 में गैर-तेल गैर-सोने के आयात में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जिससे घरेलू आर्थिक गतिविधि में पुनरुत्थान के संकेत मिले (चार्ट 18)। लौह अयस्क, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स और चावल के प्रदर्शन से निर्यात वृद्धि हुई है, जो महामारी के दौरान भी सुदृढ़ रहा था। रसायन और प्लास्टिक जैसे अन्य क्षेत्र भी कोविड19 के पहले के स्तर पर वापस आ गए हैं। हालांकि, पेट्रोलियम उत्पादों, जवाहरात और आभूषणों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामानों के कम निर्यात ने बाधा के रूप में काम किया। फरवरी 2021 में आयात में वृद्धि को बढ़ावा देने वाली वस्तुओं की सूची में सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान और रसायन सबसे ऊपर थे। इसके विपरीत, पेट्रोलियम, कोयला और परिवहन उपकरण ऐसी वस्तुएं थीं, जिन्होंने आयात वृद्धि को नीचे ला दिया। इस व्यापार पुनरुत्थान में उज्ज्वल स्थान पूंजीगत माल का आयात है, जो अर्थव्यवस्था में निवेश की मांग के लिए अच्छी तरह से भविष्य सूचित करता है (चार्ट 19)।

जिन 9 राज्यों ने अपने बजट प्रस्तुत किए हैं, उनके लिए वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख घाटे के संकेतकों के संशोधित अनुमान





(आरई) ने महामारी प्रेरित गिरावट की सीमा को व्यक्त किया है। सकल राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 5.3 प्रतिशत हो गया जो 3.3 प्रतिशत के बजटीय आंकड़े से अधिक है। राजस्व व्यय के संशोधित अनुमानों में संकुचन देखने को मिला, जिसमें व्यय संबंधी युक्तिकरण से अधिक महामारी से संबंधित अतिरिक्त खर्चों की भरपाई की गई है। कुल मिलाकर, राजस्व संतुलन में 2.3 प्रतिशत अंकों की कमी देखी गई, जो संशोधित अनुमानों में बजटीय अधिशेष से घाटे में चल रही है, जो मुख्य रूप से राज्यों के अपने कर राजस्व में गिरावट और केंद्र से विचलन द्वारा संचालित है। वर्ष 2021-22 के लिए, राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 4.0 प्रतिशत पर बजट किया गया है। समग्र पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाते समय राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में कटौती के माध्यम से समेकन प्राप्त करने की मांग की जाती है (सारणी 2)।

समग्र आपूर्ति

समग्र आपूर्ति को वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के संदर्भ में मापा जाता है। वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में इसमें 1.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि दूसरी तिमाही से अधिक तीव्र क्रमिक बहाली को प्रदर्शित करता है (चार्ट 20)। हालिया फसल उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान (2^{री} ईई),

सारणी 2: राज्य सरकार वित्त * - प्रमुख संकेतक

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

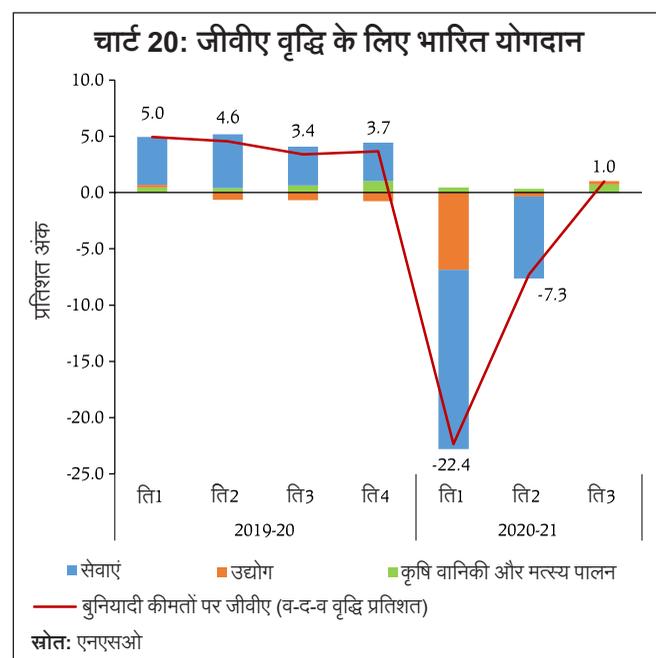
मद	2019-20	2020-21 (बीई)	2020-21 (आरई)	2021-22 (बीई)
राजस्व प्राप्ति	18.7	20.8	18.1	19.0
पूंजीगत प्राप्ति	0.4	0.1	0.1	0.1
राजस्व व्यय	18.3	20.2	19.8	18.9
पूंजीगत व्यय	3.0	4.0	3.6	4.2
राजस्व घाटा	-0.4	-0.6	1.7	-0.1
सकल राजकोषीय घाटा	2.1	3.3	5.3	4.0

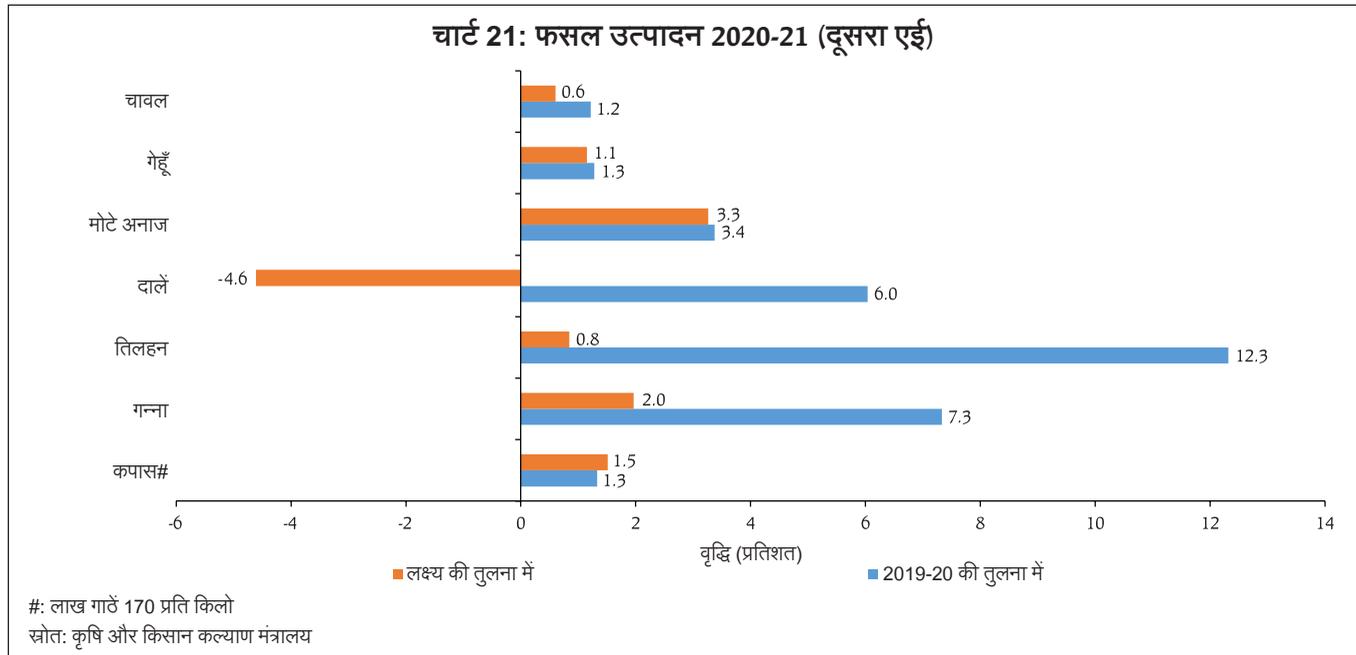
*: डेटा 9 राज्यों से संबंधित है जिन्होंने 2021-22 के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया है। ऋणात्मक (-) चिन्ह अधिशेष का संकेत देता है।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

2020-21 के अनुसार खरीफ उत्पादन में मजबूत वृद्धि के कारण, कृषि विकास दर तीसरी तिमाही में बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गई। पांच बार संकुचन के बाद विनिर्माण ने कुछ गति हासिल की और 1.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ धनात्मक क्षेत्र में लौट आया। निर्माण, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में पुनरुत्थान के साथ, वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में सेवा क्षेत्र में मूल्य वर्धन एक साल पहले के अपने स्तर पर पहुंच गया।

रबी के मौसम के करीब आने के साथ ही, वर्ष 2020-21 की 2^{री} ईई के अनुसार कृषि क्षेत्र बम्पर फसल कटाई के लिए तैयार है (चार्ट 21)। सामान्य मानसून और खरीद नीति समर्थन के कारण,

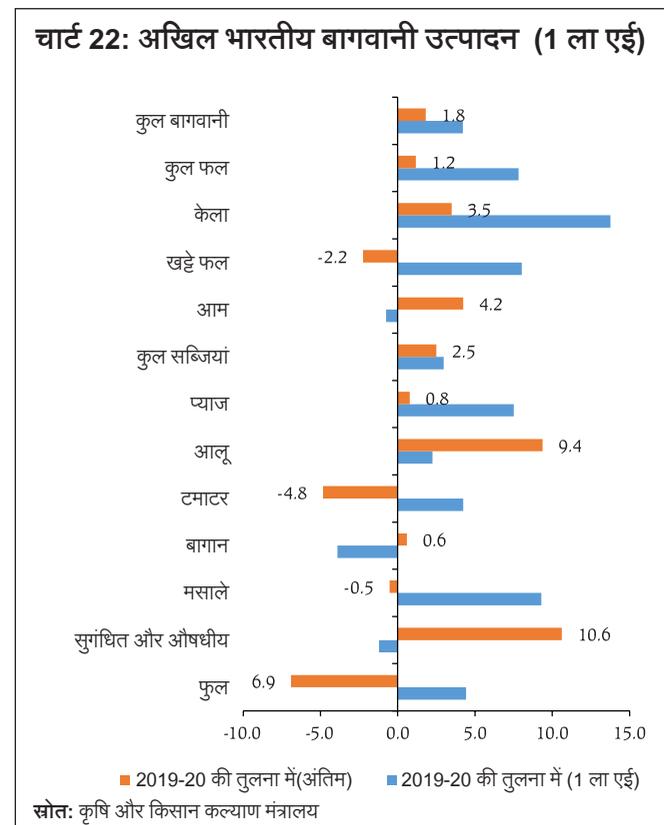




खाद्यान्न उत्पादन 303.3 मिलियन टन तक पहुँच गया है, जो एक साल पहले के अंतिम अनुमानों से 2 प्रतिशत अधिक है। खाद्यान्नों की वृद्धि रबी और खरीफ दोनों मौसमों में सभी प्रमुख फसलों में व्याप्त है। खाद्यान्नों ने लगातार पाँचवें वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन स्तर को पीछे छोड़ दिया है।

वर्ष 2012-13 के बाद के खाद्यान्न उत्पादन को पीछे छोड़ते हुए बागवानी और भूमि क्षेत्र में एक तीव्र पुनर्बहाली दर्ज की गयी है। वर्ष 2020-21 में, बागवानी फसलों का उत्पादन प्रथम एई के अनुसार 326.6 मिलियन टन रिकार्ड स्तर आंका गया है, जो वर्ष 2019-20 के अंतिम अनुमानों की तुलना में 1.8 प्रतिशत अधिक है। यह मुख्य रूप से फलों और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि हो जाने की वजह से हुआ था (चार्ट 22)। सुगंधित, औषधीय पौधों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन का अनुमान भी पिछले वर्ष की तुलना में 10.6 प्रतिशत अधिक आंका गया है। तीन प्रमुख सब्जियों (टीओपी) में, आलू और प्याज के उत्पादन में क्रमशः 9.4 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो बुआई के रकबे में वृद्धि होने से बढ़ी है। इससे आगे चलकर कीमत दबाव कम हो सकता है। लॉकडाउन के दौरान कीमतों में भारी गिरावट की वजह से बुआई क्षेत्रफल में वृद्धि के बावजूद टमाटर का उत्पादन 4.8 प्रतिशत गिर गया है, जिसके कारण किसानों की आय कम हो गयी है।

फरवरी 2021 में हेडलाइन विनिर्माण पीएमआई 57.5 पर रहा, जिसने लगातार सातवें महीने के लिए अपनी विस्तृत प्रवृत्ति को जारी रखा है, लेकिन जनवरी 2021 में दर्ज 57.7 से



थोड़ा कम है। चूंकि विनिर्माण क्षेत्र की सेहत में सुधार हुआ, कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाकर, इनपुट खरीद और खरीदी हुई वस्तुओं का स्टॉक करके मजबूत वृद्धि दिखाई। बेहतर मांग की स्थिति और स्मार्ट मार्केटिंग रणनीतियों ने नए आदेशों हासिल किए। फरवरी के आंकड़ों ने सर्वेक्षण के इतिहास में इनपुट माल सूचियों में सबसे तेज वृद्धि की ओर इशारा किया। इनपुट खरीद में विस्तार लगभग एक दशक में सबसे तेज था। भविष्य का उत्पादन 60.6 पर स्थिर रहा, जो इस क्षेत्र की निरंतर मजबूती का संकेत दे रहा है (चार्ट 23 ए)।

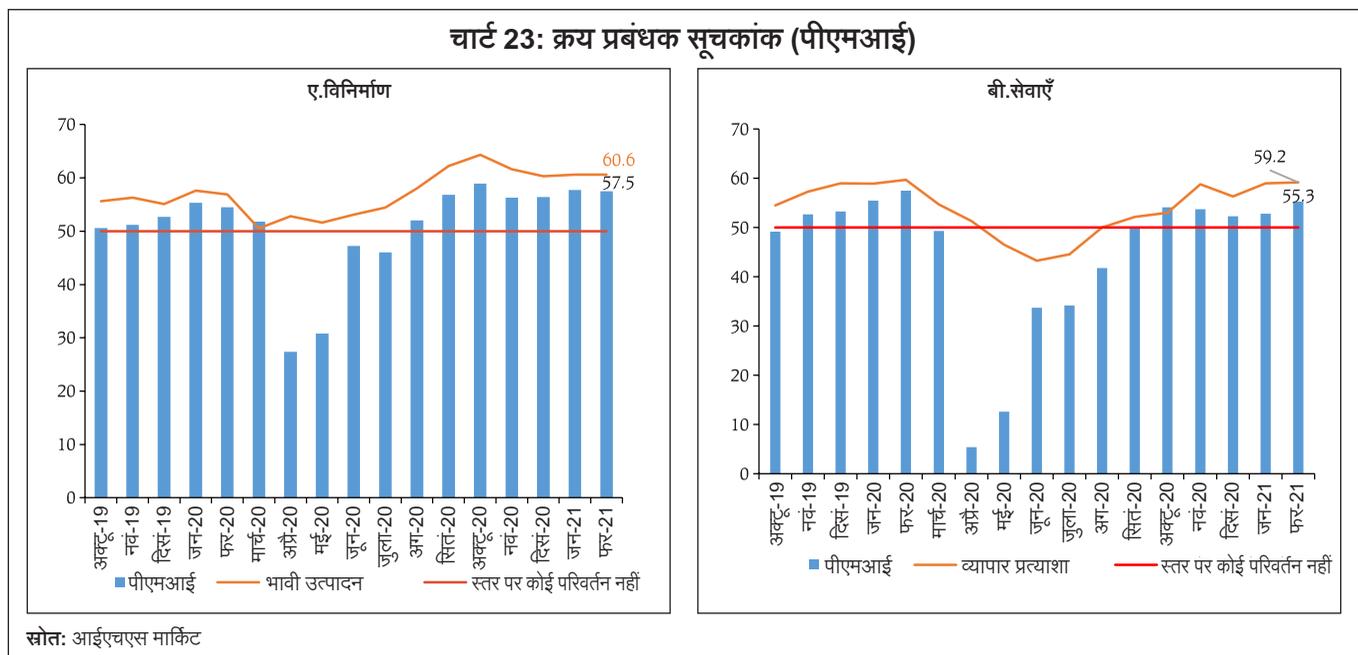
नए आदेशों में तेज वृद्धि के कारण, सेवा पीएमआई ने एक वर्ष में विस्तार की सबसे तेज गति दर्ज की, जो फरवरी 2021 में 55.3 हो गई (चार्ट 23 बी)। विस्तार की गति एक महीने पहले 52.8 से अधिक थी और लंबे समय तक रहे 53.3 के औसत से ऊपर थी। हालांकि कुल मिलाकर इनपुट लागत उच्च माल दुलाई, ईंधन और खुदरा कीमतों की रिपोर्ट के बीच बढ़ी है। कोविड-19 वैक्सीन के आ जाने से भविष्य में वृद्धि की संभावनाओं और व्यापार विश्वास में सुधार के प्रति उम्मीद जागी है, जैसा कि कारोबार प्रत्याशा सूचकांक में परिलक्षित है, जो फरवरी में बारह महीने के उच्च स्तर 59.2 तक पहुंच गया था।

नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजंप्शन इंडेक्स एक हफ्ते पहले 28 फरवरी को 99.3 पर पहुंच गया। गतिविधि अब कोविड-19 के पहले के स्तर से केवल 1.5 प्रतिशत कम है, हालांकि कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि ने गतिशीलता को प्रभावित किया और इससे सन्निकट स्थानीयकृत जोखिम पैदा हुआ। सेवाओं से संबंधित पीएमआई के अनुसार, परिवहन और भंडारण सेवा क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खंड थे। सूचना और संचार एकमात्र उप-क्षेत्र था जिसने बिक्री और व्यावसायिक गतिविधि में संकुचन दर्ज किया था।

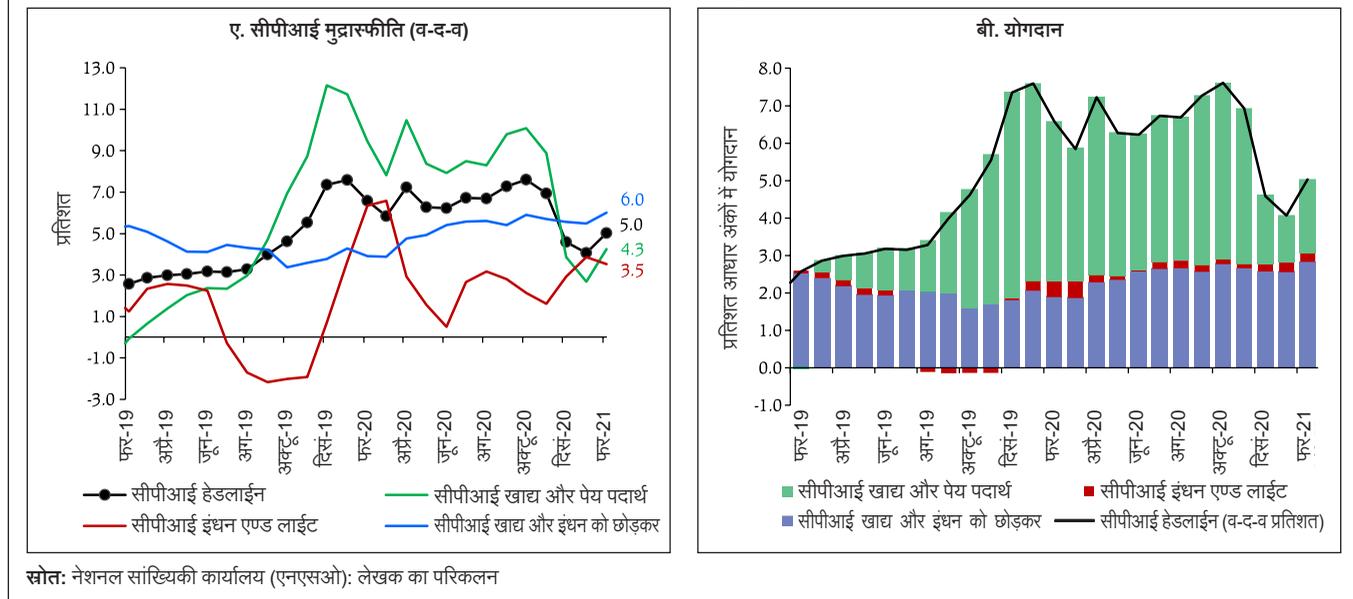
मुद्रास्फीति

फरवरी 2021 में, सीपीआई मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत पर थी, जिसमें जनवरी 2021 के 4.1 प्रतिशत की रीडिंग से 97 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि दर्ज की गई। फरवरी में खाद्य और मूल मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि (खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई) हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि के प्रमुख कारक थे (चार्ट 24ए)। फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 4.3 प्रतिशत हो गई जो जनवरी में 2.7 प्रतिशत थी। यह पूरी तरह से 200 बीपीएस के प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण था, यहां तक कि खाद्य कीमतों में भी महीने भर में लगभग 40

चार्ट 23: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)



चार्ट 24: सीपीआई मुद्रास्फीति



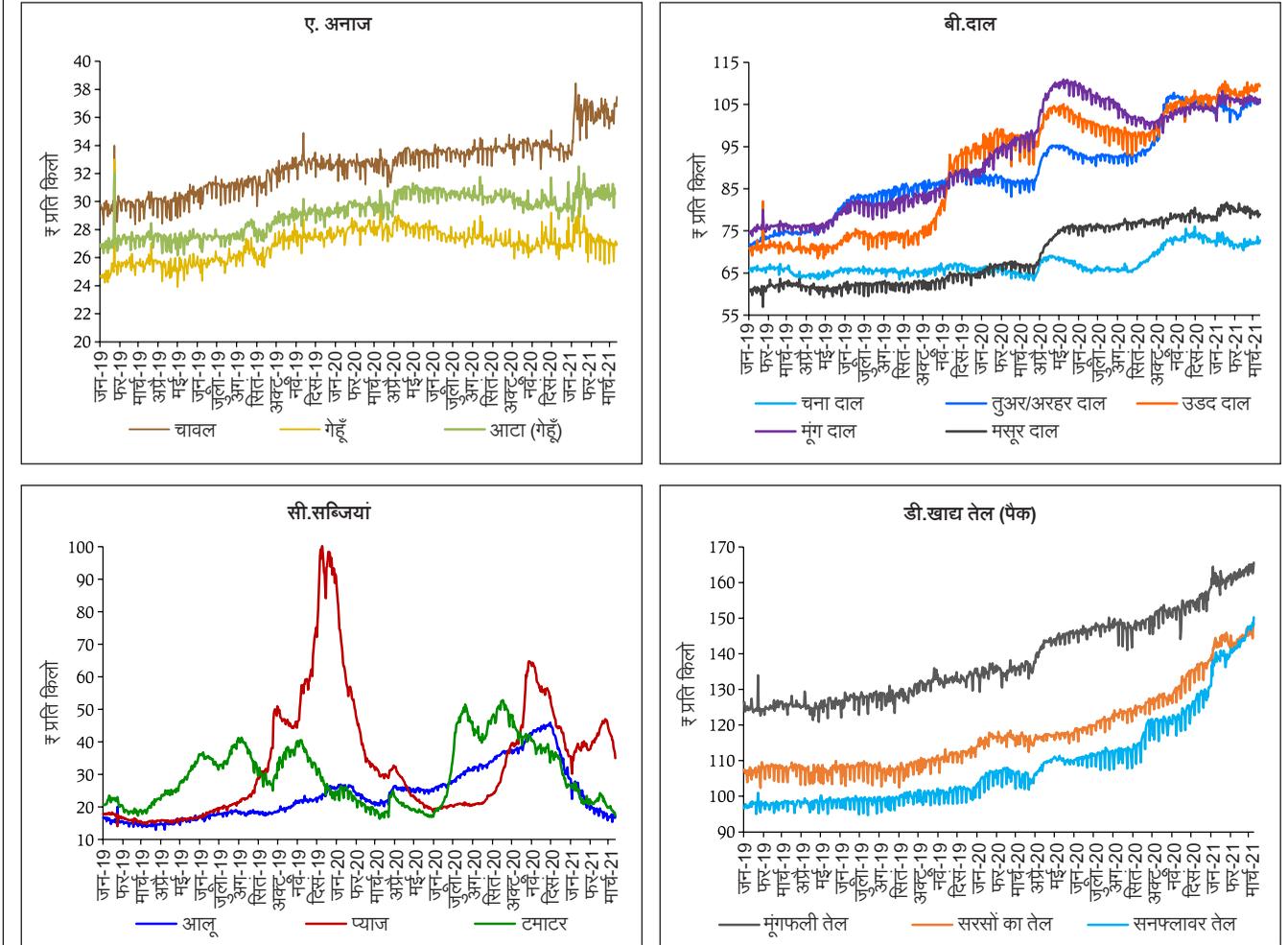
बीपीएस की गिरावट दर्ज की गई थी। फरवरी में खाद्य उप-समूहों में विशिष्ट मुद्रास्फीति उतार-चढ़ाव देखा गया। जबकि 12 खाद्य उप समूहों में से पांच ने दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति का प्रदर्शन किया, तीन उप-समूह में अपस्फीति देखी गयी। खाद्य तेलों, प्रोटीन आधारित खाद्य और बिना अलकोहोल पेय पदार्थों में मुद्रास्फीति का दबाव दिखाई दे रहा था। अनाज की कीमतों में अपस्फीति देखी गई। एलपीजी तथा लकड़ी और चिप्स के कारण फरवरी में ईंधन की कीमतों में नरमी आई। खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई, जो जनवरी में पहले से ही 5.5 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर था, फरवरी में अतिरिक्त 50 बीपीएस से बढ़कर 6.0 प्रतिशत पर आ गया, जो नवंबर 2018 के बाद का उच्चतम स्तर है। यह परिवहन और संचार, स्वास्थ्य, कपड़े और जूते, मनोविनोद और मनोरंजन तथा घरेलू वस्तुओं और सेवाओं में मुद्रास्फीति में पिक-अप द्वारा चालित था। पान, तंबाकू और नशिले पदार्थों तथा परिवहन और संचार में दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति देखी गई। सोने की कीमतों में गिरावट के कारण कुछ नरमी के बावजूद निजी देखभाल की वस्तुओं में अत्यधिक मुद्रास्फीति रही। आवास तथा शिक्षा में मुद्रास्फीति कम रही। खाद्य और ईंधन के अलावा सीपीआई का (47.3

प्रतिशत भार के साथ) समग्र हेडलाइन मुद्रास्फीति में 56 प्रतिशत हिस्सा रहा (चार्ट 24बी)।

उपभोक्ता मामलें, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामलें विभाग) से मार्च के लिए अब तक (1-12 मार्च 2021) के उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा आलू और टमाटर की कीमतों में शीतकालीन मौसमी नरमी दर्शाता है। फरवरी में प्याज की कीमतों में तेजी के बाद मार्च में नरमी आई। अनाज की कीमतें भी नीचे गिर गई हैं। हालांकि, अधिकांश दालों की कीमतें स्थिर रही है या और बढ़ गयी हैं। खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी मार्च में भी निरंतर जारी रही (चार्ट 25)।

4 मार्च 2021 के ओपीईसी प्लस के अप्रैल तक मौजूदा स्तरों पर उत्पादन बनाए रखने के निर्णय के बाद और भू-राजनीतिक तनाव में वृद्धि के कारण, मार्च में अब तक (1-12 मार्च 2021) कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी। इंडियन बास्केट कच्चा तेल 3 मार्च 2021 को 62 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर था, 8 मार्च 2021 को बढ़कर 68 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया। हालांकि, घरेलू पंप की कीमतें, पहले से ही एक ऐतिहासिक उच्च स्तर पर थी, जिसमें 2 मार्च 2021 के बाद कोई संशोधन

चार्ट 25: डीसीए आवश्यक वस्तु कीमतें



स्रोत: उपभोक्ता कार्य विभाग, भारत सरकार; तथा लेखक का परिकलन

नहीं किया गया। अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण मार्च में घरेलू केरोसिन और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि हुई (सारणी 3)।

खाद्य मुद्रास्फीति की गति, काफी हद तक, एक तरफ खरीफ और रबी के अनुकूल मौसम का अनाज की कीमतों पर और मौसमी सर्दियों की आवक से सब्जियों की कीमतों पर प्रभाव तो दूसरी तरफ खाद्य तेलों की कीमतों पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों और प्रोटीन आधारित खाद्य कीमतों के लिए बनी मांग-आपूर्ति बेमेल पर निर्भर करेगी। विनिर्माण और सेवाओं के लिए, हाल के महीनों में निविष्टि (इनपुट) मूल्य दबाव में वृद्धि हुई। फरवरी में, सेवाओं के लिए पीएमआई निविष्टि मूल्य सूचकांक आठ वर्ष के उच्च स्तर पर आ गया और विनिर्माण के लिए यह 2018 के मध्य

से उच्चतम स्तर पर था। परिणामस्वरूप, मूल मुद्रास्फीति का दबाव निरंतर जारी रहा, जो लॉकडाउन के बाद की अवधि में 6

सारणी 3: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें (चार प्रमुख महानगरों का औसत)

मद	युनिट	घरेलू कीमतें			महीना-दर महीना (प्रतिशत)	
		मार्च-20	फर-21	मार्च-21 [^]	फर-21	मार्च-21
पेट्रोल	₹/लीटर	72.9	91.3	93.3	4.2	2.2
डीजल	₹/लीटर	65.0	83.0	85.2	5.1	2.7
केरोसीन	₹/लीटर	29.4	27.4	29.4	5.9	7.4
एलपीजी	₹/सिलेंडर	811.9	771.3*	829.6	9.5	7.6

[^]: 1-12 मार्च 2021 की अवधि के लिए * फरवरी 2021 में औसत कीमतें
टिप्पणी: चार प्रमुख महानगरों (चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता) में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा लगाए जाने वाले कीमतों का औसत।
स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और लेखक का परिकलन।

प्रतिशत की नई ऊंचाई पर है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के साथ ही पेट्रोल और डीजल पर अब तक के प्रतिबंधों और पोस्ट-लॉकडाउन करों के तत्काल संकेत नहीं दिख रहे हैं, फिर भी तेल विपणन कंपनियों की मूल्य वृद्धि पर अधिकतम सीमा पंप कीमतों को ₹ 100 प्रति लीटर होने से रोक रही है। इस तरह की लागत वृद्धि के कारण, कंपनियां निविष्टि लागत में वृद्धि के कुछ हिस्से को लेने और कम मार्जिन का विकल्प चुन सकती हैं या मजबूत बहाली मांग पर यदि उन्हें मूल्य निर्धारण शक्ति प्राप्त होती है, तेजी से उसे उपभोक्ताओं की तरफ बढ़ा सकते हैं।

IV. वित्तीय स्थितियां

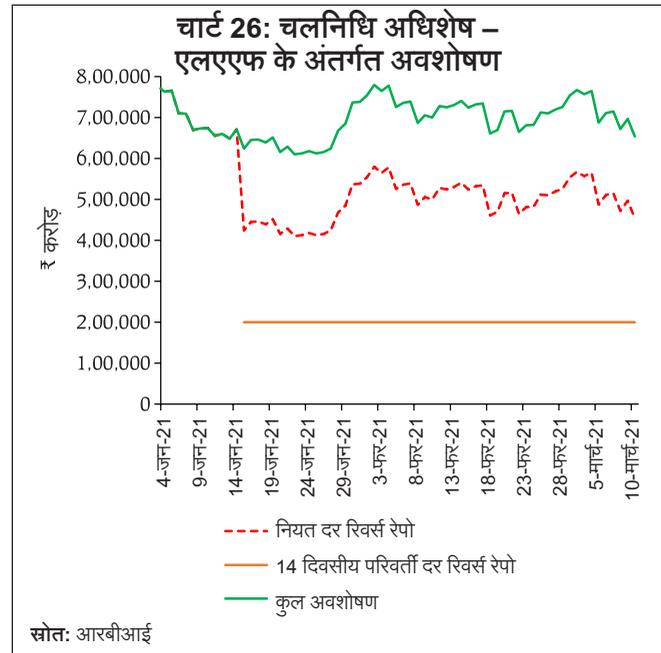
फरवरी और मार्च 2021 (12 मार्च 2021 तक) में ₹ 6.40 लाख करोड़ रुपये की औसत चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत दैनिक निवल चलनिधि अवशोषण से प्रणाली में चलनिधि की प्रचुरता रही। रिजर्व बैंक ने पाक्षिक परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो नीलामी का परिचालन जारी रखा - अधिशेष स्थितियों में इसका मुख्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन - जो ₹ 2 लाख करोड़ रुपये राशि के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) रखरखाव चक्र के साथ-साथ है (सारणी 4)। फरवरी-मार्च में आयोजित तीन नीलामियों सहित सभी नीलामियों को बाजार सहभागियों से गर्मजोशी से प्रतिसाद मिला, जिसमें 1.3 या उससे अधिक बोली-कवर अनुपात थे। जैसे-जैसे प्रणालीगत चलनिधि बढ़ी, स्थिर दर रिवर्स रेपो के अंतर्गत कुल चलनिधि अवशोषण का विस्तार जारी रहा (चार्ट 26)।

सारणी 4: 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो की नीलामी (मुख्य परिचालन)

(राशि ₹ करोड़ में)

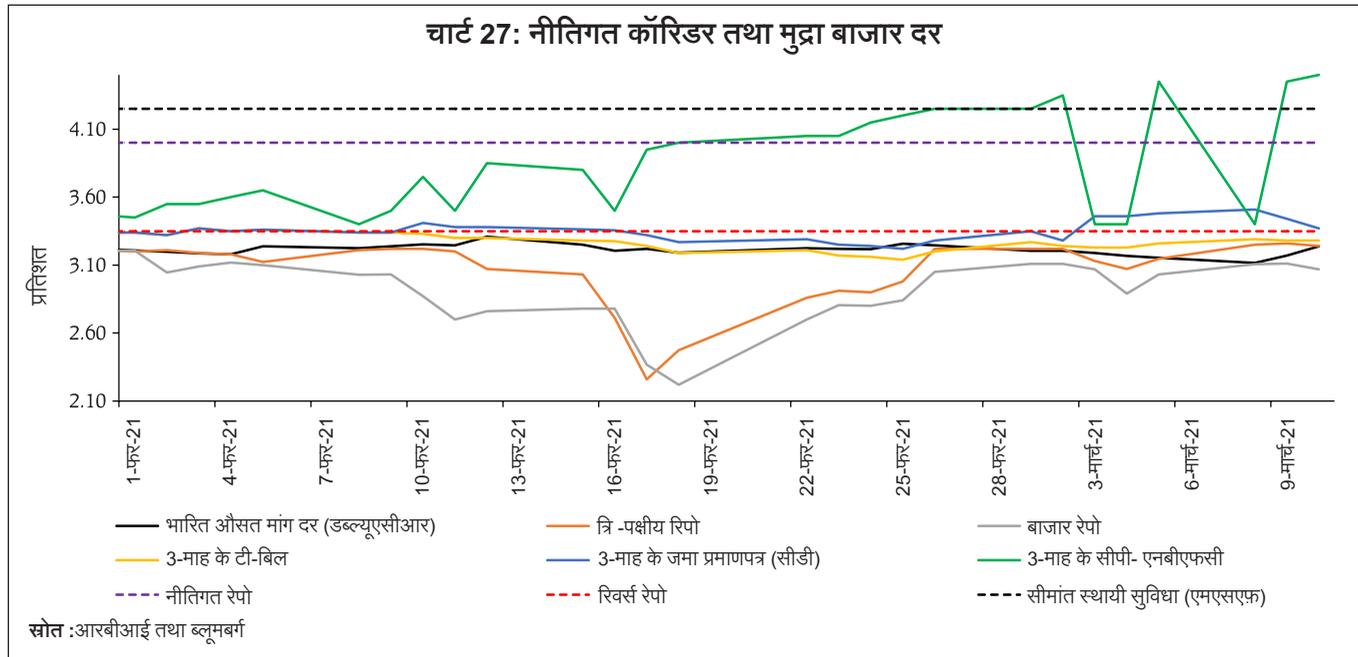
नीलामी दिनांक	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां	स्वीकृत राशि	बीड-कवर अनुपात
जनवरी 15, 2021	2,00,000	3,05,816	2,00,009	1.5
जनवरी 29, 2021	2,00,000	3,05,602	2,00,007	1.5
फरवरी 12, 2021	2,00,000	2,96,932	2,00,017	1.5
फरवरी 26, 2021	2,00,000	3,33,909	2,00,010	1.7
मार्च 12, 2021	2,00,000	2,68,860	2,00,007	1.3

स्रोत: आरबीआई



रिजर्व बैंक ने अपने खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) को बढ़ाया और 4 मार्च 2021 को ₹15,000 करोड़ रुपये की वर्धित राशि के लिए एक विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) का आयोजन किया। टर्म प्रीमिया के संकुचन का समर्थन करने के साथ-साथ अनुकूल वित्तीय स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए चलनिधि प्रदान करने हेतु ₹20,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों की खरीद और ₹15,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों की बिक्री को शामिल करते हुए 10 मार्च को विशेष विषम ओएमओ आयोजित किया, जिससे खरीद चरण पर एक उत्साहजनक प्रतिसाद मिला, जैसा कि 4.0 के बिड-कवर अनुपात और द्वितीयक बाजार प्रतिफल उतार-चढ़ाव के अनुरूप बोलियों में परिलक्षित होता है। हालांकि, बिक्री पक्ष पर, केवल ₹ 10,895 करोड़ की नीलामी की जा सकती थी। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2019 से बीस विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) आयोजित किए हैं, जिसमें खरीद और बिक्री के लिए समान राशि अधिसूचित की है और इससे चलनिधि का तटस्थ रहना अपेक्षित है।

अधिक चलनिधि भार के कारण, ओवरनाइट मुद्रा बाजार दर, अर्थात्, भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर), त्रि-पक्षीय रेपो दर और मार्केट रेपो दर ने रिवर्स रेपो दर से कम दर पर कारोबार किया। फरवरी में, बाजार में कम बिक्री के कारण

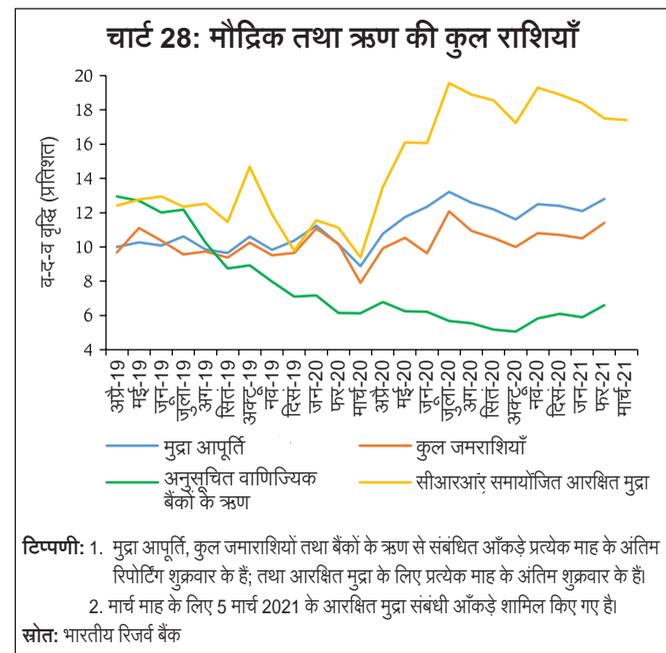


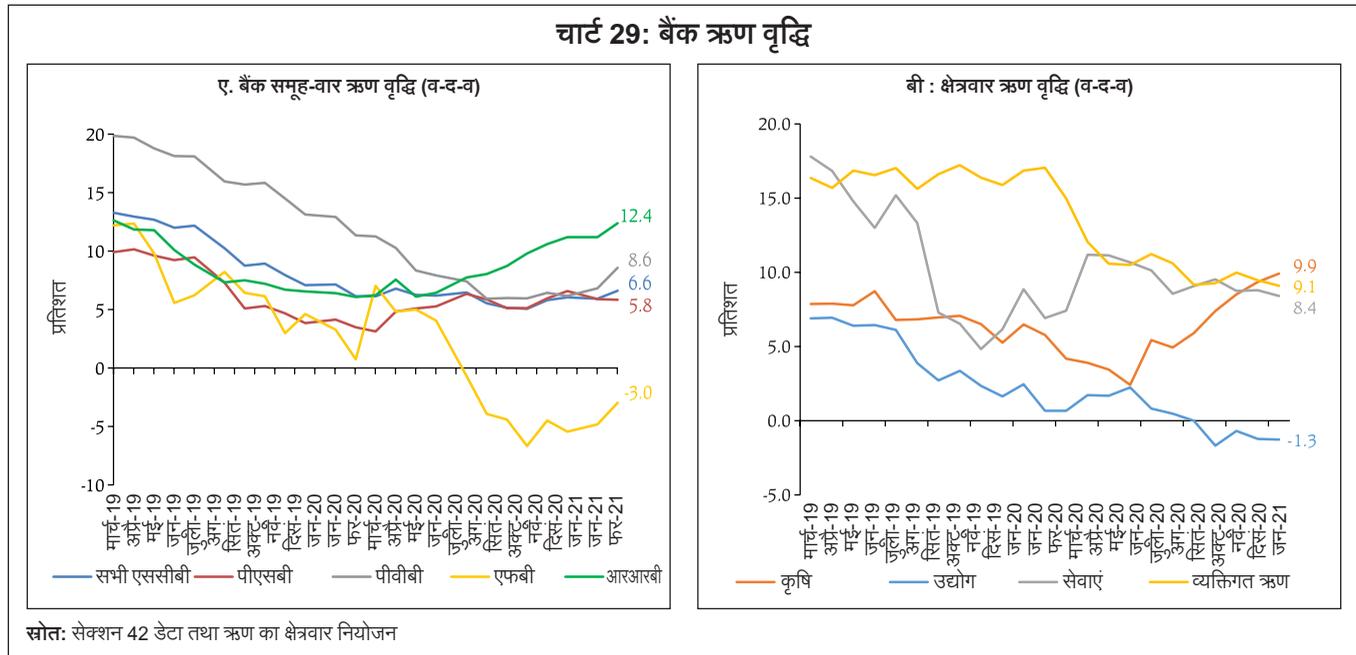
रेपो दर 0.01 प्रतिशत के निचले स्तर तक गिर गया, जिससे बाजार में प्रतिभागियों ने मंदड़िया बिक्री बाजार में अपनी बाध्यताओं को पूर्ण करने के प्रयोजन से विशिष्ट प्रतिभूतियों को हासिल करने के लिए संघर्ष किया। त्रि-पक्षीय रेपो बाजार में भी, म्यूचुअल फंडों द्वारा उधार में वृद्धि से दरों को नीचे लाया गया था। इसने गैर-संपार्श्विक और संपार्श्विक दरों के बीच एक होड़ लगा दी, जो धीरे-धीरे बंद हो गई क्योंकि दोनों खंडों में संपार्श्विक दरों को फरवरी के अंत तक डब्ल्यूएसीआर के साथ फिर से मिला दिया गया।

अन्य प्रमुख मुद्रा बाजार दरों में, 3 महीने की टी-बिल दर रिवर्स रेपो दर से नीचे कारोबार करना जारी रहा, जबकि गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3 महीने के वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और 3 महीने के जमा प्रमाण पत्र (सीडी) ने मार्च 2021 में रिवर्स रेपो दर से अधिक दर पर कारोबार किया (चार्ट 27)।

मौद्रिक और ऋण की स्थिति और सामान्य हो गई, जो प्रचलित चलनिधि की स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। घटक पक्ष में संचलन में मुद्रा (सीआईसी) 19.8 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 11.4 प्रतिशत) बढ़ने, और स्रोतों में निवल विदेशी आस्तियों (एनएफए) के कारण सीआरआर में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित आरक्षित मुद्रा (आरएम) 5 मार्च

2021 तक (एक वर्ष पहले 12.4 प्रतिशत) वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17.4 प्रतिशत तक विस्तारित हुई (चार्ट 28)। मनी सप्लाई (एम3) में 26 फरवरी, 2021 (एक वर्ष पहले 9.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी, जिसमें कुल जमा राशि में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 26 फरवरी 2021 (9.3 प्रतिशत एक वर्ष पहले) की तुलना में मुद्रा आपूर्ति (एम3) 12.8 प्रतिशत बढ़ी तथा कुल जमा में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, महामारी-





प्रेरित अनिश्चितताओं के कारण, जनता द्वारा सावधानी के तौर पर आस्तियों को सबसे अधिक तरल रूप में, नकदी में रखने से मुद्रा से कुल जमा अनुपात 17.3 प्रतिशत तक बढ़ गया।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि निम्नतर बिंदु पर पहुंची हुई प्रतीत होती है क्योंकि यह पिछले वर्ष के 6.1 प्रतिशत की तुलना में 26 फरवरी 2021 को वर्ष-दर-वर्ष 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। बैंक समूहवार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा 2021 (जनवरी-फरवरी) में वितरित ऋण वृद्धि 6 प्रतिशत के करीब स्थिर रही, फरवरी 2021 में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) ने क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 12.4 प्रतिशत तक की मजबूत वृद्धि दर्ज की, और विदेशी बैंकों (एफबीएस) के ऋण वृद्धि में संकुचन क्रमिक रूप से घटता गया (चार्ट 29ए)।

एससीबी द्वारा क्षेत्रीय ऋण वितरण से भी समग्र ऋण वृद्धि में स्थिरीकरण स्पष्ट है (चार्ट 29बी)। कृषि ऋण, एससीबी द्वारा क्षेत्रीय ऋण उठाव में सबसे उज्ज्वल बिंदु, जो 2019-20 में वितरित कुल ऋण का 13 प्रतिशत है, लगातार बढ़ रहा है और जनवरी 2021 में लगभग दोहरे अंकों में बढ़ा। सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि जनवरी में 8.4 प्रतिशत थी, जो व्यापार, पर्यटन और परिवहन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण ऋण वितरण द्वारा चालित थी।

निजी खपत के लिए बैंकों द्वारा खुदरा ऋण जनवरी 2021 में 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा। पर्सनल लोन सेगमेंट में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए ऋण में जनवरी में 14.6 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई और अन्य पर्सनल लोन¹¹ 12.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा। जनवरी 2021 में (जनवरी 2020 में 20.4 प्रतिशत) गोल्ड ज्वेलरी के बदले में पर्सनल लोन में भारी तेजी आई थी जो 132 प्रतिशत थी। जबकि उद्योग के लिए बैंकों द्वारा समग्र ऋण संकुचित बना रहा, जनवरी 2021 में मध्यम उद्योग के लिए ऋण वृद्धि 19.1 प्रतिशत थी (एक वर्ष पहले 2.8 प्रतिशत), और सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए 1 प्रतिशत (जनवरी 2020 में 0.5 प्रतिशत) के करीब है। बड़े उद्योगों के लिए बैंक ऋण के कारण बैंकों द्वारा उद्योग के लिए समग्र ऋण को नीचे ला दिया क्योंकि, विशेष रूप से उच्च श्रेणी वाले इन फर्मों ने मौजूदा कम ब्याज दर व्यवस्था का लाभ उठाया और अपने उच्च लागत वाले बैंक ऋण में से कुछ का भुगतान करने के लिए बाजार से उधार लिया।

¹⁰ अन्य सेवाओं में म्यूचुअल फंड (एमएफएस), एनबीएफसी और एमएफएस के अलावा बैंकिंग और वित्त और अन्य सेवाएं शामिल हैं, जो सेवाओं के तहत कहीं और दर्शायी नहीं जाती हैं।

¹¹ अन्य व्यक्तिगत ऋण में अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू उपभोग के लिए ऋण, चिकित्सा व्यय, यात्रा, शादी और अन्य सामाजिक समारोह शामिल हैं।

वर्तमान सामान्यीकरण के चरण में एससीबी की उधार और जमा दरों में संचरण से और सुधार हुआ। रेपो दर के 250 बीपीएस (अर्थात फरवरी 2019 से) संचयी कमी के प्रतिसाद में, एससीबी द्वारा मंजूर नये रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर में 183 बीपीएस की गिरावट आई, जिसमें से 112 बीपीएस की कटौती मार्च 2020 के बाद लागू हुई। मीडियन टर्म डिपॉजिट रेट (एमटीडीआर) जो प्रचलित कार्ड दरों को दर्शाता है, में 211 बीपीएस (फरवरी 2021 तक) की काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। कमजोर ऋण मांग के चलते लगातार अधिक चलनिधि के कारण कोविड-19 के बाद जमा दरों के समायोजन में तेजी आई है। मार्च 2020 से फरवरी 2021 के दौरान एमटीडीआर में 144 बीपीएस की कमी आई। मार्च 2020 से फरवरी 2021 के दौरान एमटीडीआर में 144 बीपीएस की कमी आई। इसी अवधि के दौरान, 1-वर्ष माध्यिका सीमांत निधि लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) एक साथ 94 बीपीएस से कम हुआ, जो कुल निधि की लागत में कमी का संकेत देता है (सारणी 5)।

महामारी के मद्देनजर चलनिधि बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों से उत्साहित, सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) पर प्रतिफल ने रेंज बाउंड करोबार किया। वक्र के लंबे अंत में, प्रतिफल, हालांकि, दुस्साध्य 5-वर्ष और 10-

सारणी 5: रेपो दर से बैंक जमा तथा उधार दरों में संचरण
आधार अंक

अवधि	रेपो रेट	मीयादी जमा दर		उधार दर		
		मध्यम अवधि डिपॉजिट रेट	डब्ल्यूएडीटी डीआर	1 वर्षीय माध्यिका एमसीएलआर	डब्ल्यूए एलआर-बकाया रुपया ऋण	डब्ल्यूए एलआर-नया रुपया ऋण
फर 2019 - सितं 2019	-110	-9	-7	-30	2	-40
अक्टू 2019 - फर 2021*	-140	-175	-138	-120	-95	-143
मार्च 2020 - फर 2021*	-115	-144	-99	-94	-77	-112
फर 2019 - फर 2021*	-250	-211	-145	-150	-93	-183

*: डब्ल्यूएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर पर नवीनतम डेटा जनवरी 2021 से संबंधित है।

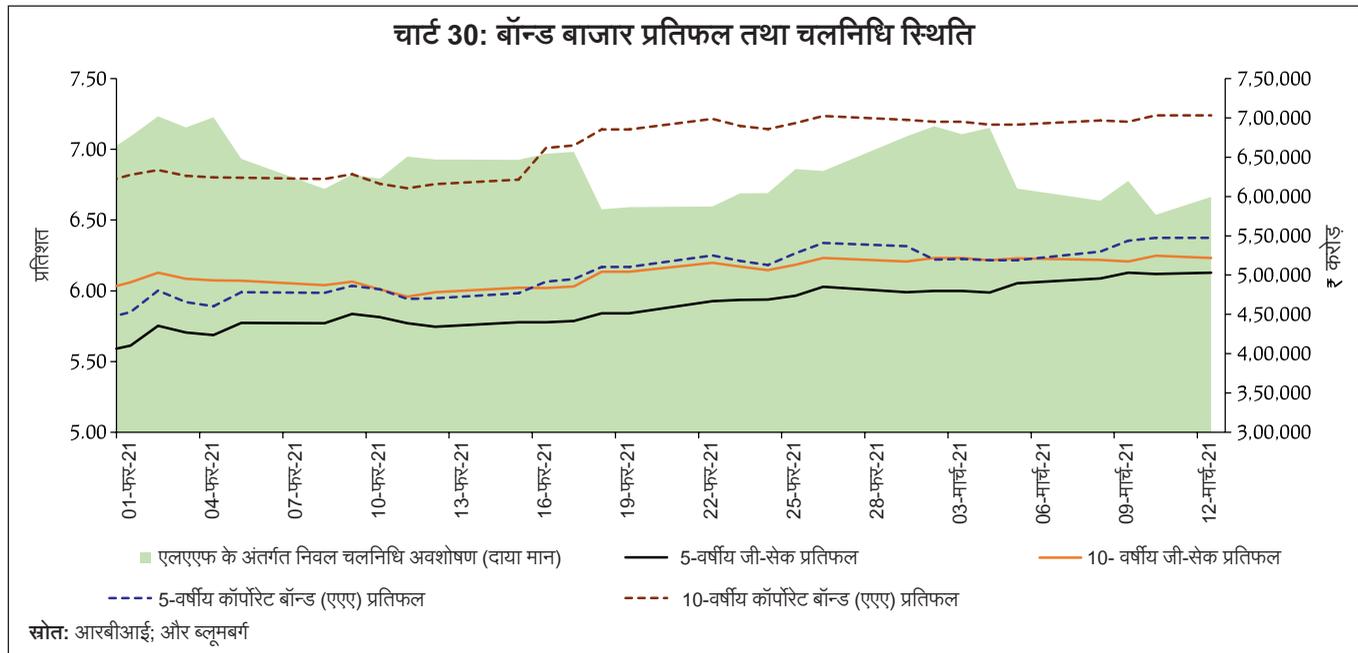
डब्ल्यूएलआर: भारत औसत उधार दर।

डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारत औसत घरेलू अवधि जमा दर;

एमसीएलआर: निधियों की सीमांत लागत आधारित उधार दरें।

स्रोत: आरबीआई

वर्ष की ब्लूमबर्ग जेनेरिक जी-सेक प्रतिफल बढ़कर फरवरी-मार्च 2021 (12 मार्च तक) के दौरान क्रमशः 64 बीपीएस और 33 बीपीएस पर स्थिर हुआ (चार्ट 30)। पहले से ही की गयी चर्चा के अनुसार आगामी वर्ष के लिए बाजार उधार के आकार पर आशंका वैश्विक स्पिलओवर के कारण बढ़ गयी और बिकवाली शुरू हो गई। हालांकि, 10 वर्ष के भारतीय जी-सेक में वृद्धि, इस अवधि के



दौरान अमेरिका के 10 वर्ष के प्रतिफल के 54 बीपीएस से बढ़ने की तुलना में मध्यम थी।

जी-सेक प्रतिफल की ट्रैकिंग करने से, कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड रेटिंग स्पेक्ट्रम और जारीकर्ता श्रेणियों में मजबूत आई। हालांकि (i) कॉर्पोरेट, और (ii) एनबीएफसी द्वारा जारी इसी परिपक्वता के कॉर्पोरेट बॉन्ड का जी-सेक पर स्प्रेड, रेटिंग स्पेक्ट्रम में संकीर्ण होना जारी रहा। पीएसयू, बैंकों और एफआई द्वारा जारी बांडों का स्प्रेड बढ़ गया है (सारणी 6)।

वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के कॉर्पोरेट के आय परिणामों ने लाभप्रदता में शानदार वृद्धि, निविष्टि लागत में महत्वपूर्ण कमी के साथ बाजार की उम्मीदों को मात दी है। इससे प्रति शेयर आय पर विशेष रूप से धातु, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, ऑटो, औद्योगिक और मूल सामग्री जैसे क्षेत्रों में आशावादी दृष्टिकोण रहा (चार्ट 31)। तांबे की कीमतों में लंदन मेटल एक्सचेंज में बहुवर्षीय उच्चांक दर्ज किया साथ-साथ एल्युमीनियम और स्टील जैसे अन्य प्रमुख जिंसों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, जो घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शा रही है। इसके अलावा, टिकाऊ उपभोक्ता क्षेत्र की कंपनियों, विशेष रूप से एयर कंडीशनर विनिर्माण

सारणी 6: 3 वर्षीय कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और स्प्रेड

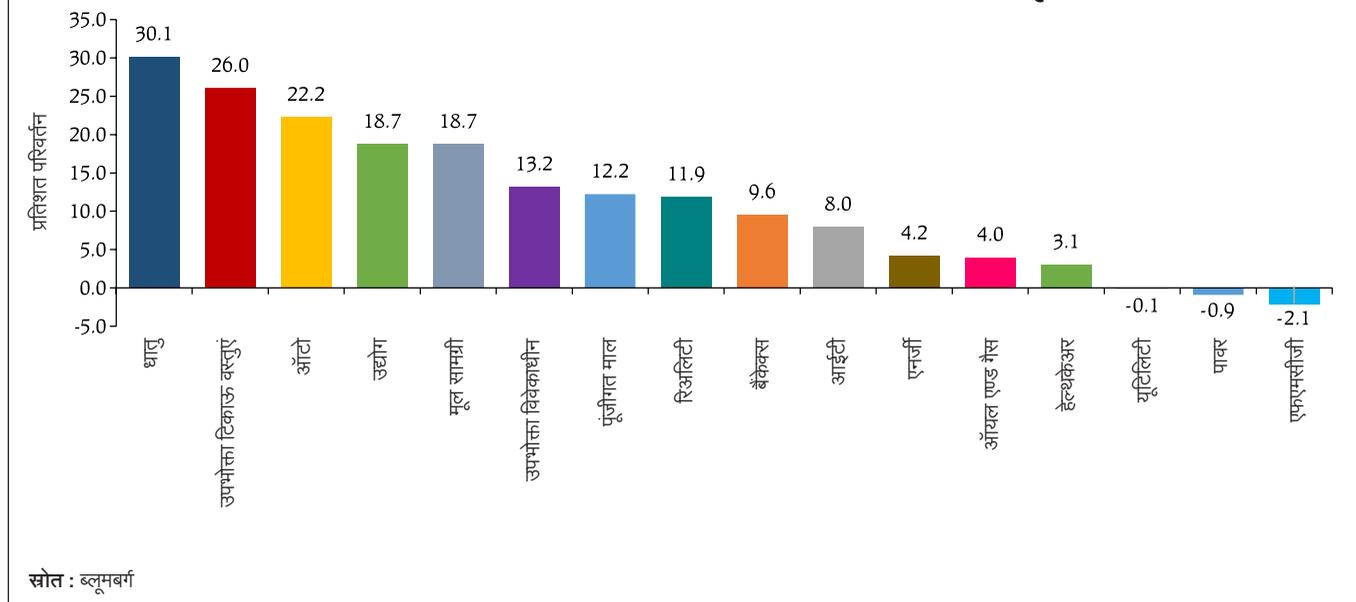
जारीकर्ता	रेटिंग	प्रतिफल			स्प्रेड		
		जन-21	फर-21	घट-बढ़	जन-21	फर-21	घट-बढ़
		(प्रतिशत)			(आधार अंक)		
पीएसयू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं	एएए	4.96	5.57	61	26	52	26
	एए	5.62	6.16	54	92	111	19
	बीबीबी-	8.75	9.32	57	405	427	22
कॉर्पोरेट	एएए	4.85	5.20	35	16	16	0
	एए	5.74	5.99	25	105	96	-9
	बीबीबी-	9.69	9.89	20	500	486	-14
एनबीएफसी	एएए	4.96	5.30	34	27	27	0
	एए	6.34	6.58	24	164	155	-9
	बीबीबी-	10.62	10.86	24	592	583	-9

टिप्पण: प्रतिफल तथा स्प्रेड माह के औसत हैं।

स्रोत: एफआईएमएमडीए

कंपनियों को, कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित वाणिज्यिक प्रशीतन आवश्यकताओं से लाभ होने की संभावना है। भारत सरकार के आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से भी विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कॉर्पोरेट आय में

चार्ट 31: जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक 12 माह की वायदा आय वृद्धि



पुनरुद्धार काफी हद तक उच्च राजस्व और बिक्री की मात्रा के बजाय, परिचालन और वित्त की कम लागत के कारण उच्च मार्जिन से प्राप्त है। निवेश कीमतों वृद्धि के कारण लागत में कटौती लंबे समय के लिए टिकाऊ नहीं हो सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में हाल का उछाल भी अगले कुछ तिमाहियों में कॉर्पोरेट मार्जिन को प्रभावित कर सकता है, हालांकि उन में से कुछ जोखिमों को पहले से ही आय अनुमानों में शामिल किया होगा।

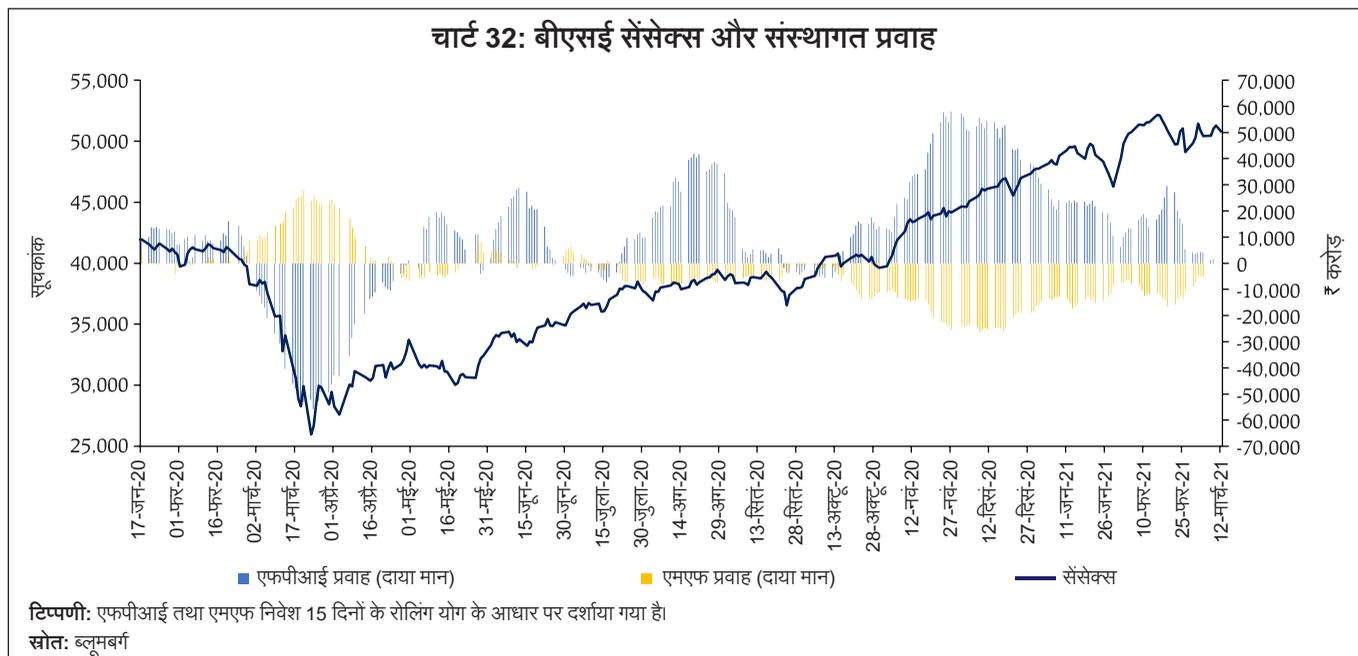
जनवरी 2021 के अंत में प्रचलित कमजोर गति के विपरित, बेंचमार्क सेंसेक्स 3 फरवरी 2021 को इतिहास में पहली बार 50,000 अंक से ऊपर बंद हुआ और बजट प्रस्तावों, रिजर्व बैंक द्वारा जीडीपी वृद्धि पर दोहरे अंकों की प्रत्याशा और वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों के कारण 15 फरवरी 2021 को 52,154 अंक के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा (चार्ट 32)। हालांकि, महीने के अंत में, अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और कुछ भारतीय राज्यों में कोविड-19 मामलों में एक नए स्पाइक के बाद बाजारों में गिरावट आई।

मार्च 2021 में बाजार आशावाद पर शुरू हुए, 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए जारी सकारात्मक जीडीपी डेटा और फरवरी 2021 के लिए ऑटो बिक्री का उत्साहजनक रिपोर्ट,

जीएसटी संग्रह और पीएमआई से उत्साहित हैं। इसके बाद, वैश्विक बाजारों में बिकवाली को ट्रैक करते हुए भारतीय इक्विटी बाजारों ने अस्थिरता का प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स में 95.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 12 मार्च 2021 को 50,792 पर बंद हुआ जो 23 मार्च 2020 को 25,981 के निचले स्तर से बहुत उपर है।

दूरसंचार लिंक की असफलता के कारण 24 फरवरी 2021 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में लगभग चार घंटे के लिए ट्रेडिंग रुकी हुई थी, जिससे एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड (एनसीएल), जो एनएसई की एक पूर्ण सहायक कंपनी है तथा एनएसई पर निष्पादित सभी लेन-देनों के समाशोधन और निपटान के लिए जिम्मेदार है, की ऑनलाइन जोखिम प्रबंधन प्रणाली अनुपलब्ध रही। फरवरी के वायदा कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति के दिन बिजली चली गयी जब लेन-देन की मात्रा सामान्य से अधिक थी। एनएसई दुनिया में सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंजों में से एक है और भारत में 2019-20 के दौरान अग्रणी बाजार हिस्सेदारी (कुल कारोबार द्वारा) इक्विटी नकदी कारोबार में 93.2 प्रतिशत और इक्विटी डेरिवेटिव कारोबार 99.9 प्रतिशत है।

24 फरवरी, 2021 को बीएसई और एनएसई में इक्विटी कैश सेगमेंट का कारोबार पिछले कारोबारी दिन की तुलना में 7.6



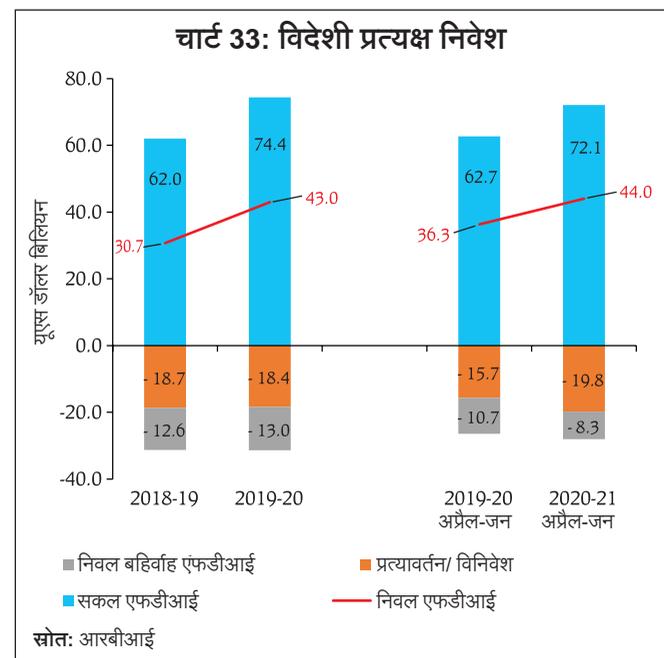
प्रतिशत बढ़ा, जिसे ज्यादातर ब्लॉक डील का समर्थन मिला। हालांकि, स्टॉक विकल्पों और वायदा और सूचकांक विकल्पों और वायदा में कुल नोशनल कारोबार में पिछले कारोबारी दिन से क्रमशः 45.1 और 20.1 प्रतिशत की गिरावट आई। व्यापारिक ठहराव जिसके कारण बाजार गतिविधि में व्यवधान उत्पन्न हुआ, के अलावा टर्नओवर में गिरावट के कारण आर्बिट्राज अवसर भी नहीं रहे तथा इसके बाद एक एक्सचेंज बंद होने तथा / या एनएसई¹² के साथ कुछ बाजार सहभागियों के व्यापारिक व्यवस्थाएं बंद हुईं। एनएसई ने अपने व्यापार सत्र को 15:30 बजे से 17:00 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की ताकि अंतर-दिवसीय स्थिति को बंद किया जा सके। बीएसई, जो सामान्य रूप से कार्य करता था, इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए देर तक खुला रहा।

इस घटना में प्रमुख मुद्दा एनसीएल के बंद होने के कारण अंतरसंचालनीयता की प्रभावहीनता थी। जबकि एनएसई के लेन-देनों को एनसीएल द्वारा मंजूरी दी जाती है, बीएसई पर लेन-देनों को इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से मंजूरी दी जाती है। 2018 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इन दोनों समाशोधन निगमों के बीच अंतरसंचालनीयता की घोषणा की थी ताकि दलालों को एक समाशोधन गृह में अपने समाशोधन और निपटान कार्यों का समेकन करने में मदद मिल सके चाहे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार निष्पादित किया गया है। परिचालनों को आपदा बहाली साइट में स्विच करने में असमर्थता और एक महत्वपूर्ण असफलता थी। आपदा प्रबंधन और बहाली के साथ मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली शेयर बाजार के सुचारू संचालन के लिए एक आवश्यक घटक है (2019 में, सेबी ने कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया था और इस तरह के व्यवधान की स्थिति में एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों सहित बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं के लिए आपदा बहाली साइटों को बनाए रखा)। ब्रोकरों का मानना है कि समय पर सूचना और स्पष्टीकरण से ऑनलाइन व्यापारियों द्वारा बीएसई पर कम दाम में की गई बिक्री टाली जा सकती थी

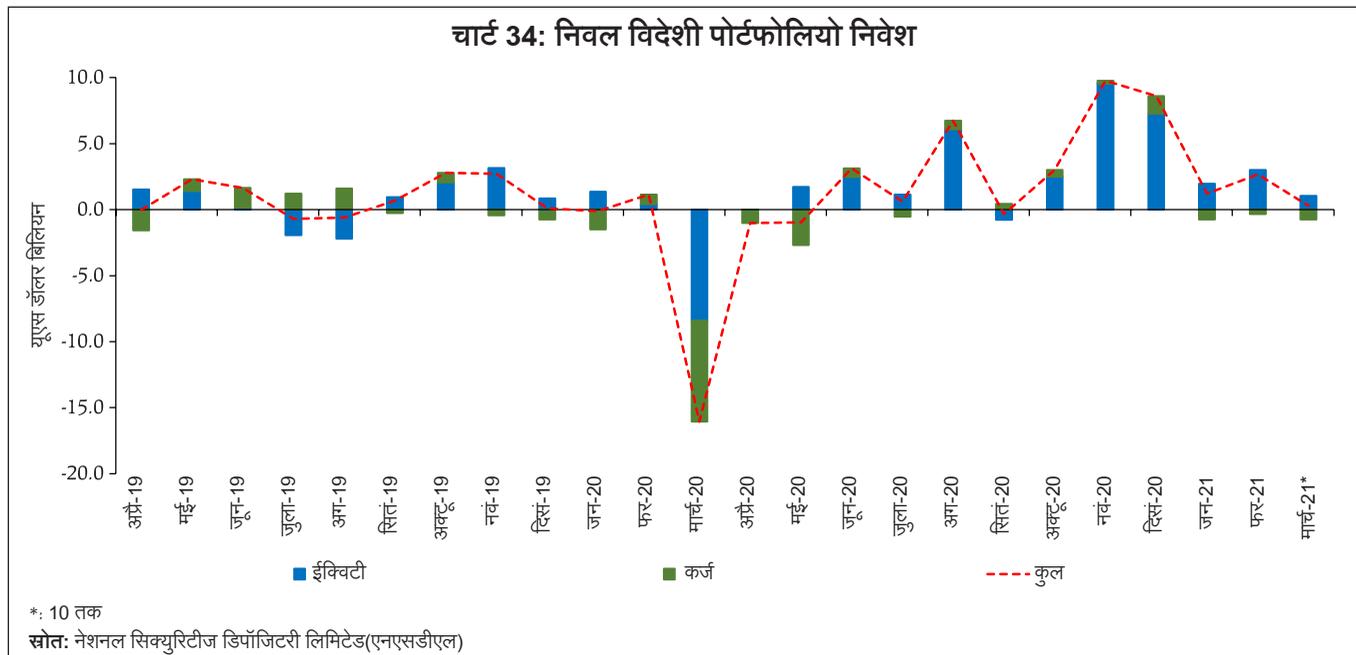
और निवेशकों का भारी नुकसान रोका जा सकता था।

इस घटना के बाद सेबी ने एनएसई को ट्रेडिंग हॉल्ट का विस्तृत मूल कारण विश्लेषण करने और आपदा बहाली साइट पर व्यापार माइग्रेट न करने के कारण देने के लिए सूचित किया। इसके अलावा, सेबी की तकनीकी सलाहकार समिति को कथित तौर पर एनएसई में व्यापार रोकने की जांच करने और जवाबदेही तय करने का आदेश दिया गया है। एक्सचेंजों में जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा बेंचमार्क निफ्टी और सेंसेक्स को, सभी स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार करने की अनुमति देना, किसी अन्य एक्सचेंज के व्यापारिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के उपयोग को शामिल करने के लिए अंतरसंचालनीयता का विस्तार और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अधिक एक्सचेंजों के प्रवेश की अनुमति देने पर विचार करने की आवश्यकता है।

इक्विटी प्रवाह कम होने के कारण जनवरी 2021 में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में कमी आई। फिर भी, निवल एफडीआई 2020-21 (अप्रैल-जनवरी) एक साथ एक वर्ष पहले के 36.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 44.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो अगस्त-दिसंबर 2020 के दौरान निवल एफडीआई में वृद्धि दर्शाता है (चार्ट 33)।



¹² मिंट रिसर्च 28 फरवरी 2021.

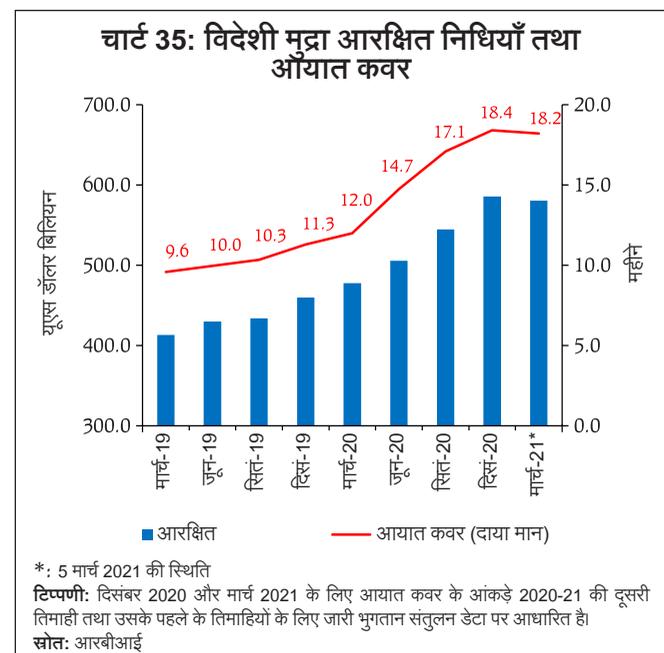


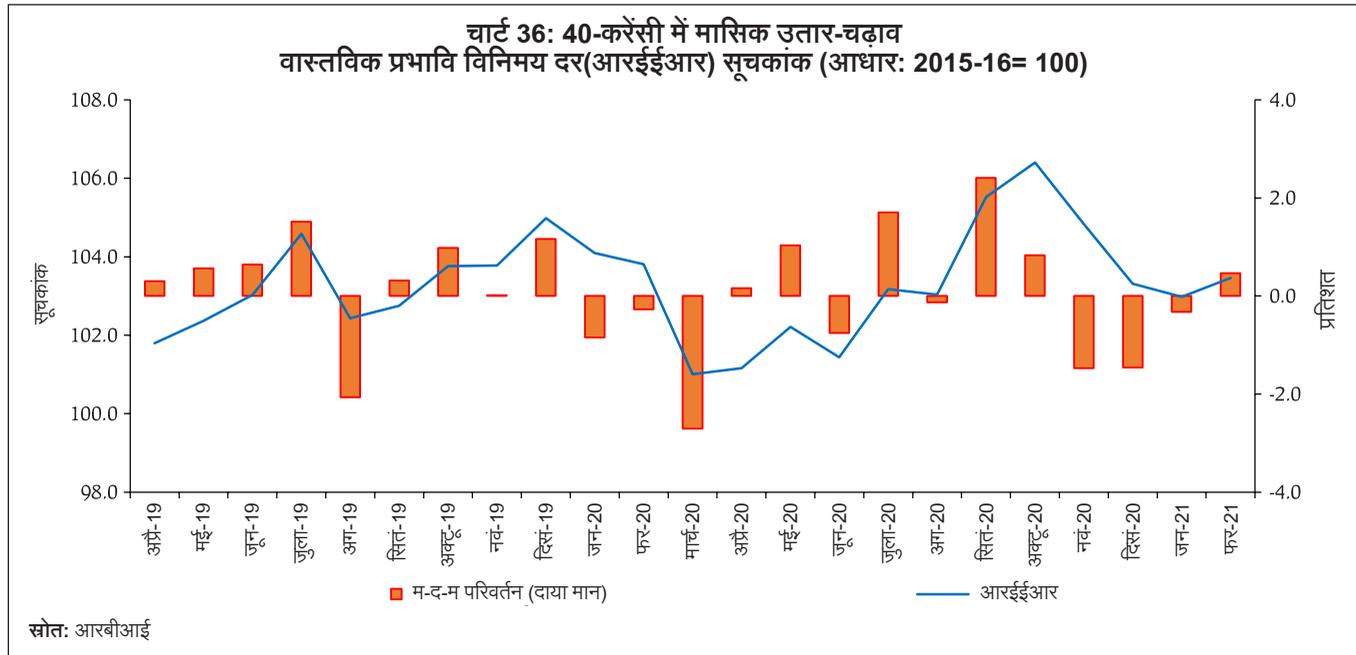
फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में बिकवाली के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मार्च 2021 के पहले सप्ताह में घरेलू पूंजी बाजार में निवल खरीदार बन गए। एफपीआई ने इक्विटी क्षेत्र में निवल खरीद की, जबकि इस अवधि के दौरान ऋण बाजार में शेष निवल विक्रेता रहे। संचित रूप में, इक्विटी में एफपीआई का निवल निवेश 2020-21 में अब तक (10 मार्च तक) 36.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2012-13 के बाद सबसे अधिक है (चार्ट 34)। इस अवधि के दौरान एफपीआई प्रवाह की गुणवत्ता में भी श्रेणी-1 एफपीआई के रूप में सुधार हुआ, जिसमें केंद्रीय बैंक, सॉवरन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, विनियमित संस्थाएं और बहुपक्षीय संगठन शामिल हैं, ने दिसंबर 2019 के अंत में 87 प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना में फरवरी 2021 के अंत में अपनी हिस्सेदारी कुल इक्विटी आस्तियों के 95 प्रतिशत तक बढ़ा दी।

29 जनवरी 2021 को विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 590.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, 5 मार्च 2021 को 580.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो 18.2 महीने आयात के समतुल्य थी (चार्ट 35)।

विदेशी मुद्रा बाजार में फरवरी 2021 के अंत तक भारतीय रुपया (रुपये) कमजोर हुआ, जो निवल एफपीआई बहिर्गमन और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि दर्शाता है। हालांकि,

इसके बाद यह रिबाउंड हुआ, एफपीआई ने इक्विटी बाजार में अपना निवेश फिर से शुरू किया। 12 मार्च 2021 तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में अपनी मार्च 2020 के अंत में स्थिति से 3.7 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई। 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक के संदर्भ में, रुपये ने मार्च 2020 के अपने स्तर से फरवरी 2021 में 2.4 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि की (चार्ट 36)।





भुगतान प्रणाली

फरवरी 2021 में, थोक और खुदरा लेन-देन काफी बढ़ जाने के कारण डिजिटल इंडिया को अचानक मांग का सुखद अनुभव हुआ। रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (आरटीजीएस)-प्रेरित थोक लेन-देन मात्रा में 18.4 प्रतिशत (व-द-व) बढ़ोतरी हुई, जो पिछले महीने की तुलना में 4 प्रतिशत अंक से अधिक है (सारणी7)। इस बीच, आरटीजीएस लेन-देन के मूल्य में अचानक मामूली झटके के बाद 0.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। खुदरा क्षेत्र में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) लेन-देन की मात्रा और मूल्य में क्रमशः 13.6 प्रतिशत और 15.1 प्रतिशत गति बनी रही। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) डिजिटल

इकोसिस्टम का मुख्य आधार बना रहा, जिसकी मात्रा लगातार पांचवें महीने 2 बिलियन अंक से ऊपर बनी रही। 100 प्रतिशत कैशलेस टोलिंग हासिल करने के लिए 16 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) फास्टैग को अनिवार्य करने के निर्णय से, इस महीने में मात्रा और मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 44.3 प्रतिशत और 38.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, 25 फरवरी 2021 तक, फास्टैग के माध्यम से दैनिक टोल संग्रह में ₹104 करोड़¹³ आज तक की सबसे तेज वृद्धि देखी गई। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से लेन-देन की मात्रा में 89.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मूल्य में 115.7 प्रतिशत की तिगुनी अंक वृद्धि हुई। कुल

सारणी 7: चयनित भुगतान प्रणालियों का वृद्धि दर

भुगतान प्रणाली	लेनदेन की मात्रा में वृद्धि (व-द-व प्रतिशत)				लेनदेन के मूल्य में वृद्धि (व-द-व प्रतिशत)			
	जन-20	जन-21	फर-20	फर-21	जन-20	जन-21	फर-20	फर-21
आरटीजीएस	16.6	14.1	20.1	18.4	-20.8	-7.2	-20.3	0.7
एनईएफटी	27.0	10.3	23.5	13.6	-1.9	12.3	-2.7	15.1
यूपीआई	94.0	76.5	96.6	73.0	96.7	99.4	108.5	91.0
आईएमपीएस	51.3	33.5	48.9	28.7	42.4	33.1	43.7	28.3
एनईटीसी	280.5	60.4	361.8	44.3	204.2	48.1	249.1	38.8
बीबीपीएस	-63.6	84.0	-62.2	89.1	102.5	106.0	118.3	115.7

स्रोत: आरबीआई

¹³ स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)।

मिलाकर, फरवरी 2021 में थोक और खुदरा दोनों प्रमुख भुगतान प्रणालियों के दैनिक औसत लेन-देन ने पिछले महीने के अपने मूल्यों पर पकड़ प्राप्त की।

डिजिटल बैंडवेगन पर पहुंचते हुए, पहले पेपरलेस यूनिजन बजट 2021 ने भुगतान के डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए ₹1500 करोड़ आवंटित किए। इसके अलावा, देश में फिनटेक क्रांति को मजबूत करने के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में फिनटेक हब स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। बाजार अनुसंधान से पता चलता है कि महामारी के बीच, भारत ने फिनटेक निवेश में 60 प्रतिशत की वृद्धि की और यूएस \$ 647.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर¹⁴ मूल्य के 33 फिनटेक फंडरेजिंग सौदें करते हुए चीन को पीछे छोड़ दिया। डिजिटल भुगतान के महामारी-प्रेरित प्रसार के कारण केवल फरवरी 2021 में भारतीय फिनटेक क्षेत्र द्वारा फंडरेजिंग में 46 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जो \$ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है और एक वर्ष पहले लगभग 137 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। संपर्क रहित डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित करने का लाभ उठाते हुए, कई फिनटेक सहभागियों ने अपने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए अनुकूल बनाया है, जिससे स्थानीय किराना (किराने) की दुकानों, बढ़ते ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और पारंपारिक दुकानों के ऑनलाइन खुदरा चैनलों को लक्षित किया गया है। कार्ड जारी करने वाले बैंकों और फिनटेक कंपनियों के बीच हालिया सहयोग के साथ-साथ अनधिकृत विदेशी-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन पर कार्रवाई घर-घर फिनटेक व्यवसायों को पनपने के लिए हेडरूम प्रदान करने की उम्मीद है।

भुगतान प्रणाली में अधिक तकनीकी नवाचार के अवसरों में वृद्धि के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी से उत्पन्न चुनौतियों भी बढ़ती है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस)¹⁵ के एक अध्ययन के अनुसार, महामारी के कारण दूरस्थ कार्य और क्लाउड सॉफ्टवेयर से विश्व स्तर पर वित्तीय सेवा फर्मों पर साइबर हमलें बढ़ गए हैं। रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा

नियंत्रणों पर एक मास्टर निर्देश जारी किया है जो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, कार्ड भुगतान जैसे चैनलों के लिए सामान्य सुरक्षा नियंत्रणों पर मजबूत शासन और कुछ न्यूनतम मानकों की निगरानी के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। यही नहीं, रिज़र्व बैंक भुगतान आउटसोर्सिंग पर दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए आचार संहिता जारी करेगा। 'आरबीआई कहता है' अभियान हाल ही में डिजिटल भुगतान में सुरक्षा के बारे में आउटरीच बढ़ाने और ग्राहकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए 'रैप' तरीका अपनाया है। पेपर आधारित क्लियरिंग में परिचालनगत कार्यक्षमता लाने के लिए अभी तक चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के दायरे से बाहर के उन सभी शाखाओं को सितंबर 2021 तक क्लियरिंग मैकेनिज्म के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। रिज़र्व बैंक ने खुदरा भुगतान के लिए अखिल भारतीय नई अब्रेला एन्टिटी (एनयूई) स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ायी थी ताकि विभिन्न डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक सक्षम और प्रतिस्पर्धी माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

आगे बढ़ते हुए, टीकाकरण अभियान और संक्रमण वक्र के समतल होने से उपभोक्ता मनोभाव में सुधार करने, व्यापारिक उत्साह को बढ़ावा देने और डिजिटल भुगतान उद्योग को कोविड-19 पुनरुद्धार एजेंडा का प्रमुख कारक बनाने में सहायता मिलेगी क्योंकि इस परिवर्तन में हम कैसे काम करते हैं, सीखते हैं, खरीदारी करते हैं, भुगतान करते हैं और रहते हैं, इसका परिचय होगा।

V. निष्कर्ष

भारत दो बिंदुओं की नोक पर स्थित है। सबसे पहले, अशुभ संकेत हैं कि संक्रमण बढ़ रहे हैं। एक दूसरी लहर? समय बताएगा। दूसरी ओर, टीकाकरण स्वास्थ्य कर्मियों से आगे निकलकर वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंच गया है, लेकिन मार्च 16 तक 3.3 करोड़ पर ही है, पूरी प्रक्रिया जल्द करने की जरूरत है। दुनिया की ओर मुड़ते हुए भारत ने महामारी के खिलाफ 60 प्रतिशत वैश्विक विनिर्माण क्षमता के साथ दुनिया की फार्मसी 16 के रूप में खुद

¹⁴ फिनटेक इंडस्ट्री इन इंडिया, आरबीएसए सलाहकार, फरवरी 2021.

¹⁵ इनाकी एल्डासोरो, जॉन फ्रॉस्ट, लियोनार्डो गाम्बोर्टा और डेविड व्हाइट द्वारा, कोविड-19 और वित्तीय क्षेत्र में साइबर जोखिम, 14 जनवरी 2020 <https://www.bis.org/publ/bisbull37.html>

¹⁶ शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने भारत की दुनिया की फार्मसी के रूप में सराहना की।

को लॉन्च किया। 20 जनवरी से 70 से अधिक देशों को भारत में बने टीके मिले हैं। आज वैश्विक टीकाकरण अभियान में भारत अब अकेला नहीं है। क्वाड पार्टनर्स - ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका - ने इंडो-पैसिफिक को टीका लगाने के लिए 2021 में सुरक्षित और प्रभावी कोविड-19 वैक्सीन निर्माण का विस्तार करने के लिए एक 'ऐतिहासिक साझेदारी'¹⁷ की। भारत जापान से रियायती ऋण लेकर अपनी सुविधानुसार टीका निर्माण का विस्तार करेगा। उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए अमेरिका वित्तपोषण करेगा। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया पर ध्यान देने के साथ-साथ टीकों और अंतिम मील वितरण सहायता प्रावधान में योगदान देगा। हम सब मिलकर, विश्व में सभी को टीका लगाएंगे और विश्व में महामारी के बाद के उज्ज्वल भविष्य का हिस्सा रहेंगे।

दूसरा, मुद्रास्फीति में वृद्धि का दबाव देखा गया। वास्तव में, सब्जियों के सिवाय, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति जून माह से 5.8 से 6.4 प्रतिशत के एक तंग दायरे में घटती-बढ़ती रही, जो मुद्रास्फीति के लक्ष्य की अधिकतम सहन सीमा को परखती है। तेल के वैश्विक बाजार, कीमतों में वृद्धि और उत्पादन में अवरोध का सामना कर रहे हैं। निविष्टि लागत का इस कदर बढ़कर एकाधिक वर्षों में उच्च स्तर पर पहुंचने से यह दुविधा पैदा होती है कि - यदि वे फैलकर आगे उपभोक्ताओं तक पहुंच जाती हैं तो मुद्रास्फीति और भी अधिक होगी क्योंकि कुल मांग जोर पकड़ने की वजह से फर्मों की कीमत निर्धारण शक्ति में वापसी हुई है; यदि उसे रोक कर रखा जाता है तो अर्थव्यवस्था में लाभप्रदता घट जाएगी और साथ ही सकल संवर्धित मूल्य भी घटेगा। भारत कई चीजों के बीच बढ़ती कीमतों की एक अजीब स्थिति से गुजर रहा है। निश्चित रूप से इसके लिए कोई उपाय है, जैसा इस लेख के पिछले अंकों में बताया गया है।

भारत में उच्च वृद्धि को बहाल करने को लेकर अत्यंत बेचैनी महसूस की जा रही है और जो डेटा प्राप्त हो रहे हैं उसके मुताबिक व्यक्तिगत देखभाल, मनोरंजन एवं आतिथ्य जैसी संपर्क-गहन सेवाएं भी तनाव में होने के साथ-साथ जोर पकड़ रही हैं, यहां तक कि कृषि क्षेत्र में विभिन्न फसलों ने और बागबानी ने पैदावार के

उच्च स्तर को पार किया है, और अंततः विनिर्माण ने संकुचन से होने वाले नुकसान को कम किया है। चारों ओर, हाउसहोल्ड्स और कारोबार, निवेशकों और बाजारों में, आशावाद अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। यह भी संभावना है कि भारत अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से स्वयं को अलग कर लेगा लेकिन वित्तपोषण की बढ़ती लागत और पहले से बढ़ता कर्ज बहाली में बाधा डालते हैं। भारत के मामले में, कर्ज की चुकौती की बंदौलत 2020-21 में बजटीय राजस्व के 25 प्रतिशत से अधिक की बचत हुई, लेकिन बचत करने के भी तौर-तरीके होते हैं: सरकारी कर्ज की परिपक्वता 11 वर्ष¹⁸ है जो पुनर्वित्त जोखिम को कम करता है। इस कर्ज की विदेशी धारिता 2 प्रतिशत से कम है, जिसका मतलब है कि अचानक होने वाले पूंजी बहिर्वाह को लेकर अतिसंवेदनशीलता कम रहती है क्योंकि इसने अपने कर्ज को अपनी ही मुद्रा में बेचने की क्षमता को दर्शाया है। साथ ही, जैसा पहले बताया गया है, भारत में संवृद्धि को लेकर विश्वसनीयता है - सरकारी कर्ज पर औसत ब्याज दर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से कम है। फिर भी, विषाणु के साथ रहने के शुरुआती अनुभव से सीखने के बावजूद एक और प्रकोप, अधिक लॉकडाउन एवं प्रतिबंध असहनीय हो जाएगा।

वर्ष 2021 में, जून के बाद मुद्रास्फीति संभवतः कम होगी, लेकिन यह एक वर्ष पहले की उच्च मुद्रास्फीति के सांख्यिकीय बेस इफेक्ट के कारण बुलेटिन के अंकों में जैसा उल्लेख किया गया है उसकी अपेक्षा अधिक होगी। विश्व स्तर पर, नीतियां प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगी, लेकिन बाजार भविष्य की ओर एवं पूर्व की सख्ती के संकेतों पर अपनी नज़रें गड़ाकर रखेंगी क्योंकि न तो वृद्धि और न ही मुद्रास्फीति के सरकारी आंकड़ों ने बाजार में उतार-चढ़ाव को अब तक सहारा प्रदान किया है। केंद्रीय बैंक अपनी समायोजनकारी परिचालन संबंधी घोषणा से परे जाएंगे यदि उनके कथित रुख को चुनौती दी जाती है। केंद्रीय बैंक शायद अपने पारंपरिक अधिदेशों के दायरे से बाहर जाएंगे और वहां की ओर रुख करेंगे जहां वे पहले नहीं गए हैं - पर्यावरणीय स्थिरता (यूके); जलवायु परिवर्तन (यूरो क्षेत्र); आवास मूल्य (न्यूजीलैंड); प्रतिफल नियंत्रण (जापान; ऑस्ट्रेलिया); आस्ति खरीद (सर्वत्र)। हम रोचक काल में रहते हैं!

¹⁷ दी स्पिरिट ऑफ दी क्वाड: जॉइंट स्टेटमेंट, 12 मार्च 2021.

¹⁸ केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए (राज्य सरकार की प्रतिभूतियों/एसडीएल के लिए 7.8 वर्ष)।

कोविड -19 के समय में अपरंपरागत मौद्रिक नीति*

अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण (यूएमपीटी) नीतिगत कार्यों की प्रकृति, उनके औचित्य, जिन चैनलों के माध्यम से वे काम करते हैं और संचालन के पैमाने के मामले में पारंपरिक उपकरणों से काफी भिन्न होते हैं। रिजर्व बैंक ने कोविड -19 के मद्देनजर कई अपरंपरागत उपाय किए; विशेष रूप से, लंबी अवधि के रेपो संचालन (एलटीआरओ) को मौद्रिक संचरण की सुविधा के लिए और क्रेडिट ऑफ्टेक का समर्थन करने के लिए पेश किया गया था, जबकि लक्षित लंबी अवधि के रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) ने विशिष्ट क्षेत्रों और संस्थाओं को चलनिधि प्रदान की, जो चलनिधि तनाव का सामना कर रहे थे। विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट) प्रीमियम को संपीड़ित करने के लिए आयोजित किया गया था, जबकि स्पष्ट फॉरवर्ड मार्गदर्शन ने सामान्य स्थिरता को बहाल करने में अन्य यूएमपीटी को पूरक किया जिसके चलते वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए वित्तीय स्थितियों आसान हुईं कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए इन उपायों ने आर्थिक सुधार की नींव रखी है।

परिचय

1990 के दशक की शुरुआत और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के आगमन के बाद से, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में केंद्रीय बैंकों ने आम तौर पर अपने प्रमुख मौद्रिक नीति साधन के रूप में अल्पकालिक ब्याज दर का उपयोग किया है। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के जवाब में, कई ईई केंद्रीय बैंकों ने अपनी नीतिगत ब्याज दरों को शून्य स्तर तक कम कर दिया। हालांकि, ऐसी कम दरों की दृढ़ता ने पारंपरिक नीति साधनों को कमजोर बना दिया, जिसने मौद्रिक संचरण तंत्र को बिगाड़ दिया। इस स्थिति में, कुछ केंद्रीय बैंकों ने आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित

* लेख मौद्रिक नीति विभाग के भीमप्पा अर्जुन तलवार, कृष्ण मोहन कुशवाहा और इंद्रनील भट्टाचार्य द्वारा तैयार किया गया है। लेखक गुमनाम रेफरी, संपादकीय समिति, श्री सितिकठ पटनायक और श्री मुनीश कपूर के बहुमूल्य सुझावों और टिप्पणियों के लिए, श्री जॉइस जॉन को तकनीकी मार्गदर्शन के लिए और श्री अक्षय शरद गोरवाडकर को डेटा सहायता के लिए आभारी हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

करने के लिए 'अपरंपरागत' मौद्रिक नीति उपकरण (यूएमपीटी) की शुरुआत की।¹ यूएमपीटी, जो जीएफसी के दौरान केंद्रीय बैंकों को अधिक लाभ प्रदान करते थे, वित्तीय स्थितियों और आर्थिक गतिविधि पर इसके घातक प्रभाव को कम करने के लिए कोविड -19 के प्रकोप के बाद फिर से तैयार किए गए थे।

महामारी से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता जल्दी ही व्यापक आर्थिक और वित्तीय संकट में बदल गई। चूंकि दुनिया भर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग उपायों को लागू किया गया था, इसने जीवन और आजीविका के लिए अभूतपूर्व चुनौतियों को पेश करने वाली आर्थिक और वित्तीय बाजार गतिविधि को लगभग ध्वस्त कर दिया। एक महामारी² के रूप में कोविड -19 की घोषणा के बाद, वित्तीय बाजार की स्थिति सख्त हो गई, जबकि प्रमुख बाजार क्षेत्रों में अस्थिरता दुनिया भर में बढ़ गई। इस पृष्ठभूमि में, केंद्रीय बैंकों ने आर्थिक और वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा और प्रतिकूल मैक्रो-फाइनेंशियल फीडबैक लूप (बीआईएस, 2020) को रोकने के लिए दुनिया भर में कई पारंपरिक और अपरंपरागत उपाय किए।

यह लेख यूएमपीटी पर भारतीय अनुभव का आकलन प्रस्तुत करता है और इसे निम्नलिखित तरीके से आयोजित किया गया है। खंड II विभिन्न यूएमपीटी और उनके औचित्य का एक समान दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कोविड -19 के प्रकाश में अधिकारियों द्वारा यूएमपीटी की तैनाती की खंड III में चर्चा की गई है जबकि भारतीय संदर्भ में किए गए उपायों को खंड IV में प्रस्तुत किया गया है। विशिष्ट उपायों और उनकी प्रभावकारिता का एक अनुभवजन्य मूल्यांकन खंड V में किया जाता है जबकि खंड VI का समापन होता है।

II. अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण (यूएमपीटी) - एक प्राइमर

यूएमपीटी परंपरागत लिखतों से नीतिगत कार्यों की प्रकृति, उनके औचित्य, उन चैनलों के माध्यम से, जिनके माध्यम से वे काम करते हैं और संचालन के पैमाने के संबंध में काफी भिन्न होते

¹ 1990 के दशक के अंत में और जीएफसी से बहुत पहले, बैंक ऑफ जापान (बीओजे) यूएमपीटी को तैनात करने वाला पहला केंद्रीय बैंक था, जिसमें फॉरवर्ड गाइडेंस (कुरोदा, 2016) शामिल था।

² विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 11 मार्च, 2020 को घोषित किया गया।

हैं। मोटे तौर पर, यूएमपीटी में शामिल होती हैं (i) नकारात्मक ब्याज दर नीतियां; (ii) विस्तारित ऋण या टर्म फंडिंग सुविधाएं; (iii) परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम; और (iv) आगे का मार्गदर्शन। नकारात्मक ब्याज दरों³ के अलावा, ये उपकरण हमेशा अधिकांश केंद्रीय बैंकों में रहे हैं और वित्तीय बाजारों के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अतीत में इनका इस्तेमाल किया गया है। मौद्रिक नीति (बीआईएस, 2019) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख तंत्र के रूप में हाल के वर्षों में यूएमपीटी का उपयोग अपरंपरागत रहा है।

(i) **ऋणात्मक ब्याज दर नीतियां (एनआईआरपी):**

नकारात्मक ब्याज दरें वास्तव में अपरंपरागत हैं क्योंकि यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि जमाकर्ताओं को बैंकों के साथ धन रखने के लिए कर लगाया जाएगा। परम्परागत ज्ञान ने सुझाव दिया कि नीतिगत दरों के लिए 'ज़ीरो लोवर बाउंड' (जेडएलबी) था, जिसका अर्थ है कि ब्याज दरें कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकती हैं।⁴ जेडएलबी, तथापि, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूरो क्षेत्र में कुछ ईई केंद्रीय बैंकों के रूप में बाधा नहीं था, जीएफसी के तुरंत बाद एनआईआरपी को लागू करने का फैसला किया।⁵ वाणिज्यिक बैंकों ने, हालांकि, खुदरा जमा दरों पर ज़ीरो की फ्लोर निर्धारित करके नकारात्मक दरों को छोड़ दिया। बहरहाल, अभी भी जमा दरों पर कम बाध्यता होने की संभावना है जिसके तहत जमाकर्ता पैसा निकालेंगे और नकदी को रोकेंगे। परिणामस्वरूप, केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत ब्याज दरों के लिए एक 'प्रभावी निचली सीमा' (ईएलबी) पर चर्चा शुरू की। कुल मिलाकर, यह रणनीति प्रभावी थी क्योंकि दीर्घकालिक यील्ड नीचे की ओर समायोजित की गई और वांछित विस्तार प्रोत्साहन प्रदान किया गया। हालांकि इसके परिणामस्वरूप बैंक ब्याज मार्जिन

कम हो गया, लेकिन यह आज तक (बीआईएस, 2019) ईई में बैंकिंग स्थिरता के लिए एक बड़ी समस्या नहीं है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में, तथापि, यील्ड की तलाश में कैपिटल इनफ्लो की अधिकता के रूप में एनआईआरपी बड़ी सीमा पारीय स्पिलओवर पैदा कर सकता है जिसके कारण भारी मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता चुनौतियों सामने आ सकती हैं।

(ii) **विस्तारित ऋण या सावधि-निधि संचालन (ईएलओ / टीएफओ):**

जीएफसी के बाद और फिर से हाल ही में महामारी के बाद, कई केंद्रीय बैंकों ने रियायती दरों पर वित्तीय संस्थानों को कम लागत वाली दीर्घकालिक निधि प्रदान की जो व्यवसायों और हाउसहोल्ड्स को लाभ प्रदान करने में उन्हें सक्षम बनाती है। यद्यपि इस तरह की सुविधाओं ने निजी क्षेत्र को क्रेडिट प्रवाह का समर्थन किया, लेकिन वे भी कभी-कभी ऋण की गुणवत्ता से समझौता करके अक्षम ऋण आवंटन का परिणाम देते हैं और अत्यधिक लीवरेज को हतोत्साहित करने का कार्य करते हैं। फिर भी, इन उपायों ने अत्यधिक तनावग्रस्त बैंक फंडिंग बाजारों में चलनिधि के दबाव को कम कर दिया और मौद्रिक प्रसारण चैनलों (लोव, 2019) को बहाल करने में मदद की।

(iii) **एसेट खरीद कार्यक्रम (एपीपी):**

एपीपी में केंद्रीय बैंकों द्वारा संपत्ति (मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड) की एकमुश्त खरीद शामिल है और लंबे समय से उनके चलनिधि प्रबंधन कार्यों की एक विशेषता है; हालांकि, इनका उपयोग जीएफसी के बाद और विशेष रूप से कोविड -19 के जवाब में अधिक व्यापक रूप से किया गया है, जिससे केंद्रीय बैंक बैलेन्स शीट का बड़ा विस्तार हो रहा है। इसके अलावा, कुछ केंद्रीय बैंकों ने जोखिम मुक्त प्रतिभूतियों से परे संपत्ति खरीद के स्पेक्ट्रम को व्यापक बनाया है। आमतौर पर, एक केंद्रीय बैंक या तो (i) स्वयं द्वारा खरेदी जाने वाली परिसंपत्ति की मात्रा के लिए एक लक्ष्य (किसी भी कीमत पर); या (ii) परिसंपत्ति मूल्य के लिए एक लक्ष्य (किसी भी मात्रा में खरीदना जो लक्षित मूल्य प्राप्त करेगा) को निर्धारित कर सकता है। जबकि एक क्वान्टिटी लक्ष्य को आमतौर पर क्वांटिटेटिव ईजिंग (क्यूई) के रूप में संदर्भित किया

³ हालांकि, नकारात्मक ब्याज दरें अभी तक नहीं हैं क्योंकि स्विस् नेशनल बैंक (एसएनबी) ने 1970 के दशक की शुरुआत में (आरबीए, 2020) गैर-निवासियों के स्विस् फ्रैंक खातों पर (-) 2 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया था।

⁴ आर्थिक एजेंट केवल अपनी बचत को निष्क्रिय नकदी के रूप में भौतिक रूप से रखने का विकल्प चुनते हैं यदि उन्हें उनकी जमा होल्डिंग्स पर दंडित किया जाता है।

⁵ इनमें से कुछ देशों को एक अपस्फीति मुद्रा की सराहना करने की आवश्यकता से प्रेरित किया गया था (लोव, 2019)।

जाता है, एक मूल्य लक्ष्य को यील्ड कर्व कंट्रोल (वाईसीसी) के रूप में जाना जाता है। क्यूई के तहत, बड़े पैमाने पर खरीद यील्ड्स को कम करती है जिससे लंबी अवधि की दरें कम होती हैं और वित्तीय स्थिति आसान होती है। वाईसीसी के मामले में, बांड बाजार द्वारा किसी भी राशि (बीआईएस, 2019) को खरीदने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को आंतरिक करने के बाद लक्ष्य मूल्य बाजार मूल्य बन जाता है। जबकि यूएस फेडरल रिजर्व (यूएस फेड) ने जीएफसी के बाद बड़े पैमाने पर क्यूई का काम किया, बीओजे ने 2016 में 10 साल की जापानी सरकार बांड (जेजीबी) पर पैग की यील्ड्स को शून्य प्रतिशत के आसपास लगातार डीफ्लेशन जोखिम से निपटने के लिए पेश किया।⁶ मार्च 2020 में, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (आरबीए) ने वाईसीसी को 3-वर्षीय बॉन्ड के साथ लगभग 0.25 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ पेश किया, जिसे बाद में नवंबर में घटाकर 0.1 प्रतिशत कर दिया गया।

ऑपरेशन ट्विस्ट (ओटी) 2012 में फेड द्वारा उपयोग किया गया क्यूई का एक प्रकार है।⁷ ऑपरेशन में "ट्विस्ट" तब होता है जब फेड लंबी अवधि के ट्रेजरी नोट खरीदने के लिए अल्पकालिक ट्रेजरी बिल की बिक्री का उपयोग करता है, जो लंबे समय तक कम होता है- इस प्रकार ब्याज दरें घटने से प्रीमियम (बर्नानके, 2020) की अवधि कम हो जाती है। बदले में कम दीर्घकालिक दरें, व्यवसायों को आर्थिक गतिविधि को उत्तेजित करने की अनुमति देती हैं।

परिसंपत्ति खरीद का सटीक लक्ष्य पूरे देश में भिन्न है, हालांकि जोखिम मुक्त परिसंपत्तियों पर ब्याज दरों को कम करना एक सामान्य विशेषता रही है। एपीपी केंद्रीय बैंक के आगे के मार्गदर्शन को भी सुदृढ़ करते हैं कि नीतिगत ब्याज दरें लंबी अवधि के लिए कम रहेंगी, जो

प्रतिफल पर नीचे के दबाव को बनाए रखती है (लोव, 2019)। एपीपी भी देश-विशिष्ट थे: जबकि यूएस फेड ने बंधक बाजारों का समर्थन करने के लिए सरकार समर्थित एजेंसी प्रतिभूतियों को खरीदा, बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) ने जीएफसी के दौरान कॉर्पोरेट क्रेडिट बाजारों में तनाव को कम करने के लिए वाणिज्यिक पत्र (सीपी) खरीदे।

(iv) **फॉरवर्ड गाइडेंस (एफजी):** एफजी - दोनों अंतर्निहित और स्पष्ट - मौद्रिक नीति के 'रुख' पर केंद्रीय बैंक संचार से संबंधित हैं, जो कि आगे चलकर, नीतिगत ब्याज दर के भविष्य का मार्ग है। आगे का मार्गदर्शन हो सकता है (ए) समय-आधारित; या (बी) राज्य आधारित। 'समय-आधारित मार्गदर्शन' के तहत केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के रुख के लिए एक विशिष्ट समय तक काम करता है। इसके विपरीत, 'राज्य-आधारित मार्गदर्शन' एक रुख से संबंधित है जब तक कि आर्थिक परिस्थितियों का स्पष्ट सेट पूरा नहीं किया जाता है। आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में अनिश्चितता के दौर में, एफजी ने केंद्रीय बैंकों के इरादे को स्पष्ट करने में एक अपरिहार्य भूमिका निभाई, जबकि वे मूल्य स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध थे। एफजी ने नीति निर्माताओं के वांछित परिणाम प्राप्त करने में अन्य यूएमपीटी की भी सहायता की।

जीएफसी और कोविड -19 के दौरान, केंद्रीय बैंक एफजी को प्रदान करने में सक्रिय थे (i) कम ब्याज दरों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं; और (ii) अनिश्चित समय में अपनी रणनीति का संचार करते हैं। इस दृष्टिकोण से एफजी आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण के बारे में अनिश्चितता को कम करने में काफी प्रभावी था।⁸ असाधारण परिस्थितियों में एफजी के साथ एक महत्वपूर्ण चुनौती संचार की स्पष्टता, अनुवर्ती कार्रवाइयों की विश्वसनीयता और बदलती वित्तीय स्थितियों (बीआईएस, 2019) के लिए भविष्य की नीति की प्रतिक्रिया के लचीलेपन के बीच ट्रेड-ऑफ्स का संतुलन है।

⁶ इसे मात्रात्मक और गुणात्मक मौद्रिक सहजता (क्यूक्यूई) के रूप में वर्गीकृत किया गया है - एक नीति जिसके द्वारा बीओजे निजी संस्थाओं की अपेक्षाओं को सक्रिय रूप से प्रभावित करने की दृष्टि से लंबे समय तक शेष परिपक्वता वाले बांड सहित जेजीबी की भारी मात्रा में खरीद करते समय मूल्य स्थिरता के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता का संकेत देता है। गठन (कुरोदा, 2016)।

⁷ कैनेडी प्रशासन के दौरान, मूल ऑपरेशन ट्विस्ट फरवरी 1961 में फेड के अध्यक्ष विलियम मैककेनी मार्टिन द्वारा शुरू किया गया था।

⁸ एक उल्लेखनीय अपवाद 203 का 'टेंपर टैंट्रम' था, जिसमें एसेट खरीद कार्यक्रम की टैपिंग पर फेड द्वारा एफजी ने कुछ ईएमई पर महत्वपूर्ण स्पिलओवर प्रभाव के साथ वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता को ट्रिगर किया था।

उपर्युक्त यूएमपीटी के अलावा, कई केंद्रीय बैंकों ने जीएफसी और कोविड -19 के बाद वित्तीय बाजार तनाव से निपटने के लिए अपने बाजार संचालन में महत्वपूर्ण समायोजन किया। इन समायोजनों में शामिल हैं (i) अभूतपूर्व रूप से बड़ी चलनिधि इंजेक्ट करना; (ii) समपार्श्विकों की सीमा का विस्तार; और (iii) 'पात्र काउंटरपार्टीज' की सीमा को बढ़ाना। इन परिशोधनों ने मार्केट सीजर और इल्लीक्विडिटी को संबोधित करने की मांग की क्योंकि वित्तीय संस्थाएं तेजी से अपनी चलनिधि पहुंच के बारे में अनिश्चित हो गईं, जो एक गंभीर 'क्रेडिट संकट' को दूर कर सकती हैं और आर्थिक संकुचन को गति प्रदान कर सकती हैं। निर्बाध चलनिधि पहुंच के बारे में वित्तीय संस्थानों को आश्वासन देकर, केंद्रीय बैंक बाजारों के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करने में सक्षम थे।

यूएमपीटी के वृहद आर्थिक और वित्तीय बाजार प्रभाव पर अनुभवजन्य साक्ष्य उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जनवरी 2008 - जून 2011 की अवधि के लिए आठ एई⁹ मासिक आंकड़ों के आधार पर, जेडएलबी में केंद्रीय बैंक बैलेंस शीट में एक बहिर्जात वृद्धि अस्थायी रूप से आर्थिक गतिविधि और उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि करने के लिए पाई गई थी, हालांकि मूल्य प्रभाव कमजोर और सतत नहीं था। व्यक्तिगत देश-विशिष्ट परिणामों ने सुझाव दिया कि देशों में किए गए उपायों की व्यापकता के बावजूद, उनके व्यापक आर्थिक प्रभाव (गाम्बकोर्टा एट अल, 2014) में कोई बड़ा अंतर नहीं था। 21 केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए 24 कोविड -19 क्यूई घोषणाओं के एक घटना-अध्ययन (ईएस) विश्लेषण में पाया गया कि औसत विकसित बाजार क्यूई की घोषणा का उनके स्थानीय 10-वर्षीय सरकारी यील्ड पर -0.14 प्रतिशत का सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जबकि ईएमई में ऐसी घोषणाओं का प्रभाव

-0.28 प्रतिशत पर काफी अधिक था। कुल मिलाकर, औसतन 1 दिन का प्रभाव -0.23 प्रतिशत (हार्टले और रेबुकी, 2020) था।

III. कोविड-19 के दौरान यूएमपीटी: क्रॉस-कट्टी प्रैक्टिसेज

वित्तीय बाजारों में सामान्य स्थिति को बहाल करने और आर्थिक गतिविधि को कम करने की तत्काल आवश्यकता से प्रेरित होकर, केंद्रीय बैंकों ने अपने जीएफसी अनुभव के आधार पर कोविड -19 के बाद विभिन्न यूएमपी उपायों को तेजी से डिजाइन और कार्यान्वित किया है। ईएमबी में ईएलबी द्वारा विवश होने पर, यूएमपीटी, कोविड -19 संकट के प्रभाव को कम करने के लिए मौद्रिक नीति स्थान बनाने में मदद करते हैं और रिकवरी (हॉफमैन और कंबर, 2020) का समर्थन करते हैं।

- (i) नकारात्मक ब्याज दर नीति: कई एई केंद्रीय बैंक जीएफसी के दौरान अपनाई गई नकारात्मक ब्याज दरों के साथ जारी रहे। स्विट्स नेशनल बैंक (एसएनबी) ने अपनी नीति दर -0.75 प्रतिशत पर बनाए रखी, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) की स्थायी जमा सुविधा दर वर्तमान में -0.50 प्रतिशत है। हालांकि बीओई और यूएस फेड ने नकारात्मक ब्याज दरों को पेश नहीं किया है, लेकिन पूर्व में इसकी मुख्य दर 0.1 प्रतिशत के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि बाद में मार्च 2020 में इसकी बेंचमार्क ब्याज दर को 0-0.25 प्रतिशत पर लाकर एक आपातकालीन कदम उठाया। स्वीडिश रिक्सबैंक ने भी रातोंरात ऋण के लिए अपनी ऋण दर को चरणों में घटाकर 0.1 प्रतिशत कर दिया।
- (ii) नए उपकरणों के माध्यम से चलनिधि समर्थन: अधिकांश केंद्रीय बैंकों ने आरक्षित आवश्यकताओं को कम कर दिया है, संपार्श्विक मानदंडों में ढील दी है और रेपो परिचालन के पैमाने और कार्यकाल में वृद्धि की है। बीओई (ए) ने लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को ऋण देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ एक नई टर्म फंडिंग योजना पेश की; और (बी) मौजूदा स्टर्लिंग चलनिधि सुविधाओं के पूरक के लिए एक आकस्मिक शब्द रेपो सुविधा को सक्रिय किया। फेड ने रातोंरात / रेपो परिचालन का विस्तार किया और क्रेडिट के प्रवाह

⁹ ये अर्थव्यवस्थाएँ जैसे कि कनाडा, यूरो क्षेत्र, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूके और अमेरिका के बीच तालमेल बिजनेस साइकल, वित्तीय बाजार की गतिशीलता और मौद्रिक नीति के उनके आचरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समान कारक था।

का समर्थन करने के लिए कई नई सुविधाओं की शुरुआत की। ये सुविधाएं हैं: (ए) कंपनियों और नगरपालिका जारीकर्ताओं के लिए वाणिज्यिक पेपर फंडिंग सुविधा (सीपीएफएफ); (बी) प्राथमिक डीलरों के वित्तपोषण के लिए प्राथमिक डीलर क्रेडिट सुविधा (पीडीसीएफ); (सी) मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड चलनिधि सुविधा (एमएमएलएफ) परिसंपत्ति खरीद के लिए डिपॉजिटरी संस्थानों को ऋण प्रदान करने के लिए; (डी) कंपनियों से नए बांड और ऋण खरीदने के लिए प्राथमिक बाजार कॉर्पोरेट क्रेडिट सुविधा (पीएमसीसीएफ); (ई) बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए चलनिधि प्रदान करने के लिए सेकंडरी बाजार कॉर्पोरेट क्रेडिट सुविधा (एसएमसीसीएफ); (एफ) परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूति ऋण सुविधा (टीएबीएसएलएफ); (जी) वित्तीय संस्थानों के लिए वेतन संरक्षण कार्यक्रम चलनिधि सुविधा (पीपीपीएलएफ) जो श्रमिकों को उनके पेरोल पर रखने के लिए छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करती है; (एच) छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए नए या विस्तारित ऋण खरीदने के लिए मेन स्ट्रीट ऋण कार्यक्रम (एमएसएलपी); और (i) राज्य और पात्र स्थानीय सरकारों से सीधे अल्पकालिक प्रतिभूतियों की खरीद के लिए नगरपालिका चलनिधि सुविधा (एमएलएफ)।

ईसीबी ने निम्नलिखित की अतिरिक्त नीलामियां कीं (ए) पूर्ण-आबंटन, जमा सुविधा दर पर निश्चित दर अस्थायी चलनिधि सुविधा की (बी) मौजूदा लक्षित लंबी अवधि के पुनर्वित्त संचालन (टीएलटीआरओ-III) पर ब्याज दरों के साथ औसत जमा सुविधा दर से 50 बीपीएस नीचे भी आयोजित कीं। अभी हाल ही में, ईसीबी ने गैर-लक्षित महामारी आपातकालीन दीर्घावधि पुनर्वित्त संचालन (पीईएलटीआरओ) की एक श्रृंखला शुरू की। जापान में, विशेष धन-आपूर्ति संचालन ने योग्य समकक्षों और निजी ऋण के संपार्श्विक की सीमा को बढ़ाया है। मई 2020 में बीओजे ने एसएमई के वित्तपोषण के समर्थन के लिए एक नया फंड-प्रोविजनिंग उपाय पेश किया।

ईएमई के बीच, बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने दैनिक नीलामी की शुरुआत करते हुए रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशंस की अधिकतम अवधि (12 महीने तक) बढ़ा दी। दक्षिण अफ्रीका के रिजर्व बैंक (आरबीएसए) ने कॉर्पोरेट बॉन्ड को संपार्श्विक के रूप में स्वीकार करके वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान किया। बैंक ऑफ थाईलैंड (बीओटी) द्वारा किए गए उपायों में एसएमई को ऋण देने के लिए वित्तीय संस्थानों को सस्ता ऋण और बैंकों के माध्यम से म्यूचुअल फंडों को चलनिधि प्रदान करने की एक विशेष सुविधा शामिल है।

- (iii) संपत्ति खरीद: केंद्रीय बैंकों ने महामारी से प्रेरित उच्च अनिश्चितता से उत्पन्न होने वाले बैंक भंडार की अतिरिक्त मांग को पूरा करने और लंबी अवधि के ब्याज दरों को कम करने के लिए अपने एपीपी का विस्तार किया। बीओई ने यूके के सरकारी बॉन्ड और गैर-वित्तीय निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड की £ 300 बिलियन तक हिस्सेदारी का विस्तार किया, जबकि यूएस फेड ने ट्रेजरी और एजेंसी प्रतिभूतियों की किसी भी राशि की खरीद के लिए प्रतिबद्ध किया। मार्च में, ईसीबी ने महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम (पीईपीपी) की शुरुआत की, जिसे चरणों में € 1.85 ट्रिलियन तक बढ़ा दिया गया और इसकी अवधि मार्च 2022 के अंत तक बढ़ा दी गई। मार्च में बीओजे ने सीपी और कॉर्पोरेट बॉन्ड की लक्षित खरीद के साथ जेजीबी खरीद के आकार और आवृत्ति को बढ़ा दिया। बाद में, बीओजे ने निर्णय लिया कि जेजीबी की खरीद किसी भी सीमा के बिना की जाए। कई ईएमई केंद्रीय बैंकों उदाहरणार्थ इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस और थाईलैंड ने बांड खरीद कार्यक्रम भी शुरू किया है, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने सरकार से सीधे बांड खरीदकर ऋण का मुद्रीकरण किया है (अनुबंध तालिका 1)। मेक्सिको और ब्राजील ने ऑपरेशन ट्विस्ट किया।
- (iv) फॉरवर्ड गाइडेंस: फेड ने संकेत दिया कि जब तक अर्थव्यवस्था हाल की घटनाओं का सामना नहीं करती है और अपने अधिकतम रोजगार और मूल्य स्थिरता

लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर हैं, तब तक दरें कम रहेंगी। ईसीबी को उम्मीद थी कि दरें अपने वर्तमान या निचले स्तर पर तब तक बनी रहेंगी जब तक कि मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अपने प्रक्षेपण क्षितिज के करीब, लेकिन 2 प्रतिशत से कम नहीं हो जाता।

इसके अलावा, कई केंद्रीय बैंकों ने विनियामक और पर्यवेक्षी उपायों का सहारा लिया है, जिसमें (ए) जवाबी चक्रीय पूंजीगत बफ़र में कमी शामिल है; (बी) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) में छूट; (सी) लाभांश और बायबैंक का निलंबन; (डी) ऋण पुनर्गठन और हानि प्रावधान में छूट; (ई) विवेकपूर्ण मानदंडों में ढील और (एफ) रिपोर्टिंग और अनुपालन में विनियामक बाध्यता की कमी। पर्यवेक्षक बैंकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं (1) अपने ऋणों की सेवा के लिए संघर्ष करने वालों के लिए विवेकपूर्ण ऋण शर्तों को प्रोत्साहित कर रहे हैं; (2) मौजूदा पूंजी और चलनिधि बफ़र का उपयोग करने के लिए; और (3) अपने नियामक और लेखांकन ढांचे का उपयोग लचीले ढंग से नुकसान (बीआईएस, 2020) को अवशोषित करने के लिए।

उपरोक्त उपायों को दर्शाते हुए, फंडिंग बाजार, हालांकि अस्थिरता के रुक-रुक कर मुकाबलों का अनुभव कर रहे हैं, जबकि निवेशक भावना में सुधार हुआ है और वित्तीय बाजार प्रसार चलनिधि की स्थिति में सुधार के साथ संकुचित हो गया है। बाजार की प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि ये उपाय बॉन्ड मार्केट एक्टिविटी में सुधार, यील्ड को कम करने और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सफल रहे हैं (बीआईएस, 2020)।

IV. यूएमपीटी - भारतीय अनुभव ¹⁰

रिज़र्व बैंक ने COVID-19 के मद्देनजर कई पारंपरिक और अपरंपरागत उपाय किए। जबकि पारंपरिक उपायों में पॉलिसी रेपो दर में 115 बीपीएस और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 100 बीपीएस की कमी शामिल है, अपरंपरागत उपायों में

¹⁰ इन उपायों को कई विनियामक / पर्यवेक्षी पहल और विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों द्वारा पूरक किया गया था। सभी कोविड -19 संबंधित उपायों के विवरण के लिए, < https://www.rbi.org.in/scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=3894 > देखें।

शामिल हैं (i) पुनर्वित्त के माध्यम से तरलता समर्थन सहित विस्तारित उधार या टर्म-फंडिंग संचालन; (ii) ऑपरेशन ट्विस्ट (ओटी) सहित परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम; और (iii) आगे का मार्गदर्शन, जिसकी विस्तृत रूपरेखा नीचे चर्चा की गई है।

(i) चलनिधि सहायता संचालन

(ए) विस्तारित उधार/सावधि-वित्त पोषण: जीएफसी के बाद ईसीबी के समान, रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2020 में मौद्रिक नीति संचरण की सुविधा और क्रेडिट ऑफ़टेक का समर्थन करने के लिए दीर्घकालिक रेपो संचालन (एलटीआरओ) की शुरुआत की। इस योजना के तहत, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को पूर्ववर्ती नीति रेपो दर (5.15 प्रतिशत) पर दीर्घकालिक तरलता प्रदान की - जो कि मौजूदा बाजार दरों के साथ-साथ बैंकों की अपनी जमा लागत से कम दर है - ताकि उनकी निधियों की लागत कम हो सके। फरवरी-मार्च 2020 के दौरान, पांच एलटीआरओ नीलामियां (प्रत्येक 1 वर्ष की अवधि के साथ ₹25,000 करोड़ की राशि और 3-वर्ष की अवधि में से चार) आयोजित की गईं, जिससे सिस्टम की तरलता में ₹1,25,117 करोड़ की वृद्धि हुई। हालांकि, सितंबर 2020 में, बैंकों ने परिपक्वता से पहले पूर्व भुगतान के विकल्प का प्रयोग करके अपनी निधि की लागत को कम करने के लिए ₹1,23,572 करोड़ (प्राप्त निधि का लगभग 98.8 प्रतिशत) चुकाया। घोषणा के दिनों के आसपास एक घटना अध्ययन (ईएस) विश्लेषण ने संकेत दिया कि एलटीआरओ का कुछ परिपक्वता (दास एट अल., 2020; आरबीआई, 2020 ए) के जी-सेक प्रतिफल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

कोविड -19 के प्रकोप ने वित्तीय बाजारों में बिकवाली के दबाव को बढ़ावा दिया क्योंकि बड़े वैश्विक स्पिलओवर ने सुरक्षा के लिए उड़ान शुरू की। नतीजतन, कॉरपोरेट बॉन्ड, सीपी और डिबेंचर पर जोखिम प्रीमियम में तेज उछाल के कारण वित्तीय स्थिति सख्त हो गई, जिससे व्यापारिक गतिविधि

¹¹ रेपो दर को दो चरणों में 115 बीपीएस से कम किया गया और सितंबर 2020 में यह 4.0 प्रतिशत पर पहुंच गई।

समाप्त हो गई जिसके परिणामस्वरूप बाजार में अनकदी की स्थिति आ गई। तदनुसार, चलनिधि तनाव का सामना कर रहे विशिष्ट क्षेत्रों और संस्थाओं को चलनिधि प्रदान करने के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) शुरू किए गए थे। मार्च-अप्रैल 2020 के दौरान चार टीएलटीआरओ नीलामियां (प्रत्येक तीन साल की अवधि में ₹ 25,000 करोड़) आयोजित की गईं, जिसमें निवेश ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड, सीपी और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में तैनाती के लिए बैंकों को ₹1,00,050 करोड़ प्रदान किए गए। बैंकों को प्राथमिक बाजार से पात्र लिखतों की अपनी वृद्धिशील होल्डिंग का पचास प्रतिशत तक हासिल करना था और शेष द्वितीयक बाजार से हासिल करना था, जिसमें म्यूचुअल फंड (एमएफ) और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) शामिल थीं।

चूंकि टीएलटीआरओ फंड की तैनाती बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं और बड़े कॉरपोरेट्स के प्राइमरी ईसुएन्सेज तक ही सीमित थी, टीएलटीआरओ 2.0 को एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) सहित छोटे और मध्यम आकार के कॉरपोरेट्स को राहत प्रदान करने के लिए पेश किया गया था। बैंकों को निवेश ग्रेड बांड, सीपी और एनबीएफसी के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश करना आवश्यक था, जिसमें कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे और मध्यम आकार के एनबीएफसी और एमएफआई को जाता था। हालांकि, मांग कम थी ₹12,850 करोड़ अतिरिक्त चलनिधि के लिए बाजार की मांग की कमी को दर्शाता है। नवंबर 2020 में, बैंकों ने एलटीआरओ के पूर्व भुगतान के समान एक योजना के तहत टीएलटीआरओ फंड (प्राप्त राशि का 33.1 प्रतिशत) के 37,348 करोड़ रुपये वापस कर दिए।

जैसा कि चलनिधि के उपायों में वृद्धि पर कई गुना प्रभाव वाले विशिष्ट क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, 'ऑन टैप टीएलटीआरओ' को अक्टूबर 2020 में ₹ 1,00,000 करोड़ तक की कुल राशि के लिए लाया गया था, जिसमें एक फ्लोटिंग दर

पॉलिसी रेपो दर से तीन साल तक के कार्यकाल के लिए लिंक थी। प्राप्त निधि को कॉरपोरेट बॉन्ड, सीपी और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में पांच विशिष्ट क्षेत्रों में संस्थाओं द्वारा जारी किया जाना है; इसके अतिरिक्त, इसका उपयोग इन क्षेत्रों में बैंक ऋण और अग्रिमों को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बाद, कामथ कमेटी (2020) द्वारा पहचाने गए 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों को दिसंबर में इस योजना के दायरे में लाया गया था, जिसे फरवरी 2021 में एनबीएफसी को बैंक ऋण देने के लिए विस्तारित किया गया था।

(बी) चलनिधि समर्थन: सख्त वित्तीय स्थितियों को देखते हुए, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) को संसाधन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी चलनिधि के तनाव को कम करने और क्षेत्रीय ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ¹² को कुल ₹ 60,000 करोड़ की राशि के लिए पॉलिसी रेपो दर पर विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं। परस्पर आवंटन में शामिल थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों और एमएफआई के पुनर्वित्तीयन के लिए नाबार्ड को परस्पर आवंटन में ₹30,000 करोड़; ऑन-लेंडिंग/रीफाइनेंसिंग के लिए सिडबी को ₹15,000 करोड़; और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को समर्थन देने के लिए एनएचबी को ₹15,000 करोड़। विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूएस डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठाने के लिए 90 दिनों की अवधि (एक वर्ष तक अधिकतम रोलओवर के साथ) के लिए ₹15,000 करोड़ की क्रेडिट लाइन एक्विजम बैंक को दी गई थी। इस प्रकार, एआईएफआई को कुल पुनर्वित्त सहायता ₹75,000 करोड़ थी।

¹² चूंकि क्षेत्र-विशिष्ट पुनर्वित्त सुविधाएं बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित दरों पर सुनिश्चित चलनिधि तक पहुंच प्रदान करती हैं, इसलिए वे मौद्रिक संचरण प्रक्रिया को बाधित करते हैं। नतीजतन, मौद्रिक नीति ढांचे (आरबीआई, 2014) को संशोधित और मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 2015 में निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) वापस ले लिया गया था।

म्यूचुअल फंड (एमएफ) पर ऋण मोचन दबाव को कम करने के लिए कुछ ऋण एमएफ को बंद करने और उनके संभावित संक्रामक प्रभावों को कम करने के लिए, अप्रैल 2020 में (50,000 करोड़ के म्यूचुअल फंड (एसएलएफ-एमएफ) के लिए एक विशेष चलनिधि सुविधा पेश की गई थी, हालांकि इसका उपयोग ₹2,430 करोड़ की अल्प राशि थी। रिजर्व बैंक ने पहले 2008 में जीएफसी के दौरान और बाद में 2013 में टेपर टैंट्रम के बाद एमएफ के लिए एक समान सुविधा का विस्तार किया था।

- (ii) **एसेट खरीद कार्यक्रम (एपीपी):** कई केंद्रीय बैंकों के विपरीत, रिजर्व बैंक की खरीद केवल द्वितीयक बाजार तक सीमित है और पूरी तरह से सरकारी प्रतिभूतियों में है। अक्टूबर 2020 में एक नवाचार को राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है - आमतौर पर राज्य विकास ऋण (एसडीएल) के रूप में जाना जाता है - 2020-21 के लिए एक विशेष मामले के रूप में। नेट ओएमओ की खरीद 2020-21 (26 फरवरी तक) के दौरान ₹3,04,754 करोड़ (एसडीएल सहित ₹ 30,000 करोड़) की राशि है।

ओटी पर फेड के अनुभव की पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक ने विशेष ओएमओ (ओटी) की घोषणा की, जिसमें भारत में कोविड -19 का प्रकोप होने से पहले, दिसंबर 2019 में दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की दीर्घकालिक खरीद और बिक्री शामिल है। इन ऑपरेशनों का उद्देश्य प्रीमियम शब्द को संपीडित करना और उपज वक्र की स्थिरता को कम करना था। दीर्घकालिक जोखिम-मुक्त (जी-सेक) दरों में मॉडरेशन, बदले में, अन्य वित्तीय बाजार साधनों में परिलक्षित होता है जो जी-सेक दर की कीमत होती है, जिससे मौद्रिक संचरण में सुधार होता है। फरवरी 2021 के अंत तक, रिजर्व बैंक ने ₹ 10,000 करोड़ प्रत्येक (अनुलग्नक - तालिका 2) के 20 ऐसे परिचालन संचालन किए।¹³ ओटी की सफलता ने एकमुश्त ओएमओ के

माध्यम से चलनिधि इंजेक्शन के साथ संयुक्त यील्ड को कम किया और सरकार के लिए 2020-21¹⁴ में उधार लेने की लागत कम कर दी। आगे चलकर, ओटी के साथ संयोजन में आउटराइट ओएमओ रिजर्व बैंक के पास एक शक्तिशाली उपकरण बनकर रहेगा।

- (iii) **फॉरवर्ड गाइडेंस (एफजी):** महामारी के बाद, एफजी ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के समायोजन रुख का समर्थन करने के लिए रिजर्व बैंक की संचार रणनीति में प्रमुखता प्राप्त की। एमपीसी का यह कथन कि नीतिगत रुख तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि विकास के सुधार के लिए स्पष्ट समय-आकस्मिक और राज्य-आकस्मिक एफजी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, एमपीसी ने अक्टूबर 2020 में नोट किया "... जब तक आवश्यक हो, तब तक कम से कम चालू वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्तीय वर्ष में - एक स्थायी आधार पर वृद्धि को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड -19 के प्रभाव को कम करने के लिए, आगे यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे" (आरबीआई, 2020 बी)। इसके अलावा, गवर्नर ने वित्तीय बाजारों को आश्वासन दिया कि रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के रुख के साथ सहज चलनिधि की स्थिति बनाए रखेगा और वित्तीय बाजार स्थिरता और उपज वक्र के क्रमिक विकास पर जोर देते हुए सहकारी समाधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला (आरबीआई, 2020 सी)। बहाली को बरकरार रखने के लिए अनुकूल वित्तीय स्थितियों को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता ने अनकदी के डर को समाप्त कर दिया और बाजार की भावना को सहारा दिया। रुख के समर्थन में रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन परिचालन ने बाजार सहभागियों को समकालिक और सहकारी रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए आश्चस्त किया, जो मौद्रिक नीति संचार में एफजी की प्रभावशीलता का प्रमाण है। इस प्रकार एफजी ने कोविड के बाद के वातावरण में अन्य यूएमपीटी उपायों की सराहना की। इस प्रकार, एफजी ने कोविड के बाद के वातावरण में अन्य यूएमपीटी उपायों को पूरा किया।

¹³ इन परिचालनों को चलनिधि तटस्थ माना जाता है; फिर भी, चार परिचालनों के परिणामस्वरूप ₹11,824 करोड़ की तरलता का शुद्ध अंतःक्षेपण हुआ और एक ऑपरेशन के परिणामस्वरूप ₹2,868 करोड़ का शुद्ध अवशोषण हुआ, जिससे प्रणालीगत चलनिधि (निवल) में ₹8,956 करोड़ की वृद्धि हुई।

¹⁴ अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि ओटी की घोषणा के दिनों के आसपास कुछ परिपक्वताओं की जी-सेकेंड यील्ड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा (दास एट अल, 2020)।

यूएमपीटी के साथ-साथ पॉलिसी दर में कटौती के कारण, यील्ड में गिरावट आई और कॉर्पोरेट बॉन्ड परिपक्वता स्पेक्ट्रम और रेटिंग श्रेणियों (अनुबंध - तालिका 3) में काफी हद तक फैल गया। वास्तव में, कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड पूर्व-कोविड स्तरों तक पहुंच गए हैं। कम दरों से प्रेरित, कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने की दर 2019-20 (20.2 प्रतिशत की वृद्धि) की इसी अवधि के दौरान ₹ 5.3 लाख करोड़ के साथ तुलना करते हुए 2020-21 (अप्रैल-जनवरी) दर ₹ 6.4 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। निम्नतम निवेश श्रेणी (बीबीबी-) में जारीकर्ताओं के साथ - जिनके पास इसके बाद की कोई बाजार पहुंच नहीं थी - वे संसाधन जुटाने में सक्षम थे (अनुबंध - तालिका 4)।

V. अनुभवजन्य आकलन

यूएमपीटी की प्रभावकारिता पर अनुभवजन्य आकलन दो भागों में किया जाता है। सबसे पहले, एलटीआरओ और टीएलटीआरओ नीलामियों के धन और बांड बाजारों के दैनिक डेटा पर प्रभाव का अनुमान है। दूसरी एक्सरसाइज में जी-सेक मार्केट में टर्म प्रीमियम पर ऑपरेशन ट्विस्ट की घोषणा के प्रभाव का मूल्यांकन शामिल है।

(i) मनी और बॉन्ड बाजार पर नीलामी प्रभाव

रिजर्व बैंक द्वारा प्रणाली-स्तर की चलनिधि (एलटीआरओ) और लक्षित चलनिधि (टीएलटीआरओ) को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय, धन की आवश्यकता की बदलती तीव्रता के संदर्भ में अंतर प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जैसा कि उनके बिड-कवर अनुपात (अनुबंध - चार्ट 1) में परिलक्षित होता है। जबकि पहले और तीसरे एलटीआरओ की नीलामी ने बहुत अधिक रुचि पैदा की, पांचवें एलटीआरओ और टीएलटीआरओ (2.0) की नीलामी के प्रति प्रतिक्रिया लचर थी।

एलटीआरओ और टीएलटीआरओ की मनी और बांड बाजारों पर तात्कालिक प्रभाव की जांच हाल के साहित्य (हार्टले और रेबुकी, 2020) से ईएस ढांचे में की गई है। 3 महीने के सीपी की ब्याज दरों पर दैनिक डेटा, 10 साल की सरकारी प्रतिभूतियों पर यील्ड और 10 साल के एएए कॉर्पोरेट बॉन्ड की अवधि दिसंबर 2019-सितंबर 2020 तक होती है, जो अनुमान के लिए इस्तेमाल की जाती है, पहले अंतर में स्थिर होती है (अनुलग्नक - तालिका 5)।

विशेष रूप से, 3-महीने की सीपी दरों और 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड (जी-सेकंड के साथ-साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड, अलग-अलग) में दैनिक परिवर्तन एलटीआरओ और टीएलटीआरओ नीलामी की तारीखों (डमी के रूप में) अन्य प्रमुख चर के लिए नियंत्रण के साथ पुनः प्राप्त होते हैं जो दैनिक दरों / यील्ड, अर्थात् पॉलिसी रेपो रेट में बदलाव; और अमेरिकी आर्थिक नीति अनिश्चितता¹⁵ (अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों और अमेरिकी यील्ड मूवमेंट्स के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में) में परिवर्तन, निम्नलिखित विशेषताओं के साथ प्रभावित कर सकते हैं।

$$\Delta CP_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i * \Delta CP_{t-i} + \sum_{i=1}^n \Delta Policy^i + \sum_{i=1}^n \gamma_i * \Delta US_Index^i + \sum_{i=1}^5 \delta_i * LTRO^i + \sum_{i=1}^5 \psi_i * TLTRO^i + \varepsilon_t \quad \dots(i)$$

$$\Delta Gsec_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i * \Delta Gsec_{t-i} + \sum_{i=1}^n \Delta Policy^i + \sum_{i=1}^n \gamma_i * \Delta US_Index^i + \sum_{i=1}^5 \delta_i * LTRO^i + \sum_{i=1}^5 \psi_i * TLTRO^i + \varepsilon_t \quad \dots(ii)$$

$$\Delta Corpbt_t = \alpha_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i * \Delta Corpbt_{t-i} + \sum_{i=1}^n \Delta Policy^i + \sum_{i=1}^n \gamma_i * \Delta US_Index^i + \sum_{i=1}^5 \delta_i * LTRO^i + \sum_{i=1}^5 \psi_i * TLTRO^i + \varepsilon_t \quad \dots(iii)$$

अनुमानों से पता चलता है कि एलटीआरओ और टीएलटीआरओ नीलामियों का संचयी प्रभाव बांड बाजारों की तुलना में मुद्रा बाजार पर अधिक था (अनुलग्नक - तालिका 6)। विशेष रूप से, संचयी प्रभाव ने द्वारा सी.पी. दरों को 259 बीपीएस कम किया जबकि 10 साल के जी-सेक पर और 10 साल के कॉर्पोरेट बांडों पर यील्ड लगभग 32 बीपीएस और 46 बीपीएस द्वारा क्रमशः कम हुई¹⁶। व्यक्तिगत रूप से, हालांकि, एलटीआरओ और टीएलटीआरओ का अंतर प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए, जबकि एलटीआरओ ने सीपी की दरों में 307 बीपीएस की कमी की, टीएलटीआरओ का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरी ओर, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड पर 22 बीपीएस की तुलना में 8 बीपीएस पर जी-सेक यील्ड पर एलटीआरओ का प्रभाव था, दोनों खंडों पर टीएलटीआरओ का प्रभाव 23-24

¹⁵ पद्धति के लिए बेकर एट अल, (2016) और डेटा स्रोत के लिए सेंट लुइस वेबसाइट के यूएस फेडरल रिजर्व बैंक देखें।

¹⁶ टीएलटीआरओ2 पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि, 3 अप्रैल, 2020 की नीलामी तिथि निम्नलिखित के साथ आई (i) टीएलटीआरओ 3 की घोषणा; (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार के समय में परिवर्तन; और (iii) एच 1:2020-21 के लिए बड़े उधार कार्यक्रम की घोषणा।

बीपीएस पर महत्वपूर्ण राहत देने वाला था। ऐसा अनुमान है कि पॉलिसी दर में कमी (अवधि के दौरान 5.15 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत तक) के कारण सीपी दरों में 92 बीपीएस की कमी आई है, जबकि जी-सेक और कॉरपोरेट बॉन्ड में 5-9 बीपीएस की कमी आई है। कुल मिलाकर, रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों का यील्ड और जोखिम प्रसार पर गंभीर प्रभाव पड़ा, जिससे बाजार के तनाव को कम करने और वित्तीय स्थितियों में सुधार करने में मदद मिली।

(ii) ऑपरेशन ट्विस्ट

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ओटी का आयोजन टर्म प्रीमिया को कम करने के लिए किया गया था। इस उद्देश्य के लिए, दिसंबर 2019-जनवरी 2021,¹⁷ की अवधि के लिए दैनिक डेटा के आधार पर 10-वर्ष और 1-वर्ष की जी-सेक दरों के बीच प्रसार की गणना की जाती है, जिसमें अठारह ओटी घोषणाएं देखी गईं। चूंकि ये सभी घोषणाएं व्यावसायिक घंटों के बंद होने के बाद हुई थीं, इसलिए घोषणा के दिन समापन दर और अगले दिन खुलने की दर के बीच यील्ड के अंतर को 10 साल और 1 साल के सरकारी पेपर के लिए अलग से लिया जाता है। स्प्रेड में परिणामी अंतर (घोषणा दिवस और अगले दिन के बीच) को मॉडल में आश्रित चर के रूप में लिया जाता है और व्याख्यात्मक चर, जैसे, लैंग्ड स्प्रेड, ओटी घोषणा तिथियां (डमी के रूप में) और यूएस में आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक में परिवर्तन पर निम्नलिखित विनिर्देश के साथ वापस ले लिया जाता है:

$$\Delta Spread_t = \alpha_0 + \beta_i * Spread_{t-1} + \sum_{t=1}^{18} \psi_t * \Delta OT_{t-1} + \sum_{i=1}^n \gamma_i * \Delta US_Index^i + \varepsilon_t \quad \dots (iv)$$

अनुमानों से संकेत मिलता है कि सभी ओटी के संचयी घोषणा प्रभाव ने अवधि को 29 बीपीएस तक कम कर दिया, जिससे उपज वक्र समतल हो गया (अनुलग्नक - तालिका 7)। हालांकि, यह ध्यान दिया जाता है कि छह घोषणा तिथियों (अर्थात्, 2 जनवरी, 23 अप्रैल, 12 नवंबर, 11, 24

और 31, दिसंबर 2020) पर बाजार-विशिष्ट घटनाओं के कारण प्रसार में वृद्धि हुई। ये निम्नलिखित थे: (i) 2 जनवरी, 2020 को राजकोषीय गिरावट की चिंता; (ii) 23 अप्रैल को म्यूचुअल फंडों द्वारा सामना किए गए मोचन दबाव; (iii) 12 नवंबर को अक्टूबर के लिए उच्च मुद्रास्फीति प्रिंट की प्रत्याशा; (iv) 11 दिसंबर को दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में कम बोली लगाना; (v) रिज़र्व बैंक द्वारा 24 दिसंबर को 5.85% जीएस 2030 के लिए बोलियों को अस्वीकार करने के बाद लंबी अवधि की दरों पर उच्च यील्ड पर बाजार की परेशानी; और (vi) सरकारी ऋण की बड़ी साप्ताहिक बिक्री से पहले व्यापारियों को ओएमओ घोषणा के बारे में अनिश्चितता है। कुल मिलाकर, निष्कर्ष उपज वक्र की स्थिरता को कम करने में ओटी की प्रभावकारिता का साक्ष्य प्रदान करता है, जिससे वित्तपोषण की स्थिति को आसान बनाने में मदद मिली।

VI. निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय अनुभव से सबक लेते हुए, रिज़र्व बैंक ने महामारी के जवाब में पारंपरिक, नियामक और विवेकपूर्ण नीतियों द्वारा समर्थित अपरंपरागत उपायों की एक श्रृंखला का अनावरण किया। मार्च 2020 में घरेलू बाजारों में भारी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय स्पिलओवर को देखते हुए, न केवल प्रणालीगत चलनिधि को बढ़ाने के लिए बल्कि विशिष्ट क्षेत्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए लक्षित अभिनव और व्यापक उपायों के लिए समय की आवश्यकता थी। उस दृष्टिकोण से, एलटीआरओ और टीएलटीआरओ योजनाओं ने यील्ड में नरमी और फैलाव को नियंत्रित करके वित्तीय स्थितियों को आसान बनाने में नियमित ओएमओ के पूरक के रूप में कार्य किया, जिससे बाजार सहभागियों के बीच विश्वास पैदा हुआ।

महामारी के संबंध में एक व्यापक वित्तीय प्रतिक्रिया को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए बड़ी फंडिंग आवश्यकता को देखते हुए ओएमओ के माध्यम से चलनिधि इंजेक्शन के आकार और पैमाने के साथ, ओटी ने जी-सेक टर्म स्प्रेड को महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित किया और सरकार के लिए उधार लेने की लागत को कम कर दिया, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। लंबी अवधि की दरों में कमी के चलते लिखतों और जारीकर्ता श्रेणी के स्पेक्ट्रम में ब्याज दरों में नरमी आई, जिसने बाजार की

¹⁷ डेटा श्रृंखला को पहले अंतर में स्थिर पाया गया था।

गतिविधि को फिर से जगाया और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए सामान्य स्थिति बहाल की। पुनर्वित्त सुविधाओं और म्यूचुअल फंडों को चलनिधि समर्थन जैसे विशिष्ट उपायों ने क्षेत्र-विशिष्ट चलनिधि तनाव को कम किया और मोचन दबाव को कम किया।

अंत में, स्पष्ट समय-आकस्मिक और राज्य-आकस्मिक अग्रगामी मार्गदर्शन, कोविड -19 के दौरान मौद्रिक नीति संचार की ध्यान देने योग्य विशेषता बन गया। इसके नवीन उपयोग ने बाजारों को पुनर्जीवित करने में अन्य उपायों को प्रबल किया और पूरक बनाया, और इसकी सफलता को देखते हुए, रिजर्व बैंक के नीति टूलकिट में यह एक महत्वपूर्ण साधन बना रहेगा। कुल मिलाकर, महामारी के दौरान उठाए गए सक्रिय कदमों ने आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सुधार की नींव रखी है।

संदर्भ

बेकर, एसआर ब्लूम, एन. और एसजे डेविस (2016): मापने वाली आर्थिक नीति अनिश्चितता, त्रैमासिक जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम 131: 4, पीपी 1593-1636।

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2019): अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण: एक क्रॉस-कंट्री विश्लेषण, सीजीएफएस पेपर्स नंबर 63, अक्टूबर।

बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (2020): बीआईएस वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट, जून।

बर्नानके, बीएस, (2020): मौद्रिक नीति के नए उपकरण, अमेरिकी आर्थिक संघ के अध्यक्षीय भाषण, 4 जनवरी।

दास, एस, घोष, एस, और वी कामटे (2020): मौद्रिक नीति और वित्तीय बाजार: ट्विस्ट और टैंगो, आरबीआई बुलेटिन, अगस्त।

गैम्बाकोर्टा, एल, हॉफमैन, बी. और जी. पीर्समैन (2014): ज़ीरो लोअर बाउंड में अपरंपरागत मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता: एक क्रॉस-कंट्री एनालिसिस, जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट और बैंकिंग, वॉल्यूम 46, नंबर 4 (जून)।

हार्टले, जे.एस. और ए. रेबुकी (2020): एनएवी वर्किंग पेपर नंबर 27339, जून में उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सीओवीआईडी -19 सेंट्रल बैंक क्वांटिटेटिव ईजिंग का एक इवेंट स्टडी।

हॉफमैन, डी और जी. काम्बर (2020): इमर्जिंग मार्केट में अपरंपरागत मौद्रिक नीति और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, सीओवीआईडी -19 पर विशेष श्रृंखला, मौद्रिक और पूंजी बाजार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 23 सितंबर।

कुरोदा, एच. (2016): जेई स्टिग्लिट्ज़ और एम. गुजमैन (संस्करण) में द अपरंपरागत मौद्रिक नीति का अभ्यास और सिद्धांत, मैक्रोइकॉनॉमिक्स में समकालीन मुद्दे, पालग्रेव मैकमिलन।

लोव, पी.(2019): अपरंपरागत मौद्रिक नीति: ओवरसीज़ से कुछ सबक, एंड्रेस टू आस्ट्रेलियन बिजनेस इकोनोमिस्ट डिनर, 26 नवंबर।

भारतीय रिजर्व बैंक (2020): अपरंपरागत मौद्रिक नीति, शिक्षा।

भारतीय रिजर्व बैंक (2014): मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (अध्यक्ष: डॉ. उर्जित आर.पटेल), जनवरी।

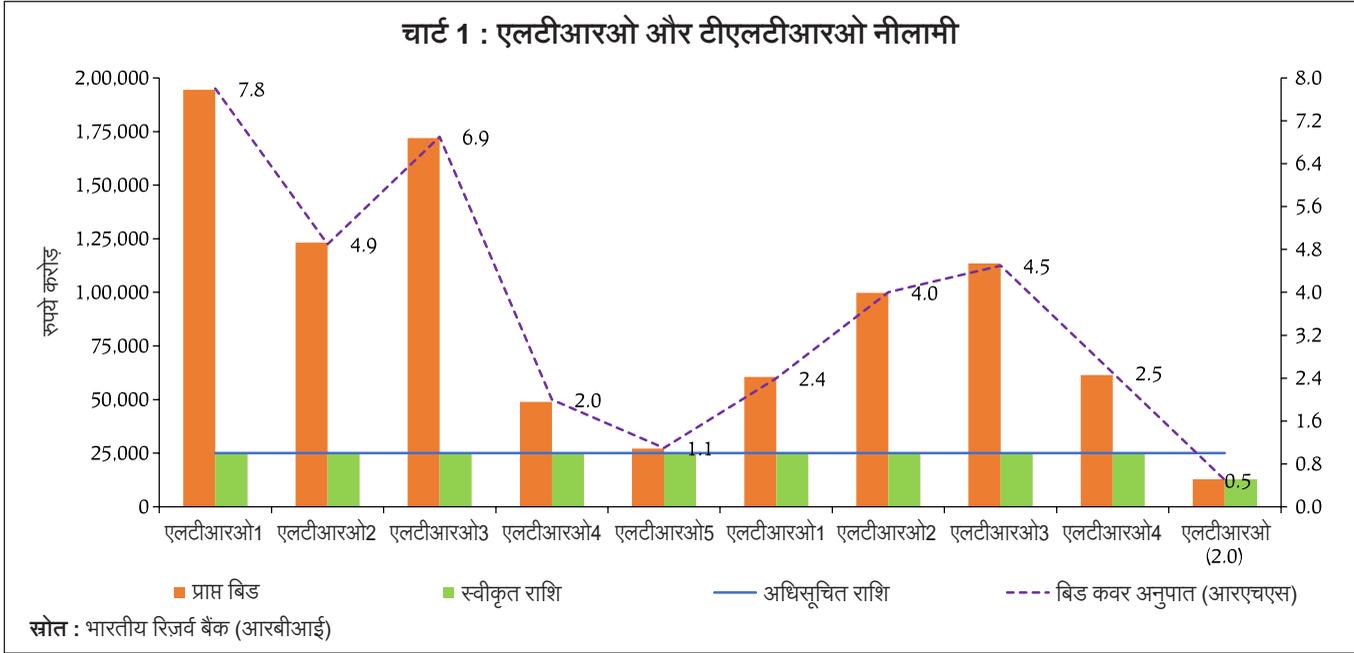
भारतीय रिजर्व बैंक (2020): कोविड -19 संबंधित तनाव (अध्यक्ष: श्री के.वी.कामथ), 7 सितंबर के लिए रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क पर विशेषज्ञ समिति।

भारतीय रिजर्व बैंक (2020 ए): वित्तीय बाजार और चलनिधि की स्थिति, मौद्रिक नीति रिपोर्ट, 9 अक्टूबर।

भारतीय रिजर्व बैंक (2020 बी): मौद्रिक नीति समिति का संकल्प, 9 अक्टूबर।

भारतीय रिजर्व बैंक (2020 सी): गवर्नर का वक्तव्य, 9 अक्टूबर।

अनुबंध



तालिका 1: कोविड -19 के दौरान केंद्रीय बैंक के उपाय

देश	एसेट खरीद			उधार / चलनिधि		एफएक्स स्वैप / हस्तक्षेप		विवेकपूर्ण विनियम
	सरकारी बॉन्ड	वाणिज्यिक पत्र	कॉर्पोरेट बॉन्ड	सामान्य चलनिधि की सुविधा	विशिष्ट उधार	यूएसडी स्वैप लाइन	एफएक्स हस्तक्षेप	
एईएस	ऑस्ट्रेलिया	√			√	√	√	√
	यूरो क्षेत्र	√	√	√	√	√	√	√
	जापान	√	√	√	√	√	√	√
	न्यूजीलैंड	√			√	√	√	
	स्वीडन	√		√		√	√	√
	स्विट्ज़रलैंड					√	√	√
	यूनाइटेड किंगडम	√	√	√	√	√	√	√
	संयुक्त राज्य अमेरिका	√	√	√	√	√		√
ईएमई	अर्जेंटीना		√			√		
	ब्राज़िल				√	√	√	√
	भारत	√			√	√	√	√
	इंडोनेशिया	√			√			√
	मलेशिया				√	√		
	मेक्सिको				√	√	√	√
	फिलीपींस	√				√		
	रूस				√	√	√	√
	सिंगापुर				√	√	√	
	दक्षिण अफ्रीका	√			√			√
	कोरिया				√	√	√	√
थाईलैंड	√				√		√	

स्रोत: बीआईएस वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट, 2020: आईएमएफ और संबंधित केंद्रीय बैंक वेबसाइट।

तालिका 2: विशेष ओएमओ (ऑपरेशन ट्विस्ट)

तारीख			ओएमओ खरीद (₹ करोड़)		ओएमओ बिक्री (₹ करोड़)		नेट ओएमओ खरीद (+) / बिक्री (-) (₹ करोड़)
घोषणा	नीलाम	समझौता	अधिसूचित राशि	राशि स्वीकृत	अधिसूचित राशि	राशि स्वीकृत	
19-12-2019	23-12-2019	24-12-2019	10,000	10,000	10,000	6,825	3,175
26-12-2019	30-12-2019	31-12-2019	10,000	10,000	10,000	8,501	1,499
02-01-2020	06-01-2020	07-01-2020	10,000	10,000	10,000	10,000	0
16-01-2020	23-01-2020	24-01-2020	10,000	10,000	10,000	2,950	7,050
23-04-2020	27-04-2020	28-04-2020	10,000	10,000	10,000	10,000	0
29-06-2020	02-07-2020	03-07-2020	10,000	10,000	10,000	10,000	0
25-08-2020	27-08-2020	28-08-2020	10,000	10,000	10,000	10,000	0
31-08-2020	03-09-2020	04-09-2020	10,000	7,132	10,000	10,000	-2,868
07-09-2020	10-09-2020	11-09-2020	10,000	10,000	10,000	9,900	100
14-09-2020	17-09-2020	18-09-2020	10,000	10,000	10,000	10,000	0
24-09-2020	01-10-2020	05-10-2020	10,000	10,000	10,000	10,000	0
05-11-2020	12-11-2020	13-11-2020	10,000	10,000	10,000	10,000	0
12-11-2020	19-11-2020	20-11-2020	10,000	10,000	10,000	10,000	0
19-11-2020	26-11-2020	27-11-2020	10,000	10,000	10,000	10,000	0
11-12-2020	17-12-2020	18-12-2020	10,000	10,000	10,000	10,000	0
24-12-2020	30-12-2020	31-12-2020	10,000	10,000	10,000	10,000	0
31-12-2020	07-01-2021	08-01-2021	10,000	10,000	10,000	10,000	0
07-01-2021	14-01-2021	15-01-2021	10,000	10,000	10,000	10,000	0
15-02-2021	25-02-2021	26-02-2021	10,000	10,000	10,000	10,000	0
24-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	15,000	15,000	15,000	15,000	0

स्रोत: आरबीआई

तालिका 3: वित्तीय बाजार - दरें और प्रसार

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम रहित दर पर)		
	26 मार्च, 2020 तक	26 फरवरी, 2021 तक	भिन्नता (बीपीएस में)	26 मार्च, 2020 तक	26 फरवरी, 2021 तक	भिन्नता
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
सीपी (3 महीने) कॉरपोरेट बॉन्ड	6.74	4.25#	-249	170	105	-65
(i) एए (1-वर्ष)	7.76	4.33	-343	246	22	-224
(ii) एए (3- वर्ष)	8.47	5.60	-287	276	37	-239
(iii) एए (5- वर्ष)	7.84	6.35	-149	141	-3	-144
(iv) एए (3- वर्ष)	9.15	6.40	-275	344	97	-247
(iv) बीबीबी-माइनस (3-वर्ष)	12.29	10.23	-206	658	412	-246
10- वर्ष जी-सेक	6.22	6.23	1	-	-	-

#: सीपी-एनबीएफसी दर

स्रोत: सीसीआईएल:एफ-टीआरएसी; एफआईएमएमडीए ; और ब्लूमबर्ग

तालिका 4: कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करना

महीना	2019-20	2020-21	भिन्नता (प्रतिशत)
	(₹ करोड़)		
अप्रैल	72,255	54,741	-24.2
मई	44,626	84,871	90.2
जून	50,008	70,536	41.0
जुलाई	46,082	48,122	4.4
अगस्त	43,431	58,419	34.5
सितंबर	49,124	64,538	31.4
अक्टूबर	48,291	65,028	34.7
नवंबर	49,192	45,688	-7.1
दिसंबर	58,677	88,130	50.2
जनवरी	71,712	60,871	-15.1
अप्रैल-जनवरी	5,33,398	6,40,943	20.2

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

तालिका 5: एडीएफ यूनिट रूट टेस्ट
(2019:12 – 2020:9)

परिवर्तनशील	स्तर	पहला अंतर
जी -सेक	-1.484	-14.899***
कॉर्पोरेट बॉन्ड	-1.364	-14.855***
सीपी	-2.574*	-12.344***

नोट: *, ** और *** का क्रमशः 10%, 5% और 1% पर महत्व है।

तालिका 6: एलटीआरओ और टीएलटीआरओ मनी और बॉन्ड बाजार पर प्रभाव

चर	Δ सीपी दर	Δ जी-सेक यील्ड	Δ कार्प. बांड यील्ड
Σ लैंग (-1 से -2)	-0.62***	-0.23	0.00
Δ पॉलिसी रेट	0.80**	0.04***	0.08***
Δ यूएस पॉलिसी अनिश्चितता (-1)	0.00	0.00	0.00
Σ एलटीआरओ1 (0 से -1)	0.71***	-0.90***	-0.04***
Σ एलटीआरओ2 (0 से -1)	-0.09	0.00	-0.11***
Σ एलटीआरओ3 (0 से -1)	0.73**	-0.03***	-0.14***
Σ एलटीआरओ4 (0 से -1)	-4.78***	-0.09***	-0.04
Σ एलटीआरओ5 (0 से -1)	0.36**	0.13***	0.11
ΣLTRO	-3.07***	-0.08*	-0.22***
Σ एलटीआरओ1 (0 से -1)	2.34***	-0.06	0.04**
Σ एलटीआरओ3 (0 से -1)	0.18	0.08***	0.03
Σ एलटीआरओ4 (0 से -1)	-0.83***	-0.26***	-0.26***
Σ एलटीआरओ5 (0 से -1)	-1.21***	-0.06***	-0.08***
Σटीएलटीआरओ	0.49	-0.24***	-0.23***
Σएलटीआरओ+ एलटीएलटीआरओ	-2.59**	-0.32***	-0.46***
डायग्नोस्टिक्स (पी - मूल्य)			
सशर्त विषमता के लिए आर्क एलएम परीक्षण	0.92	0.51	0.96
अवशेषों के व्हाइट नोइज़ के लिए पोर्टमंटो परीक्षण	0.42	0.43	0.06

*, ** और *** का अर्थ क्रमशः 10%, 5% और 1% है।

स्रोत: लेखक का अनुमान

तालिका 7: टर्म स्प्रेड पर ओटी की घोषणा का प्रभाव

परिवर्तनशील	स्प्रेड
लैंग (-1)	-0.06
Δ यूएस अनिश्चितता (-1)	0.00
ओटी1 (-1)	-0.12***
ओटी2 (-1)	-0.98***
ओटी3 (-1)	-0.01
ओटी4 (-1)	-0.03***
ओटी5 (-1)	0.05***
ओटी6 (-1)	-0.04***
ओटी7 (-1)	-0.02***
ओटी8 (-1)	-0.12***
ओटी9 (-1)	-0.05***
ओटी10 (-1)	-0.08**
ओटी11 (-1)	-0.02***
ओटी12 (-1)	-0.01***
ओटी13 (-1)	0.09***
ओटी14 (-1)	-0.02**
ओटी15 (-1)	-0.00
ओटी16 (-1)	0.09***
ओटी17 (-1)	0.03***
ओटी18 (-1)	-0.01***
Σओटी	-0.29***
डायग्नोस्टिक्स (पी - मूल्य)	
ब्रेस्च-गॉडफ्रे एलएम परीक्षण	0.06
सशर्त विषमता के लिए आर्क एलएम परीक्षण	0.94

*, ** और *** का अर्थ क्रमशः 10%, 5% और 1% है।

स्रोत: लेखक का अनुमान

केंद्रीय बजट 2021-22: एक आकलन*

केंद्रीय बजट 2021-22 ने वृद्धि में कोविड के बाद की अवधि में समुत्थान के लिए प्रति-चक्रिय निवेश के कारण राजकोषीय सहायता को प्राथमिकता देकर सही शुरुआत की है। विनिर्माण क्षेत्र में अंतर्निहित सुधार पैकेज (इनबिल्ट रिफॉर्म्स पैकेज) के अंतर्गत निजीकरण, आस्तियों का मुद्रीकरण, आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के दीर्घकालिक वित्तपोषण पर नयी पहलें और बैंकिंग प्रणाली में अनर्जक आस्तियों का परिशोधन, और प्रोत्साहन संबद्ध लक्ष्यित गतिविधियों के संवर्धन शामिल हैं, जो संवृद्धि की गति को मध्यम अवधि में बढ़ाएंगे। अधिक राजकोषीय पारदर्शिता, राजस्व बजट-निर्धारण के लिए आधारभूत पूर्वानुमानों का उपयोग और कर-व्यवस्था में स्थिरता बजट की अन्य मुख्य बातें हैं। जैसे ही अर्थव्यवस्था कोविड-19 के आघातों से उबरेगी, राजकोषीय सुदृढीकरण का मार्ग भारत के सार्वजनिक वित्त को राजकोष के पुनर्निर्माण के लिए एक धारणीय पथ पर रखेगा।

भूमिका

केंद्रीय बजट 2021-22 भारत में मध्यावधि संवृद्धि पथ के विकास के लिए निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, वृद्धि में कोविड के बाद के हालात में सुधार को बनाए रखने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। केंद्रीय बजट 2021-22 निम्न छः विषय-वस्तुओं पर आधारित है: स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), आकांक्षी भारत (एसपिरेशनल इंडिया) के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को सुदृढ बनाना, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। केंद्रीय बजट ने विकास को गतिशक्ति प्रदान करने के लिए अनेक उपाय आरंभ किए हैं, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देना,

* यह आलेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), भारतीय रिजर्व बैंक के राजकोषीय प्रभागों में इप्सिता पाधी, सक्षम सूद, राहुल अग्रवाल, अनूप के. सुरेश, बिचित्रानंद सेठ, डॉ. समीर रंजन बेहरा और डॉ. संगीता मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। यह दल डॉ. देबा प्रसाद रथ को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और ये आवश्यक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त नहीं करते हैं।

यह आलेख 1 फरवरी, 2021 को जारी बजट 2021-22 के भाषण और संबंधित दस्तावेजों पर आधारित है। केंद्रीय बजट 2020-21 पर पिछला आलेख भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अप्रैल 2020 में प्रकाशित हुआ था।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) जैसे विपरीत प्रभाव झेलने वाले क्षेत्रों (हार्ड-हिट सेक्टर्स) के लिए राहत के साथ-साथ अभिशासन संरचना में सुधार। महत्व वाले क्षेत्रों जैसे कि आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), स्वास्थ्य और पूंजीगत व्यय के आबंटन में बढ़ोतरी का गुणक प्रभाव होगा, जिससे निवेश की स्थिति में सुधार लाने के बदले घरेलू मांग, आय और रोजगार बढ़ेगा।

प्रचलित अनिश्चितताओं के मद्देनजर राजकोषीय अति-प्रतिबद्धता से बचने के लिए, वर्ष 2025-26 तक सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) से 4.5 प्रतिशत कम करने से राजकोषीय समेकन को फिर से शुरू करने की आवश्यकता पर विचार किया गया है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय समेकन को अनुपालन में सुधार और आस्तियों के विनिवेश और मुद्रीकरण से प्राप्तियों को बढ़ाकर कर राजस्व संग्रहण में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयोजन है।

इस पृष्ठभूमि में, शेष आलेख को तीन खंडों में विभाजित किया गया है: खंड II में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई है, अर्थात्, पहले के केंद्रीय बजटों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण, मुख्य घाटा संकेतक, वर्ष 2020-21 के दौरान राजकोषीय गिरावट का विश्लेषण, कर-संग्रहण में उछाल और अंत में, पूंजीगत व्यय और सामाजिक क्षेत्र के खर्च पर ध्यान केंद्रित करना। खंड III में इस बजट से उभरने वाले कुछ प्रमुख राजकोषीय मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, यथा विनिवेश और आस्तित्व मुद्रीकरण, बैंकों का पुनःपूंजीकरण, राजकोषीय पारदर्शिता, बाजार उधार एवं कर्ज के गतिमान आयामों और अंततः पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संबंध में राज्यों के लिए न्यायमन और प्रभावा। ये सभी मुद्दे मध्यावधि में राजकोषीय नीति की प्रकृति और सफलता का निर्धारण करेंगे। खंड IV में समापन टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

II. केंद्रीय बजट: मुख्य पहलू

ए. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में बजट

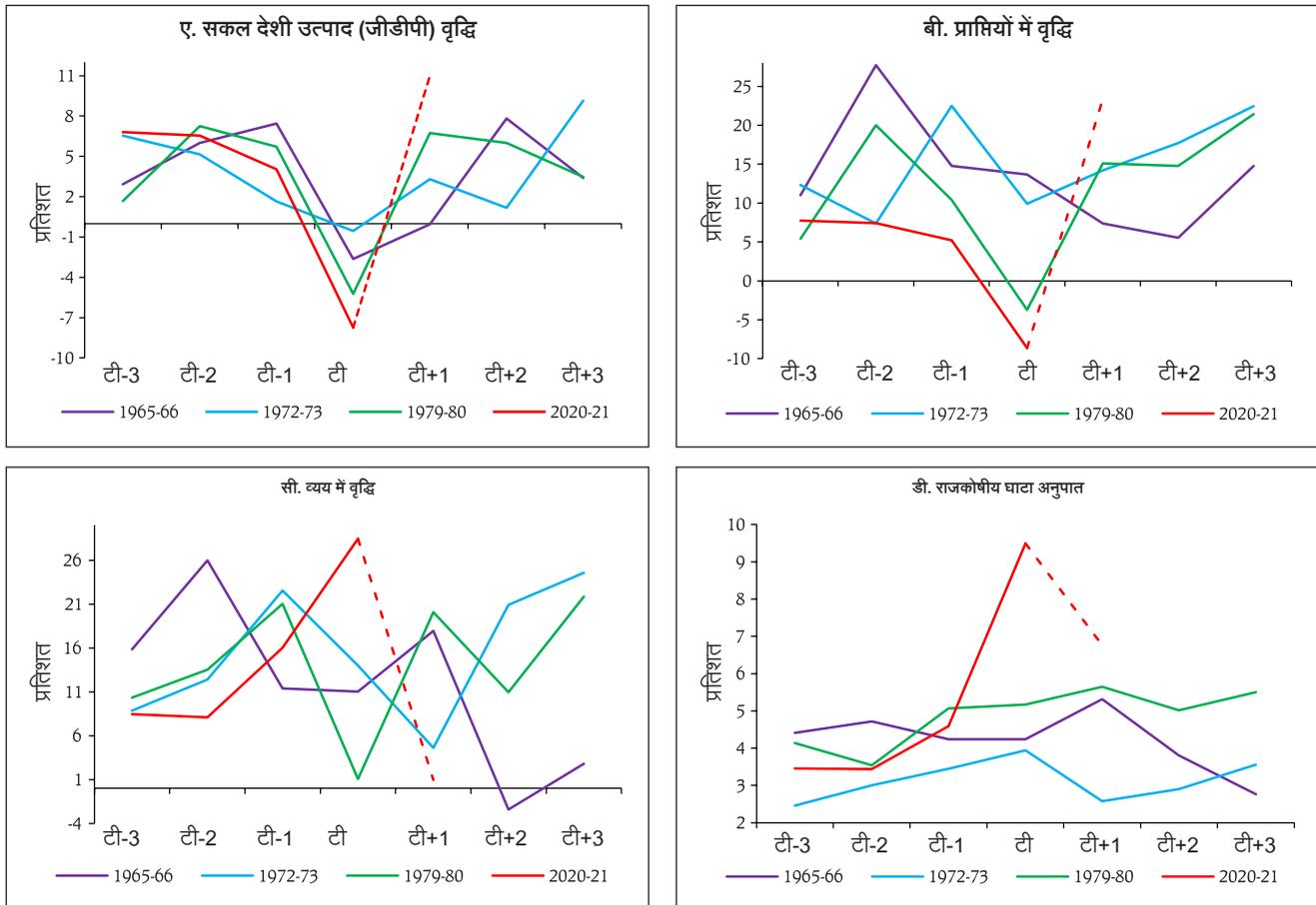
केंद्रीय बजट 2021-22 को उस समय जीडीपी में 7.8 प्रतिशत संकुचन की असाधारण परिस्थितियों में तैयार किया गया था¹। 1960 के दशक से जीडीपी संकुचन केवल तीन बार हुआ है:

¹ 2020-21 के लिए जीडीपी के अग्रिम अनुमान और 2019-20 के लिए जीडीपी के पहले संशोधित अनुमान, जो बजट प्रस्तुति के समय उपलब्ध थे, इस आलेख में उपयोग किए गए हैं। बाद में 26 फरवरी, 2021 को जारी 2020-21 के लिए जीडीपी के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2020-21 के लिए जीडीपी में संकुचन को संशोधित कर 8.0 प्रतिशत कर दिया गया है।

1965-66, 1972-73, और 1979-80 (चार्ट 1बी)। वृद्धि के संकुचन के पहले दो प्रसंगों की पृष्ठभूमि का कारण मानसून की विफलता के साथ युद्ध था और 1979-80 का जीडीपी संकुचन मानसून के मौसम में वर्षा में 19 प्रतिशत की कमी के साथ भयंकर सूखे की स्थिति का परिणाम था। इन वर्षों के दौरान राजकोषीय प्रभावों पर एक घटना अध्ययन से सरकारी प्राप्तिओं के लिए विस्तृत रूप से एक समान स्वरूप का पता चलता है (चार्ट 1बी), जिसमें वृद्धि के संकुचन के अनुरूप, प्रत्येक संकटपूर्ण वर्ष में प्राप्तिओं की वृद्धि में गिरावट हुई। इसके आगामी वर्ष में सुधार हुआ (1965-66 को छोड़कर, जब संकटकाल के बाद केवल तीसरे वर्ष में प्राप्तिओं में वृद्धि में सुधार आया)। दूसरी ओर, व्यय का स्वरूप भिन्न रहा है (चार्ट 1सी)।

1965-66 और 1979-80 के संकटपूर्ण वर्षों में, संकट के प्रति राजकोषीय प्रतिक्रियाओं में विलंब हुआ था, जिससे संकट के बाद के वर्ष में ही टी+1 की अवधि में व्यय वृद्धि में तेजी दर्ज की गई। पिछले स्वरूप के विपरीत, वर्ष 2020-21 में शुरुआत में अधिक व्यय किये जाने के परिणामस्वरूप संकट वर्ष में ही 28.4 प्रतिशत की उच्चतर व्यय वृद्धि दर्ज की गई। परिणामतः, वर्ष 2020-21 में जीएफडी-जीडीपी अनुपात परिशोधित होकर 9.5 प्रतिशत के शीर्ष स्तर पर पहुँच चुका है। संकुचन के दौरान के वर्षों में भिन्न राजकोषीय अंतर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण रूप से व्यय में वर्धन पर निर्भर करते हैं (चार्ट 1डी)।

चार्ट 1: भारत में संकुचन के बाद के बजट का एक घटना अध्ययन



टिप्पणियाँ: बिंदीदार रेखाएँ बजट अनुमानों को दर्शाती हैं।
स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट दस्तावेज़

² 1966-67 में 0.06 प्रतिशत के मामूली संकुचन को छोड़कर।

बी. प्रमुख घाटा संकेतक

2020-21 के लिए जीडीपी के 3.5 प्रतिशत के बजटीय जीएफडी के समक्ष, संशोधित अनुमान (आरई) ने जीएफडी को जीडीपी के 9.5 प्रतिशत पर रखा, यह गिरावट मुख्य रूप से महामारी से उपजे अभूतपूर्व संकुचन के आलोक में कर राजस्व में बड़ी गिरावट के कारण आयी, जिसे विनिवेश से कोई छूट नहीं मिली (सारणी 1)। व्यय को बड़े पैमाने पर युक्तिसंगत बनाने के साथ, मुख्य रूप से सब्सिडी के लिए निर्धारित बजट के आलोक में उच्च राजस्व व्यय ने भी हास में योगदान दिया है, जो कुछ हद तक महामारी संबंधित प्रोत्साहन के कारण हुई कमी को पूरा कर रहे हैं। 2021-22 के लिए, राजस्व व्यय और उच्चतर विनिवेश प्राप्ति में कटौती के आलोक में जीएफडी-जीडीपी³ अनुपात का 6.87 प्रतिशत पर बजट निर्धारित किया है। व्यय का मुख्य केंद्र पूंजीगत व्यय पर स्थानांतरित हो गया है, जबकि कर राजस्व यथार्थवादी स्तरों पर आंका गया है, अर्थात्, जो कि 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान में प्राप्त किए गए।

सी. 2020-21 में राजकोषीय गिरावट का विश्लेषण

2020-21 के लिए कुल राजकोषीय गिरावट 595 आधार अंक थी, जिसमें से 255 आधार अंकों के लिए चक्रीय कारकों⁴ को

सारणी 1: मुख्य राजकोषीय संकेतक

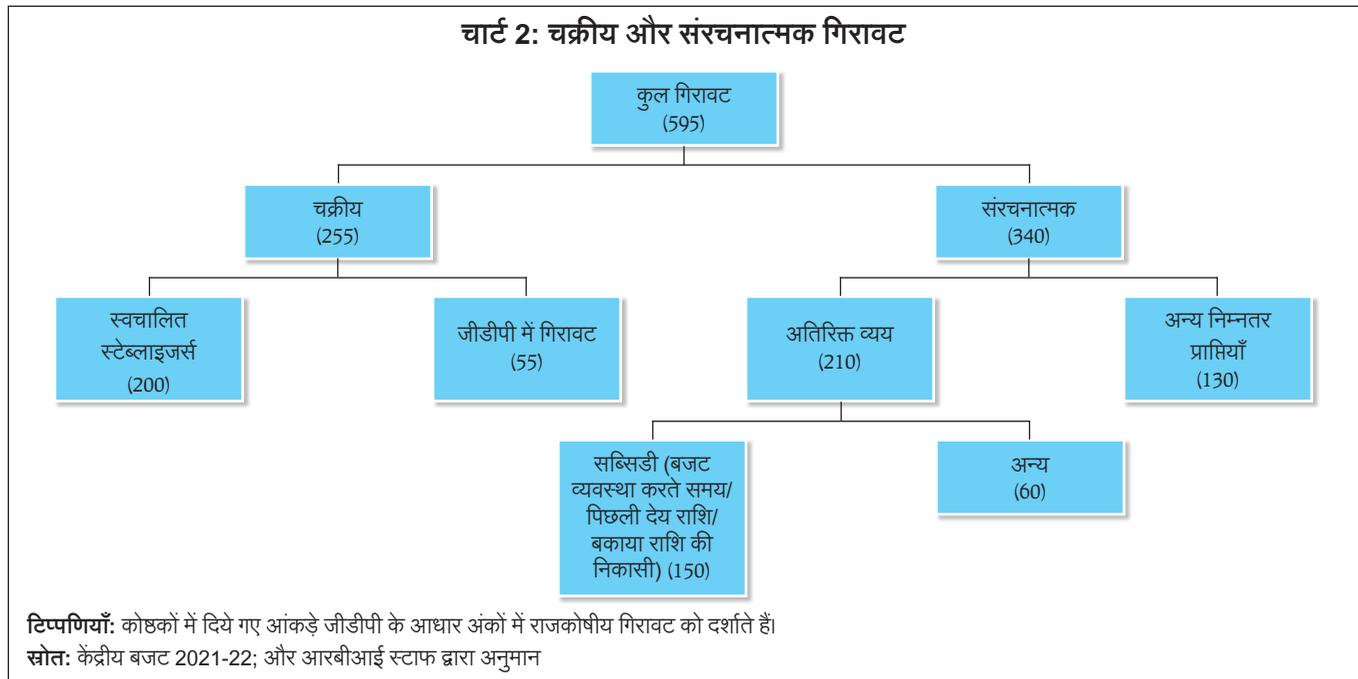
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

	2019-20	2020-21		2021-22
	वास्तविक	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ.
1	2	3	4	5
1. राजकोषीय घाटा	4.6	3.5	9.5	6.8
2. राजस्व घाटा	3.3	2.7	7.5	5.1
3. प्राथमिक घाटा	1.6	0.4	5.9	3.1
4. सकल राजस्व कर	9.9	10.8	9.8	9.9
5. कर-रहित राजस्व	1.6	1.7	1.1	1.1
6. राजस्व व्यय	11.6	11.7	15.5	13.1
7. पूंजीगत व्यय	1.6	1.8	2.3	2.5
8. केंद्रीय सरकार का कर्ज	52.3	50.6	64.3	62.5

स्रोत: केंद्रीय बजट 2021-22

जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: (i) कर राजस्व में कमी के साथ सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन ने स्वचालित स्टेबलाइजर्स को ट्रिगर किया, जिसके कारण लगभग 200 आधार अंकों की गिरावट आयी; (ii) निम्नतर सकल घरेलू उत्पाद ने जीएफडी-जीडीपी अनुपात के हर के मान को बढ़ा दिया, जिसके परिणामस्वरूप अन्य 55 आधार अंकों की गिरावट हुई (चार्ट 2)। सरकार द्वारा विवेकाधीन कार्रवाइयों के कारण 340 आधार अंकों की संरचनात्मक राजकोषीय गिरावट आयी, जिसमें से सरकार ने

चार्ट 2: चक्रीय और संरचनात्मक गिरावट



³ केंद्रीय बजट 2021-22 में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाते हुए, 2020-21 के लिए ₹194,81,975 करोड़ की अनुमानित जीडीपी की तुलना में 2021-22 के लिए जीडीपी (ब.अ.) को ₹222,87,379 करोड़ पर अनुमानित किया गया है।

⁴ फेडेलिनो, ए. और अन्य (2009) का उपयोग करते हुए परिकलित किया है।

सारणी 2: सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) का अपघटन

(प्रतिशत)

	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22
	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	सं.अ.	ब.अ
1	2	3	4	5	6	7	8
1. राजस्व घाटा	66.6	70.0	68.9	71.4	76.5	78.8	75.7
2. पूंजीगत परिव्यय	44.6	43.0	44.2	33.3	47.8	18.0	34.1
3. निवल उधार	1.5	1.6	1.8	0.7	2.1	5.0	1.8
4. विनिवेश (ऋणात्मक)	12.8	14.6	14.9	5.4	26.4	1.7	11.6

स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट दस्तावेज

अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त खर्च किया (210 आधार अंक) और निम्नतर 'अन्य प्राप्तियों' से परस्पर असंबंधित चक्रीय उतार-चढ़ाव (130 आधार अंक) हुआ। इस संरचनात्मक घाटे का एक प्रमुख घटक (लगभग 150 आधार अंक) सब्सिडी के लिए परिव्यय में वृद्धि के कारण एक 'एकबारगी' घटना का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अधिकांश भाग का उद्देश्य पिछली देय राशि/ बकाया राशि को चुकाना है।

डी. जीएफडी का अपघटन

जीएफडी का अपघटन दर्शाता है कि राजस्व घाटा, जिसने 2018-19 से 2019-20 के दौरान जीएफडी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा पहले ही ले लिया था, उसकी 2020-21 (सं.अ.) में जीएफडी हिस्सेदारी 79 प्रतिशत और 2021-22 (ब.अ.) में 76 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर, 2020-21 में उल्लेखनीय गिरावट के बाद 2021-22 में विकास-प्रेरित पूंजी परिव्यय का योगदान तेजी से बढ़ने की उम्मीद है (सारणी 2)।

ई. कर संग्रहण में उछाल

केंद्रीय बजट 2021-22 में कर सुधारों को पेश किया गया है जिनका उद्देश्य विकास को प्रोत्साहित करना, कर प्रशासन को सरल बनाना और मुकदमों को कम करना है। प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर, मौजूदा कर ढांचे को व्यापक रूप से बनाए रखते हुए, अनुपालन में सुधार के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अप्रत्यक्ष करों के संबंध में, विकृतियों को दूर करने और घरेलू उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। अनुपालन में सुधार लाने के लिए छोटे करदाताओं के लिए एक चेहराविहीन विवाद समाधान समिति, एक चेहराविहीन आयकर अपील न्यायाधिकरण, और कर अपवंचकों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने सहित कई उपायों का प्रस्ताव रखा गया है।

अनुपालन में अपेक्षित सुधार (अनुबंध 1) के आलोक में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में 2021-22 में सकल कर राजस्व में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों को क्रमशः 22.4 प्रतिशत और 11.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। 2021-22 के लिए बजटीय कर में उछाल प्रत्यक्ष करों, विशेष रूप से निगम कर के लिए प्रवृत्ति स्तरों (2010-11 से 2019-20 के लिए औसत से अनुमानित) से अधिक है। हालांकि, कुल मिलाकर, निगम कर राजस्व के बजट को 2018-19 और 2019-20 में निम्नतर स्तरों पर रखा गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बजटीय संकुचन के कारण अप्रत्यक्ष करों (सीमा शुल्क को छोड़कर) के लिए बजटीय उछाल कम है (सारणी 3)। कुल मिलाकर, इस स्थिति पर बजटीय कर में उछाल उचित प्रतीत होता है।

सारणी 3: कर संग्रहण में उछाल

	कर संग्रहण में औसत उछाल (2010-11 से 2019-20)	2021-22 (ब.अ.)
1	2	3
1. सकल कर राजस्व	0.96	1.16
2. प्रत्यक्ष कर	0.83	1.56
(i) निगम कर	0.62	1.57
(ii) आय कर	1.20	1.58
3. अप्रत्यक्ष कर	1.15	0.79
(i) जीएसटी	1.68*	1.55
(ii) सीमा शुल्क	0.19	1.49
(iii) उत्पाद शुल्क	0.86	-0.50

*: दो वर्षों का औसत

टिप्पणी: कर संग्रहण में उछाल को नामिक जीडीपी में बदलाव के कारण कर राजस्व की अनुक्रियाशीलता के रूप में परिभाषित किया गया है।

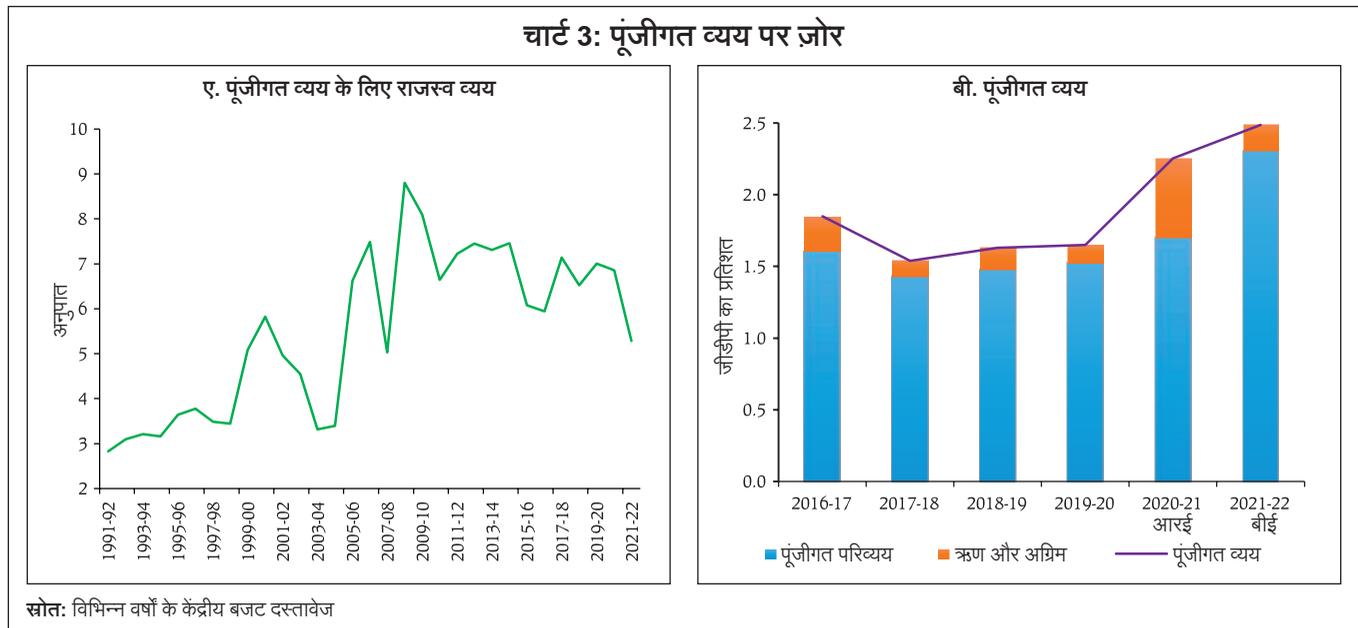
स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट दस्तावेजों पर आधारित आरबीआई स्टाफ अनुमान

एफ. पूंजीगत व्यय और सामाजिक क्षेत्र के व्यय पर मुख्य केंद्र

केंद्रीय बजट प्रस्तावों के छः प्रमुख स्तंभों में से एक 'भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं आधारभूत संरचना' के होने के साथ, निवेश और विकास को पुनर्जीवित करने के लिए पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तदनुसार, पूंजीगत व्यय, जो 2020-21 (सं.अ.) में सकल घरेलू उत्पाद का 2.3 प्रतिशत हो गया, को 2010-11 से 2019-20 के दौरान 1.7 प्रतिशत के औसत से 2021-22 में जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक और बढ़ने का अनुमान है। इसके विपरीत, 2021-22 में राजस्व व्यय में मामूली कमी का अनुमान है, जो व्यय की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है और अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन के संदर्भ में अधिकतम 'वैल्यू फॉर मनी' प्राप्त करने के लिए है (चार्ट 3ए)। हालांकि, 2020-21 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि अधिकांशतः ऋण और अग्रिम में वृद्धि के कारण हुई है। पूंजीगत परिव्यय (ऋण और अग्रिमों को छोड़कर पूंजीगत व्यय) में केवल 6.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 3बी)⁵।

पूंजीगत परिव्यय में 2021-22 में 54.7 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि का अनुमान है, प्रमुख आधारभूत संरचना, यथा रेलवे, सड़कों और पुलों तथा संचार में, पूंजी परिव्यय में 90 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि का अनुमान है (सारणी 4)। पूंजीगत व्यय आबंटन में वृद्धि के माध्यम से, सरकार ने आर्थिक गतिविधियों की गति को पुनर्जीवित करने और विश्वास की भावना को फिर से जगाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया है। हालांकि इससे अधिक घाटा और उधार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन पूंजीगत व्यय में तीव्र वृद्धि के साथ व्यय की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक निवेश पुनरुद्धार के लिए शुभ संकेत है।

सामाजिक क्षेत्र का व्यय, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास और इसी प्रकार पर व्यय शामिल है, 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.7 प्रतिशत हो गया क्योंकि सरकार ने महामारी के दौरान आबादी के कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए कई हस्तक्षेप किए। जैसा कि महामारी ने हमारी स्वास्थ्य प्रणाली को पीड़ित करने वाली आधारभूत समस्याओं को उजागर



⁵ 2020-21 (सं.अ.) में ऋण और अग्रिम में वृद्धि मुख्य रूप से केंद्र द्वारा रेलवे को दिए गए ऋण (₹79,398 करोड़) के कारण है, जो कि कोविड से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों के कारण होने वाले संसाधन अंतराल को कवर करने के लिए है।

सारणी 4: पूंजीगत परिव्यय

	₹ हजार करोड़				वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2019-20	2020-21 (ब.अ.)	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)	2019-20	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. कुल पूंजीगत परिव्यय	311	380	332	514	11.4	6.7	54.7
2. रक्षा	111	114	135	135	16.7	21.1	0.4
3. पूंजी परिव्यय (रक्षा को छोड़कर)	200	267	198	379	8.7	-1.2	91.6
(i) प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर	146	175	124	236	9.4	-14.9	90.0
सिंचाई	0.3	0.3	0.1	0.3	-3.0	-55.4	150.0
ऊर्जा	1	2	3	1	-61.5	147.5	-65.6
भारतीय रेल	68	70	29	107	28.4	-57.3	269.3
सड़कें और पुल	71	77	87	101	1.4	22.8	16.1
सिविल विमानन	0.02	0.03	0.04	0.04	-99.5	87.1	-11.2
बंदरगाह और लाइट							
आवास	0.2	0.1	0.2	0.2	35.9	-33.8	-1.3
संचार	5	26	4	26	103.1	-15.1	486.1
(ii) उद्योग और खनिज	6	7	5	7	55.6	-22.7	53.6
(iii) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	9	10	6	11	26.4	-35.6	77.0
(iv) अन्य	39	74	63	125	-1.8	61.1	99.0

स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट दस्तावेज

किया है, 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दोगुना यानी 0.4 प्रतिशत तक होने का बजटीय प्रावधान है (सारणी 5)।

III. केंद्रीय बजट: उभरते मुद्दे

ए. आस्ति मुद्रीकरण और विनिवेश

केंद्रीय बजट 2021-22, व्यय की दोहरी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए राजकोषीय सुदृढीकरण की राह पर चलते

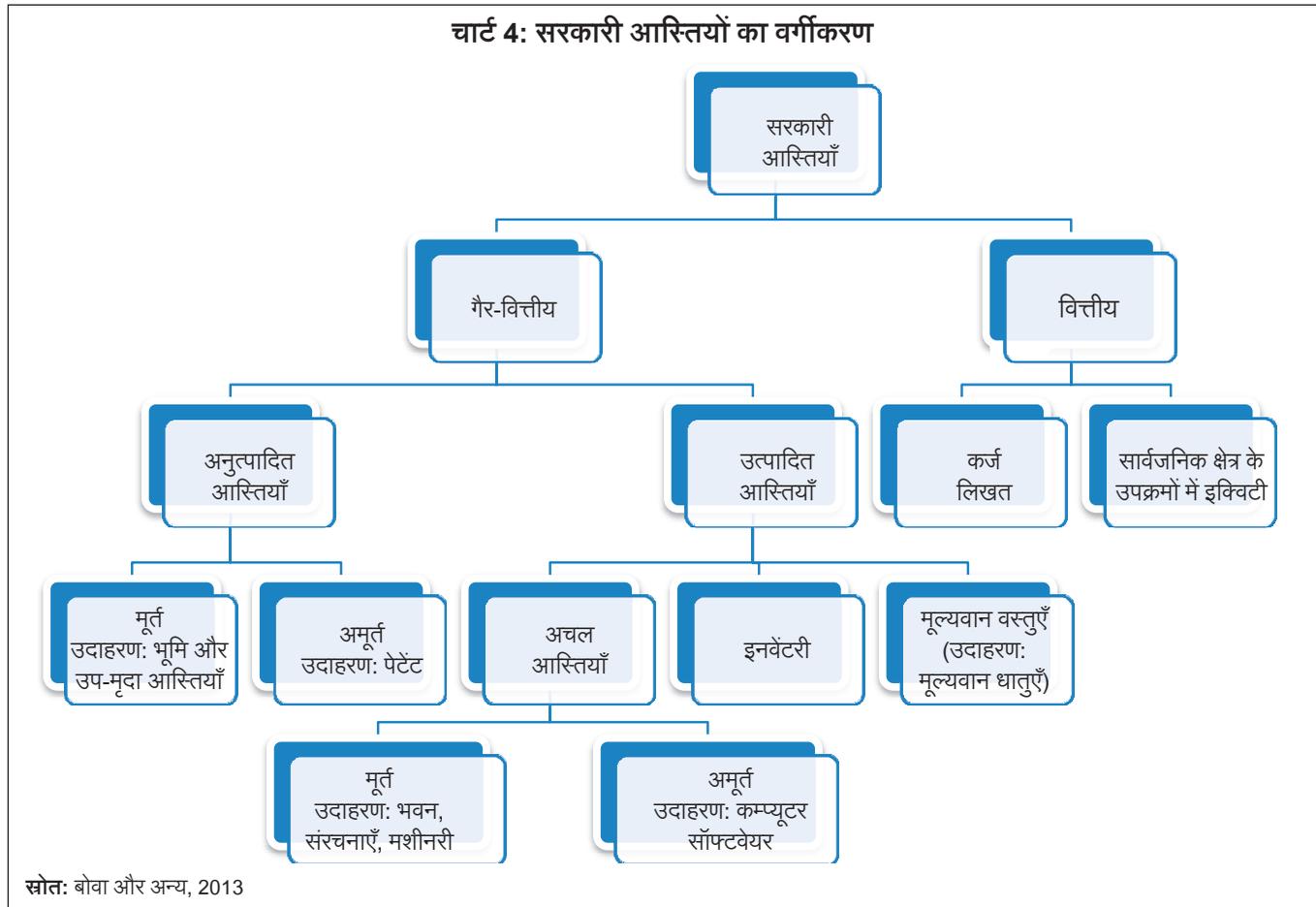
हुए, आस्ति मुद्रीकरण और विनिवेश से प्राप्तियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। एक आर्थिक संपत्ति, आर्थिक मालिक को अर्जित होने वाले लाभ या लाभों की श्रृंखला दर्शाती है। वे या तो उत्पादन में उपयोग के माध्यम से (उदाहरण के लिए, एक कार्यालय भवन), या एक अवधि (उदाहरण के लिए, भूमि) के लिए रख कर मूल्य अर्जित करते हैं [राष्ट्रीय लेखा प्रणाली, 2008]। सरकारी आस्तियों को वित्तीय और गैर-वित्तीय आस्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है; गैर-वित्तीय संपत्तियों को आगे उत्पादित और गैर-उत्पादित संपत्तियों, और मूर्त और गैर-मूर्त संपत्तियों (चार्ट 4) में वर्गीकृत किया जा सकता है। गैर-वित्तीय आस्तियां सभी देशों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, और औसतन उनका मूल्य वित्तीय आस्तियों के 1.2 से 1.3 गुना होने का अनुमान होता है और अधिकांश देशों में वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का संयुक्त मूल्य सकल कर्ज से अधिक रहता है (बोवा और अन्य, 2013)।

1991 के सुधारों के बाद से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में सरकारी इक्विटी के विनिवेश के रूप में वित्तीय आस्तियों का मुद्रीकरण केंद्रीय बजट की एक नियमित विशेषता रही है। हालांकि आम तौर पर विनिवेश से प्राप्त राजस्व बजटीय लक्ष्यों से कम हो गया है, 2017-18 और 2018-19 के अपवाद

सारणी 5: केंद्रीय सरकार का सामाजिक क्षेत्र में व्यय

वर्ष	₹ हजार करोड़	जीडीपी का प्रतिशत		
		सामाजिक क्षेत्र में व्यय	सामाजिक क्षेत्र में व्यय	स्वास्थ्य
1	2	3	4	5
2012-13	244	2.5	0.6	0.3
2013-14	270	2.4	0.6	0.3
2014-15	184	1.5	0.2	0.1
2015-16	239	1.7	0.2	0.1
2016-17	271	1.8	0.2	0.2
2017-18	274	1.6	0.3	0.1
2018-19	290	1.5	0.2	0.1
2019-20	339	1.7	0.2	0.2
2020-21 (सं.अ.)	721	3.7	0.2	0.2
2021-22 (ब.अ.)	543	2.4	0.2	0.4

स्रोत: विभिन्न वर्षों के केंद्रीय बजट दस्तावेज



स्रोत: बोवा और अन्य, 2013

वर्षों को छोड़कर, जब विनिवेश का एक बड़ा हिस्सा सीपीएसई (चार्ट 5)⁶ की क्रॉस-सेल जैसे कम प्रचलित माध्यम से प्राप्त हुआ। 2020-21 में विनिवेश को अमल में नहीं लाया जा सका और 2020-21 के संशोधित अनुमान इस अवधि की बजटीय राशि ₹2.10 लाख करोड़ से 85 प्रतिशत तक कम हो गई।

सरकार ने 2021-22 में एक नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति पेश करके बड़े पैमाने पर विनिवेश किए जाने के अपने इरादे का संकेत दिया है, जिसकी घोषणा पूर्व में *आत्मनिर्भर भारत 1.0* योजना के तहत की गई थी। यह स्पष्ट रूप से महत्व वाले क्षेत्रों की पहचान करके विनिवेश के लिए एक विश्वसनीय रोडमैप प्रदान करता है जिसमें सीपीएसई की न्यूनतम उपस्थिति होगी, और सभी गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई का निजीकरण/ बंदी की जाएगी। इसी तरह, राज्यों द्वारा विनिवेश को प्रोत्साहित करने के

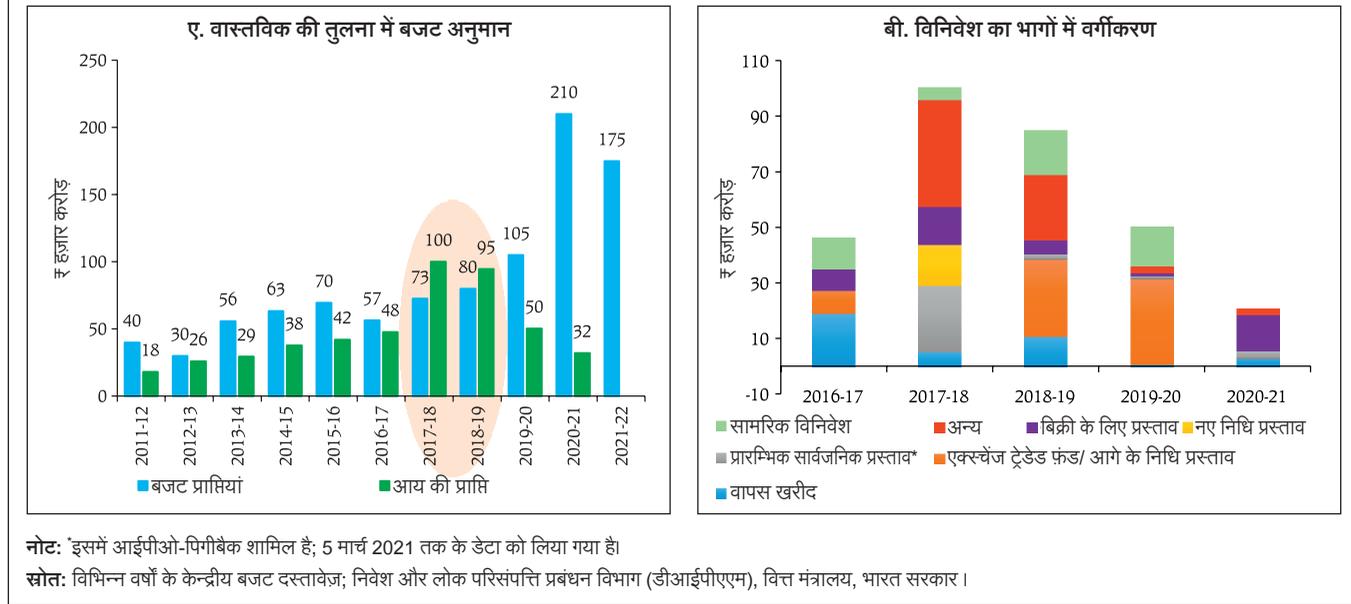
⁶ उदाहरण के लिए, 2017-18 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के सौदे को 'अन्य' श्रेणी में दिखाया गया है।

लिए राज्यों के लिए केंद्रीय कोष का प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। 2021-22 के लिए, कई प्रस्तावों के साथ⁷, विनिवेश लक्ष्य ₹1.75 लाख करोड़ रखा गया है। भले ही नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति और बाजार की उत्साहजनक स्थिति विनिवेश के लिए अच्छी है, बजटीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विनिवेश योजना का सक्रिय रूप से अनुसरण करने की आवश्यकता होगी।

सरकारी उपार्जन और घाटे को कम करने के लिए विनिवेश एक सहायक के रूप में एक अधिमानित विकल्प हो सकता है, विशेषकर जब कम राजस्व के बावजूद उच्च व्यय करना अपरिहार्य हो जाता है, विनिवेश भविष्य के राजस्व नुकसान (जैसे, सरकार के लिए लाभांश आय राशि की हानि और सरकार द्वारा धारित

⁷ प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) और दो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल), पवन हंस, नीलाचल इस्पात निगम, एक सामान्य बीमा कंपनी और जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) शामिल हैं।

चार्ट 5: विनिवेश प्राप्ति



आस्तियों में स्थायी कमी) के बारे में भी बताता है और आस्तियों की 'विक्रेयता' के संदर्भ में परेशानी का सामना कर सकता है। ऐसी चिंताओं के कारण, विनिवेश के मोर्चे पर पिछला प्रदर्शन काफी खराब रहा है। विनिवेश का एक विकल्प/ पूरक गैर-वित्तीय आस्ति मुद्रीकरण है, जिसमें मूल्य को अनलॉक करके राजस्व के नए स्रोतों का निर्माण शामिल है। इसमें सरकारी विभागों या सीपीएसई (भारत सरकार, 2019) द्वारा नियंत्रित विभिन्न अन्य सार्वजनिक आस्तियाँ सम्मिलित हैं, जैसे कि भूमि, भवन, बाँध, पाइपलाइन, सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बिजली पारेषण लाइनें और मोबाइल टावर। इसका उद्देश्य मौजूदा आस्तियों के प्रबंधन की दोहरी समस्याओं को हल करने में मदद करने हेतु सार्वजनिक आस्तियों में किए गए निवेश के मूल्य को अनलॉक करना है, जिन्होंने अब तक उचित या संभावित रिटर्न नहीं दिया है (कांत, 2021) और इसके माध्यम से निजी क्षेत्र की दक्षता का दोहन और नयी आधारभूत संरचना का वित्तपोषण करना है। आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए एक तंत्र के रूप में मुद्रीकरण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक नियोजित किया गया है, उनमें से सबसे आगे ऑस्ट्रेलिया की आस्ति पुनर्चक्रण पहल है, जिसके तहत केंद्र सरकार उप-राष्ट्रीय सरकारों को मौद्रिक प्रोत्साहन (अनुमानित प्राप्ति का अतिरिक्त 15 प्रतिशत) उस स्थिति में प्रदान करती है, जब वे किसी आस्ति (बिक्री या पट्टे के माध्यम से) का मुद्रीकरण करती हैं और प्राप्ति का उपयोग नयी आधारभूत संरचना में पुनः निवेश करने के लिए करती हैं।

केंद्रीय बजट 2021-22 गैर-वित्तीय आस्ति मुद्रीकरण के लिए मार्ग निर्धारित करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 'संभावित ब्राउनफील्ड आधारभूत संरचना आस्ति की 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' और प्रगति को ट्रैक करने और निवेशकों को दृश्यता प्रदान करने के लिए 'आस्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड' शामिल है। 2021-22 में मुद्रीकरण के लिए विनिर्दिष्ट की गई कुछ आस्तियों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की चालू सड़कें, पावर ग्रिड की प्रसारण आस्ति, भारतीय रेलवे के समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और टियर- II और टियर- III शहरों में हवाई अड्डे शामिल हैं। यद्यपि गैर-वित्तीय आस्ति मुद्रीकरण से केंद्र सरकार को प्राप्त राशि को विनिवेश प्राप्ति के तहत शामिल किया जाएगा, यह आवश्यक नहीं कि इसका तात्पर्य आस्ति की सीधी बिक्री से हो। यह लंबी अवधि के पट्टे का रूप ले सकता है, जिसे रियायती करार के रूप में जाना जाता है, जो अनिवार्य रूप से सरकार को वापस आस्ति का अंतरण करता है और मूल आधारभूत संरचना आस्ति के मुद्रीकरण का मुख्य तरीका हो सकता है। आस्ति के मुद्रीकरण के लिए प्रत्यक्ष संविदात्मक दृष्टिकोण, संरचित वित्त दृष्टिकोण और भूमि की बिक्री और पट्टे कुछ उदाहरण मॉडल हैं।

भारत में उप-राष्ट्रीय सरकारों के कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं, जो नए राजस्व संसाधन उत्पन्न करने के लिए अपनी आस्ति का लाभ उठा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आस्ति मुद्रीकरण

के माध्यम से उत्पन्न राजस्व को सार्वजनिक कर्ज का सहारा लिए बिना नए आधारभूत संरचना में निवेश किया जाए। भारत में आस्ति पर निर्भर हुए बिना मुद्रीकरण के बाद आधारभूत संरचना के निर्माण का एक चक्र, आधारभूत संरचना निवेश में एक खेल परिवर्तक साबित हो सकता है।

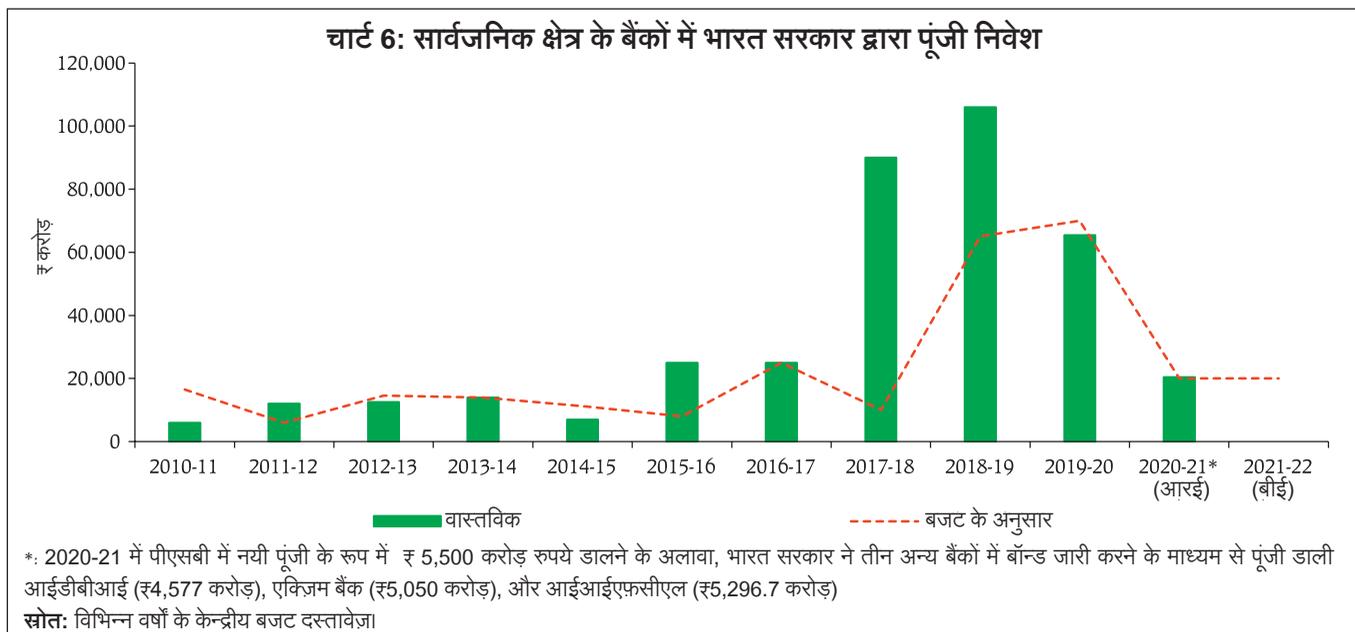
बी. पुनःपूंजीकरण

केंद्रीय बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ₹20,000 करोड़ के लिए पुनःपूंजीकरण का प्रस्ताव है⁸। 2020-21 के दौरान महामारी के झटके की स्थिति के कारण आघात-सहनीयता में सुधार करने के लिए पीएसबी सक्रिय रूप से बफर बना रहे हैं और इस प्रक्रिया को 2021-22 में जारी रखने की आवश्यकता होगी, जिसमें कुछ योगदान बजट से आया है। क्रेडिट और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैंक पुनःपूंजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाने वाला पर्याप्त साहित्य मौजूद है। बैंक पुनःपूंजीकरण का बैंक ऋण आपूर्ति पर एक मजबूत प्रभाव पाया गया है और यह प्रभावी आपूर्ति और ऋण के आबंटन के लिए भी एक पूर्वापेक्षा है (गंबरकोर्ट और शिन, 2016)। भारत के विशिष्ट संदर्भ में यह पाया गया कि बैंक पूंजी और क्रेडिट के बीच संबंध अरैखिक है और बैंकों में पुनःपूंजीकरण की कोई भी राशि ऋण

वृद्धि में तेजी लाने में सहायक है (वर्मा और हेरवाडकर, 2019)। भारतीय मौद्रिक नीति बैंकों की पूंजी की स्थिति के आधार पर उनकी ऋण आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है (मुदुली और बेहरा, 2020)।

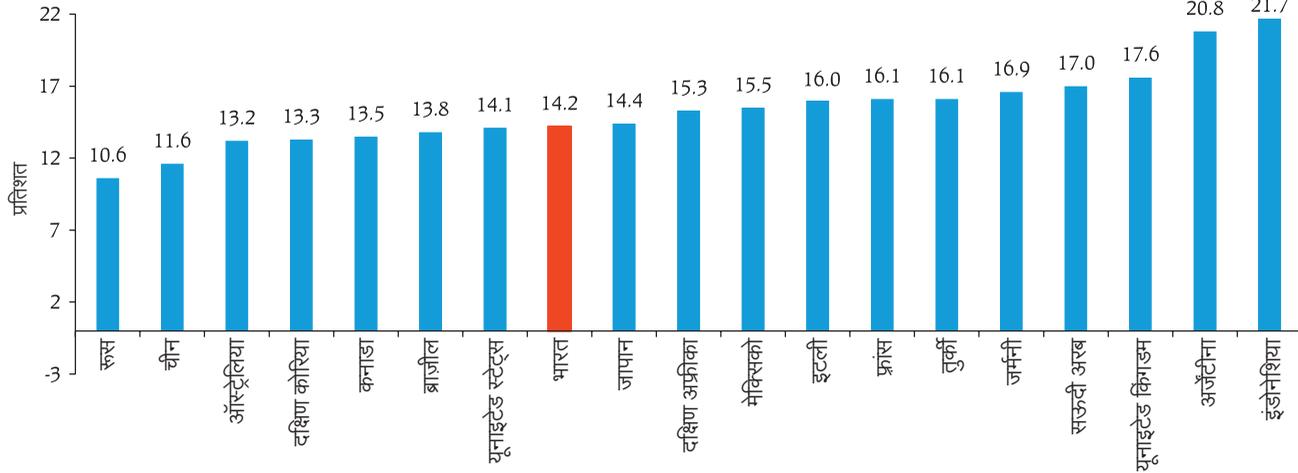
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों ने विभिन्न उपायों के माध्यम से बैंकों का पुनःपूंजीकरण किया है, जैसे, बांड अंतरण के माध्यम से पूंजी लगाना (अशोध्य ऋण या अनुत्तरित के बदले में), नकद अंतरण या संपत्ति आस्ति का अंतरण; सरकार या सार्वजनिक एजेंसी द्वारा बैंक देयताओं में कमी; पुनर्क्रय करार; बकाया ऋणों पर गारंटी का प्रावधान; लघु/मध्यम अवधि के ऋण जारी करना; बैंक ऋण की चुकौती/ पुनर्भुगतान की अनुमति देने के लिए उद्यमों पर कार्रवाई और अपचारी उधारकर्ताओं को उनके बैंक उधारों को चुकाने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें सब्सिडी देना (अनुबंध II)।

2007-08 के वित्तीय संकट के बाद विभिन्न यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य राज्यों ने वित्तीय संस्थानों की विफलता का प्रबंधन करने के प्रयास किए। पुनःपूंजीकरण इन साधनों में से एक है। भारत ने समय-समय पर अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए बैंक पुनःपूंजीकरण पैकेजों की घोषणा के साथ उन्हें लागू भी किया है (चार्ट 6)।



⁸ बैंक पुनःपूंजीकरण बैंक में नई पूंजी लगाने का पर्याय है। यह बैंक के तुलन-पत्र में सुधार करने के लिए तथा अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के रूप में उनकी आरक्षित पूंजी को बढ़ाने के लिए किया गया है ताकि वे बैंकिंग विनियामक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा कर सकें।

चार्ट 7: विभिन्न देशों की व्यवस्था में बैंकों का पूंजीकरण, 2020



जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में नियामक टियर 1 पूंजी

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक, आईएमएफ, 2020

वित्तीय खातों में बैंक पुनःपूंजीकरण लागत को दर्ज करने के संबंध में, भारत सरकार ने पीएसबी में सरकार के बॉण्ड-वित्तपोषित इक्विटी हिस्सेदारी के मूल्य निर्धारण में अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का पालन किया था। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के नियमों द्वारा अधिदेशित लागू फार्मूले के अनुसार, बाजार मूल्य का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया गया था और इक्विटी का एक बड़ा आबंटन प्राप्त करने वाले पसंदीदा शेयरधारक के अनुरूप होने के कारण, पुनःपूंजीकरण को वित्तीय लेनदेन (आईएमएफ, 2018) के रूप में लाभ निकालने के बाद दर्ज किया गया था। फिर भी, भारत में समय-समय पर विशाल पुनःपूंजीकरण पैकेज के कार्यान्वयन के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय बैंक नियामक न्यूनतम पूंजी आवश्यकता से ऊपर रहते हैं; जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में से कई अर्थव्यवस्थाएँ भारत की तुलना में अपनी बैंकिंग प्रणालियों में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी के साथ काम करती हैं (चार्ट 7)।

पिछले कई वर्षों में भारत में हुए पुनःपूंजीकरण पैकेज में कुछ अनूठी वांछनीय विशेषताएँ थीं। मुख्य रूप से पुनःपूंजीकरण बॉण्ड जारी करने के माध्यम से वित्तपोषण करने की योजना बनाना, एक अवधि में साथ के राजकोषीय निहितार्थ में बड़ा नुकसान करते हुए पूंजी इंजेक्शन को शुरुआत में ही खर्च कर दिया गया। इसके अलावा, वार्षिक राजकोषीय घाटे में योगदान देने वाले ब्याज व्यय को छोड़कर सरकार के लिए पुनःपूंजीकरण

बॉण्ड की तरलता तटस्थ थी (सारणी 6)। यह कुछ वर्षों में सरकारी व्यय में वृद्धि (पूंजीगत व्यय में वृद्धि के माध्यम से) के अलावा है, जिसका कारण प्रमुख रूप से बैंक पुनःपूंजीकरण (सीएजी, 2020) का कार्यान्वयन है। अंत में, पुनःपूंजीकरण पैकेज को बैंक के कार्य निष्पादन के साथ जोड़ने से बाजार अनुशासन के आने की उम्मीद थी।

आगे बढ़ते हुए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा किए गए अग्रिमों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) का एक बड़ा योगदान होने के कारण, पुनःपूंजीकरण पर और उपायों की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि बैंकों में पूंजी के अंतःप्रवाह की आवश्यकता केवल नियामक दृष्टिकोण से ही नहीं है, बल्कि जब ऋण की मांग में और तेजी आती है तो बेहतर क्रेडिट उठाव

सारणी 6: बजट पर पुनःपूंजीकरण का भार

	संक्षिप्त (रिफ़ैप) बॉण्ड पर बैंकों को दिए गए ब्याज (₹ करोड़)	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	संक्षिप्त बॉण्ड पर दिये गए ब्याज प्रतिशत में	
			जीडीपी	कुल बजट व्यय
1	2	3	4	5
2018-19	5,800.6	3.4	0.03	0.25
2019-20	16,286.0	4.6	0.08	0.61
2020-21 (आरई)	19,292.8	9.5	0.10	0.56
2021-22 (बीई)	19,292.8	6.8	0.09	0.55

स्रोत: विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेज़।

के माध्यम से वृद्धि के निधीयन के दृष्टिकोण से भी है। साथ ही, पीएसबी का पुनःपूँजीकरण और निजीकरण को साथ-साथ करने की जरूरत है। भारत सरकार द्वारा 2017 के बाद से अपनाए गए विलय और समामेलन पहल जैसे कार्यनीतिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 7 बड़े और 5 लघु पीएसबी (2017 में कुल 27 पीएसबी के बाद से) बने हैं। विलय और समामेलन के उपाय (अशोध्य ऋण और क्षेत्रीय कारकों पर आधारित) का उद्देश्य पूँजी का अधिक प्रभावी तरीके से प्रबंधन करना था। परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवाओं को बढ़ाने के लिए अभिशासन-सुधार और कार्य योजनाएँ, पुनःपूँजीकरण पैकेज के अभिन्न अंग हैं। इसके अलावा, विलय और समामेलन के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि समेकित इकाई अच्छी तरह से पूँजीकृत हो। केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुसार, भविष्य में दो और पीएसबी के निजीकरण का प्रस्ताव है और साथ ही, बैंकिंग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों का विनिवेश बैंकिंग प्रणाली में दक्षता को बढ़ावा देने में योगदान दे सकता है।

सी. पारदर्शिता

राजकोषीय पारदर्शिता सार्वजनिक वित्त की अतीत, वर्तमान, और भविष्य की स्थिति पर सार्वजनिक रिपोर्टिंग की व्यापकता, स्पष्टता, विश्वसनीयता, समयबद्धता और प्रासंगिकता को संदर्भित करती है। यह न केवल बजटीय प्रथाओं को मजबूत करने और जवाबदेही में सुधार करने में मदद करता है बल्कि सरकार की विश्वसनीयता और बाजार के विश्वास में भी सुधार करता है। आईएमएफ का वित्तीय पारदर्शिता कोड, 2014 सार्वजनिक वित्त के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मानक है। इसमें चार स्तंभों

के तहत सिद्धांतों का एक सेट शामिल है, जैसे राजकोषीय रिपोर्टिंग, राजकोषीय पूर्वानुमान और बजट, वित्तीय जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन, और संसाधन राजस्व प्रबंधन। इस कोड के तहत पहला सिद्धान्त राजकोषीय रिपोर्टों का कवरेज है, जो राजकोषीय रिपोर्टिंग प्रथाओं को बुनियादी, अच्छे, और उन्नत के रूप में वर्गीकृत करता है (चार्ट 8)।

पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने केन्द्रीय बजट में अपनी अतिरिक्त बजटीय गतिविधियों को स्वीकार करने/शामिल करने के उपायों को अपनाया है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना है और पारदर्शिता और क्षमता बढ़ाने में काफी आगे तक ले जाना है। इनमें शामिल हैं:

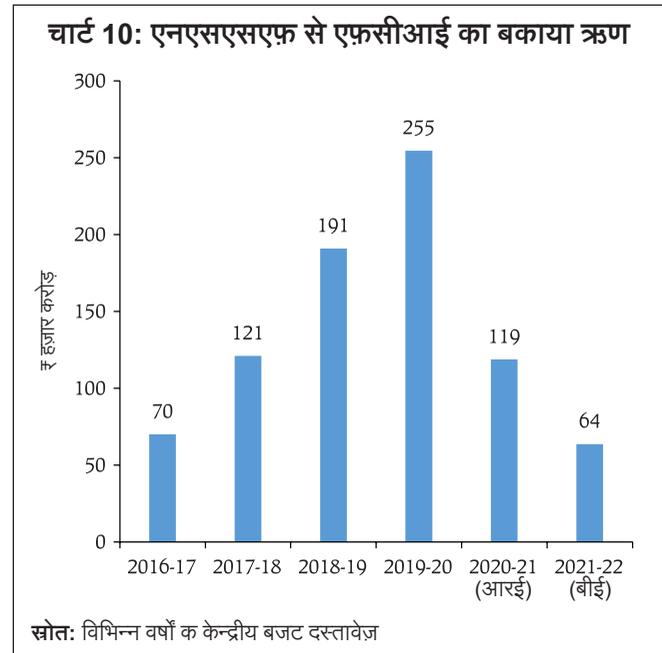
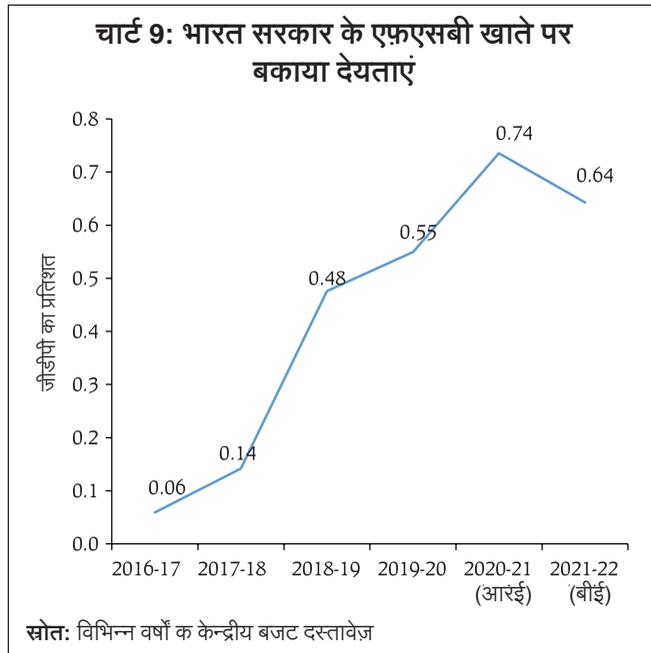
सबसे पहले, भारत सरकार-पूरी तरह से सेवित बॉण्ड (भारत सरकार-एफएसबी) जारी करने के माध्यम से सीपीएसई द्वारा जुटाये गए अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों (ईबीआर) का प्रकटीकरण। 2016-17 के बाद से, कुछ सीपीएसई को भारत सरकार-एफएसबी जारी करने की अनुमति है, जिसके लिए पूरे मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। जबकि भारत सरकार-एफएसबी के माध्यम से जुटाई गयी राशि का उपयोग बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों (जैसे स्वच्छ भारत मिशन, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, कई अन्य योजनाओं के बीच) में किया जाता है, ये उधार और व्यय बजट के बाहर रहते हैं।

जबकि, केन्द्रीय बजट 2019-20 में ईबीआर के कारण देनदारियों को पहली बार स्वीकार किया गया था, पाँच सालों के समय में ईबीआर स्टॉक में वृद्धि को शून्य करने के लक्ष्य के साथ। 2020-21 से, सरकार ने केन्द्रीय बजट दस्तावेजों में भारत

चार्ट 8: राजकोषीय विवरण की प्रथाएं

बुनियादी	अच्छा	उन्नत
राजकोषीय विवरण (रिपोर्ट) केंद्र सरकार की सभी संस्थाओं, जिसमें न केवल मंत्रालय शामिल हैं बल्कि अन्य कार्यकारी एजेंसियां जो बजट में हैं, साथ ही अतिरिक्त बजट गतिविधियों को भी समेकित करता है।	राजकोषीय विवरण (रिपोर्ट) सभी सामान्य सरकारी संस्थाओं को समेकित करता है जिसमें केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारें शामिल हैं।	राजकोषीय विवरण (रिपोर्ट) समेकित करता है सभी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को, जिसमें सामान्य सरकार तथा उनके स्वामित्व और नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक निगम शामिल हैं।

स्रोत: राजकोषीय पारदर्शिता पुस्तिका, आईएमएफ, 2018.



सरकार-एफएसबी के माध्यम से जुटाये गए संसाधनों के योजनावार उपयोग का विवरण प्रकाशित करना शुरू कर दिया है (चार्ट-9)।

दूसरे, 2016-17 से, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्य सब्सिडी के बदले राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से ऋण प्रदान करने की प्रथा का सहारा लिया। केंद्रीय बजट 2021-22 में वार्षिक खाद्य सब्सिडी के एक बड़े हिस्से को ऑफ-बजट करने की इस प्रथा को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि, खाद्य सुरक्षा प्रणाली में और सुधारों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, सरकार ने 2020-21 (आरई) और 2021-22 (बीई) में खाद्य सब्सिडी के लिए एक बढ़ा हुआ परिव्यय भी प्रदान किया है, जिससे एफसीआई की बकाया राशि इस वर्ष के अंत तक ₹2.55 लाख करोड़ के शिखर से घटकर ₹1.19 लाख करोड़ और 2021-22 तक और भी घटकर ₹64,000 करोड़ होने की उम्मीद है (चार्ट-10)।

अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों के प्रकटीकरण और एनएसएसएफ को एफसीआई बकाया के बजट पर, केंद्र ने राजकोषीय रिपोर्टिंग प्रथाओं में सुधार की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं। एक व्यापक सामान्य सरकारी डेटाबेस तैयार करने की दिशा में काम करना भी आवश्यक है, जिसमें सरकार

के सभी स्तरों के लिए अतिरिक्त बजटीय डेटा के साथ स्थानीय सरकारों के वित्तीय डेटा शामिल होंगे। इस संबंध में अगली चुनौती यू.के.⁹ में सम्पूर्ण सरकारी खातों (डबल्यूजीए) की तर्ज पर व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र के आंकड़ों पर पहुँचने के लिए सामान्य सरकारी डेटा के साथ सीपीएसई के डेटा को समेकित करना होगा।

डी. बाज़ार उधार और ऋण गतिशीलता

2020-21(आरई) के ₹12,80,000 करोड़ की तुलना में 2021-22 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाज़ार उधार का बजट ₹12,05,500 करोड़ किया गया है। केंद्र सरकार फरवरी-मार्च, 2020-21 के दौरान अतिरिक्त ₹80,000 करोड़ रुपये जुटा रही है। बाज़ार उधारी के अलावा, जो कि केंद्र की जीएफडी की प्रमुख वित्तीय मद बनी हुई है, एनएसएसएफ जीएफडी के लगभग 26 प्रतिशत के लिए वित्तपोषण लेखांकन के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है (अनुबंध III चार्ट 11ए)। एक उल्लेखनीय परिवर्तन जो इस बजट में है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एनएसएसएफ तक पहुँच की प्रथा को समाप्त

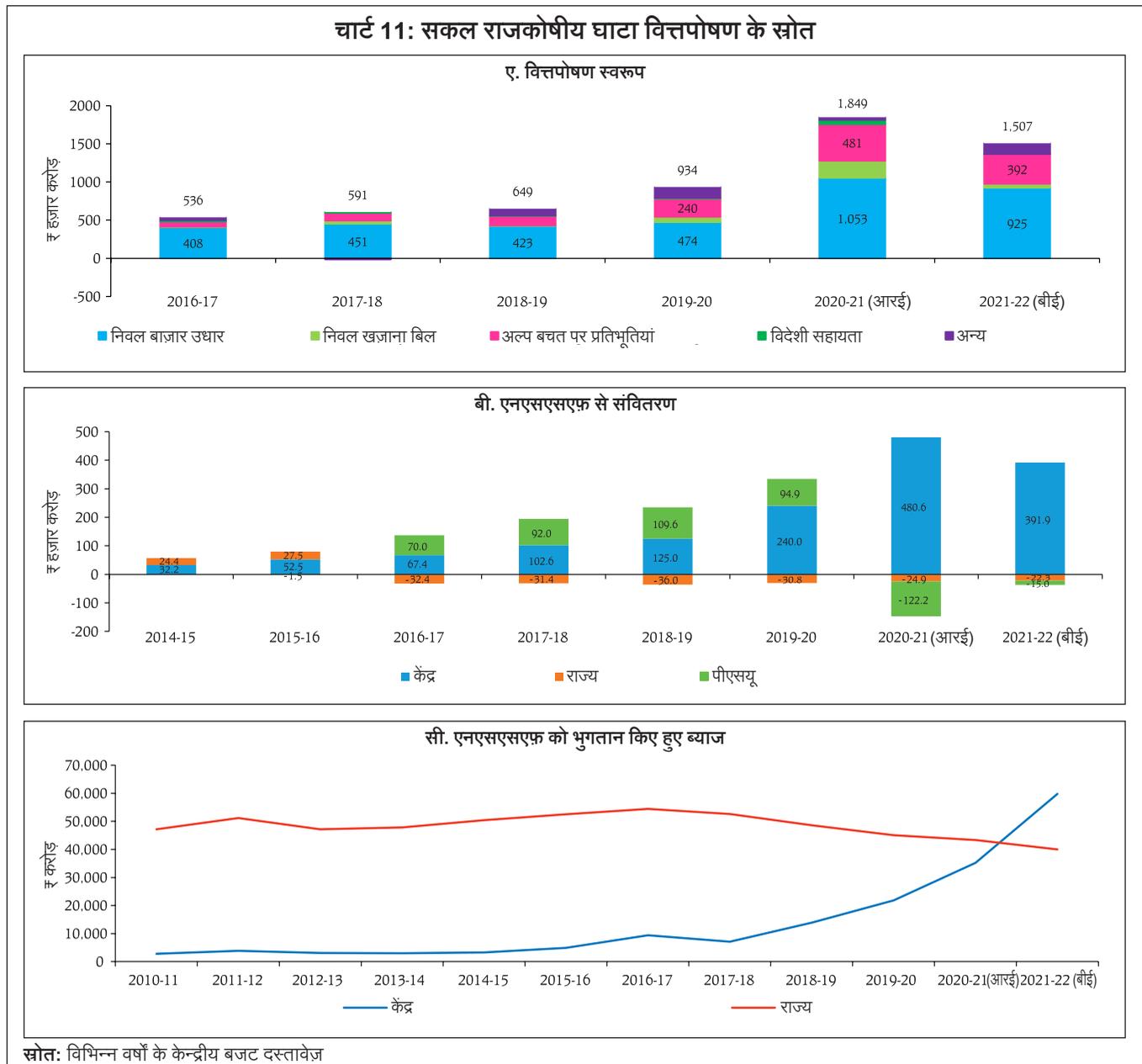
⁹ यह विश्व स्तर पर प्रकाशित लेखापरीक्षित समेकित खातों के सबसे व्यापक सेट में से एक है, जिसमें यूके में सार्वजनिक क्षेत्र की 5,500 इकाइयां शामिल हैं।

करने की परिकल्पना की गयी है, जैसा कि 2015-16 के बाद हुआ था (चार्ट 11 बी)। राज्यों ने पहले मुख्य रूप से एफसी-XIV द्वारा अनुशंसित उच्च ब्याज लागत के कारण एनएसएसएफ की अपनी बकाया देनदारियों को उत्तरोत्तर कम कर दिया था। इसे दर्शाते हुए, जबकि राज्यों के एनएसएसएफ उधारों के कारण ब्याज व्यय घट रहा है, केंद्र के लिए यह बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है (चार्ट 11सी)। एनएसएसएफ के उधार में किसी भी कमी को बाज़ार उधार से पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। 5

फरवरी, 2021 को जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य के माध्यम से, लगातार दूसरे वर्ष के लिए बड़े बाज़ार उधार और हाल के महीनों में वैश्विक बॉण्ड की बिक्री के बीच, रिज़र्व बैंक ने आश्वासन दिया है कि वह बाज़ार उधार कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से पूरा करना सुनिश्चित करेगा।

5 फरवरी, 2021 को जारी नीति वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक और केंद्र ने खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में ऑनलाइन पहुँच प्रदान करने का प्रस्ताव पेश किया-

चार्ट 11: सकल राजकोषीय घाटा वित्तपोषण के स्रोत



प्राथमिक और द्वितीयक दोनों सीधे रिज़र्व बैंक ('खुदरा प्रत्यक्ष') के माध्यम से। इस कदम से निवेशक आधार का विस्तार होने की उम्मीद है और खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में भाग लेने के लिए बढ़ी हुई पहुँच प्रदान करने की उम्मीद है। यह एक प्रमुख ढांचागत सुधार है जो भारत को कुछ चुनिंदा देशों में रखता है जिनके पास समान सुविधाएं हैं। यह 2021-22 में सरकारी उधार कार्यक्रम को सुचारु रूप से पूरा करने में भी मदद करेगा।

2020-21 में उच्च उधारी के कारण, केंद्र का कर्ज़-जीडीपी अनुपात बढ़कर 64.3 प्रतिशत (2020-21 बीई में 50.6 प्रतिशत) हो गया, जिसमें ईबीआर (तालिका 7) भी शामिल है। राज्यों के कर्ज़-जीडीपी अनुपात को जोड़ने पर, सामान्य सरकार का कर्ज़ 90 फीसदी को पार करने की उम्मीद है। जैसा कि केंद्र 2021-22 में शुद्ध उधारी को कम करने की योजना बना रहा है, ऋण-जीडीपी अनुपात 62.5 प्रतिशत से कम होने की उम्मीद है, जिसमें ईबीआर के लिए 0.6 प्रतिशत शामिल है। इसके अलावा, भले ही राज्यों की उधार सीमा बढ़ा दी गयी है, आर्थिक गतिविधियों में अपेक्षित सामान्यीकरण राज्यों को 2021-22 में कर्ज़ कम करने के लिए प्रेरित करेगा; इसे सामान्य सरकारी ऋण को 90 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए। पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ़सी-XV) ने 1 फरवरी 2021 को जारी अपनी रिपोर्ट में केंद्र और सामान्य सरकार के लिए कर्ज़ पथ की सिफ़ारिश की है। कोविड-19 से संबंधित अनिश्चितता के कारण, केंद्र ने आर्थिक विकास और राजकोषीय चर, साथ ही वापसी पथ की विशिष्टता के पूर्वानुमान को चुनौतीपूर्ण पाया है। हालांकि, यह कहा गया है कि जैसे ही आर्थिक विकास और प्राप्तियाँ अपने दीर्घकालीन औसत पर लौटती हैं, राजकोषीय समेकन की स्थिति में लौट आना है।

सारणी 7: केंद्र सरकार का बकाया कर्ज़

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

	कर्ज़	जिनमें से ईबीआर
1	2	3
2018-19	49.6	0.5
2019-20	52.3	0.6
2020-21 (आरई)	64.3	0.7
2021-22 (बीई)	62.5	0.6

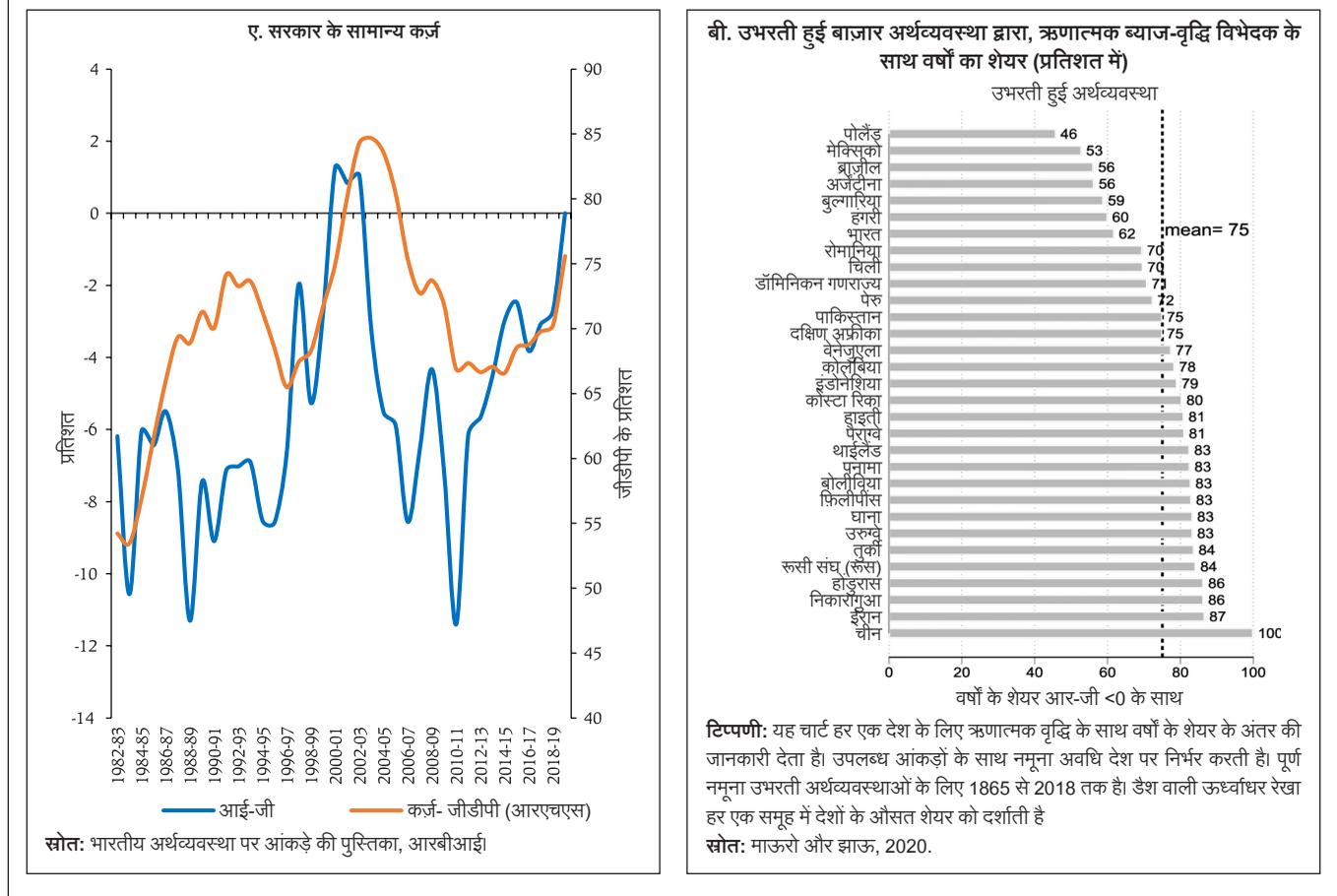
स्रोत: विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेज़; और आरबीआई स्टाफ के आंकड़ों के अनुसार।

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, ने यह संदेश दिया कि विकास कर्ज़ स्थिरता की ओर ले जाता है, और उधार की लागत (आर) और आर्थिक विकास (जी) के बीच एक नकारात्मक अंतर एक स्वस्थ संकेत है। सामान्य सरकार के ब्याज दर- जीडीपी विकास अंतर (आर-जी) के दीर्घकालिक विश्लेषण से पता चलता है कि यह, आमतौर पर, 2000-01 से 2002-03 को छोड़कर पिछले चार दशकों में भारत में नकारात्मक रहा (चार्ट 12ए)¹⁰। 'आर-जी' की यह विशेषता ब्याज दर में बदलाव के बजाय जीडीपी विकास दर में बदलाव के कारण थी (जीओआई-2021)। इसके अलावा, देशों में नकारात्मक ब्याज-विकास अंतर सभी स्तरों पर विकास में आम है (चार्ट 12बी) (मौरो और झाऊ, 2020)। साथ ही, स्पष्ट है कि एशियाई वित्तीय संकट के दौरान और बाद में टेपर टैट्रम अवधि के दौरान भारत में 'आरजी' धीरे-धीरे कम और नकारात्मक हो गया, कर्ज़-जीडीपी अनुपात में लगातार वृद्धि हुई, इस प्रकार, यह दर्शाता है कि केवल 'आर-जी' की कीमत ही नहीं बल्कि इसकी प्रवणता भी कर्ज़ स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। आर और जी के बीच का अंतर, जो महामारी के पहले भी 2019-20 में शून्य के करीब था, 2020-21 में सकारात्मक होने की संभावना है- मुख्य रूप से जीडीपी में तेज़ संकुचन और कम स्थिर ब्याज दर के कारण। 2020-21 में जीडीपी वृद्धि में गिरावट, हालांकि, अस्थायी है और उच्च जीडीपी वृद्धि (2021-22 के लिए दोहरे अंकों में) आगे जाकर स्थिति को उलट देगी ऐसी संभावना है।

'आर-जी' के अलावा जो अनिवार्य रूप से कर्ज़ के स्टॉक का काम करता है, प्राथमिक शेष राशि का प्रवाह भी कर्ज़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक उच्च प्राथमिक घाटा (पीडी) कर्ज़ के उच्च स्टॉक और ब्याज भुगतान में वृद्धि की ओर जाता है, जैसे दिया गया है 'आर-जी'। यह उत्पादक दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के लिए खर्च करने के लिए स्थान को कम करता है और भविष्य के राजस्व सृजन को पिछले कर्ज़ को चुकाने के लिए बाध्य करता है। इसलिए, नकारात्मक (सकारात्मक) 'आर-जी' अंतर में वृद्धि (गिरावट) से लाभ प्राथमिक घाटे में वृद्धि के

¹⁰ जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 (खंड I, कर्ज़ स्थिरता पर अध्याय) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर वार्षिक भारित औसत ब्याज दर का उपयोग सामान्य सरकार के लिए उधार लेने की लागत की गणना के लिए 'आर' के रूप में करता है, यह विश्लेषण सामान्य सरकार के लिए अवधि 'टी' के लिए ब्याज भुगतान का उपयोग अवधि 'टी-1' के लिए बकाया ऋण से विभाजित करके डोमर स्थिति की जांच के लिए 'आर' के रूप में करता है।

चार्ट 12: ब्याज दर- जीडीपी वृद्धि विभेदक



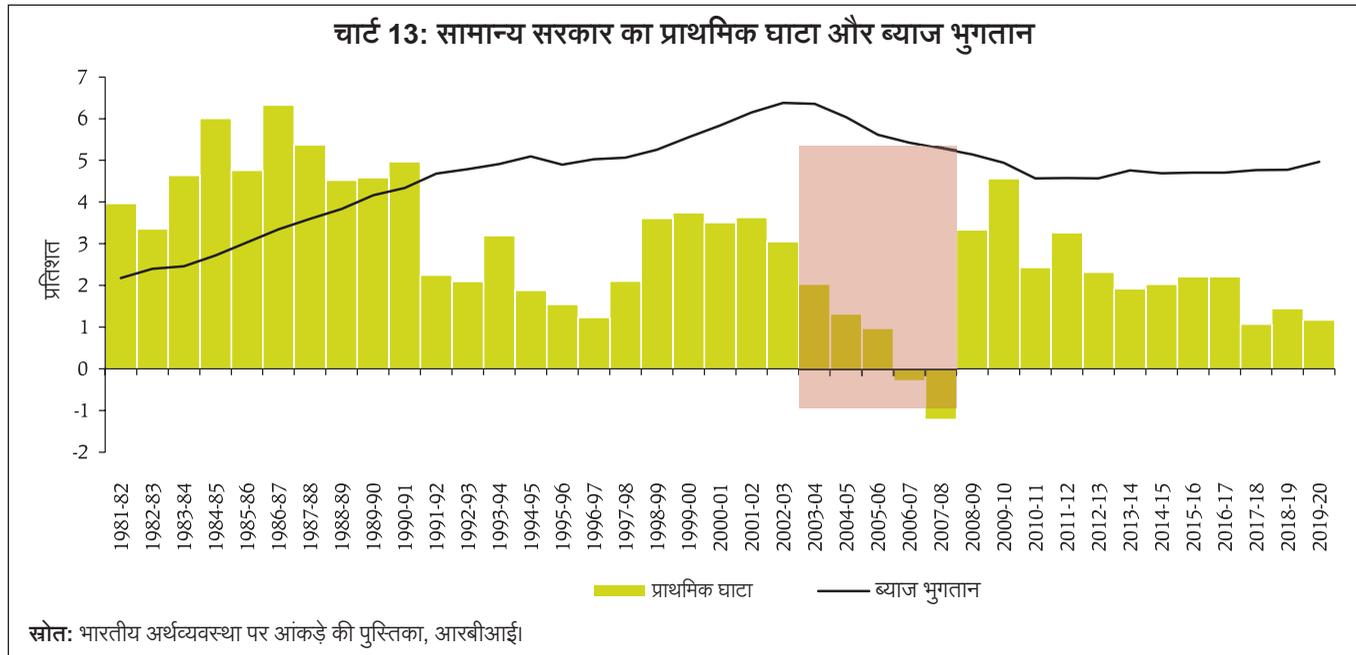
समायोजन से अधिक होता है। चूंकि भारत का प्राथमिक संतुलन घाटे में था, इसलिए 2002-03 तक जीडीपी के अनुपात में ब्याज भुगतान में लगातार वृद्धि हुई (चार्ट 13)। उसके बाद, राजकोषीय समेकन के परिणामस्वरूप, उच्च प्राथमिक घाटे को अधिशेष में बदलने से अनुपात में तेज़ी से गिरावट आयी। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद घाटे की प्रवृत्ति फिर से प्रतिध्वनित हुई। 2020-21 के दौरान, प्राप्ति में बहिर्जात रूप से संचालित संकुचन और राजस्व खाते पर खर्च में वृद्धि के कारण केंद्र के प्राथमिक संतुलन में गिरावट आयी, हालांकि 2021-22 के लिए कम घाटा बजट में है।

उच्च ऋण/प्राथमिक घाटे के जोखिम के बावजूद, मध्यम से दीर्घावधि में ऋण/प्राथमिक घाटा की गुणवत्ता मायने रखती है। 'सुनहरे नियम' के अनुसार, राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्ति से पूरा किया जाना चाहिए, और उधार को पूंजीगत व्यय के लिए

निर्देशित किया जाना चाहिए। भारत में, हालांकि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से पूंजीगत व्यय के लिए राजस्व व्यय का अनुपात घट रहा है, राजस्व संतुलन हमेशा घाटे में था, और इसलिए, उधार का हिस्सा राजस्व व्यय की ओर बढ़ गया। जहां राजस्व व्यय के तहत कुछ खर्च अनिवार्य है, वहीं कुछ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सुचारु या कुशल कामकाज के लिए भी आवश्यक हैं। इसलिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा राजस्व और पूंजी का सही मिश्रण तैयार करने की आवश्यकता है। व्यय की गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने से विकास का समर्थन करते हुए राजकोषीय स्थिरता के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी (दास, 2021)।

जैसा कि पहले कहा गया है, जबकि वर्तमान महामारी के प्रतिकूल प्रभाव ने केंद्र सरकार का ध्यान राजस्व व्यय जैसे कि स्वास्थ्य, भोजन, पीएम किसान और मनरेगा के तहत हस्तांतरण

चार्ट 13: सामान्य सरकार का प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान



पर खर्च करना आवश्यक बना दिया है, वित्तीय पारदर्शिता और 2020-21 में पूंजीगत व्यय पर अधिक खर्च कल्याणकारी और आवश्यक थे। इसलिए, जबकि केंद्र की वर्तमान उच्च उधारी और परिणामी उच्च कर्ज का उद्देश्य सामाजिक कल्याण को बढ़ाना और जीडीपी की वृद्धि में सुधार को बनाए रखना है, संरचनात्मक सुधारों के साथ बढ़ी हुई वित्तीय पारदर्शिता और व्यय की गुणवत्ता कर्ज स्थिरता में मदद कर सकती है।

ई. वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों के लिए हस्तांतरण और निहितार्थ

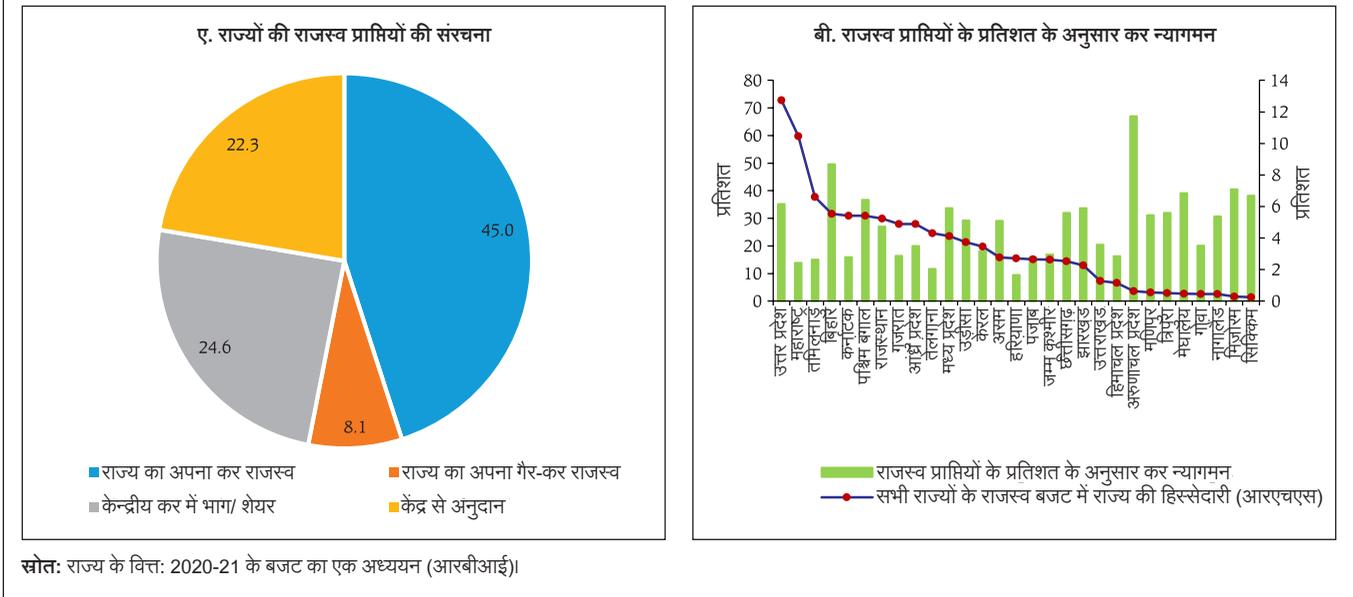
2020-21 में केंद्र से राज्यों को संसाधनों का शुद्ध हस्तांतरण बजटीय राशि की तुलना में संशोधित अनुमानों में 5.6 प्रतिशत कम है। संशोधित अनुमानों में राजस्व खातों के हस्तांतरण में 15.1 प्रतिशत की कमी आयी है क्योंकि कर हस्तांतरण में तेज़ गिरावट देखी गयी (29.9 प्रतिशत), आंशिक समायोजन उच्च राजस्व घाटा अनुदान और योजना संबंधी हस्तांतरण के कारण हुआ। राजस्व खाता हस्तांतरण में इस तेज़ कमी को देखते हुए, राज्यों के संसाधनों को जीएसटी मुआवज़े की कमी और पूंजीगत व्यय के लिए विशेष ऋण सहायता के लिए एक के बाद एक ऋण के रूप में अतिरिक्त ऋण के माध्यम से बढ़ाने की मांग की गयी है। जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के लिए एक के बाद एक ऋण एक

वित्तपोषण व्यवस्था है जिसके द्वारा केंद्र बाज़ार से राशि उधार लेता है और राज्यों को उधार देता है; इस प्रकार, केंद्र के लिए घाटा तटस्थ रहता है। 2021-22 में, कर हस्तांतरण का बजट 2019-20 के स्तर के करीब वसूली के लिए है, जबकि राजस्व घाटा अनुदान एफ़सी-XV की सिफारिशों के बाद उल्लेखनीय रूप से बढ़ने का बजट है (अनुबंध IV)।

एफ़सी-XV ने व्यापक रूप से सम्पूर्ण पुरस्कार अवधि के लिए सीधे हस्तांतरण हिस्सेदारी के साथ-साथ राज्यों में प्रगति की क्षैतिज डिग्री को बनाए रखने की कोशिश की है। हस्तांतरण के समग्र पूल में अनुदान की बढ़ती हिस्सेदारी, जो विभाज्य पूल के प्रतिशत के बजाय एक निश्चित राशि के रूप में आबंटित की जाती है, निधि प्रवाह की मात्रा और समय की भविष्यवाणी को जोड़ती है, इस प्रकार राजस्व अनिश्चितता को कम करती है। इसके अतिरिक्त, जबकि एफ़सी-XV द्वारा अनुशंसित अधिकांश क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान बजट में प्रदान नहीं किए गए हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र के अनुदानों को पेश किया गया है (अनुबंध V)।

राज्यों के वित्त की बात करें तो केन्द्रीय बजटों का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि केंद्र से उच्च स्तर की राजस्व

चार्ट 14: राज्यों की अंतरण पर राजस्व निर्भरता 2020-21 (बीई)



निर्भरता होती है। सभी राज्यों को मिलाकर, केंद्र से हस्तांतरण राजस्व प्राप्तियों का 46.9 प्रतिशत है, मोटे तौर पर 2020-21 (बीई) में कर हस्तांतरण और अनुदान के बीच समान रूप से विभाजित है (चार्ट 14ए)। जबकि केन्द्रीय बजट के 2020-21 (आरई) में अनुदान के रूप में हस्तांतरण को व्यापक रूप से बनाए रखा गया है, राज्यों के अपने करों में संभावित चक्रीय कमी के साथ-साथ कर हस्तांतरण में भारी कमी, ऐसी उम्मीद की गयी कि 2020-21 के राज्यों के बजट के संशोधित अनुमानों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। स्रोत से निर्भरता के विभिन्न स्तरों को देखते हुए, राज्यों में कम कर हस्तांतरण का प्रभाव असममित होने की उम्मीद है। बड़े राज्यों में (उनके राजस्व बजट के आकार के अनुसार) उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में कर पर अत्यधिक निर्भरता है (चार्ट 14बी)।

निष्कर्ष

केन्द्रीय बजट 2021-22, भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सदी में एक बार के संकट के लिए प्रदर्शित लचीलेपन पर बैंकिंग ने अपना ध्यान उच्च पूंजीगत व्यय और विभिन्न सुधारों के माध्यम से मध्यम-अवधि की विकास क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया है जो कि सरकार के वित्त वर्ष 2020-21

में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और महामारी से उबरने के ध्यानकेंद्रण के लिए है। ऐसा करते हुए, बजट नाज़ुक परिस्थितियों से गुजरता है, विकास पुनरुद्धार के लिए प्रति-चक्रीय समर्थन प्रदान करते हुए धन की कमी को कम करने के तरीकों की खोज करता है। यह बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व की उछाल को बढ़ाकर, और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और भूमि के साथ-साथ रणनीतिक विनिवेश सहित परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से प्राप्तियों को बढ़ाकर बजटीय व्यय के वित्तपोषण की दिशा में प्रयास करता है।

सरकार द्वारा बढ़ाए गए पूंजीगत व्यय निवेश से न केवल निजी निवेश में भीड़ होगी बल्कि रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने और आत्मविश्वास में सुधार के साथ, एहतियाती बचत कम होने की उम्मीद है। बुनियादी ढांचे के विकास और स्वास्थ्य सेवा पर नए सिरे से ज़ोर विकास के लिए शुभ संकेत होगा। एमएसएमई जैसे कठिन क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ घरेलू विनिर्माण पर ज़ोर, निर्यात और रोजगार को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित उपाय जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण, पुनर्पूजीकरण के लिए आबंटन और बीमा में एफडीआई सीमा में वृद्धि उल्लेखनीय और प्रगतिशील है।

अंत में, एफ़सी-XV के आधार पर, अगले कार्यकाल में राज्यों को अधिक छूट देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तुलना में पूंजीगत व्यय पर अधिक खर्च करती हैं। एक और सकारात्मक पहलू गैर-विवेकाधीन बजट में बजट के बाहर व्यय के संबंध में पारदर्शिता, जिसे बाजारों द्वारा भी अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है। जबकि सरकार द्वारा प्रदान किया गया राजकोषीय गणित यथोचित यथार्थवादी प्रतीत होता है, केंद्र सरकार के खर्च में ब्याज लागत जैसी गैर-विवेकाधीन वस्तुओं का प्रभुत्व चिंता का विषय है। हालांकि राजकोषीय सुदृढीकरण का रास्ता बढ़ाया गया है, लेकिन बजट में प्रस्तावित उपायों को अगर अच्छी तरह से लागू किया जाता है, तो यह इसके इरादे और उद्देश्यों को साकार करने में मदद कर सकता है, और मध्यम अवधि में उच्च विकास प्राप्त करने में खेल परिवर्तक हो सकता है।

संदर्भ

- Andrews, M. (2003), "Issuing government bonds to finance bank recapitalisation and restructuring: Design factors that affect banks' financial performance", IMF Policy Discussion Paper, November.
- Bova, E., Dippelsman, R., Rideout, K., and Schaechter, A. (2013), "Another look at governments' balance sheets: The role of non-financial assets", IMF Working Paper, No. 13/95.
- Comptroller and Auditor General of India (2020), "Accounts of the Union Government for the year 2018-19", Report No.4.
- Fedelino, A., Horton, M., and Ivanova, A. (2009), "Computing cyclically-adjusted balances and automatic stabilisers", Technical Notes and Manuals, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, Vol. 2009, pp. 1-12, December.
- Gambarcota, L., and Simonov, A. (2016), "Why bank capital matters for monetary policy", BIS Working Paper, No. 558, April.
- Government of India (2019), "Asset monetisation: Procedures and mechanism thereof", Department of Investment and Public Asset Management, Office Memorandum F.No.3/3/2018/DIPAM-II.
- (2020), Report of the Fifteenth Finance Commission, Ministry of Finance.
- (2020), Press Information Bureau, Release ID: 1664833, Special Window to States for meeting the GST Compensation Cess shortfall, October.
- (2021), "Chapter 2: Does Growth Lead to Debt Sustainability? Yes, But Not Vice-Versal", Economic Survey 2020-21, January.
- International Monetary Fund (2018), Fiscal Transparency Handbook, April.
- (2018), Article IV Consultation, IMF Country Report, No. 18/254, August.
- Kant, A (2021), Effective Asset Monetisation Can Help Create Substantial Fiscal Impact, World-Class Infrastructure in India; Financial Express, January 5.
- Mauro, P., and Zhou, J. (2020), "r-g<: Can we sleep more soundly?", IMF Working Paper, March.
- Muduli, S., and Behera, H. (2020), "Bank capital and monetary policy transmission in India", RBI Working Paper Series, No. 12, October.
- Reserve Bank of India (2020), State Finances: A Study of Budgets of 2020-21, October.
- (2020), Report of the Internal Working Group to Review Extant Ownership Guidelines and Corporate Structure for Indian Private Sector Banks, November.
- (2021), Towards a Stable Financial System, Nani Palkhivala Memorial Lecture delivered by Shri. Shaktikanta Das, RBI Bulletin, February.
- Verma, R. and Herwadkar, S. (2019), "Bank recapitalisation and credit growth: The Indian case", MPRA Paper No. 97394, December.

अनुबंध I: केन्द्रीय बजट 2020-21: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

	करोड़ में					जीडीपी के प्रतिशत		वृद्धि दर	
	2018-19	2019-20	2020-21 (बीई)	2020-21 (आरई)	2021-22 (बीई)	2020-21 (आरई)	2021-22 (बीई)	2020-21 (आरई)	2021-22 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. प्रत्यक्ष कर	11,36,615	10,49,549	13,19,000	9,05,000	11,08,000	4.6	5.0	-13.8	22.4
(i) निगम	6,63,572	5,56,876	6,81,000	4,46,000	5,47,000	2.3	2.5	-19.9	22.6
(ii) आय	4,61,488	4,80,398	6,25,000	4,47,000	5,48,500	2.3	2.5	-7.0	22.7
2. अप्रत्यक्ष कर	9,43,850	9,60,510	11,04,020	9,95,280	11,09,059	5.1	5.0	3.6	11.4
(i) जीएसटी	5,81,559	5,98,749	6,90,500	5,15,100	6,30,000	2.6	2.8	-14.0	22.3
(ii) कस्टम/ सीमा शुल्क	1,17,813	1,09,283	1,38,000	1,12,000	1,36,000	0.6	0.6	2.5	21.4
(iii) एक्साइज/ उत्पाद शुल्क	2,31,982	2,40,615	2,67,000	3,61,000	3,35,000	1.9	1.5	50.0	-7.2
3. सकल कर राजस्व (1+2)	20,80,465	20,10,059	24,23,020	19,00,280	22,17,059	9.8	9.9	-5.5	16.7
4. राज्यों को समनुदेशन	7,61,454	6,50,677	7,84,181	5,49,959	6,65,563	2.8	3.0	-15.5	21.0
5. एनसीसीडी अंतरण	1,800	2,480	2,930	5,820	6,100	0.0	0.0	134.7	4.8
6. शुद्ध कर राजस्व (3-4-5)	13,17,211	13,56,902	16,35,909	13,44,501	15,45,397	6.9	6.9	-0.9	14.9
7. गैर कर राजस्व	2,35,705	3,27,157	3,85,017	2,10,653	2,43,028	1.1	1.1	-35.6	15.4
(i) लाभांश और लाभ	1,13,421	1,86,133	1,55,395	96,544	1,03,538	0.5	0.5	-48.1	7.2
(ii) ब्याज प्राप्तियाँ	12,145	12,349	11,042	14,005	11,541	0.1	0.1	13.4	-17.6
8. राजस्व प्राप्तियाँ (6+7)	15,52,916	16,84,059	20,20,926	15,55,153	17,88,424	8.0	8.0	-7.7	15.0
9. गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ	1,12,779	68,620	2,24,967	46,497	1,88,000	0.2	0.8	-32.2	304.3
(i) विनिवेश प्राप्तियाँ	94,727	50,304	2,10,000	32,000	1,75,000	0.2	0.8	-36.4	446.9
(ii) ऋण की उगाही	18,052	18,316	14,967	14,497	13,000	0.1	0.1	-20.9	-10.3
10. कुल प्राप्तियाँ (उधार छोड़कर) (8+9)	16,65,695	17,52,680	22,45,893	16,01,650	19,76,424	8.2	8.9	-8.6	23.4
11. राजस्व व्यय	20,07,399	23,50,604	26,30,145	30,11,142	29,29,000	15.5	13.1	28.1	-2.7
(i) ब्याज भुगतान	5,82,648	6,12,070	7,08,203	6,92,900	8,09,701	3.6	3.6	13.2	16.9
(ii) प्रमुख सब्सिडी	1,96,769	2,28,341	2,27,794	5,95,620	3,36,439	3.1	1.5	160.8	-43.5
खाद्य	1,01,327	1,08,688	1,15,570	4,22,618	2,42,836	2.2	1.1	288.8	-42.5
खाद	70,605	81,124	71,309	1,33,947	79,530	0.7	0.4	65.1	-40.6
पेट्रोल	24,837	38,529	40,915	39,055	14,073	0.2	0.1	1.4	-64.0
12. पूंजी व्यय (i+ii)	3,07,714	3,35,726	4,12,085	4,39,163	5,54,236	2.3	2.5	30.8	26.2
(i) पूंजी परिव्यय	2,79,492	3,11,312	3,80,322	3,32,247	5,13,862	1.7	2.3	6.7	54.7
(ii) ऋण और अग्रिम	28,221	24,414	31,763	1,06,916	40,374	0.5	0.2	337.9	-62.2
13. कुल व्यय (11+12)	23,15,113	26,86,330	30,42,230	34,50,305	34,83,236	17.7	15.6	28.4	1.0
14. राजकोषीय घाटा (13-10)	6,49,417	9,33,651	7,96,337	18,48,655	15,06,812	9.5	6.8	98.0	-18.5

स्रोत: विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेज़।

अनुबंध II: बैंक पुनर्पूजिकरण- अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

देश	वर्ष	जारीकर्ता	ब्याज दर (प्रतिशत)	परिपक्वता (वर्ष)
1	2	3	4	5
भारत	1980-90s	सरकार	7.75-10	12
अल्जीरिया	1996	सरकार	10	20
क्रोएशिया	1996	बैंक के पुनर्वास के लिए एजेंसी	5	15
इक्वाडोर	1999	सरकार	बाजार से नीचे	3-5
हंगरी	1992	सरकार	91 दिनों के टी-बिल दर से जोड़ा हुआ	20, 25 और 30 वर्ष
तंज़ानिया	1992	सरकार	11	20
युगांडा	1996	सरकार	91 दिनों के टी-बिल दर से जोड़ा हुआ	1-5
पोलैंड	1991 और 1993-94	सरकार	1991-95: 6 महीने का एलआईबीओआर +2 प्रतिशत. From 1996: 6 महीने का एलआईबीओआर + 0.5 प्रतिशत 1993-94: केन्द्रीय बैंक के पुनर्भुनाए दर	1 और 15
इंडोनेशिया	1998	सरकार	12 प्रतिशत	3-10
मलेशिया	1998	बैंक पुनर्निर्माण एजेंसी	बाजार आधारित	एनए
मेक्सिको	1996	बैंक पुनर्निर्माण एजेंसी	91 दिनों के टी-बिल दर से जोड़ा हुआ	10
कोरिया	1998	केएएमसीओ (आस्ति प्रबंधन कंपनी)	परिवर्ती अमेरिकी डॉलर	एनए
स्पेन	2012	बैंक के व्यवस्थित पुनर्निर्माण के लिए निधि (एफआरओबी)	-	12.5 (औसत भारत परिपक्वता)
थाइलैंड	1999-00	सरकार	बाजार आधारित	10

एनए: उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: आईएमएफ और विश्व बैंक।

अनुबंध III: जीएफ़डी वित्तपोषण

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बीई)	2020-21 (आरई)	2021-22 (बीई)
1	2	3	4	5
सकल राजकोषीय घाटा	9,33,651 (100.0)	7,96,337 (100.0)	18,48,655 (100.0)	15,06,812 (100.0)
<i>द्वारा वित्तपोषित</i>				
निवल बाज़ार उधार	4,73,968 (50.8)	5,44,870 (68.4)	10,52,788 (56.9)	9,24,708 (61.4)
निवल खज़ाना बिल	70,103 (7.5)	25,000 (3.1)	2,25,000 (12.2)	50,000 (3.3)
अल्प बचत (निवल) पर प्रतिभूतियाँ	2,40,000 (25.7)	2,40,000 (30.1)	4,80,574 (26.0)	3,91,927 (26.0)
विदेशी सहायता	8,682 (0.9)	4,622 (0.6)	54,522 (2.9)	1,514 (0.1)
राज्य भविष्य निधि	11,635 (1.2)	18,000 (2.3)	18,000 (1.0)	20,000 (1.3)
आरक्षित निधि	10,411 (1.1)	2,978 (0.4)	-3,450 (-0.2)	5,051 (0.3)
जमा और अग्रिम	-14,227 (-1.5)	35,987 (4.5)	29,050 (1.6)	28,868 (1.9)
नकदी शेष की आहरण द्वारा कमी	4,971 (0.5)	-53,003 (-6.7)	-17,358 (-0.9)	71,383 (4.7)
अन्य	1,28,107 (13.7)	-22,117 (-2.8)	9,528 (0.5)	13,361 (0.9)

टिप्पणी: 1. निवल बाज़ार उधार में केवल दिनांकित प्रतिभूति द्वारा लिए गए उधार शामिल हैं।
 2. निवल खज़ाना बिल में 90-दिन, 182-दिन और 364-दिन के खज़ाना बिल द्वारा लिया गया उधार शामिल है।
 3. अन्य में शामिल है प्रतिभूतियों की वापस-खरीद, प्रतिभूतियों को बंद करना, बचत बॉण्ड, राहत बॉण्ड, आदि।
 कोष्ठक में दिये गए आंकड़े जीएफ़डी के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत: केन्द्रीय बजट 2021-22.

अनुबंध IV: पंद्रहवें वित्त आयोग की राज्यों से संबंधित प्रमुख सिफ़ारिशें

पंद्रहवें वित्त आयोग (अध्यक्ष : श्री एन. के. सिंह) की पूरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को जमा की गयी तथा 1 फरवरी 2021 को संसद के समक्ष रखी गयी। आयोग की 2021-26 की अवधि को कवर करने वाली सिफ़ारिशें नीचे दी गयी हैं:

कर हस्तांतरण

- राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले केन्द्रीय करों (विभाज्य पूल) का हिस्सा 42 प्रतिशत से घटकर 41 प्रतिशत हो गया, जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को आबंटित 1 प्रतिशत हिस्से के लिए समायोज्य है।
- राज्यों के बीच करों के परस्पर वितरण के लिए, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन मानदंड का प्रारम्भ किया गया उन राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए जिसने जनसंख्या वृद्धि पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाए हैं। वन आवरण मानदंड का भार बढ़ा दिया गया और कर प्रयास का एक नया मानदंड पेश किया गया। प्रति व्यक्ति आय दूरी का मानदंड हस्तांतरित करों में एक अकेले राज्य के हिस्से का निर्धारण करने में उच्चतम महत्व रखता है।

अनुदान सहाय

- हस्तांतरण के बाद राज्यों के राजस्व घाटे को कम करने, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण, आपदा राहत कोष में वृद्धि, क्षेत्र-विशिष्ट पहल और राज्य विशिष्ट जरूरतों के लिए अनुदान अनुशंसित किए गए। अनुदान में स्थानीय निकायों का शेयर सबसे ज्यादा था उसके बाद हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटे के लिए अनुदान था।
- स्थानीय निकायों को अनुदान प्राप्ति के लिए प्रवेश स्तर पर शर्तें, जिसमें राज्य वित्त आयोगों की स्थापना और राज्य विधानमंडल को मार्च 2024 के पहले इसके द्वारा की गयी कारवाई का ज्ञापन देना, स्थानीय निकायों के वित्तीय खातों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना और संपत्ति कर के लिए न्यूनतम मंजिल तय करना शामिल है (शहरी स्थानीय निकायों के लिए)।

- स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले अनुदान का 60 प्रतिशत स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल और जल संचयन के समर्थन और सुदृढीकरण से जुड़ा होना चाहिए।
- हस्तांतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान 2021-22 में 17 राज्यों के लिए अनुशंसित, 2025-26 में घटाकर 6 राज्यों तक लाना।
- स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कृषि, ग्रामीण सड़कें, आकांक्षी जिलों, न्यायपालिका और सांख्यिकी नामक आठ क्षेत्रों में क्षेत्र-विशिष्ट अनुदाना रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष (एमएफडीआईएस)।

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष (एमएफडीआईएस)

- बजटीय आवश्यकताओं और रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आबंटन के बीच की खाई को पाटने के लिए एमएफडीआईएस का भारत के सार्वजनिक खाते में एक समर्पित गैर-व्यपगत निधि के रूप में होना।

राजकोषीय रोडमैप

- अंतिम वर्ष (2025-26) जीडीपी के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार के लिए सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) का उन्नत पथ।
- राज्य सरकारों की निवल उधारी की सामान्य सीमा 2021-22 में जीएसडीपी का 4 प्रतिशत, 2022-23 में जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत और उसके बाद जीएसडीपी का 3 प्रतिशत तय की गयी। बिजली वितरण कंपनियों के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर सशर्त, 2021-22 से 2024-25 की चार साल की अवधि के दौरान जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त उधार के लिए स्थान।
- ऋण धारणीयता के मुद्दे की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह के साथ संघ और राज्य दोनों द्वारा एफआरबीएम अधिनियमों का पुनर्गठन आवश्यक है।

अनुबंध V: केंद्र से राज्य को सकल और निवल अंतरण

मदें	राजस्व/ पूंजी/ उधार	राशि (₹ '000 करोड़)				अनुमान में अंतर (प्रतिशत)		जीडीपी का प्रतिशत			
		2018-19	2019-20	2020-21 आरई	2021-22 बीई	2019-20 वास्तविक बनाम आरई	2020-21 आरई बनाम बीई	2018-19	2019-20	2020-21 आरई	2021-22 बीई
1. कर्षों में राज्यों के भाग का न्यायमन	राजस्व	761.5	650.7	550.0	665.6	-0.8	-29.9	4.0	3.2	3.3	3.5
2. वित्त आयोग अनुदान		93.7	123.7	182.4	220.8	0.0	21.6	0.5	0.6	0.6	0.7
ए. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	राजस्व	35.1	59.4	60.8	44.9	1.3	-13.1	0.2	0.3	0.3	0.3
बी. शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	राजस्व	14.4	25.1	25.0	22.1	-2.9	-16.7	0.1	0.1	0.1	0.1
सी. एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान	राजस्व	9.7	10.9	22.3	22.2	0.0	11.3	0.1	0.1	0.1	0.1
डी. उत्तर न्यायमन राजकोषीय घाटा अनुदान	राजस्व	34.6	28.3	74.3	118.5	0.0	147.8	0.2	0.1	0.1	0.1
ई. स्वास्थ्य के लिए क्षेत्र विशेष अनुदान	राजस्व	0.0	0.0	0.0	13.2	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
3. योजना संबंधित अंतरण		286.0	289.2	358.8	363.4	-10.3	6.8	1.5	1.6	1.5	1.5
ए. केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत	राजस्व	271.5	275.4	315.2	318.9	-2.7	6.8	1.4	1.4	1.4	1.3
बी. केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत	राजस्व	13.6	12.9	42.4	43.0	-66.3	7.4	0.1	0.2	0.1	0.2
सी. अन्य अंतरण	राजस्व	0.9	0.9	1.0	1.3	-20.0	-9.5	0.0	0.0	0.0	0.0
डी. पूंजी अंतरण	पूंजी	0.0	0.0	0.1	0.2			0.0	0.0	0.0	0.0
4. अंतरण की कुछ प्रमुख मदें		46.2	53.7	49.7	80.1	-6.3	-32.2	0.2	0.3	0.3	0.3
ए. विशेष सहायता	राजस्व	4.7	1.6	3.0	15.0	-59.4	-80.0	0.0	0.0	0.0	0.1
बी. एनडीआरएफ से राज्य को सहायता	राजस्व	10.0	18.9	10.0	12.4	-5.6	-60.0	0.1	0.1	0.1	0.1
सी. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना ऋण	उधार	23.8	24.7	32.0	46.8	-1.3	28.1	0.1	0.1	0.1	0.1
डी. अन्य अंतरण	राजस्व	7.8	8.5	4.6	5.9	2.2	-43.9	0.0	0.0	0.0	0.0
5. जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले राज्यों को एक पर एक ऋण	उधार	0.0	0.0	110.2	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
6. पूंजी व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	उधार	0.0	0.0	12.0	10.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
7. दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर के लिए अंतरण	राजस्व	8.0	28.2	51.0	48.7	-0.9	7.5	0.0	0.1	0.1	0.2
8. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अंतरण (1 से 7) जिनमें		1,195.4	1,145.5	1,313.9	1,388.5	-3.6	-5.5	6.3	5.8	5.9	6.2
राजस्व		1,171.6	1,120.8	1,159.6	1,331.5	-3.6	-15.1	6.2	5.7	5.8	6.1
पूंजी		0.0	0.0	0.1	0.2			0.0	0.0	0.0	0.0
ऋण		23.8	24.7	154.2	56.8	-1.3	516.9	0.1	0.1	0.1	0.1
9. ऋण और अग्रिम की वसूली		14.4	12.5	12.5	12.5			0.1	0.1	0.1	0.1
10. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निवल संसाधन अंतरण (6-7)		1,181.0	1,133.0	1,301.4	1,376.0	-3.5	-5.6	6.3	5.8	5.8	6.2

स्रोत: विभिन्न वर्षों के केन्द्रीय बजट दस्तावेज़।

गृहस्थ (हाउसहोल्ड) वित्तीय बचत और गृहस्थ ऋण-जीडीपी अनुपात के आकलन - 2020-21 की दूसरी तिमाही*

2020-21 की पहली तिमाही में कोविड-19 के चलते गृहस्थ वित्तीय बचत दर में आई बचत दूसरी तिमाही (ति2) में प्रति-मौसमी ढंग से घट गई। गृहस्थों की जमाराशियां और उधार जहाँ बढ़े, वहीं मुद्रा में उनकी धारिताएं और म्यूचुअल फंडों में बचत घटी। गृहस्थ उपभोग, विशेषतः इसके विवेकाधीन घटक में, वृद्धि लॉकडाउन में ढील के बाद आर्थिक गतिविधि की फिर से शुरुआत के कारण हुई हो सकती है। वित्तीय बचत में विपर्यय की पुष्टि चालू खाता शेष में पहले से कम अधिशेष से होती है। जीडीपी की तुलना में गृहस्थ ऋण अनुपात ति1:2020-21 के 35.4 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर ति2:2020-21 में 37.1 प्रतिशत पर आ गया। प्रारंभिक संकेत बताते हैं कि उपभोग और आर्थिक गतिविधि में तेजी आने के साथ गृहस्थ वित्तीय बचत दर ति3:2020-21 में और नीचे गई होगी।

प्रस्तावना

ति2:2020-21 के प्रारंभिक अनुमानों का संकेत है कि गृहस्थ (हाउसहोल्ड) वित्तीय बचत ति1:2020-21 की 21.0 अभूतपूर्व ऊँचाई को छूने के बाद महामारी-पूर्व के स्तरों के करीब सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) के 10.4 प्रतिशत पर पहुँच गई। यह वापसी मुख्यतः बैंकों और एनबीएफसी से गृहस्थ उधारियों में

वृद्धि के साथ म्यूचुअल फंडों और मुद्रा के रूप में गृहस्थ वित्तीय आस्तियों में कमी के कारण है। फिर भी, ति2: 2020-21 के लिए गृहस्थों की वित्तीय बचत दर ति2: 2019-20 में देखी गई 9.8 प्रतिशत से अधिक रही (सारणी 1)।

अर्थव्यवस्था के क्रमशः फिर से खुलने / अनलॉकिंग से गृहस्थ 'केवल आवश्यक' व्यय से विवेकाधीन व्यय की ओर मुड़े जिससे ति1: 2020-21 में प्राप्त शिखर से गृहस्थ व्यय की वापसी हुई। लॉकडाउन प्रतिबंधों की कड़ाई में क्रमिक कमी – ऑक्सफोर्ड कोविड-19 सरकारी कड़ाई सूचकांक (गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस इंडेक्स) के ति1: 2020-21 85.6 से ति2: 2020-21 में घटकर 78.5 होने में भी प्रतिबिंबित – उपभोग के कुछ घटक विशेषतः विवेकाधीन, एक तिमाही की सुषुप्ति के बाद बढ़े जिससे गृहस्थों की वित्तीय बचत में कमी आई। गृहस्थ वित्तीय बचत में प्रवृत्ति विपर्यय की पुष्टि अंतिम खपत व्यय के संकुचन में कमी के साथ-साथ ति2:2020-21 में चालू खाते में पहले से कम अधिशेष से भी होती है। इसके अलावा, निजी खपत में वृद्धि दूसरी तिमाही के लिए विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों में दिखती है। उदाहरण के लिए, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, जिसने ति1:2020-21 की पहली तिमाही में 67.6 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया, सितंबर 2020 में 5.3 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि के साथ दूसरी तिमाही के अंत में धनात्मक क्षेत्र में चला गया। गैर-टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन भी ति 2: 2020-21 में 0.4 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि पर मजबूत हुआ, जबकि ति1 में 16.9 प्रतिशत की अ-वृद्धि आई थी। 2020-21

सारणी 1: गृहस्थ (हाउसहोल्ड) वित्तीय बचत

(₹ लाख करोड़)

	2018-19					2019-20					2020-21	
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2
निवल वित्तीय आस्तियां (ए-बी)	2.57 (5.6)	2.23 (4.8)	2.08 (4.3)	6.68 (13.9)	13.56 (7.2)	2.02 (4.0)	4.85 (9.8)	4.20 (8.1)	5.14 (9.8)	16.20 (8.0)	8.16 (21.0)	4.92 (10.4)
ए. वित्तीय आस्तियों का प्रवाह	3.49 (7.6)	4.77 (10.3)	3.46 (7.1)	9.62 (20.0)	21.34 (11.3)	3.83 (7.7)	5.65 (11.4)	5.51 (10.6)	7.86 (15.1)	22.85 (11.2)	7.38 (19.0)	7.47 (15.8)
बी. वित्तीय देयताओं का प्रवाह	0.91 (2.0)	2.55 (5.5)	1.38 (2.8)	2.94 (6.1)	7.78 (4.1)	1.81 (3.6)	0.80 (1.6)	1.31 (2.5)	2.72 (5.2)	6.64 (3.3)	-0.78 (-2.0)	2.55 (5.4)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

स्रोत: लेखकों द्वारा गणना

* यह आलेख राष्ट्रीय लेखा विश्लेषण प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के संजय कुमार हांसदा, अनुपम प्रकाश, आनंद प्रकाश एक्का और इशु ठाकुर द्वारा तैयार किया गया है। ड्राफ्ट पर अंतर्दृष्टि से परिपूर्ण विचार-विमर्श के लिए लेखकगण डॉ. मृदुल कुमार सागर के आभारी हैं। ति1: 2020-21 से संबंधित पिछला आलेख आरबीआई बुलेटिन के नवंबर अंक में प्रकाशित हुआ। आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

की पहली तिमाही में क्रमशः 35.9 प्रतिशत और 33.3 प्रतिशत के संकुचन के बाद मोटर स्परिट और हाई-स्पीड डीजल की खपत, अगली तिमाही में सुधरी जो क्रमशः 5.0 प्रतिशत और 15.6 प्रतिशत के कम संकुचन में परिलक्षित हुई। नतीजतन, जीडीपी के तिमाही आकलन के अनुसार निजी अंतिम खपत में संकुचन की गति ति1: 2020-21 में 26.3 प्रतिशत के तेज संकुचन से नरम पड़कर ति2: 2020-21 में 11.3 प्रतिशत तक कम हो गई। हालांकि, गृहस्थ वित्तीय बचत में दूसरी तिमाही में नरमी, प्रति-मौसमी थी जिसने उच्च आधार के प्रभाव को क्रमिक रूप से और लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद अवरुद्ध मांग में उछाल के साथ गृहस्थों के विवेकाधीन व्यय में वृद्धि को दर्शाया।

ति1: 2020-21 में 21.0 प्रतिशत की गृहस्थ वित्तीय बचत दर के साथ जहाँ 24.4 प्रतिशत का वास्तविक जीडीपी संकुचन देखा गया, वहीं जीडीपी संकुचन में ति2 में 7.3 प्रतिशत की कमी गृहस्थ वित्तीय बचत दर के घटकर 10.4 प्रतिशत होने के साथ घटित हुई। घरेलू वित्तीय बचत दर और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के बीच उलटा संबंध अस्वाभाविक लग सकता है, लेकिन अध्ययनों से पता चला है कि आर्थिक मंदी और आय को लेकर अधिक अनिश्चितता के दौरान परिवार अधिक बचत करते हैं [लेवनॉन और फ्रेंको, 2011¹; मोदी व अन्य, 2012]। इसी तरह की प्रवृत्ति वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखी गई थी जब 2008-09 के दौरान गृहस्थ वित्तीय बचत दर में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 170 आधार अंकों की वृद्धि हुई थी, जो बाद में अर्थव्यवस्था में सुधार आने पर कम हुई।

शेष आलेख को चार खंडों में विभाजित किया गया है। खंड II भारत में वित्तीय बचत की तुलना में गृहस्थ बचत की देशों की (क्रॉस-कंट्री) प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है। खंड III पिछली तिमाही में गृहस्थ वित्तीय आस्तियों और देयताओं की संरचना में भिन्नता दर्शाता है जिसमें गृहस्थ ऋण-जीडीपी अनुपात पर कुछ विचार शामिल हैं। खंड IV में व्यक्ति-आधार (माइक्रो-फाउंडेशन) स्तर पर गृहस्थों की बैलेंस शीट की आस्तियों और देयताओं दोनों में क्षेत्र और लिखत-वार प्रमुख उतार-चढ़ाव को समाहित किया गया है।

¹ लेखकों ने कहा कि 2005-07 के दौरान यू.एस. गृहस्थ बचत दर 1-2 प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले स्तर पर थी, लेकिन वैश्विक वित्तीय संकट के बाद एक वर्ष के भीतर लगभग छह प्रतिशत तक बढ़ गई।

खंड V ति3:2020-21 में वित्तीय बचत पर परिदृश्य प्रस्तुत करता है। चुनिंदा आस्तियों और देयताओं के बकाया सहित गृहस्थ वित्तीय आस्तियों और देयताओं के लिखत-वार प्रवाह, अनुबंध I, II और III में दिए गए हैं।

II. गृहस्थ बचत में देशों की प्रवृत्ति

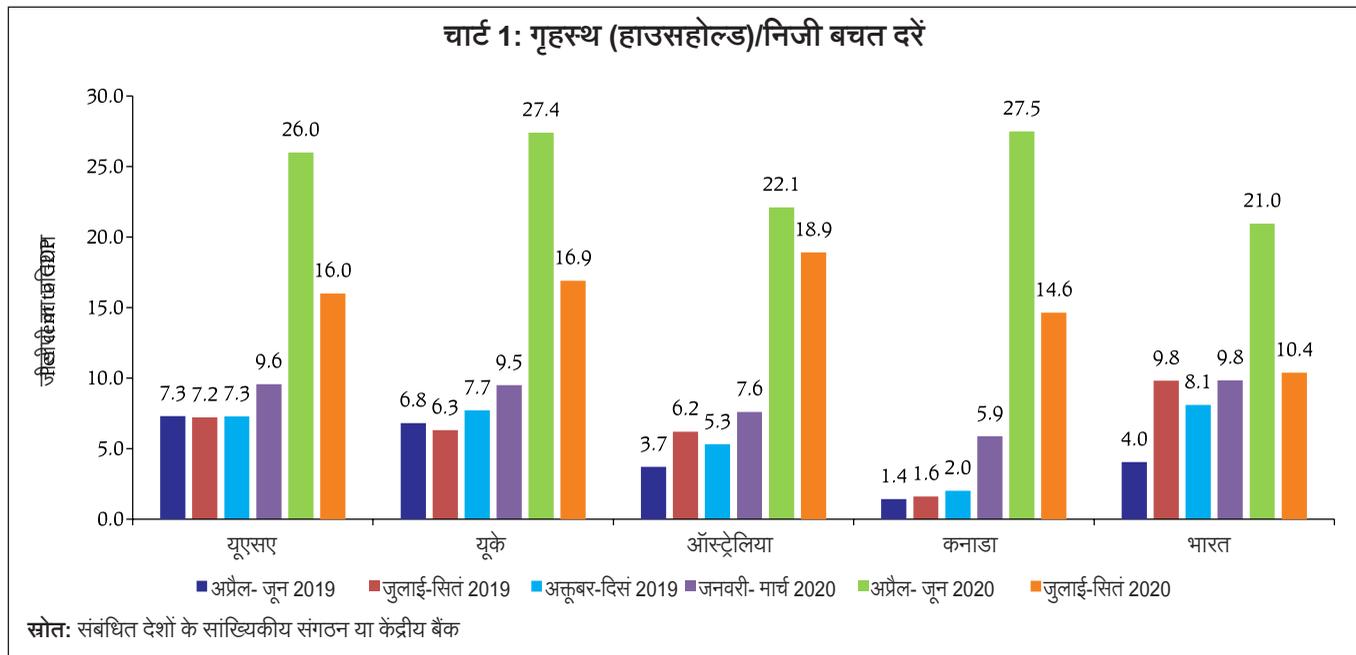
वैश्विक स्तर पर, खर्च की मात्रा और संरचना में सपष्ट परिवर्तन देखा गया क्योंकि महामारी-जनित गतिशीलता प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप 2020-21 की पहली तिमाही (चार्ट 1) के दौरान विवशता और एहतियात में बचत हुई। आर्थिक गतिविधि में सचेत बेहतरी के साथ, अवरुद्ध मांग के मुक्त होने पर सेवाओं की तुलना में वस्तुओं की अधिक मांग के कारण ति2: 2020-21 में विवशता/एहतियात की बचत जमा करने की प्रवृत्ति कम हो गई। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को समुत्थान (रिकवरी) की अपनी यात्रा में वायरस की दूसरी लहर और अधिक उग्र रूपों के भय-जनित बाधाओं का सामना करना पड़ा और उनकी गृहस्थ/ व्यक्तिगत बचत जुलाई-सितंबर तिमाही में पूर्व-महामारी के स्तर से कहीं अधिक रही। यूएस², यूके³, आस्ट्रेलिया⁴ और कनाडा⁵ में गृहस्थ/ व्यक्तिगत बचत दर, जो अप्रैल-जून 2020 में 20 प्रतिशत से अधिक हो गई, अगली तिमाही में उल्लेखनीय रूप से संशोधित हुई, लेकिन महामारी-पूर्व-स्तरों की तुलना में बहुत ऊँची दर पर कायम रही। इसके विपरीत, भारतीय गृहस्थों की वित्तीय बचत महामारी-पूर्व-स्तरों के करीब लौट आई। यह देखना भी दिलचस्प है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में घरेलू/ व्यक्तिगत बचत में महामारी पूर्व मौसमी पैटर्न काफी समान हैं। महामारी-पूर्व चरण में गृहस्थ / व्यक्तिगत बचत दर के बहुत निम्न स्तर को देखें तो कनाडा में, अप्रैल-जून तिमाही में उछाल तीव्रतम में से एक था।

² ब्यूरो ऑफ़ इकॉनॉमिक एनालिसिस, यूएस (<https://www.bea.gov/news/2020/gross-domestic-product-third-estimate-corporate-profits-revised-and-gdp-industry-third>)

³ ऑफिस ऑफ़ द नेशनल स्टैटिस्टिक्स, यूके (<https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/dgd8/ukea>)

⁴ ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स (<https://www.abs.gov.au/statistics/economy/national-accounts/australian-national-accounts-national-income-expenditure-and-product/sep-2020>)

⁵ स्टैटिस्टिक्स कनाडा (<https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3610011201>)



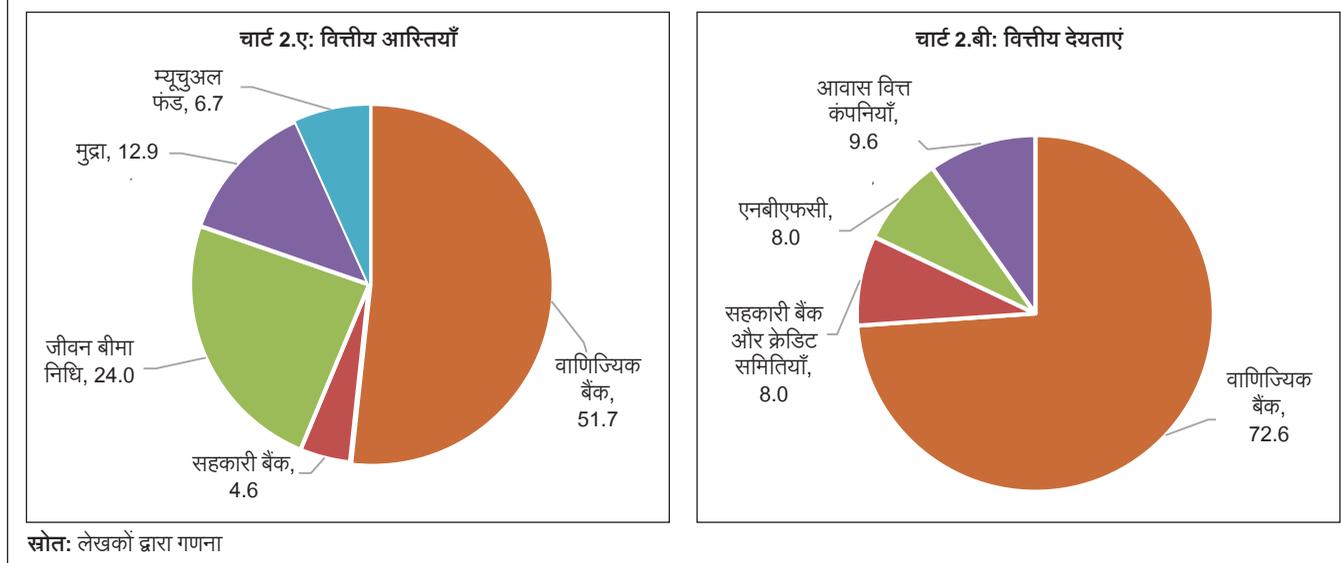
भारत संभवतः आने वाले त्योहारी मौसम की मांग के साथ अवरुद्ध मांग के मुक्त होने के कारण खर्च बढ़ाने में अपेक्षाकृत तेज प्रतीत हुआ, और इस प्रकार ति2: 2020-21 में गृहस्थ वित्तीय बचत के पूर्व-महामारी के स्तर के निकटतर पहुँच गया। यद्यपि महामारी के दौरान कुल बचत में वृद्धि हुई है, पर, संभव है कि इससे गृहस्थ बचत और गैर-आवश्यक वस्तुओं के उपभोग व्यय के मामले में असमान प्रभाव का पता न चले क्योंकि असंगठित क्षेत्र में कई गृहस्थों ने रोजगार, आय और उधार के अवसरों के नुकसान को झेला। आगे, बड़े पैमाने पर टीकाकरण में प्रगति की आशा के साथ, भारत के साथ-साथ अन्य देशों में गृहस्थ वित्तीय बचत के घटकर महामारी-पूर्व के स्तरों तक आने की उम्मीद है।

III. गृहस्थ वित्तीय संविभाग की संरचना और ऋण-जीडीपी अनुपात

विगत तिमाहियों में, गृहस्थ वित्तीय संविभाग (पोर्टफोलियो) में विभिन्न लिखतों की हिस्सेदारी स्थिर रही है, जिसमें आस्तियों और देयताओं दोनों पक्षों पर बैंकिंग क्षेत्र हावी है। बैंकिंग क्षेत्र के अलावा, गृहस्थों के पास मुद्रा के साथ-साथ जीवन बीमा और

म्यूचुअल फंड दो अन्य प्रमुख साधन हैं, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) से उधार उनकी देयताओं के अन्य प्रमुख हिस्से हैं। कॉर्पोरेट क्षेत्र और सामान्य (जेनरल) सरकार से गृहस्थों का उधार नगण्य बना हुआ है (चार्ट 2)।

यद्यपि, गृहस्थ संविभाग (पोर्टफोलियो) के आस्ति पक्ष में विभिन्न लिखतों (इन्सट्रुमेंट्स) का हिस्सा ति1: 2018-19 से ति2: 2020-21 के दौरान मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा है, मुद्रा धारिता (होलिडिंग) का हिस्सा, जो अत्यधिक अनिश्चितता में नकदी की ओर पलायन को दर्शाते हुए ति1: 2020-21 के दौरान बढ़ा, दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के साथ अपने महामारी-पूर्व के स्तर पर वापस आ गया है। देयताओं की ओर देखें तो, बैंकिंग और एचएफसी क्षेत्र से गृहस्थ देयताओं का हिस्सा कम हो गया है, जबकि ति1: 2020-21 व उसके बाद से एनबीएफसी की बढ़ गई है। आर्थिक संकट और आय प्रवाह की भावी धारा को लेकर नैराश्य के समय में एनबीएफसी की ओर झुकाव जोखिम विमुखता के बढ़ने और एनबीएफसी की तुलना में बैंक ऋणों के लिए सख्त पात्रता मानदंडों के कारण हो सकता है।

चार्ट 2: हाउसहोल्ड वित्तीय आस्तियों और देयताओं का संघटन- बकाया
(सितंबर 2020 की स्थिति)

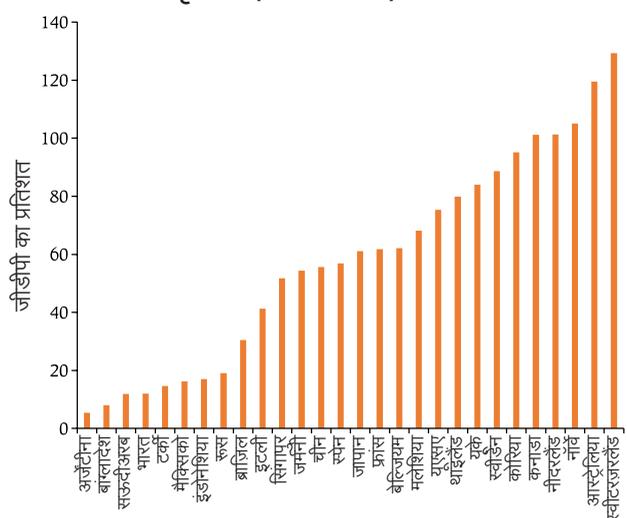
जीडीपी की तुलना में गृहस्थ ऋण⁶ का अनुपात, जो 2018-19 की पहली तिमाही से लगातार बढ़ रहा है, 2020-21 की पहली तिमाही में 35.4 से तेजी से बढ़कर 2020-21 की दूसरी तिमाही में 37.1 प्रतिशत हो गया। हालांकि, यहाँ प्रस्तुत भारत के गृहस्थ ऋण के आंकड़े, गैर-संस्थागत क्षेत्र के प्रति उनकी ऋणग्रस्तता को नहीं दर्शाते हैं।

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से घरेलू ऋण के स्तर और प्रवृत्ति (जीडीपी के अनुपात के रूप में) पर आधारित अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) के एक अध्ययन ने देशों को चार श्रेणियों में रखा है: i) उच्च और बढ़ती, ii) उच्च और सपाट / गिरती, iii) निम्न और उठती हुई, iv) नीची और सपाट/गिरती (ज़बाई, 2017)। अध्ययन के अनुसार, यूरो क्षेत्र, जापान, जर्मनी, इटली और मैक्सिको के साथ भारत ऐसे देशों के चौथे समूह में है। हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के 2019 के तुलनीय आंकड़े भी यह दर्शाते हैं कि जीडीपी की तुलना में गृहस्थ ऋण के अनुपात के संदर्भ में, जिसमें कर्ज (लोन्स) और ऋण प्रतिभूतियाँ (डेट सिक्क्यूरिटीज़) शामिल हैं, भारत निचले समूह (बॉटम ग्रुप) में स्थित है (चार्ट 3)।

भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के पास कुल बैंक जमा राशियों में लगातार वृद्धि हुई और सितंबर 2020

⁶ बैंकों, एचएफसी और एनबीएफसी के प्रति गृहस्थों की बकाया देयताओं के रूप में आकलित। डेटा के अभाव में गैर-संस्थागत क्षेत्र के प्रति देयताओं को दर्शाया नहीं जाता है। घरेलू ऋण का आकलन दशकीय अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस) से भी उपलब्ध है, लेकिन काफी अंतराल पर इनकी जानकारी हो पाती है।

के अंत में ₹142.6 लाख करोड़ तक पहुँच गई - जून 2020 के अंत से ₹4.0 लाख करोड़ की वृद्धि। इसके विपरीत, बैंक अग्रिम जून 2020 में 1.2 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 0.2 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करते हुए सितंबर के अंत में ₹102.7 लाख करोड़ पर आ गए, जो आर्थिक गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी को दर्शाती है। 2020 की जुलाई-

चार्ट 3: गृहस्थ (हाउसहोल्ड) ऋण – 2019

नोट: गृहस्थ ऋण में ऋण और ऋण प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

स्रोत: वैश्विक ऋण (ग्लोबल डेट) डेटाबेस, आईएमएफ।⁷

⁷ ग्लोबल डेटाबेस, आईएमएफ, https://www.imf.org/external/datamapper/HH_LS@GDD/SWEas. Accessed 17 मार्च 2021।

सितंबर तिमाही के दौरान गृहस्थों को दिए गए ऋण और उनसे जुटाई गई जमाराशियों के बीच घटे हुए अंतर का गृहस्थों की निवल वित्तीय बचत में कमी लाने में हाथ रहा।

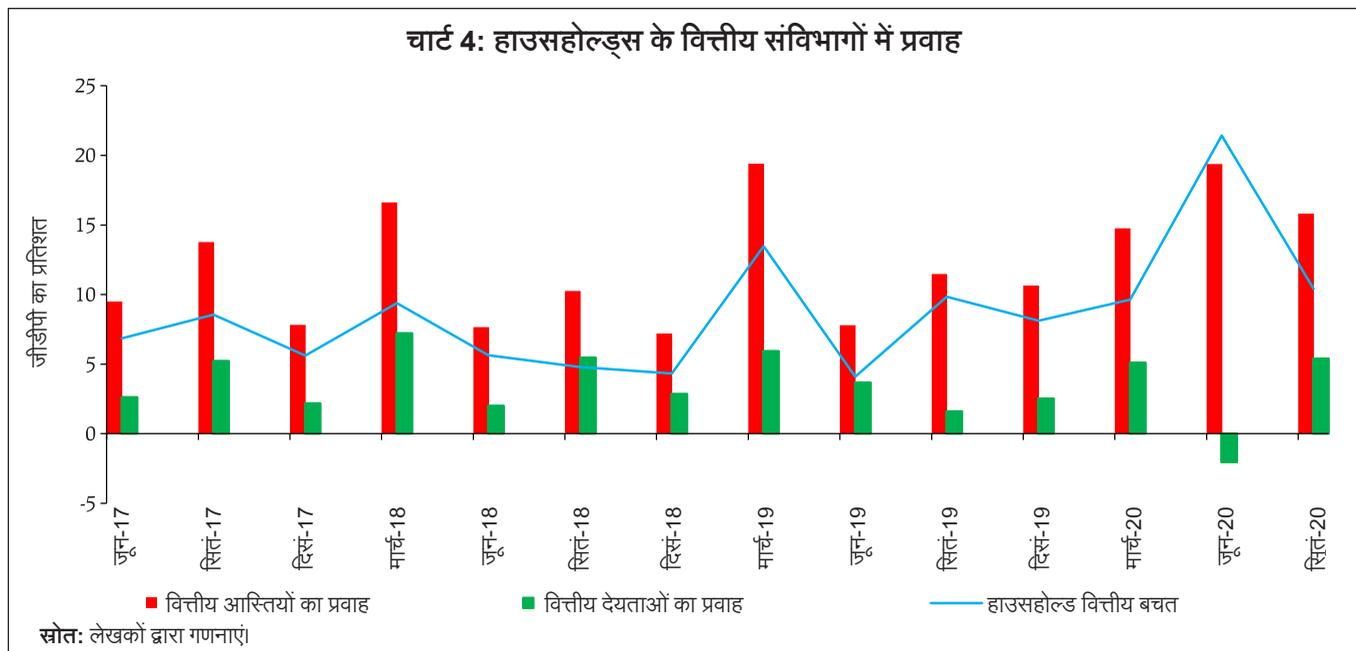
IV. घरेलू वित्तीय बचत: क्षेत्र और लिखत

माइक्रो-फाउंडेशन की तलाश में, 2020-21 की दूसरी तिमाही में गृहस्थ आस्ति/देयता प्रवाह के भिन्न व्यवहार की जांच सेक्टरों और उपकरणों (लिखतों/इन्सट्रुमेंट्स) के संदर्भ में निम्नानुसार की जाती है (चार्ट 4)।

- गृहस्थ वित्तीय बचत में कमी उनकी वित्तीय आस्तियों में वृद्धि के बावजूद हुई है, क्योंकि वित्तीय देयताओं का प्रवाह 2020-21 की दूसरी तिमाही में धनात्मक क्षेत्र में वापस आ गया है। गृहस्थ वित्तीय आस्तियों का प्रवाह बैंकों में उनकी जमाराशियों के कारण बढ़ा है, बावजूद इसके कि मुद्रा और म्यूचुअल फंड में उनकी धारिताओं में महत्वपूर्ण गिरावट आई है (अनुबंध I)।
- गृहस्थ वित्तीय आस्तियों का प्रवाह, हालांकि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 2020-21 की पहली तिमाही में 19.0 प्रतिशत से कम होकर 2020-21 की दूसरी तिमाही में 15.8 प्रतिशत हो गया है। परिवारों की मुद्रा

धारिता ति1: 2020-21 में 5.3 प्रतिशत से घटकर ति2: 2020-21 में जीडीपी का 0.4 प्रतिशत हो गई है। म्यूचुअल फंड उत्पादों में गृहस्थ निवेश इसी अवधि में 1.7 प्रतिशत से घटकर 0.3 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। इसी तरह, बीमा उत्पादों के रूप में बचत पिछली तिमाही के 3.2 प्रतिशत से घटकर 3.0 प्रतिशत रह गई (चार्ट 5ए और अनुबंध I)।

- वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की स्थिति में और विभिन्न विवेकपूर्ण नियामक उपायों के चलते भारत की बैंकिंग प्रणाली ने महामारी का सामना अपेक्षाकृत मजबूत पूँजी और तरलता/चलनिधि बफर के साथ किया (आरबीआई, 2020; आरबीआई, 2021) और 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान बैंकों के पास जमाराशियों के रूप में गृहस्थ वित्तीय बचत में वृद्धि हुई, जो उनकी सुरक्षित आश्रय स्थिति की बहाली को दर्शाती है। विनियामकीय राहतों और रियायतों के कारण बैंकों के प्रदर्शन और स्थिरता में सुधार हुआ। हालांकि, इस अवधि के दौरान गैर-बैंकों में गृहस्थ जमाराशियों में गिरावट आई।

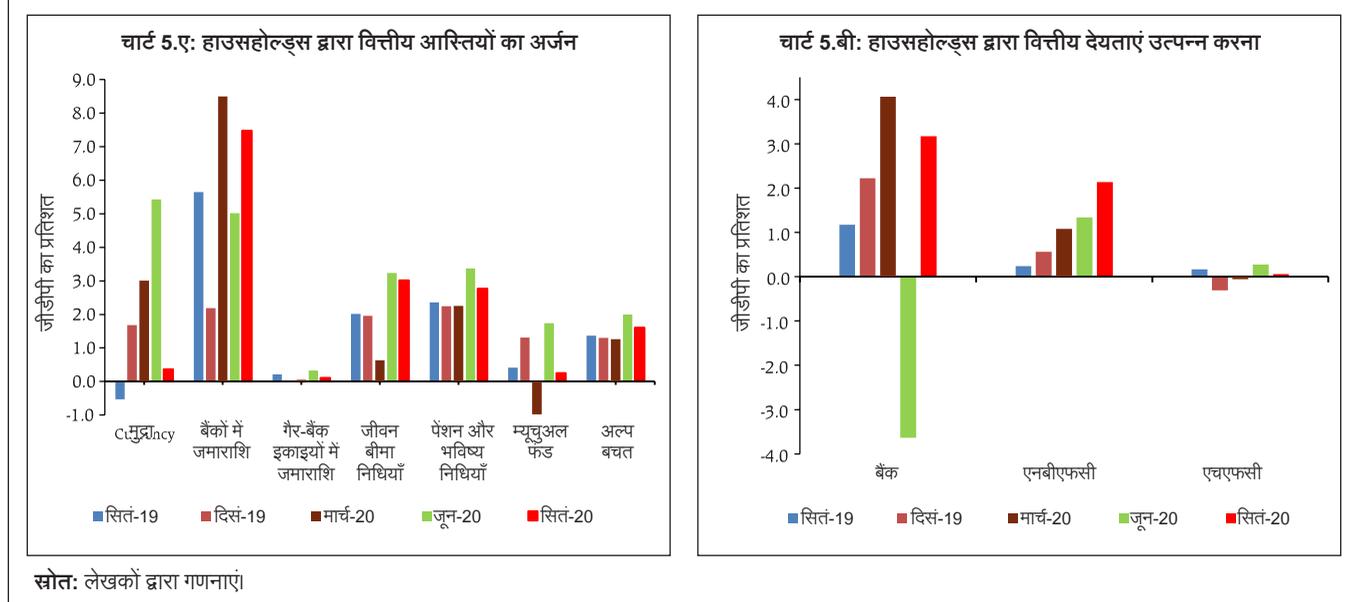


- गृहस्थों की नकदी धारिता दर में कमी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के खुलने और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने को लेकर कम अनिश्चितता के कारण आई। महामारी के मद्देनजर लेनदेन के लिए डिजिटल मोड का अधिक उपयोग भी इस प्रक्रिया में सहायक हुआ (आरबीआई, 2021)।
- अभिवृद्धि (एक्रीशन) में कमी के बावजूद, गृहस्थों द्वारा बीमा निधियों की अभिदान दर (सब्सक्रिप्शन रेट) उच्च बनी रही, जो कि ति2:2020-21 में महामारी के कारण परिवारों के बीच जीवन बीमा के प्रति बढ़ी जागरूकता को दर्शाती है। इस प्रकार, बीमा पॉलिसियां जो टैक्स-बचत के एक साधन के रूप में खरीदी जाती थीं, स्वास्थ्य की आपात स्थिति के इस दौर में, घरों की जीवन शैली का हिस्सा बन गई हैं।
- भारत सरकार द्वारा पेंशन छत्र (नेट) के तहत असंगठित क्षेत्र और निम्न-आय वर्ग के कवरेज को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी के कारण, कुछ कमी के बावजूद ति2: 2020-21 में पेंशन और भविष्य निधि की सदस्यता दर भी ऊँची बनी रही। नेशनल पेंशन

सिस्टम (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में नामांकन (एनरोलमेंट) और प्रबंधाधीन आस्तियां (एयूएम) भी सितंबर 2020 के अंत (आरबीआई, 2021) में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़ी हैं।

- तथापि ति2: 2020-21 में म्यूचुअल फंडों में गृहस्थ बचत घट गई, क्योंकि शेयर बाजारों में तेज सुधार के कारण, म्यूचुअल फंड के बजाय, लोगों ने संभवतः इक्विटी में प्रत्यक्ष निवेश किया, जैसा कि अप्रैल-जून तिमाही में खोले गए 23 नए लाख डीमैट खातों के मुकाबले सितंबर को समाप्त तिमाही में खोले गए 34 लाख में परिलक्षित होता है। म्यूचुअल फंड पर हाल ही में एक विनियामकीय कदम⁸ ने भी कथित तौर पर मल्टी-कैप म्यूचुअल फंड पर मोचन/शोधन (रिडेम्पशन) दबाव में योगदान दिया।
- पिछली तिमाही की तुलना में ति2: 2020-21 के दौरान शेयरों में गृहस्थ निवेश में गिरावट आई क्योंकि ति1: 2020-21 में ₹ 53,125 करोड़ का एक मेगा राइट्स इश्यू था।

चार्ट 5: हाउसहोल्ड वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- बकाया की स्थिति



⁸ सितंबर 2020 में, मल्टी-कैप फंड, जिनके पोर्टफोलियो में लार्ज-कैप शेयरों का वर्चस्व है, को जनवरी 2021 से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप शेयरों में से प्रत्येक में न्यूनतम 25% निवेश करने का निर्देश दिया गया था।

- बैंकों और एनबीएफसी से ऋण के कारण गृहस्थों की वित्तीय देयताओं में प्रवाह के धनात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने का आकलन है। यह वृद्धि 2020-21 की दूसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियों में अच्छी वापसी, जो प्रत्याशा से अधिक तेज है और साथ ही राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाए जाने के बाद सकारात्मक परिदृश्य (चार्ट 5 बी) का भी प्रतिबिंब है (चार्ट 5बी)।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के व्यक्तिगत ऋणों, वाहन ऋण, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं (कंज्यूमर ड्यूरेबल्स) और क्रेडिट कार्ड के व्यक्तिगत ऋणों में ऋण प्रवाह ने पिछली तिमाही में संकुचन के मुकाबले 2020-21 की दूसरी तिमाही में धनात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए स्थिति बेहतर कर दी। आवास के लिए ऋण वृद्धि ति1 में 0.4 प्रतिशत से बढ़कर ति2: 2020-21 में 1.3 प्रतिशत हो गई।
- कुल बैंक ऋण में धीमी वृद्धि के साथ गृहस्थ ऋणों में महत्वपूर्ण वृद्धि तथा हुई तथा पिछली तिमाही की तुलना में 2020-21 की दूसरी तिमाही में कुल ऋण में अपनी हिस्सेदारी में 1.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि करते हुए गृहस्थ ऋण 51.5 प्रतिशत तक पहुँचा।

बैंकिंग क्षेत्र की राह पर, एनबीएफसी से गृहस्थों को ऋण प्रवाह में ति2: 2020-21 में वृद्धि देखी गई, जबकि ति2 में उनकी समग्र ऋण वृद्धि ति1 की तुलना में कम रही।

V. आगे की राह

अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे खुलने/अनलॉक होने के साथ, गृहस्थ 'केवल आवश्यक' वाले दृष्टिकोण से विवेकाधीन खर्च की ओर मुड़े हैं, जो कि ति1: 2020-21 में 26.3 प्रतिशत की तुलना में 11.3 प्रतिशत के संकुचन की घटी रफ्तार में भी दिखता है जिससे गृहस्थ वित्तीय बचत में पिछली तिमाही के शिखर से कमी आई। अधिक उग्र रूपों सहित वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे कई यूरोपीय देशों के विपरीत भारतीय संदर्भ में उलटफेर/विपर्यय तेज रहा है। वस्तुओं और कुछ हद तक

सेवाओं के लिए अवरुद्ध मांग के मुक्त होने से भी भारत की गृहस्थ वित्तीय बचत में विपर्यय (रिवर्सल) तेज हो गया।

कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में बीमा क्षेत्र को प्रभावित किया है। बढ़ते दावों के मद्देनजर, अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स / आईएआईएस) ने एक बयान में संरक्षण की उन सीमाओं पर प्रकाश डाला, जिसकी बीमा क्षेत्र द्वारा स्वयं प्रदान करने की उम्मीद की जा सकती है। महामारी से उत्पन्न होने वाले विविध जोखिमों के मद्देनजर, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने "महामारी जोखिम पूल" ("पैंडेमिक रिस्क पूल") के तंत्र के माध्यम से इन जोखिमों को दूर करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया (आरबीआई, 2021)। भविष्य में, बीमा निधियों के बारे में बढ़ती जागरूकता इन उत्पादों के प्रति अधिक गृहस्थों को आकर्षित कर सकती है। बैंक जमाराशियों पर कम रिटर्न, और प्रतिस्पर्धी माध्यमों, विशेषतः बीमा और म्यूचुअल फंडों के बारे में बढ़ती जागरूकता के मद्देनजर, गृहस्थ वित्तीय आस्तियों के विविधीकरण की महामारी-पूर्व प्रवृत्ति को और बल मिल सकता है।

बैंकों व एनबीएफसी से गृहस्थ उधारी बढ़ी है और जमाराशियों के रूप में बचत में वृद्धि के बावजूद गृहस्थ वित्तीय बचत में कमी आई है। 22 जनवरी 2021 को, रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के लिए चार स्तरीय संरचना के आधार पर एक संशोधित विनियामकीय ढांचा प्रस्तावित किया, जो बड़े एनबीएफसी को बैंकों की तरह विनियमित करने की अनुमति देगा। लागू होने पर, यह बैंकों और गैर-बैंकों के बीच गृहस्थ संविभाग (पोर्टफोलियो) के वितरण को प्रभावित कर सकता है। मुद्रा और म्यूचुअल फंड के रूप में गृहस्थ बचत में उल्लेखनीय गिरावट ने भी गृहस्थ वित्तीय बचत में कमी लाने में योगदान दिया है। ति2:2020-21 में अभिवृद्धि में नरमी के बावजूद बीमा निधियों के रूप में बचत ऊँची बनी हुई है।

आगे, उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण में प्रगति की आशा उपभोग मांग को और बढ़ावा देगी तथा महामारी-पूर्व व्यय व बचत के पैटर्न की बहाली की दिशा में कार्य करेगी। नवंबर

2020 के दौर के रिज़र्व बैंक के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण ने सितंबर 2020 के दौर में दर्ज किए गए सर्वकालिक निम्न स्तर से मामूली सुधार दिखाया, जो आगे चलकर गृहस्थ वित्तीय बचत में और कमी की गुंजाइश दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, दिसंबर के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों ने पिछली तिमाही में 0.2 प्रतिशत की धीमी वृद्धि से तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 2.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की, जबकि जमाराशियों में इसी अवधि के 2.9 प्रतिशत की तुलना में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह ति3: 2020-21 के दौरान घरेलू वित्तीय बचत दर में और कमी का लक्षण हो सकता है, हालांकि म्यूचुअल फंड की इकाइयों के साथ-साथ शेयरों और डिबेंचरों में निवेश के माध्यम से गृहस्थों द्वारा पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन के जरिये उत्साही शेयर बाजार कुछ भरपाई कर सकते हैं।

संदर्भ:

- Levanon, Gad and Lynn Franco (2011), "The Great Recession and Household Savings", The Conference Board, February 2011.
- Mody, A., Ohnsorge, F., & Sandri, D. (2012), "Precautionary savings in the great recession", IMF Economic Review, 60 (1), 114-138.
- RBI (2020), Report on Trend and Progress of Banking in India 2019-20, Reserve Bank of India.
- RBI (2021), Financial Stability Report , Issue No. 22, January, Reserve Bank of India.
- Zabai, Anna (2017), "Household debt: recent developments and challenges", BIS Quarterly Review, December 2017.

अनुबंध I
गृहस्थों की वित्तीय आस्तियां: समग्र प्रवाह (जारी)

(₹ करोड़)

मद	2018-19				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
वित्तीय आस्तियां	3,48,568.2	4,77,165.0	3,46,489.3	9,61,845.5	21,34,068.0
<i>जिसमें से:</i>					
1. कुल जमाराशियां (ए) + (बी)	-55,939.4	3,01,417.0	21,884.7	5,42,776.4	8,10,138.7
(ए) बैंक जमाराशियां	-65,261.8	2,92,618.3	13,121.4	5,39,472.8	7,79,950.6
i. वाणिज्यिक बैंक जमाराशियां	-62,126.9	2,89,468.1	10,634.6	4,90,680.6	7,28,656.4
ii. सहकारी बैंक	-3,134.9	3,150.2	2,486.8	48,792.1	51,294.2
(बी) बैंकेतर जमाराशियां	9,322.4	8,798.7	8,763.3	3,303.6	30,188.1
2. जीवन बीमा निधियां	63,747.6	95,463.2	47,456.3	1,50,854.6	3,57,521.6
3. पेंशन और भविष्य निधियां (पीपीएफ सहित)	98,461.4	97,964.4	99,515.4	10,3367.4	3,99,308.5
4. मुद्रा	1,11,589.6	-32,134.4	1,02,656.5	95,760.4	2,77,872.1
5. निवेश	78,397.2	-37,856.9	22,664.7	16,774.9	79,979.8
<i>जिसमें से</i>					
i. म्यूचुअल फंड	69,897.4	-46,008.0	21,369.6	12,342.5	57,601.4
ii. इक्विटी	2,001.2	3,054.4	471.0	855.8	6,382.4
6. अल्प बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	51,259.6	51,259.6	51,259.6	51,259.6	2,05,038.3
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में					
वित्तीय आस्तियां	7.6	10.3	7.1	20.0	11.2
<i>जिसमें से:</i>					
1. कुल जमाराशियां (ए) + (बी)	-1.2	6.5	0.4	11.3	4.3
(ए) बैंक जमाराशियां	-1.4	6.3	0.3	11.2	4.1
i. वाणिज्यिक बैंक जमाराशियां	-1.4	6.2	0.2	10.2	3.8
ii. सहकारी बैंक	-0.1	0.1	0.1	1.0	0.3
(बी) बैंकेतर जमाराशियां	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
2. जीवन बीमा निधियां	1.4	2.1	1.0	3.1	1.9
3. पेंशन और भविष्य निधियां (पीपीएफ सहित)	2.2	2.1	2.0	2.2	2.1
4. मुद्रा	2.4	-0.7	2.1	2.0	1.5
5. निवेश	1.7	-0.8	0.5	0.3	0.4
<i>जिसमें से</i>					
i. म्यूचुअल फंड	1.5	-1.0	0.4	0.3	0.3
ii. इक्विटी	...	0.1
6. अल्प बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

... : नगण्य।

स्रोत: लेखकों द्वारा गणनाएं।

अनुबंध I
गृहस्थों की वित्तीय आस्तियां: समग्र प्रवाह (समाप्त)

(₹ करोड़)

मद	2019-20					2020-21	
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2
वित्तीय आस्तियां	3,83,124.6	5,64,598.2	5,50,679.8	7,86,160.4	22,84,563.0	7,38,208.1	7,46,821.4
<i>जिसमें से:</i>							
1. कुल जमाराशियां (ए) + (बी)	7,811.9	2,88,775.0	1,13,439.5	4,55,464.1	8,65,490.5	1,25,848.6	3,67,264.2
(ए) बैंक जमाराशियां	-7,074.1	2,78,084.6	1,13,314.3	4,52,959.0	8,37,283.8	1,13,327.7	3,62,343.5
i. वाणिज्यिक बैंक जमाराशियां	-13,293.8	2,69,475.5	63,997.5	4,48,586.5	7,68,765.7	1,17,962.1	3,51,860.2
ii. सहकारी बैंक	6,219.7	8,609.1	49,316.8	4,372.4	68,518.1	-4,634.4	10,483.3
(बी) बैंकेतर जमाराशियां	14,886.0	10,690.4	125.3	2,505.1	28,206.8	12,521.0	4,920.7
2. जीवन बीमा निधियां	1,08,873.1	99,209.1	1,01,373.7	33,549.3	3,43,005.2	1,23,324.5	1,42,422.5
3. पेंशन और भविष्य निधियां (पीपीएफ सहित)	106,969.6	1,09,961.6	1,10,044.6	1,13,602.6	4,40,578.3	1,19,308.7	1,21,831.7
4. मुद्रा	61,637.1	-26,104.8	86,843.5	1,60,255.1	2,82,630.8	2,06,889.6	17,225.3
5. निवेश	29,703.1	24,627.5	70,848.6	-44,840.5	80,338.6	85,893.1	21,134.2
<i>जिसमें से</i>							
i. म्यूचुअल फंड	8,578.0	20,198.4	67,521.1	-51,926.1	44,371.5	66,195.3	11,909.0
ii. इक्विटी	18,644.7	2,172.4	936.2	4,980.4	26,733.7	18,599.2	8,291.5
6. अल्प बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	67,065.7	67,065.7	67,065.7	67,065.7	2,68,262.9	75,879.4	75,879.4
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में							
वित्तीय आस्तियां	7.7	11.4	10.6	15.1	11.2	19.0	15.8
<i>जिसमें से:</i>							
1. कुल जमाराशियां (ए) + (बी)	0.2	5.8	2.2	8.7	4.3	3.2	7.8
(ए) बैंक जमाराशियां	-0.1	5.6	2.2	8.7	4.1	2.9	7.6
i. वाणिज्यिक बैंक जमाराशियां	-0.3	5.5	1.2	8.6	3.8	3.0	7.4
ii. सहकारी बैंक	0.1	0.2	1.0	0.1	0.3	-0.1	0.2
(बी) बैंकेतर जमाराशियां	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1
2. जीवन बीमा निधियां	2.2	2.0	2.0	0.6	1.7	3.2	3.0
3. पेंशन और भविष्य निधियां (पीपीएफ सहित)	2.1	2.2	2.1	2.2	2.2	3.1	2.6
4. मुद्रा	1.2	-0.5	1.7	3.1	1.4	5.3	0.4
5. निवेश	0.6	0.5	1.4	-0.9	0.4	2.2	0.4
<i>जिसमें से</i>							
i. म्यूचुअल फंड	0.2	0.4	1.3	-1.0	0.2	1.7	0.3
ii. इक्विटी	0.4	0.1	0.1	0.5	0.2
6. अल्प बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.9	1.6

... : नगण्य।

स्रोत: लेखकों द्वारा गणनाएं।

अनुबंध II
गृहस्थों की वित्तीय देयताएं: समग्र प्रवाह (जारी)

(₹ करोड़)

मद	2018-19				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
वित्तीय देयताएं	91,404.7	25,4518.4	1,38,159.7	2,94,278.0	7,78,360.8
निम्नलिखित से कर्ज (उधार)					
ए. वित्तीय निगम (i+ii)	91,217.9	2,54,331.7	1,37,973.0	2,94,091.3	7,77,613.9
(i) बैंकिंग क्षेत्र	47,825.7	1,70,950.3	1,40,677.9	2,49,387.0	6,08,840.8
जिसमें से:					
वाणिज्यिक बैंक	39,856.4	1,69,638.4	1,41,334.6	2,23,609.8	5,74,439.2
(ii) अन्य वित्तीय संस्थाएं	43,392.3	83,381.4	-2,704.9	44,704.3	1,68,773.0
(ए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	15,260.0	52,605.2	-3,755.8	28,952.6	93,062.0
(बी) आवास वित्त कंपनियां	23,560.2	28,328.8	-786.8	14,118.7	65,220.9
(सी) बीमा कंपनियां	4,572.1	2,447.4	1,837.7	1,633.0	10,490.1
बी. गैर-वित्तीय कॉरपोरेशन्स	49.0	49.0	49.0	49.0	196.1
(निजी कॉरपोरेट कारोबार)					
सी. सामान्य (जेनरल) सरकार	137.7	137.7	137.7	137.7	550.7
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में					
वित्तीय देयताएं	2.0	5.5	2.8	6.1	4.1
निम्नलिखित से कर्ज (उधार)					
ए. वित्तीय निगम (i+ii)	2.0	5.5	2.8	6.1	4.1
(i) बैंकिंग क्षेत्र	1.0	3.7	2.9	5.2	3.2
जिसमें से:					
वाणिज्यिक बैंक	0.9	3.6	2.9	4.7	3.0
(ii) अन्य वित्तीय संस्थाएं	1.0	1.8	-0.1	0.9	0.9
(ए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	0.3	1.1	-0.1	0.6	0.5
(बी) आवास वित्त कंपनियां	0.5	0.6	...	0.3	0.3
(सी) बीमा कंपनियां	0.1	0.1	0.1
बी. गैर-वित्तीय कॉरपोरेशन्स
(निजी कॉरपोरेट कारोबार)					
सी. सामान्य (जेनरल) सरकार

... : नगण्य।

स्रोत: लेखकों द्वारा गणनाएं।

अनुबंध II
गृहस्थों की वित्तीय देयताएं: समग्र प्रवाह (समाप्त)

(₹ करोड़)

मद	2019-20					2020-21	
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2
वित्तीय देयताएं निम्नलिखित से कर्ज (उधार)	1,81,090.7	79,839.0	1,30,840.9	2,72,337.1	66,4107.7	-77,678.5	2,54,915.2
ए. वित्तीय निगम (i+ii)	1,81,011.8	79,760.1	1,30,762.0	2,72,258.2	6,63,792.1	-77,757.5	2,54,836.2
(i) बैंकिंग क्षेत्र	1,61,317.2	57,886.0	1,15,246.1	2,16,572.4	5,51,021.7	-1,38,472.5	1,49,880.3
जिसमें से:							
वाणिज्यिक बैंक	1,35,575.1	56,900.7	85,897.8	2,05,938.4	4,84,311.9	-1,30,636.5	1,35,587.1
(ii) अन्य वित्तीय संस्थाएं	19,694.6	21,874.1	15,515.9	55,685.8	1,12,770.4	60,715.0	1,04,955.9
(ए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	-519.7	11,651.3	29,216.9	57,511.4	97,860.0	51,035.5	1,01,056.9
(बी) आवास वित्त कंपनियां	17,033.0	8,093.1	-15,710.4	-3,093.1	6,322.6	10,516.6	2,875.1
(सी) बीमा कंपनियां	3,181.3	2,129.7	2,009.4	1,267.4	8,587.8	-837.1	1,023.9
बी. गैर-वित्तीय कॉरपोरेशन्स (निजी कॉरपोरेट कारोबार)	49.0	49.0	49.0	49.0	196.1	49.2	49.2
सी. सामान्य (जेनरल) सरकार	29.9	29.9	29.9	29.9	119.4	29.9	29.9
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में							
वित्तीय देयताएं	3.6	1.6	2.5	5.2	3.3	-2.0	5.4
निम्नलिखित से कर्ज (उधार)							
ए. वित्तीय निगम (i+ii)	3.6	1.6	2.5	5.2	3.3	-2.0	5.4
(i) बैंकिंग क्षेत्र	3.2	1.2	2.2	4.1	2.7	-3.6	3.2
जिसमें से:							
वाणिज्यिक बैंक	2.7	1.2	1.7	3.9	2.4	-3.4	2.9
(ii) अन्य वित्तीय संस्थाएं	0.4	0.4	0.3	1.1	0.6	1.6	2.2
(ए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	0.0	0.2	0.6	1.1	0.5	1.3	2.1
(बी) आवास वित्त कंपनियां	0.3	0.2	-0.3	-0.1	...	0.3	0.1
(सी) बीमा कंपनियां	0.1
बी. गैर-वित्तीय कॉरपोरेशन्स (निजी कॉरपोरेट कारोबार)
सी. सामान्य (जेनरल) सरकार

... : नगण्य।

स्रोत: लेखकों द्वारा गणनाएं।

अनुबंध III
गृहस्थों की आस्तियां और देयताएं: चुनिंदा लिखत (जारी)

(₹ करोड़)

मद	2018-19			
	ति1	ति2	ति3	ति4
सकल वित्तीय आस्तियां				
<i>जिसमें से:</i>				
ए. बैंक जमाराशियां (i+ii)	80,16,804.2	83,09,422.5	83,22,543.8	88,62,016.6
i. वाणिज्यिक बैंक जमाराशियां	73,54,053.7	76,43,521.8	76,54,156.4	81,44,837.0
ii. सहकारी बैंक	6,62,750.5	6,65,900.7	6,68,387.4	7,17,179.6
बी. जीवन बीमा निधियां	34,83,772.7	35,77,442.2	36,61,493.5	37,85,298.5
सी. मुद्रा	17,82,923.3	17,50,788.9	18,53,445.4	19,49,205.8
डी. म्यूचुअल फंड	11,93,500.8	11,50,708.8	11,93,246.1	12,42,184.1
कुल (ए+बी+सी+डी)	1,44,77,001.0	1,47,88,362.4	1,50,30,728.8	1,58,38,705.0
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में				
ए. बैंक जमाराशियां (i+ii)	45.4	45.8	44.6	46.9
i. वाणिज्यिक बैंक जमाराशियां	41.7	42.1	41.0	43.1
ii. सहकारी बैंक	3.8	3.7	3.6	3.8
बी. जीवन बीमा निधियां	19.7	19.7	19.6	20.0
सी. मुद्रा	10.1	9.7	9.9	10.3
डी. म्यूचुअल फंड	6.8	6.3	6.4	6.6
कुल (ए+बी+सी+डी)	82.0	81.5	80.5	83.9
वित्तीय देयताएं				
ए. वित्तीय निगम (i+ii)	55,38,093.5	57,92,425.2	59,30,398.2	62,24,489.4
(i) बैंकिंग क्षेत्र	44,38,575.4	46,09,525.8	47,50,203.7	49,99,590.6
<i>जिसमें से:</i>				
वाणिज्यिक बैंक	39,79,179.8	41,48,818.2	42,90,152.8	45,13,762.6
सहकारी बैंक और क्रेडिट समितियां	4,58,988.3	4,60,294.8	4,59,632.6	4,85,404.3
(ii) अन्य वित्तीय संस्थाएं	10,99,518.0	11,82,899.4	11,80,194.5	12,24,898.8
<i>जिसमें से:</i>				
(ए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	3,74,640.0	4,27,245.2	4,23,489.4	4,52,442.0
(बी) आवास वित्त कंपनियां	6,14,618.4	6,42,947.2	6,42,160.4	6,56,279.2
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में				
ए. वित्तीय निगम (i+ii)	31.4	31.9	31.8	33.0
(i) बैंकिंग क्षेत्र	25.2	25.4	25.4	26.5
<i>जिसमें से:</i>				
वाणिज्यिक बैंक	22.5	22.9	23.0	23.9
सहकारी बैंक और क्रेडिट समितियां	2.6	2.5	2.5	2.6
(ii) अन्य वित्तीय संस्थाएं	6.2	6.5	6.3	6.5
<i>जिसमें से:</i>				
(ए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	2.1	2.4	2.3	2.4
(बी) आवास वित्त कंपनियां	3.5	3.5	3.4	3.5

स्रोत: लेखकों द्वारा गणनाएं

अनुबंध III
गृहस्थों की आस्तियां और देयताएं: चुनिंदा लिखत (समाप्त)

(₹ करोड़)

मद	2019-20				2020-21	
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2
सकल वित्तीय आस्तियां						
<i>जिसमें से:</i>						
ए. बैंक जमाराशियां (i+ii)	88,54,942.5	91,33,027.1	92,46,341.4	96,99,300.4	98,12,628.0	1,01,74,971.5
i. वाणिज्यिक बैंक जमाराशियां	81,31,543.2	84,01,018.7	84,65,016.2	89,13,602.7	90,31,564.8	93,83,425.0
ii. सहकारी बैंक	7,23,399.3	7,32,008.4	7,81,325.2	7,85,697.6	7,81,063.2	7,91,546.5
बी. जीवन बीमा निधियां	38,99,633.0	40,03,691.7	41,10,052.2	41,44,294.2	42,74,225.4	44,24,463.7
सी. मुद्रा	20,10,842.9	19,84,738.1	20,71,581.5	22,31,836.6	24,38,726.3	24,55,951.6
डी. म्यूचुअल फंड	12,65,870.9	12,79,310.8	13,85,427.2	11,62,077.9	13,30,498.9	14,02,082.6
कुल (ए+बी+सी+डी)	1,60,31,289.3	1,64,00,767.8	1,68,13,402.3	1,72,37,509.1	1,78,56,078.6	1,84,57,469.3
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में						
ए. बैंक जमाराशियां (i+ii)	45.8	46.6	46.4	47.7	51.0	53.5
i. वाणिज्यिक बैंक जमाराशियां	42.1	42.8	42.5	43.8	46.9	49.3
ii. सहकारी बैंक	3.7	3.7	3.9	3.9	4.1	4.2
बी. जीवन बीमा निधियां	20.2	20.4	20.6	20.4	22.2	23.2
सी. मुद्रा	10.4	10.1	10.4	11.0	12.7	12.9
डी. म्यूचुअल फंड	6.6	6.5	7.0	5.7	6.9	7.4
कुल (ए+बी+सी+डी)	83.0	83.6	84.4	84.7	92.8	97.0
वित्तीय देयताएं						
ए. वित्तीय निगम (i+ii)	64,05,501.2	64,85,261.3	66,16,023.3	68,88,281.5	68,10,523.9	70,65,360.1
(i) बैंकिंग क्षेत्र	51,60,907.8	52,18,793.8	53,34,039.9	55,50,612.3	54,12,139.7	55,62,020.1
<i>जिसमें से:</i>						
वाणिज्यिक बैंक	46,49,337.7	47,06,238.4	47,92,136.2	49,98,074.6	48,67,438.1	50,03,025.3
सहकारी बैंक और क्रेडिट समितियां	5,10,908.4	5,11,655.8	5,40,766.1	5,51,158.9	5,42,978.8	5,56,804.4
(ii) अन्य वित्तीय संस्थाएं	12,44,593.4	12,66,467.5	12,81,983.4	13,37,669.2	13,98,384.2	15,03,340.1
<i>जिसमें से:</i>						
(ए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4,51,922.3	4,63,573.6	4,92,790.6	5,50,302.0	6,01,337.5	7,02,394.4
(बी) आवास वित्त कंपनियां	6,73,312.1	6,81,405.2	6,65,694.8	6,62,601.7	6,73,118.3	6,75,993.4
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में						
ए. वित्तीय निगम (i+ii)	33.1	33.1	33.2	33.8	35.4	37.1
(i) बैंकिंग क्षेत्र	26.7	26.6	26.8	27.3	28.1	29.2
<i>जिसमें से:</i>						
वाणिज्यिक बैंक	24.1	24.0	24.0	24.6	25.3	26.3
सहकारी बैंक और क्रेडिट समितियां	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9
(ii) अन्य वित्तीय संस्थाएं	6.4	6.5	6.4	6.6	7.3	7.9
<i>जिसमें से:</i>						
(ए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	2.3	2.4	2.5	2.7	3.1	3.7
(बी) आवास वित्त कंपनियां	3.5	3.5	3.3	3.3	3.5	3.6

स्रोत: लेखकों द्वारा गणनाएं

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी लेखा और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक शृंखला

विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	97
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	98
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	99
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	100
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	101
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	101
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	102
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	103
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	104
9	कुल चलनिधि राशियां	104
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	105
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	105
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	106
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	106
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	107
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	108
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	109
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	110
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	111
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	111
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	111
21	थोक मूल्य सूचकांक	112
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	116
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	116
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	117
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	117
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	118
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	119
28	वाणिज्यिक पत्र	119
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	119
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	120

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	121
32	विदेशी मुद्रा भंडार	121
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	121
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	122
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	122
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	123
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	123
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	124
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	125
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	126
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	127
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	128
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	129
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	131
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	132
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	133
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	134
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	135
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	136

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

— = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2019-20	2019-20		2020-21	
		ति2	ति3	ति2	ति3
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	4.1	4.6	3.4	-7.3	1.0
1.1.1 कृषि	4.3	3.5	3.4	3.0	3.9
1.1.2 उद्योग	-2.0	-2.7	-3.0	-1.6	1.4
1.1.3 सेवाएं	6.4	7.3	5.8	-10.9	-0.04
1.1क अंतिम खपत व्यय	5.9	7.0	6.8	-13.6	-2.2
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	5.4	3.9	2.4	-6.8	2.6
	2019-20	2019	2020	2021	
	1	दिसं.	जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-0.8	0.4	2.2	1.0	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	7.9	9.7	9.9	10.8	11.1
2.1.2 ऋण	6.1	7.0	7.2	6.2	5.9
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	6.1	6.9	7.1	6.2	5.9
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	10.6	12.9	11.2	17.3	18.8
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	9.4	10.2	12.3	14.9	14.5
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.9	10.4	11.2	12.4	12.1
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.25	18.50	18.25	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.6	4.8	4.7	3.7	3.8
3.4 ऋण-जमा अनुपात	76.4	76.2	75.8	73.1	72.3
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	60.3	39.0	44.4	23.5	27.1
3.6 निवेश-जमा अनुपात	27.6	28.7	28.0	30.4	30.0
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	36.2	74.1	46.9	72.0	56.4
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.40	5.15	5.15	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	4.00	4.90	4.90	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.65	5.40	5.40	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.65	5.40	5.40	4.25	4.25
4.5 आधार दर	8.15/9.40	8.45/9.40	8.45/9.40	7.30/8.80	7.30/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.40/7.90	7.65/8.00	7.50/7.95	6.55/7.10	6.55/7.05
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	5.90/6.40	6.20/6.40	6.10/6.40	4.90/5.50	4.90/5.50
4.8 बचत जमा दर	3.00/3.50	3.25/3.50	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	5.05	5.11	4.94	3.24	3.23
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.36	5.03	5.13	3.08	3.35
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.97	5.22	5.24	3.34	3.56
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.94	5.30	5.29	3.46	3.68
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.71	6.78	6.86	5.89	5.96
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	74.84	71.22	71.51	73.58	72.95
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	82.64	79.19	78.82	89.81	88.30
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरीकी डॉलर					
1-माह (%)	8.98	3.96	3.52	3.84	4.19
3-माह (%)	5.93	3.90	4.25	3.75	5.48
6-माह (%)	5.05	4.38	4.21	4.35	5.13
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.76	7.4	7.6	4.6	4.1
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	7.54	9.6	7.5	3.7	3.2
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.69	2.8	3.5	1.2	2.0
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	6.77	11.5	10.0	-1.6	-2.2
6.3.2 ईंधन और पावर	-1.63	0.4	5.4	-8.7	-4.8
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	0.29	-0.3	0.6	4.2	5.1
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-7.66	-6.5	-0.7	7.6	2.0
7.2 निर्यात	-5.06	-2.7	-2.1	0.2	6.2

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2019-20	2020	2021				
			फर.	जन. 29	फर. 5	फर. 12	फर. 19
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2412993	2321924	2780045	2796268	2814203	2809908	2809858
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	10	13	13	12	17	14	21
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2413003	2321937	2780058	2796281	2814220	2809923	2809879
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	103439	100833	114391	110163	113240	109433	110589
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2308718	2220225	2664788	2685256	2700136	2699657	2698474
1.2.3 रुपया सिक्का	846	879	879	862	844	833	816
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1187409	990618	1512883	1472060	1503322	1520251	1532207
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	100	101	100	101	100	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	536186	550033	476349	483345	464804	499898	462156
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7603	6739	6536	5801	5224	5550	5257
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3445	3132	2619	2546	2533	2572	2430
2.1.1.7 अन्य बैंक	32641	31600	26397	26083	27273	27078	27383
2.1.1.8 अन्य	605100	398150	987112	943318	990850	972581	1018787
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	2291	822	13726	10825	12493	12429	16050
2.1.2 अन्य देयताएं	1350333	1219283	1440272	1412879	1421401	1409070	1415428
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	2537742	2209901	2953154	2884939	2924722	2929320	2947634
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	10	13	13	13	17	14	21
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1006357	1022250	1357052	1296393	1262183	1265537	1314777
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	50477	5081	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1967	2882	4769	9230	10918	6441	3938
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	285623	54186	84597	84614	84620	90521	84651
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	36	35	35
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	26181	23776	23996	26628	26848
2.2.3.7 एक्विजिशन बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	10064	1815	6643	6662	6662	6662	6662
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	2300	10336	6521	12016	28960	28857	29509
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1042951	983803	1308808	1299243	1348740	1349265	1322118
2.2.6 अन्य आस्तियां	137993	129535	158570	152992	158590	155361	159077
2.2.6.1 सोना	127644	120566	150412	144851	150344	146687	149649

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	विक्रय	क्रय	दीर्घावधि रिपो परिचालन&	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/एचएफसीएस के लिए विशेष चलनिधि योजना **	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12+13-2-4-7-8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जन. 1, 2021	-	733305	-	-	43	-399	-	-	-	-	-	-	-	-733661
जन. 2, 2021	-	42849	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-42818
जन. 3, 2021	-	1294	-	-	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-790
जन. 4, 2021	-	762852	-	-	102	-1201	-	-	-	-	-	-	-	-763951
जन. 5, 2021	-	765155	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-765118
जन. 6, 2021	-	710047	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-709992
जन. 7, 2021	-	709041	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-709041
जन. 8, 2021	-	669422	-	-	0	-	-	10000	10000	-	-	-	-	-669422
जन. 9, 2021	-	3483	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-3233
जन. 10, 2021	-	949	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-859
जन. 11, 2021	-	655478	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-655478
जन. 12, 2021	-	659817	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-659814
जन. 13, 2021	-	648243	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-648190
जन. 14, 2021	-	670642	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-670641
जन. 15, 2021	-	423872	-	200009	96	-553	-	10000	10000	-	-	-	-	-624338
जन. 16, 2021	-	20857	-	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-20694
जन. 17, 2021	-	869	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-849
जन. 18, 2021	-	438666	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-438545
जन. 19, 2021	-	451593	-	-	31	-	-	-	2895	-	-	-	-	-448667
जन. 20, 2021	-	415601	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-415579
जन. 21, 2021	-	428965	-	-	0	-834	-	-	-	-	-	-	-	-429799
जन. 22, 2021	-	409837	-	-	10	-	-	-	10000	-	-	-	-	-399827
जन. 23, 2021	-	2286	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-2251
जन. 24, 2021	-	5795	-	-	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-5716
जन. 25, 2021	-	412343	-	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-412218
जन. 26, 2021	-	3390	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-3115
जन. 27, 2021	-	424147	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-424147
जन. 28, 2021	-	467451	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-467397
जन. 29, 2021	-	485019	-	200007	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-685026
जन. 30, 2021	-	51422	-	-	0	-2500	-	-	-	-	-	-	-	-53922
जन. 31, 2021	-	1826	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-1825

नोट: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) शामिल है। ऋणात्मक (-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

** 01 जुलाई 2020 के आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिन्ह विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश के लिए प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।

& ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2019-20	2020		2021
		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	45097	10266	3991	2854
1.1 क्रय (+)	72205	11486	10014	18225
1.2 विक्रय (-)	27108	1220	6023	15371
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	312005	72793	29439	21486
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	45097	40007	72379	75233
(करोड़ ₹)	312005	278096	538628	560113
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-4939	-1215	39792	47383

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2019-20	2020		2021
		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7713	400	3985	1962
1.2 विक्रय (-)	7713	400	3985	1962
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	-500	0	1962	2196

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	31 जनवरी 2021 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	7047	1095	5952
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	5537	200	5337
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	44049	0	44049
4. 1 वर्ष से अधिक	2065	10020	-7955
कुल (1+2+3+4)	58698	11315	47383

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2019-20	2020					2021	
		फर. 28	सितं. 25	अक्टू. 23	नव. 20	दिसं. 18	जन. 29	फर. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	1262	4130	50	6	266	1	0	58
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	10000	2800	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	4782	1815	0	-	0	0	0	0
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	65000	65000	75000	82500	75000	75000
4.2 बकाया	-	-	37691	36488	33234	34760	32205	32842
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	6044	5945	37741	36494	33500	34761	32205	32900

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एक्विजिब बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू/एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2019-20	2020		2021	
		जन. 31	दिसं. 18	जन. 15	जन. 29
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2349748	2218776	2681512	2717023	2707213
1.1 संचलन में नोट	2420964	2284695	2749859	2783749	2780045
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25605	25537	25875	25938	26004
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	97563	92198	94965	93407	99579
2 जनता की जमाराशियां	1776200	1583039	1728417	1738318	1857474
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1737692	1549183	1686628	1695727	1814252
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	33856	41788	42591	43222
3 एम₁ (1 + 2)	4125948	3801815	4409929	4455341	4564687
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	150963	143624	150963	150963	150963
5 एम₂ (3 + 4)	4276911	3945439	4560892	4606304	4715650
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	12674016	12616809	13645443	13783957	13836979
7 एम₃ (3 + 6)	16799963	16418625	18055372	18239299	18401666
8 कुल डाकघर जमाराशियां	433441	415251	433441	433441	433441
9 एम₄ (7 + 8)	17233404	16833876	18488813	18672740	18835107

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2020		2021	
		जन. 31	दिसं. 18	जन. 15	जन. 29
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5014594	5637236	5718167	5735483
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	992192	1057037	980473	1051665	1058048
1.1.1 सरकार पर दावे	1047808	1057180	1290946	1304662	1312493
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1045314	1055970	1284643	1294706	1307724
1.1.1.2 राज्य सरकारें	2494	1210	6303	9955	4769
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाशियां	55616	143	310473	252996	254445
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	55573	101	310431	252954	254403
1.1.2.2 राज्य सरकारें	43	42	42	43	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3968170	3957557	4656763	4666502	4677435
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	10756624	11204826	11298773	11362375
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13166	6380	11205	9341	8601
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11025478	10750244	11193621	11289433	11353774
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10370861	10105176	10547037	10640563	10704637
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	637776	632356	636368	638529	639026
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	16842	12711	10216	10341	10111
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	3801036	3559574	4565412	4548358	4576923
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	3590402	3351074	4267681	4250627	4279192
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	3590636	3351293	4267926	4250872	4279437
3.1.2 विदेशी देयताएं	234	219	245	245	245
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	210634	208500	297731	297731	297731
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26280	26618	26681	26747
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	3026427	2938447	3378721	3352681	3299860
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1378342	1158386	1478577	1446551	1436430
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1648085	1780061	1900144	1906130	1863430
एम₃ (1+2+3+4-5)	16799963	16418625	18055372	18239299	18401666

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2020		2021	
		जन. 31	दिसं. 18	जन. 15	जन. 29
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4125948	3801815	4409929	4455341	4564687
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	9745776	9399400	10476478	10584092	10716907
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	16923893	16552196	18142693	18319205	18479351
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2218776	2681512	2717023	2707213
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	14226198	13988261	15167848	15315172	15485853
1.2.1 मांग जमाराशियां	1737692	1549183	1686628	1695727	1814252
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	12488506	12439078	13481220	13619445	13671601
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5619828	5597585	6066549	6128750	6152220
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	176959	67260	68287	63159
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6868678	6841493	7414671	7490695	7519380
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	33856	41788	42591	43222
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	309439	311303	251545	244418	243063
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16857025	16647002	17794756	17966992	18048596
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5014594	5637236	5718167	5735483
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	992192	1057037	980473	1051665	1058048
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3968170	3957557	4656763	4666502	4677435
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11896663	11632408	12157520	12248825	12313113
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	13166	6380	37338	35522	34782
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11883497	11626028	12120182	12213303	12278331
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	846284	865080	917177	914395	914781
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26280	26618	26681	26747
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3612303	3307262	4461072	4480078	4486180
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3351074	4267681	4250627	4279192
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	21900	-43812	193391	229451	206988
2.4 पूंजी खाता	2670439	2497037	2872234	2845759	2839875
2.5 अन्य मदें (निवल)	901344	931311	1267520	1308788	1242296

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2019-20	2020			2021
		जन.	नव.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	16923893	16552196	18036372	18142693	18479351
2 डाकघर जमाराशियां	433441	415251	433441	433441	433441
3 एल₁ (1 + 2)	17357334	16967447	18469813	18576134	18912792
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	57479	56400	34778	34794	31930
4.1 सावधि मुद्रा उधार	7928	2976	2645	2645	2645
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	46249	49631	28600	28865	25065
4.3 सावधि जमाराशियां	3302	3793	3533	3284	4220
5 एल₂ (3 + 4)	17414812	17023847	18504591	18610928	18944722
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	..
7 एल₃ (5 + 6)	17446717	18642833	..

टिप्पणी : 1. नवंबर 2019 के बाद से, वित्तीय संस्थानों की देयताओं पर अद्यतन डेटा इस सारणी में शामिल किया गया है, और इसलिए, पिछले डेटा के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

2. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2020		2021	
		जन. 31	दिसं. 18	जन. 15	जन. 29
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2447312	2310975	2776477	2810430	2806792
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	543888	592254	522176	518348	511901
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	505131	550704	488262	483618	476349
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	33856	41788	42591	43222
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3029707	2937085	3340442	3371369	3361915
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	791299	718117	524719	540613	492406
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	992192	1057037	980473	1051665	1058048
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	989741	1055869	974212	1041752	1053321
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	73545	-	-	-
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1044468	981706	1283889	1293804	1306845
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1044468	981706	1283889	1293804	1306845
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	846	719	754	902	879
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	55573	101	310431	252954	254403
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	2451	1168	6261	9913	4727
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-214059	-345300	-493092	-546574	-600423
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-214059	-345300	-466959	-520393	-574242
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	13166	6380	37338	35522	34782
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	5920	1872	1	1	1
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	26133	26181	26181
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26280	26618	26681	26747
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3351074	4267681	4250627	4279192
2.3.1 सोना	230527	206919	272328	263499	264803
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3359893	3144172	3995371	3987145	4014406
2.4 पूंजी खाता	1165066	1010660	1292910	1259803	1250074
2.5 अन्य मदें (निवल)	213276	147726	185667	186748	186356

सं. 11: रिज़र्व बैंक - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

Item	मार्च 31/माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया							
	2019-20	2020		2021				
		जन. 31	दिसं. 25	जन. 1	जन. 8	जन. 15	जन. 22	जन. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3029707	2937085	3314167	3322152	3327913	3371369	3351957	3361915
1 घटक								
1.1 संचलन में मुद्रा	2447312	2310975	2778139	2770377	2797923	2810430	2811202	2806792
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	543888	592254	493293	509365	487500	518348	498025	511901
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	33856	42736	42410	42490	42591	42730	43222
2 स्रोत								
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	992192	1057037	1011641	1102053	1047688	1051665	1014168	1058048
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-214059	-345300	-524695	-630217	-567224	-520393	-498966	-574242
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	13166	6380	11205	11496	11122	9341	8515	8601
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	3351074	4263000	4269569	4279363	4250627	4245756	4279192
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26348	26280	26681	26681	26681	26681	26681	26747
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1378342	1158386	1473664	1457429	1469718	1446551	1444196	1436430

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2020		2021	
		जन. 31	दिसं. 18	जन. 15	जन. 29
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	13381983	13146270	14314737	14460445	14632387
1.1.1 मांग जमाराशियां	1617003	1431011	1564598	1573361	1691542
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11764979	11715259	12750139	12887084	12940845
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5294241	5271866	5737562	5799188	5823380
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	176959	67260	68287	63159
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6470739	6443392	7012576	7087896	7117465
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	309439	311303	251545	244418	243063
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14967529	14707775	15878503	15977889	16055128
2.1.1 सरकार को ऋण	3738696	3730741	4411845	4420359	4432987
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11228833	10977034	11466658	11557530	11622141
2.1.2.1 बैंक ऋण	10370861	10105176	10547037	10640563	10704637
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10319097	10026276	10453884	10553613	10617527
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	11997	10967	9647	9739	10040
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	8653	4773	1759	1796	1646
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	837321	856117	908214	905432	905819
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	21900	-43812	193391	229451	206988
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	315641	242206	418715	449581	428781
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	185510	177731	164224	164512	165378
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	108231	108287	61101	55617	56415
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	899410	977849	1040155	1087439	1140062
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	536186	550704	488262	483618	476349
2.3.2 उपलब्ध नकदी	87260	81845	84934	83428	89471
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-275964	-345300	-466959	-520393	-574242
2.4 पूंजी खाता	1481202	1462206	1555153	1561785	1565630
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	716216	722033	990614	1028130	961097
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	495445	435443	553551	514540	558300
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	66273	54114	69404	82356	73170

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 27, 2020 की स्थिति	2020		2021	
		जन. 31	दिसं. 18	जन. 15	जन. 29
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3747349	3735514	4413605	4422032	4434633
2 वाणिज्यिक पत्र	104526	94533	75341	72243	74534
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	14106	12172	11241	11671	12011
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	75415	67153	70834	70218	69795
3.3 अन्य	5734	5558	5409	5463	5450
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	125710	128910	127646	126269	127296
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	226559	230608	313097	313456	311745
4.3 अन्य	191690	191035	142431	140726	141012
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	35610	42463	29618	33711	30468
5.2 वित्तीय संस्थाएं	97665	79815	132419	131674	133507

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2019-20	2020		2021	2019-20	2020		2021
		जन.	दिसं.	जन.		जन.	दिसं.	जन.
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	219	219	208	208	142	142	132	132
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	320240	279961	269495	261071	314513	274771	264487	256186
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	239943	199889	208104	202625	234348	194935	203319	197957
1.2 बैंकों से उधार राशि	64001	66900	44060	41913	64001	66868	44058	41913
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	16295	13172	17331	16533	16163	12968	17110	16316
2 अन्य के प्रति देयताएं	14905949	14598202	15805240	16090003	14480607	14179034	15372567	15655544
2.1 कुल जमाराशियां	13975551	13726481	14904791	15216594	13567492	13324001	14488370	14797766
2.1.1 मांग	1653242	1463589	1601779	1728346	1617003	1431011	1565783	1691542
2.1.2 मीयादी	12322309	12262891	13303012	13488248	11950489	11892990	12922587	13106224
2.2 उधार	313908	315590	257321	247395	309439	311303	252891	243063
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	616491	556132	643127	626015	603676	543730	631306	614715
3 रिजर्व बैंक से उधार	285623	16915	77318	84597	285623	16915	77318	84597
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	285623	16915	77318	84597	285623	16915	77318	84597
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	643038	650927	557529	581938	623446	632549	542590	565820
4.1 उपलब्ध नकदी	89671	84191	86836	91572	87260	81845	84872	89471
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	553367	566736	470693	490366	536186	550704	457719	476349
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	323680	290256	264863	254454	260238	231623	204254	193056
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	181460	178084	180945	173964	155401	151373	147352	140128
5.1.1 चालू खाते में	17204	24273	17423	15853	14457	21376	15174	13638
5.1.2 अन्य खातों में	164256	153811	163522	158111	140945	129997	132178	126491
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	43335	37079	31389	32442	20273	20180	8512	10113
5.3 बैंकों को अग्रिम	38266	32315	21271	19319	30531	24959	20573	17286
5.4 अन्य आस्तियां	60619	42777	31259	28730	54032	35111	27817	25529
6 निवेश	3865544	3849568	4537040	4566911	3747349	3735514	4403341	4434633
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3850819	3838797	4528809	4558741	3738696	3730741	4401696	4432987
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	14724	10771	8231	8170	8653	4773	1645	1646
7 बैंक ऋण	10705336	10431745	10926301	11046806	10370861	10105176	10587475	10704637
7क खाद्यान्न ऋण	82172	108222	126156	117510	51763	78899	95755	87110
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	10480934	10214455	10752941	10865977	10149509	9891378	10416107	10525849
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	26214	25518	22894	23812	25658	24595	22629	23549
7.3 देशी बिल - भुनाए गए	147209	136629	101639	108219	145683	135171	100728	107357
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20866	23000	18020	18217	20458	22422	17727	17852
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	30114	32142	30808	30581	29554	31611	30285	30031

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति			वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2020	2021	वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जन. 31	जन. 29		
	1	2	3	%	%
1 सकल बैंक ऋण	9263132	8978800	9497150	2.5	5.8
1.1 खाद्यान्न ऋण	51590	78664	86817	68.3	10.4
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	9211542	8900136	9410333	2.2	5.7
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1157795	1153386	1267714	9.5	9.9
1.2.2 उद्योग	2905151	2817524	2781575	-4.3	-1.3
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु ¹	385834	373050	376297	-2.5	0.9
1.2.2.2 मझौले	101588	106813	127227	25.2	19.1
1.2.2.3 बड़े	2417729	2337661	2278051	-5.8	-2.5
1.2.3 सेवाएं	2594947	2431976	2636628	1.6	8.4
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	140142	139160	151553	8.1	8.9
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20050	18775	18731	-6.6	-0.2
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	45978	45395	49413	7.5	8.9
1.2.3.4 शिपिंग	6557	6682	7183	9.5	7.5
1.2.3.5 नौवहन	6429	5581	12280	91.0	120.0
1.2.3.6 पेशेवर सेवाएं	176997	172206	129080	-27.1	-25.0
1.2.3.7 व्यापार	552391	519547	600957	8.8	15.7
1.2.3.7.1 थोक व्यापार	263396	237341	298232	13.2	25.7
1.2.3.7.2 खुदरा व्यापार	288995	282207	302725	4.8	7.3
1.2.3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	229770	227266	233671	1.7	2.8
1.2.3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ²	904785	831186	885852	-2.1	6.6
1.2.3.9.1 आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	216532	149684	150390	-30.5	0.5
1.2.3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	39789	28325	71109	78.7	151.0
1.2.3.10 अन्य सेवाएं ³	511847	466179	547910	7.0	17.5
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2553649	2497250	2724415	6.7	9.1
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	9299	6453	7397	-20.4	14.6
1.2.4.2 आवास	1338961	1316473	1417538	5.9	7.7
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	79494	67240	67176	-15.5	-0.1
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	5334	5185	4163	-22.0	-19.7
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	108097	110864	116361	7.6	5.0
1.2.4.6 शिक्षा	65744	67038	64364	-2.1	-4.0
1.2.4.7 वाहन ऋण	220610	220240	235882	6.9	7.1
1.2.4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	26192	18596	43141	64.7	132.0
1.2.4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	699919	685162	768392	9.8	12.1
1.2ए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)					
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां ⁴	1133726	1125885	1246880	10.0	10.7
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	1078702	1079522	1148502	6.5	6.4
1.2अ.3 मध्यम उद्यम ⁶	132360	127608	163182	23.3	27.9
1.2अ.4 आवास	459573	463249	470361	2.3	1.5
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	50335	53335	50014	-0.6	-6.2
1.2अ.6 नवीकरणीय ऊर्जा	1037	875	1282	23.6	46.4
1.2अ.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	997	997	1971	97.6	97.7
1.2अ.8 निर्यात ऋण ⁷	16575	13508	17151	3.5	27.0
1.2अ.9 अन्य	12852	14055	14765	14.9	5.0
1.2अ.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	725267	735960	766466	5.7	4.1

टिप्पणी : 1: डेटा अनंतिम हैं और उन चुनिंदा बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत कवर करते हैं।

टिप्पणी : 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता- प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण और पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल हैं।
7. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत निर्यात ऋण विदेशी बैंकों से संबंधित हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति			वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2020	2021	वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		जन. 31	जन. 29	2020-21	2021
	1	2	3	%	%
1 उद्योग (2.1 से 2.19)	2905151	2817524	2781575	-4.3	-1.3
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	43926	41886	45477	3.5	8.6
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	154145	150279	155367	0.8	3.4
1.2.1 चीनी	27382	26288	21261	-22.4	-19.1
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19239	20745	19678	2.3	-5.1
1.2.3 चाय	5374	5438	5728	6.6	5.3
1.2.4 अन्य	102149	97809	108700	6.4	11.1
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	16523	14991	15084	-8.7	0.6
1.4 वस्त्र	192423	190108	209457	8.9	10.2
1.4.1 सूती वस्त्र	89283	87850	94115	5.4	7.1
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2116	2198	2606	23.2	18.5
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	26074	26017	29779	14.2	14.5
1.4.4 अन्य वस्त्र	74951	74044	82957	10.7	12.0
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11098	10882	11203	0.9	3.0
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	12234	12205	13285	8.6	8.8
1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	30965	31085	34933	12.8	12.4
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आपिचक इंधन	75834	55621	56586	-25.4	1.7
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	202949	183049	181423	-10.6	-0.9
1.9.1 उर्वरक	49066	34535	40642	-17.2	17.7
1.9.2 औषधि और दवाइयां	53427	52073	49688	-7.0	-4.6
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	42233	40697	37497	-11.2	-7.9
1.9.4 अन्य	58223	55744	53596	-7.9	-3.9
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	50415	49254	50630	0.4	2.8
1.11 कांच और कांच के सामान	8777	8678	9147	4.2	5.4
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	58689	57715	57536	-2.0	-0.3
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	350325	335104	328174	-6.3	-2.1
1.13.1 लोहा और स्टील	262396	252173	240332	-8.4	-4.7
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	87930	82931	87841	-0.1	5.9
1.14 सभी अभियांत्रिकी	157258	157586	142592	-9.3	-9.5
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	30158	33594	30866	2.3	-8.1
1.14.2 अन्य	127100	123992	111726	-12.1	-9.9
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	82606	79794	83784	1.4	5.0
1.16 रत्न और आभूषण	59515	59841	61347	3.1	2.5
1.17 निर्माण	104288	105113	99542	-4.6	-5.3
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1053913	1036852	996326	-5.5	-3.9
1.18.1 पावर	559774	559305	557395	-0.4	-0.3
1.18.2 दूरसंचार	143760	136080	85984	-40.2	-36.8
1.18.3 सड़क	176549	182064	194843	10.4	7.0
1.18.4 हवाई अड्डा	4824	3871	5840	21.1	50.9
1.18.5 बंदरगाह	10880	7227	7481	-31.2	3.5
1.18.6 रेलवे	10607	9905	10723	1.1	8.3
1.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	147518	138400	134059	-9.1	-3.1
1.19 अन्य उद्योग	239269	237480	229682	-4.0	-3.3

जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2019-20	2019	2020						
		दिसं. 27	अक्टू. 30	नव. 06	नव. 20	नव. 27	दिसं. 04	दिसं. 18	दिसं. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	31	31	31	31	31	31	31
1 कुल जमा राशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	124101.8	124123.0	127348.2	126623.2	126400.7	124182.3	124679.0	127836.9	127688.1
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	26213.8	23898.4	22714.0	22228.4	21539.4	22657.4	22959.7	22479.4	22420.6
2.1.1 जमा राशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5295.0	4319.4	4028.2	4299.3	4178.6	3926.9	4406.7	4330.2	4320.8
2.1.1.2 अन्य	14523.6	13592.6	13517.3	12827.8	13208.0	13223.4	13330.3	14031.1	13619.4
2.1.2 बैंकों से उधार	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	6295.2	5986.4	5168.5	5101.3	4152.8	5507.1	5222.7	4118.0	4480.4
2.2 मीयादी देयताएं	167684.5	163309.8	172354.2	171935.1	171251.9	170392.8	170213.1	172959.7	173948.2
2.2.1 जमा राशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	56564.0	51119.9	56969.6	56563.3	55366.5	57870.7	57309.3	56572.7	57412.6
2.2.1.2 अन्य	109578.2	110530.4	113830.9	113795.4	113192.7	110958.9	111348.7	113805.9	114068.7
2.2.2 बैंकों से उधार	630.2	743.7	629.9	629.9	635.6	629.9	629.9	630.0	630.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	912.1	915.9	923.8	946.4	2057.1	933.2	925.2	1951.2	1836.9
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	52772.2	48678.0	55909.0	56918.9	57068.0	58359.7	57545.6	57588.8	58628.3
4.1 मांग	13764.4	14382.0	13041.1	13813.2	14207.1	14440.6	13705.2	13030.4	13515.1
4.2 मीयादी	39007.8	34296.0	42867.9	43105.7	42860.9	43919.1	43840.4	44558.4	45113.2
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	9428.2	8953.3	7238.4	7031.6	6877.4	7131.8	7135.7	7052.5	7115.9
5.1 उपलब्ध नकदी	750.5	723.4	558.9	552.9	576.0	546.8	540.3	585.2	559.5
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	8677.8	8229.9	6679.5	6478.6	6301.4	6585.0	6595.4	6467.4	6556.4
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1521.7	745.6	935.7	837.1	822.1	897.3	967.2	768.5	925.6
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	50626.9	50055.0	58774.4	60209.9	59731.1	60795.8	61404.9	60836.1	61776.2
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	25283.9	25039.3	24871.2	24593.9	23939.7	24676.4	24138.4	25466.5	25977.3
9 बैंक ऋण (10.1+11)	110905.5	101056.2	111109.5	110024.6	110526.4	110246.6	108885.6	110148.8	111467.9
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	110901.5	101051.9	111093.5	110008.6	110510.4	110230.7	108869.6	110132.9	111451.9
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	81300.1	77214.1	82258.8	83798.2	84174.2	84270.3	84699.4	86694.6	86450.6
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	4.0	4.3	16.0	16.0	16.0	16.0	15.9	15.9	16.0

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2019-20			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जन. '20	दिसं.'20	जन.'21(अ)	जन.'20	दिसं.'20	जन.'21(अ)	जन.'20	दिसं.'20	जन.'21(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	146.3	149.6	147.5	153.0	159.6	155.7	154.4	163.4	160.8	153.5	161.0	157.6
1.1 अनाज और उत्पाद	140.7	143.2	141.4	143.7	143.4	142.9	145.6	148.0	147.7	144.3	144.9	144.4
1.2 मांस और मछली	163.3	161.4	162.6	167.3	187.5	186.1	167.6	194.8	192.5	167.4	190.1	188.4
1.3 अंडा	142.1	145.7	143.5	153.5	173.4	174.3	157.0	178.4	175.7	154.9	175.3	174.8
1.4 दूध और उत्पाद	146.5	146.0	146.3	150.5	154.0	154.1	149.3	154.4	154.4	150.1	154.1	154.2
1.5 तेल और चर्बी	127.1	121.8	125.1	132.0	154.8	159.7	126.3	144.1	148.4	129.9	150.9	155.5
1.6 फल	144.0	148.8	146.2	142.2	147.0	147.9	144.4	152.6	153.1	143.2	149.6	150.3
1.7 सब्जी	163.5	187.8	171.7	191.5	187.8	157.1	207.8	206.8	182.8	197.0	194.2	165.8
1.8 दाल और उत्पाद	133.7	132.0	133.1	141.1	159.5	158.7	139.1	162.1	160.2	140.4	160.4	159.2
1.9 चीनी और उत्पाद	112.0	113.4	112.5	113.8	113.8	112.9	114.8	116.3	115.5	114.1	114.6	113.8
1.10 मसाले	145.6	145.1	145.5	151.6	164.5	165.2	149.5	163.0	163.0	150.9	164.0	164.5
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	138.8	130.2	135.2	139.7	156.1	158.6	131.1	145.9	147.7	136.1	151.8	154.0
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	157.6	156.7	157.2	158.7	164.3	165.1	158.5	167.2	168.5	158.6	165.6	166.7
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	166.3	169.0	167.0	168.6	184.6	185.8	170.8	191.8	192.7	169.2	186.5	187.6
3 कपड़ा और जूते	151.3	143.7	148.3	152.1	156.8	157.5	144.9	150.2	151.0	149.2	154.2	154.9
3.1 कपड़ा	152.0	145.7	149.5	152.8	157.5	158.2	147.0	152.5	153.3	150.5	155.5	156.3
3.2 जूते	146.9	132.4	140.9	147.4	152.4	153.1	133.2	137.3	137.8	141.5	146.1	146.7
4 आवास	--	152.2	152.2	--	--	--	153.9	157.7	158.9	153.9	157.7	158.9
5 ईंधन और लाइट	148.6	131.5	142.2	150.4	150.9	152.9	135.1	142.9	145.7	144.6	147.9	150.2
6 विविध	145.6	135.9	140.9	148.1	155.9	156.7	138.4	147.6	148.4	143.4	151.9	152.7
6.1 घरेलू सामान और सेवा	150.6	138.7	145.0	151.7	153.9	154.2	140.1	145.7	146.0	146.2	150.0	150.3
6.2 स्वास्थ्य	153.6	142.1	149.3	155.7	162.5	163.5	143.8	154.1	155.1	151.2	159.3	160.3
6.3 परिवहन और संचार	132.6	122.2	127.1	136.3	147.5	148.7	126.1	136.9	138.1	130.9	141.9	143.1
6.4 मनोरंजन	148.3	135.9	141.3	150.1	155.1	156.1	137.2	145.4	146.5	142.8	149.6	150.7
6.5 शिक्षा	159.8	150.9	154.5	161.7	163.5	163.3	152.1	156.1	156.8	156.1	159.2	159.5
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	139.2	138.4	138.9	142.5	156.2	156.9	142.1	157.7	158.2	142.3	156.8	157.4
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	147.3	145.1	146.3	151.9	158.5	156.8	148.2	156.0	155.7	150.2	157.3	156.3

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2019-20	2020		2021
				जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	--	--	118.8	118.2
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	980	1016	1047	1038
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	--	986	1021	1053	1045

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2019-20	2020		2021
		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	37018	39984	49444	49612
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	42514	46498	64757	66785

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2020			2021
			जन.	नव.	दिसं. (अ)	जन. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	121.8	123.4	125.1	124.5	125.9
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	143.3	147.2	152.8	146.5	143.9
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	155.8	160.5	170.1	160.8	156.0
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.6	165.0	158.8	157.5	157.2
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	174.7	180.9	218.8	179.2	158.6
1.1.1.3 दूध	4.440	146.7	149.0	154.7	154.3	154.3
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	147.0	153.1	149.0	151.3	150.4
1.1.1.5 मसाले	0.529	143.9	156.9	156.5	153.4	151.4
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.0	143.5	165.7	164.4	166.2
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	128.7	132.1	138.0	138.2	137.6
1.1.2.1 फाइबर	0.839	128.2	124.1	120.3	123.5	125.9
1.1.2.2 तिलहन	1.115	151.4	157.1	162.0	164.4	171.0
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	104.8	105.8	114.0	114.3	114.2
1.1.2.4 फूल	0.204	238.0	280.7	310.4	285.0	228.7
1.1.3 खनिज	0.833	154.5	153.8	157.4	153.3	157.4
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	147.4	144.4	150.1	146.8	150.1
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	179.0	186.6	183.0	176.1	183.0
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	85.3	86.9	67.5	67.5	73.9
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	102.2	104.7	94.2	94.2	99.7
1.2.1 कोल	2.138	125.3	126.5	126.5	127.0	127.0
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	138.1	141.9	141.9	141.9	141.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	129.1	131.1	131.1	131.1	131.1
1.2.2 खनिज तेल	7.950	92.3	93.8	76.6	81.1	85.6
1.2.3 बिजली	3.064	111.8	117.9	117.4	105.3	117.4
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	118.3	118.8	121.6	123.0	124.9
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	133.9	138.3	142.4	143.7	144.9
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.5	135.8	137.2	137.7	139.0
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	136.1	134.3	135.8	135.4	139.1
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	114.6	122.4	121.8	121.5
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	119.3	131.6	148.1	153.9	158.3
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	145.0	151.4	144.9	146.1	147.4
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	146.3	147.1	142.3	141.5	141.9
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	135.5	136.1	111.4	117.2	119.7
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	133.5	135.7	138.5	139.2	139.1
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	118.3	120.2	118.4	118.6	116.9
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	127.2	125.7	128.5	126.0	126.0
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.7	131.7	133.5	128.8	130.2
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	139.7	130.1	172.2	163.7	159.1
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	132.4	135.8	147.5	149.1	150.5
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	128.7	129.9	131.8	133.7	133.1
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	159.9	157.2	140.4	137.9	138.8
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	173.6	174.9	171.6	171.5	170.7
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	123.6	124.1	123.6	123.2	124.4
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	117.8	118.3	119.6	119.4	121.4
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	125.7	126.3	125.9	124.3	124.6
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	130.5	130.8	127.8	128.1	128.5
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	153.4	152.0	156.1	156.9	157.7
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	153.4	152.0	156.1	156.9	157.7

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2020			2021
			जन.	नव.	दिसं. (अ)	जन. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.7	116.4	116.8	118.3	122.4
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	107.9	105.5	105.5	107.7	113.2
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	130.1	129.8	130.9	132.1	135.3
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	114.5	114.9	115.0	114.2	114.9
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	134.5	133.4	132.5	132.8	133.5
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	143.1	147.2	157.6	159.5	160.7
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.8	116.1	114.8	114.7	115.5
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.3	137.8	139.5	139.0	139.5
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.2	138.6	138.3	137.9	138.6
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	135.9	135.7	142.8	142.0	142.0
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	118.6	117.4	117.9	118.5	117.6
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	105.5	102.4	100.6	100.4	100.6
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	136.3	136.1	137.9	139.0	139.6
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.3	119.8	120.9	121.7	120.0
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	133.7	132.8	134.7	134.7	136.3
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	122.2	121.1	120.1	121.1	122.1
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	135.5	135.1	136.1	136.3	138.2
1.3.7.3 बिल्डरों की बढईगीरी	0.036	176.2	178.0	189.5	188.5	190.2
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.7	122.3	127.5	126.2	127.1
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	121.1	120.3	120.0	120.7	123.2
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	125.0	122.6	121.3	122.5	125.3
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	115.0	116.9	123.3	123.0	125.5
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	121.2	119.9	114.8	115.5	117.3
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	150.6	152.0	157.3	158.4	155.1
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	150.6	152.0	157.3	158.4	155.1
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	117.5	116.2	118.2	119.3	120.4
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	119.9	116.8	117.8	118.7	122.0
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.1	122.7	123.0	123.6	123.6
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	112.4	110.8	118.1	121.6	122.3
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	122.6	121.5	125.8	125.8	125.3
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	114.7	114.3	114.4	115.9	116.9
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	118.6	119.0	121.3	121.4	121.5
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	114.2	113.4	115.0	114.6	116.0
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	97.9	95.6	91.5	95.7	96.7
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	127.3	130.6	132.0	131.1	131.2
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	127.3	130.6	132.0	131.1	131.2
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	108.5	108.1	112.0	113.2	116.0
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	99.3	97.5	98.0	99.4
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.5	93.2	92.6	93.4	94.1
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	115.4	114.7	121.9	123.6	127.4
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	116.7	115.7	116.9	117.3	115.9
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	124.5	126.2	126.4	127.6	129.4
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	108.7	108.6	110.2	109.7	110.1
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	102.8	104.5	113.3	110.8	108.4
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	113.9	114.8	108.0	109.7	111.1
1.3.13.5 सीमेन्ट, गूना और प्लास्टर	1.645	119.5	117.9	119.1	120.1	118.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2020			2021
			जन.	नव.	दिसं. (अ)	जन. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेंट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.6	122.5	126.0	127.2	125.9
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	120.2	118.9	120.9	121.1	122.9
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	86.6	78.1	81.3	75.2	55.3
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	106.2	106.5	111.5	115.5	121.9
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	100.6	102.3	108.4	116.0	122.8
1.3.14.2 मेटेलिक आयसन	0.653	107.7	107.8	113.6	120.8	128.0
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	95.1	96.3	100.0	103.0	106.6
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	105.5	104.9	112.8	117.3	124.5
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	108.7	106.9	118.2	123.9	135.2
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	102.8	101.6	107.7	114.4	119.8
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	102.9	105.3	106.3	107.7	125.2
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.2	126.9	126.7	130.7	132.4
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	107.0	106.9	113.5	116.9	118.8
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	112.8	111.7	109.5	108.9	110.1
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	146.5	147.1	145.4	146.5	147.6
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.5	115.2	115.9	118.0	119.6
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	113.9	113.0	113.3	114.9	117.7
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	124.4	124.2	127.4	132.7	136.4
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरस को छोड़कर	0.145	104.7	106.3	96.9	97.2	97.2
1.3.15.4 धातु की फॉर्मिंग, दबाना, स्टैंपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	100.5	98.2	98.0	100.6	96.5
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	100.5	101.8	104.1	104.7	103.9
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	124.0	124.4	125.7	125.9	128.0
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	110.4	109.6	108.6	109.2	110.1
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	98.1	97.4	100.6	100.3	99.3
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.0	135.0	134.0	134.4	134.4
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	117.0	116.8	114.4	114.6	115.1
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	98.8	96.9	94.7	95.8	99.2
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	111.5	110.6	106.4	109.6	108.8
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	139.1	140.5	141.7	141.7	141.8
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.6	104.9	103.1	102.5	101.5
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	110.2	112.2	95.6	95.2	95.2
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.3	110.8	113.2	115.0	116.0
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	109.0	108.4	112.0	115.0	115.2
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.0	116.6	117.8	117.9	118.4
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	109.9	108.0	99.5	99.4	102.7
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	109.7	110.5	116.1	119.3	122.0
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	111.3	111.2	109.5	111.4
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.9	118.3	119.2	119.8	120.6
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	108.3	109.9	111.6	111.8
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	113.1	113.2	113.8	114.5	115.2
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	104.8	104.8	104.4	107.0	106.9
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.9	120.1	120.2	120.6	120.9
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.2	112.3	111.5	111.7	111.8
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गैयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	110.1	111.2	110.4	113.5	112.8
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	80.0	80.9	83.7	83.6	84.3
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	111.5	111.7	113.5	113.8	115.9

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2020			2021
			जन.	नव.	दिसं. (अ)	जन. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	130.9	127.8	127.7	127.2	130.6
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	120.6	121.1	121.6	121.9	123.0
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.1	108.2	108.2	107.7	108.2
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.1	75.7	75.6	75.9	76.4
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	125.2	126.3	131.7	131.9	131.1
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.7	119.3	123.3	123.4	124.1
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	126.3	125.9	128.4	129.1	129.3
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	66.0	65.4	65.5	65.9	66.0
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	114.5	116.0	117.9	118.4	118.5
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	115.2	116.4	120.1	120.5	120.8
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	113.7	115.5	115.5	116.1	116.0
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	118.0	118.7	127.5	127.6	127.9
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	106.4	107.0	104.8	104.6	104.6
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	114.3	115.2	126.5	126.5	126.8
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	128.9	128.2	128.7	129.5	130.9
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	126.1	127.4	127.7	128.1	129.3
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	130.9	132.9	133.6	134.0	135.7
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	130.9	132.9	133.6	134.0	135.7
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	112.7	113.9	135.0	135.9	133.1
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	109.9	111.1	133.3	134.3	131.2
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.0	177.2	170.2	164.3	175.1
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	129.7	131.7	131.8	131.9	131.3
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	136.9	134.6	141.5	143.0	143.0
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	162.1	162.9	168.5	168.1	168.9
2 खाद्य सूचकांक	24.378	147.6	152.2	159.7	154.4	151.8

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2018-19	2019-20	अप्रैल-दिसंबर		दिसंबर	
				2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	130.1	129.0	128.8	111.4	134.5	135.9
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	107.9	109.6	104.0	92.2	120.9	115.1
1.2 विनिर्माण	77.63	131.5	129.6	130.2	110.5	135.4	137.5
1.3 बिजली	7.99	156.9	158.4	160.5	154.8	150.3	158.0
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	126.1	127.0	125.0	112.4	129.6	129.2
2.2 पूंजीगत माल	8.22	108.4	93.3	94.1	68.2	93.7	94.3
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	126.2	137.7	137.1	116.5	146.9	147.5
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	141.7	136.6	136.6	115.9	146.4	147.7
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	130.4	119.0	122.6	92.3	117.3	123.0
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.5	145.3	145.5	138.9	158.1	161.2

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-जनवरी			
	2020-21 संशोधित आकलन	2020-21 (वास्तविक)	2019-20 (वास्तविक)	संशोधित आकलनों का प्रतिशत	
				2020-21	2019-20
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्ति	1555153	1242959	1250120	79.9	67.6
1.1 कर राजस्व (निवल)	1344501	1101855	998037	82.0	66.3
1.2 करेतर राजस्व	210652	141104	252083	67.0	73.0
2 पूंजीगत प्राप्ति	46497	40355	32737	86.8	40.1
2.1 ऋण की वसूली	14497	15804	14386	109.0	86.6
2.2 अन्य प्राप्ति	32000	24551	18351	76.7	28.2
3 कुल प्राप्ति (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	1601650	1283314	1282857	80.1	66.4
4 राजस्व व्यय	3011142	2155210	2000595	71.6	85.1
4.1 ब्याज भुगतान	692900	519597	471916	75.0	75.5
5 पूंजी व्यय	439163	362108	267734	82.5	76.7
6 कुल व्यय (4+5)	3450305	2517318	2268329	73.0	84.1
7 राजस्व घाटा (4-1)	1455989	912251	750475	62.7	150.2
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	1848655	1234004	985472	66.8	128.5
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	1155755	714407	513556	61.8	362.3

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय केंद्रीय बजट 2021-22

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2020		2021				
		जन. 31	दिसं. 25	जन. 1	जन. 8	जन. 15	जन. 22	जन. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	2622	7116	2158	2499	2423	2016	2857	2964
1.2 प्राथमिक व्यापारी	17236	12593	13914	15783	16649	17917	19497	20930
1.3 राज्य सरकारें	43066	40201	90891	90891	79558	70857	65857	62912
1.4 अन्य	71027	90368	109744	116333	111524	105363	98525	92430
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	52588	73542	107133	101471	92599	83595	75620	68922
2.2 प्राथमिक व्यापारी	31277	27297	34064	27744	28410	27732	28750	31222
2.3 राज्य सरकारें	803	7155	4273	4271	4171	3871	3871	3816
2.4 अन्य	56745	19654	65892	67852	68563	71510	70654	68945
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	121328	55279	148927	150120	149497	153025	154885	154467
3.2 प्राथमिक व्यापारी	154980	55714	120863	122449	125001	133238	131993	136064
3.3 राज्य सरकारें	18515	22369	16217	16302	15855	15855	15855	15855
3.4 अन्य	170998	65783	128915	127373	130932	129154	133796	135156
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	153238	141449	144840	131696	118456	119597	175452	193438
4.4 अन्य	149	382	478	183	109	459	117	198
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	741185	477071	842989	843088	825180	814134	802159	793683

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)		
		संख्या	कुल अंकित मूल्य	संख्या	कुल अंकित मूल्य					
									प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
दिसं. 30	9000	76	35481	5	29	8995	5	9000	99.24	3.0790
जन. 6	4000	73	25912	1200	24	4000	1200	5200	99.25	3.0379
जन. 13	4000	82	22715	2001	31	3999	2001	6000	99.19	3.2799
जन. 20	4000	101	25719	2401	36	3999	2401	6400	99.18	3.3240
जन. 27	4000	76	23362	5044	19	3986	5044	9030	99.17	3.3468
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
दिसं. 30	3000	64	17482	794	17	2988	794	3781	98.36	3.3439
जन. 6	7000	124	34329	0	45	7000	0	7000	98.36	3.3501
जन. 13	7000	97	21201	3	44	6997	3	7000	98.31	3.4507
जन. 20	7000	113	19820	0	78	7000	0	7000	98.27	3.5410
जन. 27	7000	98	16805	10	46	6990	10	7000	98.26	3.5607
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2020-21										
दिसं. 30	4000	70	11325	0	31	4000	0	4000	96.67	3.4571
जन. 6	8000	112	34025	0	52	8000	0	8000	96.66	3.4681
जन. 13	8000	110	23821	0	65	8000	0	8000	96.55	3.5790
जन. 20	8000	100	24105	0	50	8000	0	8000	96.51	3.6261
जन. 27	8000	73	19151	0	36	8000	0	8000	96.46	3.6757

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1		2
जनवरी	1, 2021	1.90-3.55	3.18
जनवरी	2, 2021	2.50-3.25	2.76
जनवरी	4, 2021	1.90-3.75	3.18
जनवरी	5, 2021	1.90-3.50	3.15
जनवरी	6, 2021	1.90-3.50	3.16
जनवरी	7, 2021	1.90-3.50	3.19
जनवरी	8, 2021	1.90-3.50	3.18
जनवरी	11, 2021	1.90-3.50	3.19
जनवरी	12, 2021	1.90-3.50	3.19
जनवरी	13, 2021	1.90-3.50	3.19
जनवरी	14, 2021	1.90-3.50	3.24
जनवरी	15, 2021	1.90-3.50	3.19
जनवरी	16, 2021	2.45-3.40	2.80
जनवरी	18, 2021	1.90-3.50	3.16
जनवरी	19, 2021	1.90-3.50	3.16
जनवरी	20, 2021	1.90-3.50	3.19
जनवरी	21, 2021	1.90-3.50	3.17
जनवरी	22, 2021	1.90-3.50	3.20
जनवरी	25, 2021	1.90-3.50	3.25
जनवरी	27, 2021	1.90-3.50	3.23
जनवरी	28, 2021	1.90-3.50	3.20
जनवरी	29, 2021	1.90-3.70	3.23
जनवरी	30, 2021	2.50-3.48	2.87
फरवरी	1, 2021	1.90-3.55	3.20
फरवरी	2, 2021	1.90-3.55	3.20
फरवरी	3, 2021	1.90-3.55	3.19
फरवरी	4, 2021	1.90-3.55	3.18
फरवरी	5, 2021	1.90-3.55	3.24
फरवरी	6, 2021	2.50-3.55	3.15
फरवरी	8, 2021	1.90-3.50	3.22
फरवरी	9, 2021	1.90-3.50	3.24
फरवरी	10, 2021	1.90-3.50	3.25
फरवरी	11, 2021	1.90-3.50	3.24
फरवरी	12, 2021	1.90-3.50	3.31
फरवरी	15, 2021	1.90-3.50	3.25

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2020		2021		
	जन. 31	दिसं. 18	जन. 1	जन. 15	जन. 29
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	181309.00	68770.00	74955.00	67980.00	64080.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	16507.91	8003.34	12582.96	396.13	530.14
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	5.20-7.50	3.08-4.44	3.08-4.86	3.14-3.85	3.82-4.72

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2020			2021	
	जन. 31	दिसं. 15	दिसं. 31	जन. 15	जन. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	421988.85	390613.25	365185.05	386216.30	410651.90
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	72673.75	102307.55	87488.25	49901.80	89040.60
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	5.12-13.05	2.65-12.61	3.06-12.73	2.94-8.53	3.18-11.32

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	2020		2021				
		जन. 31	दिसं. 25	दिसं. 1	जन. 8	जन. 15	जन. 22	जन. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	26815	14691	16769	18634	17720	13805	16992	17057
2 नोटिस मुद्रा	3660	8821	354	4281	642	5149	672	4876
3 मीयादी मुद्रा	790	964	618	370	627	563	549	576
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	300691	362137	426080	648949	542622	634408	546341	589855
5 बाजार रिपो	221719	249932	295246	376407	314803	379416	336136	363896
6 कापरेट बांड में रिपो	2468	3235	1055	1090	3540	2471	2550	2957
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	72057	58809	62266	63898	62250	62051	86840
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	93960	60694	43125	38420	59575	52863	46474	36158
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5800	4535	4522	7724	4985	3988	4353	5991
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3720	2049	3635	5734	3864	2476	2055	2970
10.2 182-दिवसीय	2380	1705	4478	5985	3966	4169	3217	5074
10.3 364-दिवसीय	2900	597	1894	4851	4630	2384	3467	4138
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	2310	2179						
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	111070	71760	57652	62714	77020	65880	59566	54330
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	37	2578	4053	4676	4333	3061	242

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2019-20		2019-20 (अप्रै.-जन.)		2020-21 (अप्रै.-जन.)*		जनवरी 2020		जनवरी 2021*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	72	64926	63	64522	49	89823	7	3486	2	381
1ए प्रीमियम	70	43259	61	42878	49	86081	6	3467	2	374
1.1 पब्लिक	57	9867	51	9836	32	28827	6	56	1	300
1.1.1 प्रीमियम	55	9434	49	9414	32	25871	5	42	1	295
1.2 राइट्स	15	55059	12	54685	17	60995	1	3430	1	81
1.2.1 प्रीमियम	15	33825	12	33463	17	60210	1	3425	1	79
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	34	14984	30	14161	13	4690	3	2416	3	819
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	34	14984	30	14161	13	4690	3	2416	3	819
3.1.1 पब्लिक	34	14984	30	14161	13	4690	3	2416	3	819
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	106	79910	93	78683	62	94512	10	5902	5	1200
4.1 पब्लिक	91	24851	81	23998	45	33517	9	2472	4	1119
4.2 राइट्स	15	55059	12	54685	17	60995	1	3430	1	81

टिप्पणी: अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2019-20		2020				2021
		1	जन.	सितं.	अक्टू.	नव.	दिसं.	जन.
			2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	2219854	184370	202583	183171	174938	199755	200661
	मिलियन अमरीकी डॉलर	313361	25853	27569	24935	23570	27143	27447
1.1 तेल	करोड ₹	292340	22720	26511	11653	11436	17265	15824
	मिलियन अमरीकी डॉलर	41289	3186	3608	1586	1541	2346	2164
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1927514	161650	176072	171518	163502	182490	184837
	मिलियन अमरीकी डॉलर	272072	22667	23961	23349	22029	24797	25282
2 आयात	करोड ₹	3360954	293453	224168	247051	247857	313403	306952
	मिलियन अमरीकी डॉलर	474709	41150	30307	33631	33396	42586	41985
2.1 तेल	करोड ₹	925168	92773	42808	44081	46525	70512	68744
	मिलियन अमरीकी डॉलर	130550	13009	5826	6001	6269	9581	9403
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2435787	200679	181361	202970	201332	242891	238208
	मिलियन अमरीकी डॉलर	344159	28140	24481	27630	27127	33004	32582
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1141100	-109083	-21585	-63880	-72919	-113648	-106290
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-161348	-15296	-2738	-8695	-9826	-15443	-14539
3.1 तेल	करोड ₹	-632828	-70053	-16297	-32429	-35089	-53247	-52920
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-89262	-9823	-2218	-4415	-4728	-7235	-7239
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-508273	-39030	-5288	-31452	-37830	-60401	-53370
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-72087	-5473	-520	-4281	-5098	-8207	-7300

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2020		2021					
		1	फर. 21	जन. 15	जन. 22	जन. 29	फर. 5	फर. 12	फर. 19
			2	3	4	5	6	7	
1 कुल भंडार	करोड ₹	3410238	4269145	4271528	4306005	4258725	4246990	4242355	
	मिलियन अमरीकी डॉलर	476122	584242	585334	590185	583945	583697	583865	
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	3161973	3956894	3956665	3992516	3955297	3935956	3938898	
	मिलियन अमरीकी डॉलर	441458	541507	542192	547218	542338	540951	542106	
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	212456	263499	266058	264803	255014	263585	256120	
	मिलियन अमरीकी डॉलर	29662	36060	36459	36294	34967	36227	35250	
	Volume (Metric Tonnes)	639.01	676.65	676.65	676.65	676.65	680.38	684.12	
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1045	1049	1049	1049	1049	1049	1049	
	करोड ₹	10216	11046	11038	11006	10960	11005	10958	
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1426	1512	1513	1508	1503	1513	1508	
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	25593	37706	37767	37679	37454	36444	36378	
	मिलियन अमरीकी डॉलर	3575	5163	5171	5165	5138	5006	5002	

अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2019-20	2020		2021	2019-20	2020-21
		जन.	दिसं.	जन.	अप्रै.-जन.	अप्रै.-जन.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130581	133565	140496	142236	6730	8616
1.1 एफसीएनआर (बी)	24244	24408	22128	22118	1238	-2126
1.2 एनआर (ई) आरए	90367	92838	100849	101981	3886	9017
1.3 एनआरओ	15969	16319	17520	18136	1606	1724

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2019-20	2019-20	2020-21	2020		2021
		अप्रै.-जन.	अप्रै.-जन.	जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	43013	36302	44010	5252	6509	3520
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	56006	47050	52345	6229	7334	3900
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	74390	62721	72116	7585	9218	4574
1.1.1.1.1 इक्विटी	51734	43619	55839	5808	7741	2945
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	3265	3051	906	24	55	585
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	39364	33212	47427	4751	7039	1789
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7348	6076	5844	795	527	332
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1757	1280	1662	238	120	238
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	14175	11660	12660	1257	1197	1257
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	8482	7442	3617	520	281	372
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	18384	15671	19771	1357	1884	674
1.1.1.2.1 इक्विटी	18212	15504	19742	1354	1882	674
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	173	167	29	3	3	1
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12993	10748	8335	977	825	380
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	7572	6342	4675	878	600	232
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3151	2626	2666	263	263	263
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5674	4106	4145	375	476	463
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	3403	2326	3152	539	514	578
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	1403	17187	29921	2039	8403	1508
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	552	17001	31419	1706	8598	1228
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	-851	-186	1498	-333	195	-281
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	44417	53489	73931	7290	14912	5028

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2019-20	2020			2021
		जन.	नव.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	18760.69	1804.50	942.44	1149.17	1253.63
1.1 जमाराशियां	623.37	55.94	23.32	35.33	40.85
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	86.43	6.67	3.53	5.05	5.64
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	431.41	26.20	25.39	38.76	34.89
1.4 उपहार	1907.71	158.44	110.55	145.15	134.16
1.5 दान	22.33	1.10	0.65	0.67	0.67
1.6 यात्रा	6955.98	712.56	253.26	322.25	356.92
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3439.74	310.83	160.81	217.30	216.64
1.8 चिकित्सा उपचार	33.90	2.59	2.92	2.82	2.56
1.9 विदेश में शिक्षा	4991.07	510.26	355.77	373.32	455.51
1.10 अन्य	268.75	19.90	6.24	8.54	5.79

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2018-19	2019-20	2020	2021	
			फरवरी	जनवरी	फरवरी
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	97.45	98.00	97.57	93.71	94.15
1.2 रीर	100.63	103.20	103.81	102.98	103.46
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	97.13	97.38	96.91	93.30	93.68
2.2 रीर	100.29	102.88	103.69	102.57	102.99
6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	94.19	94.92	94.59	87.34	87.88
1.2 रीर	100.29	103.60	104.21	100.91	101.46
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.00	100.78	100.43	92.73	93.30
2.2 रीर	100.00	103.30	103.91	100.62	101.18

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2019-20	2020		2021
		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1292	110	95	95
1.2 राशि	38011	5869	2994	3744
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	41	4	-	-
2.2 राशि	14921	2532	-	-
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1333	114	95	95
3.2 राशि	52932	8401	2994	3744
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.00	7.10	4.59	7.50
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	1.24	1.65	2.74
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-25.00	0.00-11.10	0.00-13.00	0.00-10.25

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जुला.-सितं. 2019			जुला.-सितं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	303790	298671	5118	304250	272682	31568
1 चालू खाता (1.1+1.2)	161553	169132	-7579	150955	135448	15507
1.1 पण्य	79952	119602	-39650	75591	90375	-14784
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	81601	49530	32070	75364	45072	30292
1.2.1 सेवाएं	52777	31836	20941	49902	28733	21169
1.2.1.1 यात्रा	7643	6031	1611	2020	2737	-717
1.2.1.2 परिवहन	5181	6009	-828	5410	4759	651
1.2.1.3 बीमा	602	354	248	590	537	53
1.2.1.4 जीएनआईई	169	298	-128	144	190	-46
1.2.1.5 विविध	39182	19144	20038	41738	20510	21228
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	23247	2182	21064	25069	2769	22299
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	10878	11211	-333	11624	12379	-755
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1239	594	645	1003	1107	-104
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	635	354	281	661	355	306
1.2.2 अंतरण	21986	2034	19952	20421	2023	18398
1.2.2.1 आधिकारिक	50	286	-236	36	258	-221
1.2.2.2 निजी	21936	1748	20188	20385	1766	18619
1.2.3 आय	6838	15660	-8822	5041	14316	-9275
1.2.3.1 निवेश आय	5434	14997	-9563	3596	13615	-10020
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1404	663	741	1445	700	745
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	142237	128657	13580	152658	137234	15424
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	85751	75960	9791	97269	65689	31581
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	15650	8336	7314	30475	5892	24583
2.1.1.1 भारत में	14875	4482	10393	29501	2450	27051
2.1.1.1.1 इक्विटी	10113	4446	5668	23989	2445	21544
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3464		3464	4024	0	4024
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1298	37	1262	1488	5	1483
2.1.1.2 विदेश में	775	3854	-3079	974	3442	-2468
2.1.1.2.1 इक्विटी	775	1703	-928	974	1391	-417
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	788	-788	0	808	-808
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1363	-1363	0	1243	-1243
2.1.2 संविभाग निवेश	70101	67625	2476	66794	59796	6998
2.1.2.1 भारत में	68312	66307	2005	66420	58684	7736
2.1.2.1.1 एफआईआई	68312	66307	2005	66420	58684	7736
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	48252	51608	-3355	55007	48183	6824
2.1.2.1.1.2 ऋण	20059	14699	5361	11413	10501	912
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	1789	1318	471	375	1113	-738
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	21544	18472	3072	20225	24468	-4243
2.2.1 बाह्य सहायता	1802	1366	435	3201	1330	1870
2.2.1.1 भारत द्वारा	2	29	-27	2	28	-26
2.2.1.2 भारत को	1800	1338	462	3199	1302	1897
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	9011	5728	3283	8362	12659	-4297
2.2.2.1 भारत द्वारा	1287	1082	205	769	1005	-235
2.2.2.2 भारत को	7724	4646	3078	7593	11654	-4061
2.2.3 भारत को अल्पावधि	10731	11378	-646	8662	10479	-1817
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	10731	10940	-209	8662	9770	-1108
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	437	-437	0	709	-709
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	23881	25699	-1818	18850	30025	-11175
2.3.1 वाणिज्य बैंक	23881	25364	-1483	18837	30025	-11188
2.3.1.1 आस्तियां	9914	10148	-235	7295	16747	-9451
2.3.1.2 देयताएं	13967	15216	-1249	11541	13279	-1737
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	13458	11178	2280	10311	8377	1934
2.3.2 अन्य	0	335	-335	13	0	13
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	2	-2	0	2	-2
2.5 अन्य पूंजी	11061	8523	2538	16314	17050	-737
3 भूल-चूक		882	-882	637	0	637
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	5118	-5118	0	31568	-31568
4.1 आईएमएफ				0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)		5118	-5118	0	31568	-31568

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	जुला.-सितं. 2019			जुला.-सितं. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2139568	2103519	36049	2263084	2028270	234814
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1137803	1191185	-53382	1122840	1007492	115348
1.1 पण्य	563094	842346	-279252	562264	672233	-109969
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	574709	348839	225870	560576	335259	225317
1.2.1 सेवाएं	371704	224219	147485	371185	213726	157459
1.2.1.1 यात्रा	53826	42478	11348	15024	20359	-5335
1.2.1.2 परिवहन	36488	42320	-5833	40241	35397	4843
1.2.1.3 बीमा	4243	2494	1749	4385	3994	391
1.2.1.4 जीएनआईई	1193	2096	-904	1074	1414	-339
1.2.1.5 विविध	275955	134831	141124	310461	152561	157899
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	163725	15370	148355	186466	20598	165868
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	76611	78960	-2348	86464	92076	-5612
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	8729	4187	4543	7462	8233	-771
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4475	2494	1981	4914	2638	2275
1.2.2 अंतरण	154844	14327	140517	151896	15051	136845
1.2.2.1 आधिकारिक	349	2014	-1665	269	1916	-1647
1.2.2.2 निजी	154495	12313	142182	151627	13134	138492
1.2.3 आय	48161	110294	-62133	37495	106483	-68988
1.2.3.1 निवेश आय	38270	105623	-67353	26745	101274	-74529
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9891	4671	5220	10750	5209	5541
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1001765	906125	95640	1135504	1020778	114725
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	603940	534984	68957	723512	488607	234905
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	110224	58709	51515	226681	43826	182855
2.1.1.1 भारत में	104766	31568	73198	219436	18223	201213
2.1.1.1.1 इक्विटी	71226	31310	39916	178436	18184	160252
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	24395	0	24395	29930		29930
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	9145	258	8886	11070	39	11032
2.1.1.2 विदेश में	5458	27141	-21682	7245	25603	-18358
2.1.1.2.1 इक्विटी	5458	11997	-6538	7245	10348	-3103
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5548	-5548	0	6009	-6009
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	9596	-9596	0	9247	-9247
2.1.2 संविभाग निवेश	493716	476275	17441	496831	444780	52050
2.1.2.1 भारत में	481114	466993	14122	494044	436504	57540
2.1.2.1.1 एफआईआई	481114	466993	14122	494044	436504	57540
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	339837	363469	-23632	409153	358396	50757
2.1.2.1.1.2 ऋण	141277	103523	37754	84891	78108	6783
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	12602	9283	3320	2786	8276	-5490
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	151732	130099	21633	150435	181998	-31563
2.2.1 बाह्य सहायता	12689	9624	3065	23807	9895	13911
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	201	-187	12	208	-197
2.2.1.2 भारत को	12675	9423	3252	23795	9687	14108
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	63463	40344	23119	62198	94158	-31960
2.2.2.1 भारत द्वारा	9066	7623	1444	5722	7473	-1751
2.2.2.2 भारत को	54397	32721	21675	56476	86685	-30209
2.2.3 भारत को अल्पावधि	75580	80132	-4551	64430	77945	-13515
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	75580	77050	-1470	64430	72671	-8241
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	3081	-3081	0	5273	-5273
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	168191	180998	-12807	140212	223336	-83124
2.3.1 वाणिज्य बैंक	168191	178639	-10448	140113	223336	-83222
2.3.1.1 आस्तियां	69820	71474	-1654	54265	124564	-70299
2.3.1.2 देयताएं	98370	107165	-8794	85848	98771	-12923
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	94785	78728	16056	76699	62311	14387
2.3.2 अन्य	0	2359	-2359	99	0	99
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	15	-15	0	15	-15
2.5 अन्य पूंजी	77902	60029	17873	121345	126824	-5479
3 भूल-चूक	0	6210	-6210	4740		4740
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	36049	-36049	0	234814	-234814
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	36049	-36049		234814	-234814

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	जुला.-सित्त. 2019			जुला.-सित्त. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	161551	169104	-7553	150953	135423	15531
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	132729	151438	-18709	125493	119109	6385
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	79952	119602	-39650	75591	90375	-14784
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	79293	115248	-35955	75243	84287	-9044
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	658	0	658	348	0	348
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		4354	-4354	0	6088	-6088
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	52777	31836	20941	49902	28733	21169
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	58	33	25	68	11	56
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	44	253	-208	35	204	-169
1.अ.ख.3 परिवहन	5181	6009	-828	5410	4759	651
1.अ.ख.4 यात्रा	7643	6031	1611	2020	2737	-717
1.अ.ख.5 निर्माण	677	714	-37	589	563	26
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	602	354	248	590	537	53
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1239	594	645	1003	1107	-104
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	248	1776	-1528	313	1456	-1143
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	23947	2654	21293	25793	3290	22503
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	10878	11211	-333	11624	12379	-755
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	551	923	-372	530	817	-287
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	169	298	-128	144	190	-46
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	1539	984	555	1782	683	1099
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	6838	15660	-8822	5041	14316	-9275
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1404	663	741	1445	700	745
1.आ.2 निवेश आय	4379	14782	-10403	2808	13314	-10507
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1763	7056	-5293	1327	8038	-6711
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	54	3760	-3706	49	2126	-2076
1.आ.2.3 अन्य निवेश	602	3951	-3349	78	3150	-3072
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1960	15	1945	1354	1	1353
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1055	215	840	788	301	487
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	21984	2006	19978	20419	1998	18421
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	21936	1748	20188	20385	1766	18619
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	21291	1336	19955	19711	1287	18424
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	645	412	233	674	479	195
1.इ.2 सामान्य सरकार	48	258	-210	35	232	-198
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	90	190	-100	109	197	-87
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	9	93	-84	8	100	-92
2.2 पूंजी अंतरण	81	97	-16	101	96	5
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	142149	133614	8535	152550	168631	-16081
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	15650	8336	7314	30475	5892	24583
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	14875	4482	10393	29501	2450	27051
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	13577	4446	9131	28013	2445	25568
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	10113	4446	5668	23989	2445	21544
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3464		3464	4024	0	4024
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1298	37	1262	1488	5	1483
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1298	37	1262	1488	5	1483
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	775	3854	-3079	974	3442	-2468
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	775	2491	-1716	974	2199	-1225
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	775	1703	-928	974	1391	-417
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		788	-788	0	808	-808
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1363	-1363	0	1243	-1243
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1363	-1363	0	1243	-1243
3.2 संविभाग निवेश	70101	67625	2476	66794	59796	6998
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	68312	66307	2005	66420	58684	7736
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	48252	51608	-3355	55007	48183	6824
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	20059	14699	5361	11413	10501	912
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	1789	1318	471	375	1113	-738
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	7395	7138	257	9664	12339	-2675
3.4 अन्य निवेश	49003	45398	3605	45617	59035	-13418
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	13458	11513	1945	10325	8377	1948
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	335	-335	13	0	13
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	13458	11178	2280	10311	8377	1934
3.4.2.3 सामान्य सरकार				0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र				0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	21235	21281	-45	20088	35637	-15549
3.4.3अ भारत को ऋण	19946	20170	-224	19317	34605	-15287
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	1289	1111	178	771	1033	-262
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	54	71	-17	78	62	16
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	10731	11378	-646	8662	10479	-1817
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	3524	1155	2369	6464	4480	1984
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	5118	-5118	0	31568	-31568
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण				0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए				0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए				0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	5118	-5118	0	31568	-31568
4. कुल आस्तियां / देयताएं	142149	133614	8535	152550	168631	-16081
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	71843	67071	4772	94110	66340	27770
4.2 ऋण लिखत	66783	60270	6513	51976	66242	-14267
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	3524	6273	-2750	6464	36048	-29584
5. निवल भूल-चूक		882	-882	637	0	637

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	जुला.-सित. 2019			जुला.-सित. 2020 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1137790	1190988	-53198	1122827	1007305	115522
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	934798	1066564	-131766	933449	885959	47490
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	563094	842346	-279252	562264	672233	-109969
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	558456	811684	-253228	559675	626945	-67270
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	4638	0	4638	2588	0	2588
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	30661	-30661	0	45287	-45287
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	371704	224219	147485	371185	213726	157459
1.अ.ख.1 अन्य के स्वाभिमूर्ति वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	408	235	173	505	85	420
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	310	1779	-1468	263	1519	-1256
1.अ.ख.3 परिवहन	36488	42320	-5833	40241	35397	4843
1.अ.ख.4 यात्रा	53826	42478	11348	15024	20359	-5335
1.अ.ख.5 निर्माण	4770	5031	-261	4383	4186	197
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4243	2494	1749	4385	3994	391
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	8729	4187	4543	7462	8233	-771
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1749	12511	-10762	2330	10833	-8503
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	168656	18693	149963	191855	24472	167382
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	76611	78960	-2348	86464	92076	-5612
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3882	6503	-2621	3944	6078	-2135
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1193	2096	-904	1074	1414	-339
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	10839	6933	3906	13255	5078	8178
1.आप्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	48161	110294	-62133	37495	106483	-68988
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9891	4671	5220	10750	5209	5541
1.आ.2 निवेश आय	30842	104107	-73266	20884	99036	-78152
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	12418	49694	-37276	9869	59790	-49921
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	380	26481	-26100	366	15810	-15445
1.आ.2.3 अन्य निवेश	4241	27830	-23589	579	23428	-22848
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	13803	103	13700	10070	7	10063
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	7428	1515	5913	5861	2238	3623
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	154831	14130	140701	151883	14863	137020
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	154495	12313	142182	151627	13134	138492
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	149953	9410	140544	146616	9573	137043
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4542	2903	1639	5011	3561	1450
1.इ.2 सामान्य सरकार	336	1817	-1481	257	1729	-1472
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	632	1337	-705	813	1463	-649
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नाम) / निस्तारण (जमा)	63	656	-593	62	747	-685
2.2 पूँजी अंतरण	569	680	-112	751	716	36
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	1001146	941034	60112	1134703	1254317	-119614
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	110224	58709	51515	226681	43826	182855
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	104766	31568	73198	219436	18223	201213
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	95621	31310	64312	208366	18184	190182
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	71226	31310	39916	178436	18184	160252
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	24395	0	24395	29930	0	29930
3.1.अ.2 ऋण लिखत	9145	258	8886	11070	39	11032
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	9145	258	8886	11070	39	11032
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	5458	27141	-21682	7245	25603	-18358
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	5458	17544	-12086	7245	16356	-9111
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	5458	11997	-6538	7245	10348	-3103
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5548	-5548	0	6009	-6009
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	9596	-9596	0	9247	-9247
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	9596	-9596	0	9247	-9247
3.2 संविभाग निवेश	493716	476275	17441	496831	444780	52050
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	481114	466993	14122	494044	436504	57540
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	339837	363469	-23632	409153	358396	50757
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	141277	103523	37754	84891	78108	6783
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	12602	9283	3320	2786	8276	-5490
3.3 वित्तीय डेबिटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	52083	50270	1813	71882	91780	-19898
3.4 अन्य निवेश	345123	319731	25392	339309	439117	-99808
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	94785	81087	13697	76798	62311	14486
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	2359	-2359	99	0	99
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	94785	78728	16056	76699	62311	14387
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	149558	149878	-320	149419	265077	-115658
3.4.3अ भारत को ऋण	140478	142055	-1577	143686	257396	-113711
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	9080	7823	1257	5734	7681	-1947
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	383	501	-117	580	462	117
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	75580	80132	-4551	64430	77945	-13515
3.4.6 अन्य खाते प्राच्य/देय-अन्य	24817	8134	16683	48082	33321	14761
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	36049	-36049	0	234814	-234814
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	36049	-36049	0	234814	-234814
4. कुल आस्तियां / देयताएं	1001146	941034	60112	1134703	1254317	-119614
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	505985	472376	33609	700013	493455	206557
4.2 ऋण लिखत	470345	424475	45870	386609	492727	-106118
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	24817	44183	-19366	48082	268134	-220052
5. निवल भूल-चूक	0	6210	-6210	4740	0	4740

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2019-20		2019		2020			
			सितं.		जून		सितं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	182957	418243	176244	417145	185898	419426	188366	455989
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	118442	395426	114834	398819	120322	395835	121546	430881
1.2 अन्य पूंजी	64515	22817	61410	18327	65577	23591	66820	25108
2 संविभाग निवेश	3847	246701	4541	260195	4303	241581	5041	253289
2.1 इक्विटी	602	134778	2344	144039	830	138961	1906	149095
2.2 ऋण	3246	111923	2197	116155	3474	102621	3136	104195
3 अन्य निवेश	52422	427272	54980	428886	53694	432321	64921	432817
3.1 व्यापार ऋण	1460	104276	1633	106581	1271	104001	2917	102193
3.2 ऋण	6741	179601	7892	174823	7435	184391	9048	180264
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	26011	130761	27563	133105	27741	132942	34864	137519
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18210	12634	17892	14378	17247	10987	18092	12841
4 रिज़र्व्स	477807		433707		505702		544687	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	717033	1092216	669472	1106226	749597	1093328	803016	1142095
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-375183		-436754		-343730		-339079

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	विव 2019-20	2020		2021	विव 2019-20	2020		2021
		जन.	दिसं.	जन.		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	-	3.01	2.62	2.32	-	12826782	15757032	15723500
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	-	1.09	1.00	0.93	-	8442926	10816866	10875915
1.1.1 आउटराइट	-	0.66	0.51	0.48	-	957188	772886	657843
1.1.2 रेपो	-	0.21	0.25	0.22	-	2999019	4089804	3848935
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	-	0.22	0.24	0.24	-	4486719	5954176	6369137
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	-	1.88	1.58	1.35	-	4083916	4651382	4576570
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	-	0.05	0.04	0.04	-	299940	288785	271015
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	-	137.29	163.48	156.68	-	9880821	10659120	9170162
1.1 ग्राहक लेनदेन	-	135.09	161.72	155.07	-	8558049	9058136	7854553
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	-	2.20	1.75	1.61	-	1322772	1600984	1315609
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.7)	-	21194.18	31735.80	31708.13	-	2454378	3393355	2991919
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	-	0.76	1.03	1.09	-	37	61	65
2.2 एपीबीएस \$	-	1511.41	1018.90	1224.28	-	9427	8180	9642
2.3 आईएमपीएस	-	2595.26	3556.93	3465.52	-	216811	292325	288538
2.4 एनएसीएच जमा \$	-	1431.01	1741.20	1115.03	-	82398	118309	96624
2.5 एनईएफटी	-	2605.55	3076.15	2874.93	-	1929464	2558304	2165869
2.6 यूपीआई @	-	13050.19	22341.58	23027.28	-	216243	416176	431182
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	-	0.78	0.88	0.92	-	14	14	15
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.4)	-	812.33	922.53	928.08	-	73506	81871	78230
3.1 भीम आधार पे @	-	9.36	8.90	10.29	-	141	187	214
3.2 एनएसीएच नामे \$	-	777.36	840.43	839.08	-	73316	81576	77903
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	-	25.61	73.21	78.71	-	49	108	113
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	-	6518.12	5502.88	5459.45	-	129444	128665	128915
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	-	2017.27	1737.79	1744.20	-	66573	63487	64737
4.1.1 पीओएस आधारित \$	-	1160.35	914.20	926.09	-	35124	28961	29409
4.1.2 अन्य \$	-	856.92	823.59	818.11	-	31449	34526	35328
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	-	4500.85	3765.09	3715.25	-	62871	65178	64178
4.2.1 पीओएस आधारित \$	-	2587.38	2165.50	2148.07	-	38907	39437	39551
4.2.2 अन्य \$	-	1913.47	1599.59	1567.18	-	23964	25741	24626
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	-	5237.05	4335.04	4386.68	-	18286	18153	19419
5.1 वॉलेट	-	3876.23	3521.48	3499.66	-	15408	13392	13577
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	-	1360.82	813.55	887.02	-	2878	4761	5842
5.2.1 पीओएस आधारित \$	-	128.35	42.74	39.51	-	997	1214	1585
5.2.2 अन्य \$	-	1232.47	770.81	847.51	-	1880	3547	4257
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	-	887.17	719.40	657.01	-	662399	618015	551207
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	-	886.39	719.40	657.01	-	661741	618015	551207
6.2 अन्य	-	0.78	0.00	0.00	-	658	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	-	34648.84	43215.65	43139.35	-	3338013	4240059	3769690
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	-	34786.12	43379.13	43296.03	-	13218835	14899180	12939853
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	-	33898.96	42659.73	42639.02	-	12556435	14281164	12388646

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)			मूल्य (₹ करोड़)				
	वि. व. 2019-20	2020		2021	वि. व. 2019-20	2020		2021
		जन.	दिसं.	जन.		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	-	14402.70	25199.49	23199.84	-	521368	899401	938456
1.1 इंटर-बैंक \$	-	1304.45	2183.03	2536.27	-	107648	174603	207982
1.2 इंटर-बैंक \$	-	13098.24	23016.46	20663.57	-	413720	724798	730474
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	-	2749.95	3137.64	3084.97	-	3162106	4032311	4158231
2.1 इंटर-बैंक @	-	612.52	637.64	617.29	-	1641898	1934396	2184556
2.2 इंटर-बैंक @	-	2137.43	2500.00	2467.68	-	1520208	2097916	1973675
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	-	6537.04	5680.37	5734.25	-	295572	266709	267500
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	8.53	5.01	5.04	-	399	246	251
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	6500.08	5650.86	5704.78	-	294174	265569	266315
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	28.43	24.51	24.43	-	999	893	934
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	-	102.47	39.89	32.29	-	177	149	136
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	-	92.41	34.53	30.45	-	163	142	134
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	-	10.06	5.37	1.84	-	14	6	2
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	-	400.77	715.03	777.16	-	11109	19671	21700
5.1 एईपीएस @	-	400.77	715.03	777.16	-	11109	19671	21700

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	वि. व. 2019-20	2020		2021
		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	-	8725.30	9460.57	9491.63
1.1 क्रेडिट कार्ड	-	561.20	603.97	610.98
1.2 डेबिट कार्ड	-	8164.10	8856.60	8880.65
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	-	17574.74	20819.05	21212.16
2.1 वॉलेट @	-	16575.31	19156.35	19461.26
2.2 कार्ड @	-	999.43	1662.70	1750.90
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	-	2.33	2.33	2.34
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	-	2.10	2.08	2.09
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	-	0.23	0.25	0.25
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	-	2.56	3.56	3.73
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	-	49.47	57.85	60.27
6 भारत क्यूआर @	-	17.79	32.00	33.60
7 यूपीआई क्यूआर *	-	-	752.31	805.89

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2019		2020	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	115714	9839	15814	15184	16911
	बकाया	918459	899191	1015010	1030037	1046766
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	91108	7130	12117	11091	11460
	बकाया	618418	606920	693812	704903	716363
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31037	2360	3455	3106	2690
	बकाया	140247	134863	150462	153568	156258
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31	-19	-31	-25	-20
	बकाया	3107	2877	2984	2959	2939
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53	0	-827	-2	-3
	बकाया	10	-8	-18	-20	-23
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10967	928	1753	1712	1887
	बकाया	192658	191653	203460	205172	207059
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13990	1184	2070	2133	2131
	बकाया	55708	54446	69464	71597	73728
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25000	2451	4296	3999	4494
	बकाया	124292	121687	152622	156621	161115
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71534	70179	86344	88247	90327
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5910	5824	6749	6854	6970
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6901	6910	7328	7397	7464
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39947	38774	52201	54123	56354
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10081	215	1401	168	281
	बकाया	102401	101407	114842	115010	115291
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11	11	0	0	0
	बकाया	-26	-26	-25	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	16067	1732	3326	3524	3937
	बकाया	221517	219257	240900	244267	248022
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11318	1262	2272	2458	2619
	बकाया	98492	94795	110050	112508	115127
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334	3	0	0	1
	बकाया	263	300	-289	-289	-288
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18678	-1609	-971	-1713	-1120
	बकाया	19303	21232	6782	5069	3949
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23018	2065	2025	2782	2452
	बकाया	93630	91314	113273	116055	118507
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93	12	0	-1	0
	बकाया	2	-47	-179	-180	-180
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18	-1	0	-2	-15
	बकाया	-80	-82	-82	-84	-99
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9907	11745	11345	11188	11006
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	8539	977	371	569	1514
	बकाया	78524	73014	80298	80867	82381

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं। अर्थात् सकल प्राप्तियाँ माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

श्रेणी	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां				
	2019	2020			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं	दिसं.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	6512659	6486585	6704983	7137069	7357111
1. वाणिज्य बैंक	39.05	40.41	38.98	38.55	37.81
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.39	0.39	0.36	0.34	0.25
3. बीमाकृत कंपनियां	24.90	25.09	26.24	25.33	25.64
4. म्यूच्युअल फंड	1.53	1.43	2.02	2.42	2.62
5. सहकारी बैंक	1.97	1.90	1.86	1.86	1.83
6. वित्तीय संस्थाएं	1.14	0.53	1.19	1.42	1.00
7. कॉरपोरेट	0.84	0.81	0.78	0.94	1.05
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.33	2.44	1.79	2.05	2.10
9. भविष्य निधियां	4.93	4.72	4.96	4.77	4.61
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	14.72	15.13	14.70	15.00	15.71
11. अन्य	7.23	7.17	7.11	7.32	5.61
11.1 राज्य सरकार	1.97	2.05	1.99	1.86	1.76

श्रेणी	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां				
	2019	2020			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	3047353	3265990	3393099	3564979	3721573
1. वाणिज्य बैंक	32.46	34.99	33.54	34.60	34.19
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.64	0.76	0.74	0.54	0.36
3. बीमाकृत कंपनियां	32.50	31.63	30.85	30.26	30.25
4. म्यूच्युअल फंड	1.20	1.14	1.74	1.96	1.92
5. सहकारी बैंक	4.16	4.12	4.38	4.19	4.11
6. वित्तीय संस्थाएं	0.31	0.11	1.96	1.92	1.88
7. कॉरपोरेट	0.31	0.30	0.31	0.39	0.45
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02
9. भविष्य निधियां	23.66	22.22	21.70	21.31	21.20
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
11. अन्य	4.73	4.71	4.78	4.80	4.64
11.1 राज्य सरकार	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18

श्रेणी	खजाना बिल				
	2019	2020			
	दिसं.	मार्च	जून	सितं	दिसं.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	514588	538409	881362	982286	839729
1. वाणिज्य बैंक	45.19	61.06	46.11	53.50	54.75
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.07	2.26	1.48	2.16	1.65
3. बीमाकृत कंपनियां	5.76	7.45	4.64	4.06	4.50
4. म्यूच्युअल फंड	20.42	13.24	23.45	19.90	18.98
5. सहकारी बैंक	2.07	2.55	1.95	1.63	1.61
6. वित्तीय संस्थाएं	2.12	0.58	1.67	1.34	1.11
7. कॉरपोरेट	1.66	1.89	1.43	1.63	2.01
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.01	0.02	0.05	0.00	0.09
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	11.27	4.80	0.68
11. अन्य	20.70	10.95	7.95	10.99	1.36
11.1 राज्य सरकार	16.36	6.22	4.35	7.76	13.27

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सं.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	3760611	4265969	4515946	5040747	5875914	6470254
1.1 गतिविधियां	2201287	2537905	2635110	2882758	3486519	3818358
1.1.1 राजस्व	1668250	1878417	2029044	2224367	2708218	2920507
1.1.2 पूंजी	412069	501213	519356	596774	694262	794599
1.1.3 ऋण	120968	158275	86710	61617	84038	103252
1.2 गैर गतिविधियां	1510810	1672646	1812455	2078276	2295105	2556504
1.2.1 राजस्व	1379727	1555239	1741432	1965907	2171963	2421566
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	648091	724448	814757	894520	969344	1091617
1.2.2 पूंजी	127306	115775	69370	111029	121159	132961
1.2.3 ऋण	3777	1632	1654	1340	1984	1977
1.3 अन्य	48514	55417	68381	79713	94290	95393
2. कुल प्राप्तियां	3778049	4288432	4528422	5023352	5779396	6524526
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2748374	3132201	3376416	3797731	4338225	4828088
2.1.1 कर प्राप्तियां	2297101	2622145	2978134	3278947	3547958	3951657
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1440952	1652377	1853859	2030050	2157126	2436871
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	852271	965622	1121189	1246083	1386652	1510287
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3878	4146	3086	2814	4180	4500
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	451272	510056	398282	518783	790267	876430
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	35779	33220	34224	36273	33272	30911
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	59827	69063	142433	140287	129507	232172
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	16561	20942	42213	44667	62499	18302
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	43266	48122	100219	95621	67008	213870
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	952410	1064704	997097	1102729	1408183	1409995
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	231090	617123	144792	387091	518093	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	60472	195816	-144847	325987	190241	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	708572	429585	844375	710119	885156	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	939662	1046708	989167	1097210	1403250	1405373
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	673298	689821	794856	795845	962386	1105573
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	80015	35038	71222	88961	213430	213430
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	35261	45688	42351	51004	42900	42529
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-3322	-6436	18423	-18298	-241	2978
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	13470	17792	25138	66289	32949	35987
3ख.1.6 नकद शेष	-17438	-22463	-12476	17395	96518	-54272
3ख.1.7 अन्य	158378	287268	49653	96014	55309	59147
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12748	17997	7931	5519	4933	4622
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.3	27.7	26.4	26.6	28.9	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.4	27.9	26.5	26.5	28.4	29.0
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	20.0	20.3	19.7	20.0	21.3	21.5
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.7	17.0	17.4	17.3	17.4	17.6
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	6.9	5.8	5.8	6.9	6.3

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी 2021 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	1116	31	1473	30	466	2
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	908	26	1046	6
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	214	6	208	4	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	171	1	-	-	-	-
16	मणिपुर	58	5	235	31	172	6
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	20	3	-	-
19	नगालैंड	193	31	180	25	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	247	17	444	2	-	-
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	1043	30	1320	30	1410	13
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	जनवरी 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8499	838	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1604	2	--	-
3	असम	4637	56	--	-
4	बिहार	6292	0	--	-
5	छत्तीसगढ़	4680	0	1	4550
6	गोवा	611	308	--	-
7	गुजरात	7013	495	--	-
8	हरियाणा	906	1237	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	2300
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	185	0	--	-
12	कर्नाटक	4999	0	--	24000
13	केरल	2203	0	--	-
14	मध्य प्रदेश	0	941	--	-
15	महाराष्ट्र	42316	438	--	12000
16	मणिपुर	258	103	--	-
17	मेघालय	684	37	9	-
18	मिज़ोरम	474	47	--	-
19	नगालैंड	1683	34	--	-
20	उड़ीसा	12860	1500	87	17165
21	पुदुचेरी	300	0	--	807
22	पंजाब	951	0	8	-
23	राजस्थान	0	0	129	2000
24	तमिलनाडु	6813	0	40	19762
25	तेलंगाना	5814	1266	--	-
26	त्रिपुरा	384	9	--	-
27	उत्तराखंड	3245	82	180	-
28	उत्तरप्रदेश	859	0	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9039	547	214	-
	कुल	127310	7939	667	82584

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2018-19		2019-20		2020-21						2020-21 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	नवंबर		दिसंबर		जनवरी		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	30200	23824	42415	33444	2000	1417	5000	4708	3000	2417	47250	41126
2	अरुणाचल प्रदेश	719	693	1366	1287	53	53	-	-	-	-	481	481
3	असम	10595	8089	12906	10996	2500	2500	1100	1100	500	500	9400	9400
4	बिहार	14300	10903	25601	22601	4000	4000	-	-	4000	3000	24000	22000
5	छत्तीसगढ़	12900	12900	11680	10980	2000	2000	2000	2000	2000	500	10000	7500
6	गोवा	2350	1850	2600	2000	300	300	354	354	200	200	2554	2254
7	गुजरात	36971	27437	38900	28600	5500	3500	1500	1500	1500	500	31280	22323
8	हरियाणा	21265	17970	24677	20677	2000	2000	-	-	2000	2000	24500	21900
9	हिमाचल प्रदेश	4210	2108	6580	4460	1000	1000	1000	1000	1000	700	5000	3900
10	जम्मू और कश्मीर	6684	4927	7869	6760	1605	1605	500	500	500	21	7810	5831
11	झारखंड	5509	4023	7500	5656	-	-	1000	1000	1400	1400	5000	4500
12	कर्नाटक	39600	32183	48500	42500	8000	5400	10000	7500	2000	2000	57000	49900
13	केरल	19500	13984	18073	12617	636	-364	3000	1500	-	-	19566	17066
14	मध्य प्रदेश	20496	15001	22371	16550	4000	4000	4000	2000	2000	1000	24000	21000
15	महाराष्ट्र	20869	3107	48498	32998	5500	350	-	-	-	-1875	65000	50925
16	मणिपुर	970	667	1757	1254	-	-	180	180	150	-	1030	880
17	मेघालय	1122	863	1344	1070	-	-100	365	325	106	106	1521	1331
18	मिज़ोरम	0	-123	900	745	232	232	100	100	90	50	864	724
19	नगालैंड	822	355	1000	423	314	314	220	220	-	-	1284	1084
20	उड़ीसा	5500	4500	7500	6500	-	-1000	-	-	-	-	3000	2000
21	पुदुचेरी	825	475	970	470	200	-	100	100	250	250	900	700
22	पंजाब	22115	17053	27355	18470	3321	1871	3307	1507	2200	1400	23723	14723
23	राजस्थान	33178	20186	39092	24686	3761	3261	5000	5000	3700	3700	42911	35829
24	सिक्किम	1088	795	809	481	312	312	-	-	204	204	1131	1131
25	तमिलनाडु	43125	32278	62425	49826	4000	3375	5000	3175	6500	5875	69500	58619
26	तेलंगाना	26740	22183	37109	30697	3573	3156	7000	6792	3000	2583	39534	35158
27	त्रिपुरा	1543	1387	2928	2578	413	413	600	600	-	-	1713	1613
28	उत्तराखंड	46000	33307	69703	52744	4000	4000	8000	6922	12000	11500	45500	31213
29	उत्तरप्रदेश	6300	5289	5100	4500	-	-	-	-	500	208	4200	3208
30	पश्चिम बंगाल	42828	30431	56992	40882	4000	3500	5500	5500	7000	7000	42000	32500
	कुल	478323	348643	634521	487454	63219	47094	64826	53583	55800	45239	611652	500818

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम₂ और एनएम₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
 एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
 जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाए गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओ/शाखाओ के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का सकेंतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

○ बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल हैं।

○ जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जुला. 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2020-21 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

:- नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

'वर्तमान सांख्यिकी' का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2021	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2019-20	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 2, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपेपर, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001।

एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।